नक्सली हिंसा के विरुद्ध

गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आयोजित एक सम्मेलन में नक्सलियों से हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटने की जो अपील की है, उसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए. जाहिर है, इस साल सुरक्षा बलों की कार्रवाई में बड़ी संख्या में नक्सलियों के मारे जाने की पृष्ठभूमि में गृह मंत्री द्वारा की नक्सलियों से की गयी आत्मसमर्पण की अपील मायने रखती है. उन्होंने इस दौरान दो आंकड़े भी रखे. एक यह कि हाल के वर्षों में नक्सली हमलों में सुरक्षा बल के जवानों के मारे जाने के आंकड़े घटे हैं. और दूसरा यह कि इस दौरान नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के अभियान में तेजी आयी है. वास्तविकता यह है कि 2019 से छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में दबाव बढ़ाने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के 277 नये कैंप स्थापित किये गये. उसके बाद से नक्सलियों के खिलाफ आक्रामक अभियान चलाया गया और सुरक्षा बलों को उसमें सफलता भी मिली. अकेले इसी वर्ष राज्य के बस्तर समेत दूसरे इलाकों में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में भारी संख्या में नक्सली मारे गये और बहुतों ने आत्मसमर्पण किया. दरअसल नक्सली समस्या के समाधान के लिए सरकार दोतरफा रणनीति अपना रही है. एक तरफ नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज किया गया है, तो दूसरी ओर, स्थानीय लोगों, युवाओं और जनजातीय समाज के प्रमुखों को एक मंच पर लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि हिंसा के रास्ते पर चले लोग मुख्यधारा में शामिल हों. गृह मंत्री ने कहा भी हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास की जिम्मेदारी सरकार की है. उन्होंने यह तो कहा ही कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सलियों से मुक्त कर दिया जायेगा, उनका यह भी कहना है कि छत्तीसगढ़ के नक्सलियों से मुक्त होते ही देश नक्सल मुक्त हो जायेगा. उनका कहना था कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद से 287 नक्सली मारे गये, 992 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और 836 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया. यह आंकड़ा ही बताता है कि पिछले एक साल में छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ कितना सघन और आक्रामक अभियान चलाया. इसका दूसरा पहलू यह है कि आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों और नक्सली हिंसा का शिकार लोगों के विकास के लिए सरकार छत्तीसगढ़ में विशेष योजनाएं ला रही हैं, जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 15,000 पक्के मकान बनाना भी शामिल है. इस दोहरी रणनीति से छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या के समाधान की उम्मीद पैदा होती है.

छत्तीसगढ़ में नक्सली समस्या के समाधान के लिए सरकार ने आक्रामक अभियान चलाने के साथ आत्मसमर्पण करने वालों के पुनर्वास की जो योजना चलायी है, उससे उम्मीद बनती है.

भारत में नहीं चला सोरोस का एजेंडा

प्रभु चावला
एडिटोरियल डायरेक्टर
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस
prabhuchawla@newindianexpress.com

संसद में पिछला सप्ताह जॉर्ज सोरोस पर लगे आरोप-प्रत्यारोप में बीता. सरकार का आरोप है कि देश को अस्थिर करने के लिए सोरोस के फाउंडेशन ने यहां 18 अरब डॉलर की फंडिंग की है. सोरोस वह व्यक्ति हैं, जिन्होंने इंग्लैंड के केंद्रीय बैंक को ध्वस्त कर उसकी अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला दिया था. लेकिन उनकी तकलीफ यह है कि अपनी अकूत धनराशि और वैश्विक प्रभाव के बावजूद भारत में वह अपने एजेंडे में सफल नहीं हो पाये.

भाजपा और कांग्रेस के झगड़े में इस बार ड्रैगन सेंट जॉर्ज पर भारी पड़ रहा है. जॉर्ज सोरोस की डाका डालने की आदत 1992 में पहली बार सामने आयी थी, जब उन्होंने ब्रिटिश पाउंड पर बाजी लगायी, एक अरब अमेरिकी डॉलर का मुनाफा कमाया और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को घुटने पर ला दिया. इस बार 94 वर्षीय हंगेरियन-अमेरिकी अरबपति व्यापारी, निवेशक, परोपकारी और उदारवादी राजनीतिक कार्यकर्ता के निशाने पर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार है. भगवा संगठन जोर-शोर से आरोप लगा रहा है कि कांग्रेस के साथ साठगांठ कर सोरोस भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने में लगे हैं. हालांकि उसके आरोप अब तक बेअसर ही रहे हैं, लेकिन इसके जरिये लगभग सप्ताह भर से संसद में कामकाज ठप करने में वह सफल रहा है. सोरोस का 25 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति पर नियंत्रण है, जिनमें छह ओपन सोसाइटी फाउंडेशन भी शामिल हैं. उनकी व्यक्तिगत संपत्ति आठ अरब डॉलर से अधिक है. भारत में उस पर लग रहे राजनीतिक आरोप का कारण उसके फाउंडेशन द्वारा देश में 18 अरब डॉलर की फंडिंग करना है.

सोरोस भाजपा के निशाने पर ऐसे ही नहीं हैं. उन्होंने भारत के घरेलू मामले में न केवल निरंतर दखल दिया है, बल्कि नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमले भी किये हैं. लाखों डॉलर का निवेश कर करोड़ों डॉलर कमाने वाले सोरोस दरअसल विभिन्न देशों में सत्तारूढ़ पार्टियों को उपकृत करने का काम करते हैं. कांग्रेस, उसके पुराने नेताओं और रिटायर हो चुके अनेक नौकरशाहों ने सोरोस के आतिथ्य का लाभ उठाते हुए अपने वैश्विक एजेंडों को आगे बढ़ाया है. सोरोस का मॉडल पारदर्शी है. वह उन देशों में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की नींव रखते हैं, जिन्हें वह बंद समाज मानते हैं. और इस तरह वह उन देशों की सामाजिक-राजनीतिक माहौल को बाधित करते हैं. इससे पहले चीन, रूस और तुर्किये उनके निशाने पर थे. चूंकि भारत में कांग्रेस की सरकारें और सोरोस वैचारिक रूप से एक-दूसरे के अनुकूल रहे हैं, लिहाजा इस निर्लज्ज व्यापारी ने कांग्रेस के नेताओं को शायद ही कभी निशाना बनाया. इसके बजाय अपने संगठनों के जरिये उन्होंने इन नेताओं को वैश्विक फोरमों में उपकृत ही किया. भाजपा ने सोनिया गांधी पर सोरोस से संबंधित ऐसे ही एक अंतरराष्ट्रीय फोरम के लिए काम करने का आरोप लगाया है. पिछले सप्ताह संसद में भाजपा और विपक्ष के बीच का टकराव पूरी तरह सोरोस पर केंद्रित रहा. कांग्रेस द्वारा भाजपा पर अडानी को बचाने के आरोप पर भाजपा ने यह कहते हुए पलटवार किया कि सोरोस विपक्ष की प्रेरणा हैं. संसद में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरोप लगाते हुए कहा, 'इस देश को अस्थिर करने के लिए सोरोस ने अरबों डॉलर का निवेश किया है. और कांग्रेस चूंकि उसकी कठपुतली है, इसलिए वह सोरोस की भाषा बोलते हुए देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है. इसकी निंदा की जानी चाहिए. देश जानना चाहता है कि सोनिया गांधी का कांग्रेस से क्या रिश्ता है.' उनके कई सहयोगियों ने उनका समर्थन किया और सोनिया गांधी के परिवार के सोरोस से रिश्तों के बारे में सोशल मीडिया पर बहुत कुछ लिखा.

इस आरोप पर कांग्रेस झुकी नहीं. इसके बजाय वह आक्रामक दिखी. पार्टी के 'राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जवाबी हमला बोलते हुए कहा, प्रधानमंत्री से मेरे कुछ सवाल हैं : क्या आप एस जयशंकर से इस्तीफा लेंगे? क्या आप शमिका रवि से इस्तीफा मांगेंगे? क्या आप तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि से इस्तीफा मांगेंगे? और आगे क्या आप इस संदर्भ में जांच करायेंगे कि इन लोगों ने विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश को अस्थिर करने की, देश को नुकसान पहुंचाने की भीषण कोशिश किस तरह की? इन पर देश को अस्थिर करने के लिए जॉर्ज सोरोस से फंड लेने का आरोप है. हमें आपके जवाब का इंतजार है.' पवन खेड़ा का आरोप है कि जयशंकर के बेटे सोरोस के फाउंडेशन से जुड़े हैं. हालांकि भाजपा ने इस आरोप का खंडन किया है. सोरोस ने दरअसल नरेंद्र मोदी पर 2019 में जोरदार हमला बोला था, जब उनके नेतृत्व में भाजपा केंद्र की सत्ता में लौटी थी. जनवरी, 2020 में वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम में सोरोस ने कहा था, 'राष्ट्रवाद पीछे हटने के बजाय और मजबूत हुआ है. सबसे बड़ा और भयभीत करने वाला झटका भारत में लगा है, जहां लोकतांत्रिक तरीके से चुने गये नरेंद्र मोदी भारत को हिंदू राष्ट्रवादी देश बनाने की कोशिश में लगे हैं. वह कश्मीर जैसे अर्ध स्वायत्त मुस्लिम क्षेत्र में दंडात्मक कार्रवाई कर रहे हैं और वहां के लाखों मुस्लिमों की नागरिकता छीन लेने की धमकी दी है.' फरवरी, 2023 में म्युनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में मोदी, जिनपिंग और एर्दोगन सोरोस के निशाने पर थे. वहां अडानी का जिक्र कर मोदी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा था, 'मोदी इस मुद्दे पर खामोश हैं, लेकिन उन्हें संसद और विदेशी निवेशकों के सवालों के जवाब देने ही पड़ेंगे.' अपने प्रशंसकों और अपनी वित्तपोषित संस्थाओं के बीच लोकतंत्र के उद्धारकर्ता की छवि वाले सोरोस की भविष्यवाणी थी कि अडानी का मुद्दा नरेंद्र मोदी को राजनीतिक रूप से कमजोर करेगा, जिसका नतीजा भारत में सांस्थानिक सुधारों के रूप में सामने आयेगा. उन्होंने कहा था, 'मैं राजनीतिक रूप से नौसिखिया हो सकता हूं, लेकिन मुझे भारत में लोकतांत्रिक सुधारों की उम्मीद है.' लेकिन इस देश के मतदाताओं ने मोदी को तीसरी बार चुनकर सोरोस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया.

सत्ता में लौटने के बाद भाजपा ने सोशल मीडिया पर सोरोस पर जमकर हमला बोला है. सबसे तीखा हमला जयशंकर ने बोला. उन्हें माना कि अपना एजेंडा पूरा करने के लिए सोरोस विभिन्न संस्थाओं को भारी फंडिंग कर रहे हैं. भाजपा ने यह भी पाया है कि संसद में विपक्ष के आरोप वही हैं, जो आरोप सोरोस लगाते हैं. सोरोस के जरिये सरकार बनाने या गिराने का आरोप लगाना कुछ ज्यादा ही है. सरकार को अस्थिर करने के लिए साजिश का आरोप लगाना पार्टी या नेतृत्व की कमजोरी का ही प्रमाण है. मोदी इस देश के निर्विवाद नेता हैं. पहले गुजरात, फिर नयी दिल्ली में रहते हुए उन्होंने अनेक 'वैश्विक आरोपों' का मुकाबला किया है. किसी अकेले सोरोस में भारतीय राजसत्ता को खरोंच तक लगाने की क्षमता नहीं है, इसके लिए कई सोरोस को कई दशक लगेंगे. सोरोस पर आरोप लगाकर उन्हें व्यर्थ ही इतना ताकतवर बना दिया जा रहा है. सोरोस को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, जिसने इंग्लैंड और थाईलैंड के केंद्रीय बैंकों को ध्वस्त कर डाला था. लेकिन सोरोस को यह दुख रहेगा कि अपनी अकूत धनराशि के जरिये वह नरेंद्र मोदी का वोट बैंक नहीं तोड़ पाये. **(ये लेखक के निजी विचार हैं.)**

तबले की ताल का एक युग थे उस्ताद जाकिर हुसैन

डॉ कृष्ण कुमार रत्तू
सांस्कृतिक विषयों के जानकार
kkrattu@gmail.com

स्मृति शेष

ग्यारह साल की उम्र में पहला कंसर्ट करने के बाद से तबला उनकी जिंदगी का जुनून बन गया था. उनके जाने से संगीत की लय और ताल का एक युग खत्म हो गया है.

उस्ताद जाकिर हुसैन के जाने से भारतीय संगीत की लय और ताल का एक युग खत्म हो गया है. तबले की लयकारी तथा संगीत के साथ विज्ञापनों की दुनिया में उन्होंने तहलका मचाया था. चाय को 'वाह ताज' कहने वाले उस्ताद की उंगलियों में हुनर का जादू था. उस्ताद जाकिर हुसैन तबले को गोद में रखकर सोते थे. वह कहते थे कि गणेश वंदना से लेकर बारिश की बूंदें और शिव का तांडव जिस नजाकत से मन के अंदर रूह से संवाद करता है, उसका कोई मुकाबला नहीं है. पिछले कुछ दिनों से वह सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में दाखिल थे. उन्हें इडियोपेथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस नाम की बीमारी थी. जाकिर हुसैन ने शुरुआती तालीम अपने पिता संगीतज्ञ और तबलावादक उस्ताद अल्ला रक्खा से ली थी. ग्यारह साल की उम्र में अमेरिका में एक समारोह में उन्होंने अपना पहला कंसर्ट किया था. बाद के 63 वर्षों वर्षों तक उन्होंने तबले को ही जिया. तबला उनकी जिंदगी का जुनून बन गया था. वह एक ऐसे उस्ताद थे, जिन्होंने तबले से लेकर संगीत तथा फिल्मों से लेकर अंतरराष्ट्रीय कंसर्ट तक अपने हुनर का जादू दिखाया.

उस्ताद हमेशा कहते थे कि जिंदगी जीने का नाम है, दमदारी का नाम है. वह कहा करते थे- "जिंदगी अपनी शर्तों पर जियो, यह दोबारा लौटकर नहीं आयेगी." उस्ताद जाकिर हुसैन का जन्म जम्मू-कश्मीर के झगवाल संभाग में हुआ था. बाद में कुछ समय तक वह पंजाब के गुरदासपुर में भी रहे. और जब एक बार सफर शुरू हुआ, तो फिर लौटकर पीछे मुड़ कर उन्होंने नहीं देखा. उनके जन्म होते ही उनके पिता उस्ताद अल्ला रक्खा ने उनके कान में जो राग सुनाया था, वह भी चौंकाने वाला था.

उस्ताद हरफनमौला शख्सियत के मालिक थे. उन्होंने 'सैंड एंड डस्ट' जैसी फिल्म में 1983 में अभिनय किया, एक कलाकार की हैसियत से अपनी छाप छोड़ी तथा उसके बाद 'द परफेक्ट मर्डर' जैसी हॉलीवुड की फिल्मों में काम करते हुए अपनी दमदार कलाकारी के जौहर भी दिखाये. परंतु उनका पहला इश्क तबला था. अपनी एक मुलाकात में उस्ताद ने बताया था कि मुझे प्रेम की ताल से अपनी मां जैसा चेहरा दिखता है और यही मुझे रूह के साथ जोड़ता है और मैं उसे लोगों के साथ जोड़ देता हूं. वह बड़ी नजाकत से शिव के डमरू तांडव तथा शंकर से लेकर बारिश की हल्की बूंदों का महीन और बारीक संगीत यंत्रों की ध्वनियों के साथ पेश करते थे. महान बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया तथा संतूर वादक पंडित शिवकुमार शर्मा के साथ उनकी जुगलबंदी संगीत का अद्भुत महा आकाश पैदा करती थी. उनमें संगीत की आकाशगंगा के ध्रुवतारे उस्ताद जाकिर हुसैन ही थे.

उस्ताद जाकिर हुसैन
(9 मार्च, 1951–15 दिसंबर, 2024)

वह कई बार कहते थे कि हम जो कुछ करते हैं, वह शिव महिमा और श्री गणेश वंदना से शुरू होता है, फिर पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड उसमें समा जाता है. यही ताल और लय का संवाद है, जिसे उस्ताद ने जी भर कर जिया. उस्ताद उन्हें पंडित रविशंकर ने कहना शुरू किया था. उनका पहला एल्बम महज 12 साल की उम्र में ही 1973 में 'लिविंग इन द मैटेरियल वर्ल्ड' आया था. उन्हें भारत सरकार की ओर से 37 साल की उम्र में पद्मश्री से नवाजा गया. उसके बाद पद्मभूषण और पद्मविभूषण से भी उन्हें सम्मानित किया गया. पूरी दुनिया में घुमंतू उस्ताद के तौर पर संगीत की पताका फहराने वाले उस्ताद को आगरा बेहद पसंद था. वह हमेशा कहते थे कि आगरा किस्मत वालों को मिलता है. एक मुलाकात में उन्होंने बताया था कि उनकी मां नहीं चाहती थीं कि वह तबला बजायें, परंतु तबला उन्हें अच्छा लगता था. वह कहते थे कि जिस राग को बचपन में मैंने अनजाने में अपने पिता से कान में सुना था, वह मुझे इस मुकाम पर ले आया है. उस्ताद जाकिर हुसैन शास्त्रीय संगीत के साथ-साथ जैज फ्यूजन जैसे विश्व संगीत के विशेषज्ञों में गिने जाते थे. उन्हें कई बार ग्रैमी अवार्ड से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया था.

फिल्म 'सैंड एंड डस्ट' में काम करने के बारे में उन्होंने कहा था कि उसके सह अभिनेता शशि कपूर ने उनसे कहा था कि तुम मेरे से ज्यादा दमदार एक्टर हो, तो उस्ताद ने एकदम से कहा कि चलो, हम गुरु-शिष्य हो जाते हैं. शबाना आजमी के साथ 'साज' में वह एक प्रेमी के रूप में नजर आये थे. यह उस्ताद ही थे, जिन्हें 2016 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने स्टार ग्लोबल कंसर्ट में हिस्सा लेने के लिए विशेष तौर पर आमंत्रित किया था. उस्ताद जाकिर हुसैन उसमें शामिल होने वाले भारत के पहले संगीतकार थे.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

देश दुनिया

अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के चीन के प्रयास नाकाफी

https://t.me/AllNewsPaperPaid

कोरोना महामारी खत्म होने और जीरो कोविड लॉकडाउन हटाने के लगभग दो वर्ष बाद भी चीन की अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं लौटी है. वर्ष 2024 की पहली तीन तिमाहियों में आर्थिक वृद्धि 4.8 प्रतिशत रही. वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कमी, कमजोर उपभोक्ता मांग और रियल एस्टेट में भारी गिरावट के कारण चीन की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है. इसके अतिरिक्त, अमेरिका के साथ जारी व्यापारिक तनाव ने चीन के निर्यात को भी नुकसान पहुंचाया है. डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में यह तनाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है. 'यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड' के 'चाइना सेंटर' में रिसर्च एसोसिएट और यूबीएस के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री जॉर्ज मैग्नस की मानें, तो 'चीन काफी ज्यादा उत्पादन और कम खपत की समस्या से जूझ रहा है. चीनी नेताओं ने आखिरकार यह मान लिया है कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार सुस्त होती जा रही है और यह कोई अस्थायी समस्या नहीं है.' इसी वर्ष सितंबर में चीन ने बैंकों में 2.7 ट्रिलियन युआन (370 अरब डॉलर) डाला, ताकि बैंक ज्यादा कर्ज दे सकें. इसके अलावा, ब्याज दरें कम की गयीं. नये बुनियादी ढांचे पर खर्च करने और कर्ज में डूबे रियल एस्टेट डेवलपरों की मदद करने की घोषणा की गयी. पिछले महीने चीन की सरकार ने क्षेत्रीय सरकारों के कर्ज संकट को कम करने के लिए 10 ट्रिलियन युआन की एक और सहायता पैकेज की घोषणा की. पर मैग्नस का मानना है कि नये उपायों से विकास दर पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा. ये उपाय केवल स्थानीय और प्रांतीय सरकारों पर बजट में कटौती करने का दबाव कम करेंगे. चीनी मामलों के कई अन्य जानकार भी मानते हैं कि हाल के प्रोत्साहन उपाय पर्याप्त नहीं हैं, खासकर जब ट्रंप जनवरी 2025 में व्हाइट हाउस लौटने पर चीन के आयात पर नये शुल्क लगाने की धमकी दे रहे हैं. **-निक मार्टिन**

बोधि वृक्ष

वर्तमान को स्वीकार करना जरूरी

एक व्यक्ति बहुत समय से बेरोजगार था. एक दिन उसे एक नौकरी के लिए बुलावा आया. जब उसे नौकरी नहीं मिली, तो हताश-निराश होकर एकांत स्थान पर बैठ सोच में डूब गया. तभी किसी ने उसका कंधा थपथपाया. पलटकर उसने देखा, तो धूप का चश्मा पहने एक बच्चा खड़ा था. यद्यपि वह इस एकांत के भंग होने पर झल्लाया, परंतु अपनी झल्लाहट छिपा गया. इतना ही पूछा कि क्या बात है? बच्चे ने उसे एक मुरझाया हुआ फूल देते हुए कहा, 'इस सुंदर फूल को देखो.' अब उसे थोड़ा और क्रोध आया, इस बार भी उसने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं किया. इतना ही कहा, 'हां, सुंदर है.' बच्चे ने कहा, 'यह केवल देखने में ही सुंदर नहीं, इसकी सुगंध भी बहुत अच्छी है.' अब तो उस व्यक्ति को सचमुच क्रोध आ गया. उसने सोचा, यह बच्चा पागल तो नहीं? बासी फूल को लेकर क्यों मेरे पीछे पड़ा है? उसने तंग आ कर कहा, 'हां, तुम ठीक कहते हो. यह सुंदर व सुगंधित फूल है.' बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा, 'मैं इसे आप ही के लिए लाया हूं. ले लीजिए. परमात्मा आप पर कृपा करें. अब उसे थोड़ा बेहतर लगा, शांति का अनुभव हुआ. बच्चे का धन्यवाद करके वह क्षितिज में ताकने लगा. तभी उसने धरती पर कुछ थपथपी होती महसूस की. देखा तो वह बच्चा एक छड़ी लेकर खड़ा था. उसे बोध हुआ कि बच्चा अंधा है. उस क्षण उसे अनुभव हुआ कि उसने हाथ में जो फूल पकड़ा था, वह वास्तव में विश्व का सबसे सुंदर और सुगंधमय फूल था. उसने बच्चे को गले लगा लिया. भावविभोर होकर आंखों में आंसू लिए हुए वह बोला, 'यह कोई सामान्य फूल नहीं. यह वह फूल है जो तुम्हारे हृदय में खिला है.' वह व्यक्ति अभिभूत था. नौकरी न मिलने के कारण वह इतना निराश, हताश था कि उसके मन में जीवन का अंत करने का विचार भी आया. और यहां यह बच्चा दोनों आंखें खोकर भी न केवल प्रसन्न था, अपितु दूसरों में भी प्रसन्नता बांट रहा था. दूसरों की समस्याओं की तुलना में हमारी समस्याएं, प्रायः तुच्छ होती हैं. अतः हमें अपने वर्तमान को स्वीकारते हुए खुशी-खुशी जीवन बिताना चाहिए. **-श्री माता अमृतानंदमयी देवी**

कुछ अलग

तकनीक से जुड़ी चुनौतियां

मुकुल श्रीवास्तव
मुक्तांत्र टिप्पणीकार
srivastava_mukul@lkouniv.ac.in

जहां एक ओर तकनीक संचार को त्वरित और सुलभ बना रही है, वहीं दूसरी ओर इसका प्रभाव मानवीयता पर भी पड़ा है. संचार में मानवीय भावनाएं, आवाज की गर्माहट, और चेहरों के भाव धीरे-धीरे गायब होते जा रहे हैं. जो समस्याओं को सुलझाने के बजाय और बिगाड़ रही हैं. सोशल नेटवर्किंग साइट्स हों या हमारे जीवन को आसान बनाने वाली ऑनलाइन कंपनियां, हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन गयी हैं. चाहे अमेजन जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सामान मंगाना हो या उबर, ओला जैसी कैब सर्विस से कहीं जाना, इन एप बेस्ड कंपनियों ने हमारे रोजाना के कामों को सरल और सुविधाजनक बना दिया है. मगर इन तकनीकों और ऑनलाइन सेवाओं के लाभ के साथ कुछ चुनौतियां और समस्याएं भी जुड़ी हुई हैं.

इन प्लेटफॉर्मों पर हमारे पास सीधे और व्यक्तिगत संपर्क की कमी होती है, जिससे हमारी समस्याओं का समाधान मुश्किल हो जाता है. फेसबुक उपयोगकर्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए केवल हेल्प, सपोर्ट और रिपोर्ट जैसी सुविधाएं प्रदान करता है, जो एकतरफा तंत्र के अलावा कुछ भी नहीं है. जैसे, यदि आप अमेजन या फ्लिपकार्ट से कोई उत्पाद खरीदते हैं और वह खराब निकलता है, तो आपको अक्सर चैटबॉट से ही मदद मिलती है. वास्तविक कस्टमर सर्विस प्रतिनिधि से संपर्क करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है. इसी तरह, यदि फूड डिलीवरी एप पर आपके ऑर्डर में खराब या गलत भोजन आता है, तो आपको स्वचालित सपोर्ट और लंबे इंतजार का सामना करना पड़ता है.

इन प्लेटफॉर्मों पर स्वचालित सहायता और सीमित विकल्पों के कारण समस्या घंटों तक उलझी रहती है. यह स्थिति ग्राहक को निराश कर देती है. वहीं दूसरी ओर, ग्राहक सेवा क्षेत्र में तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल से इन नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है. धीरे-धीरे मौखिक संचार को कम कर कंपनियों ने एआइ चैटबॉट्स को तरजीह देनी शुरू कर दी है, इससे कंपनियों को ग्राहक सेवा में खर्च कम पड़ रहा है. इस कटौती की शुरुआत कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव की संख्या घटाने से शुरू हो गयी है.

तकनीक के अंधाधुंध प्रयोग से मानवीय संवाद का स्थान एक निर्जीव तंत्र ने ले लिया है, जहां अब समस्याओं का समाधान मशीनों और बिना मौखिक संवाद से बातचीत द्वारा किया जाता है. यह सिर्फ व्यापार और ग्राहक सेवा तक ही सीमित नहीं है, इसका प्रभाव हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों पर भी पड़ रहा है. यह महत्वपूर्ण समय है, जब हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि तकनीक उलझाने के बजाय हमारे जीवन को सुगम बनाये.

आपके पत्र

मोबाइल की लत ने छीना बचपन

सभी के लिए मोबाइल जरूरी वस्तु बन गयी है. इससे कई तरह के कामों में आसानी भी हुई, लेकिन छोटे बच्चों को इसकी लत लग गयी है, जिससे उनका बचपन छीन गया है. कोरोना काल के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई के कारण छोटे बच्चे मोबाइल के करीब आ गये. इस दौरान उन्हें मोबाइल पर गेम खेलने की लत लग गयी. मोबाइल के उपयोग से उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है. बच्चों को मोबाइल से दूर करने के लिए आउटडोर गेम के के प्रति रुचि पैदा करें. घर से बाहर खेलने से स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा.

अशोक कुमार, कटिहार

महंगाई ने बिगाड़ा किचेन का बजट

पिछले तीन से चार साल में खाद्य पदार्थों की कीमतों में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिससे लोगों का बजट बिगड़ गया है. कोरोना काल के बाद से लोगों की आमदनी कम हुई है, जिससे लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ा है. साथ ही खुदरा बाजार में सामान की बिक्री पर इसका असर दिख रहा है. घटती आमदनी के कारण खान-पान में आम लोगों का बजट कम हुआ है, जिसका असर स्वास्थ्य पर पड़ रहा है. केंद्र व राज्य सरकारों को बढ़ी महंगाई को कम करने के लिए ठोस नीति बनानी चाहिए.

आलोक रंजन, समस्तीपुर

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । मुंबई । मंगलवार, 17 दिसंबर 2024

चुनौतियों के बीच राह

विशाल बहुमत से शानदार जीत दर्ज करने के बावजूद महाराष्ट्र की महायुति सरकार जिस धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, उसे सतर्कता कहा जाए या बहुमत का बोझ, यह तय करना फिलहाल मुश्किल है। 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आने के 12 दिन बाद देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ ले पाए और उसके भी दस दिन बाद मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो सका। विभागों का बंटवारा होना अभी भी बाकी है।

सहज सर्वोच्चता | वैसे मौजूदा सरकार के स्वरूप पर गौर करें तो यह स्थिति ज्यादा अस्वाभाविक नहीं लगती। भले ही शिवसेना और NCP से अलग हुए धड़ों के साथ BJP की सरकार करीब ढाई साल कामयाबी से चली। फिर चुनाव में राज्य के वोटरों ने भी इस अलायंस पर सहमति की मुहर लगा दी। लेकिन इस जीत के बाद महायुति के आंतरिक समीकरण में बुनियादी अंतर आ गया है। विधायकों की संख्या चाहे कम ज्यादा रही हो, पहले एकनाथ शिंदे इसके सर्वमान्य नेता थे। अब सबसे बड़ी पार्टी का नेता होने के बावजूद इस सत्तारूढ़ गठबंधन के अंदर देवेंद्र फडणवीस की सहज सर्वोच्चता स्थापित होने में थोड़ा वक्त लग सकता है।

सरकार की धीमी रफ्तार

जारी है रस्साकशी | शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के लिए गठबंधन में अपनी दूसरे नंबर की हैसियत को पचाना और अपने समर्थकों से स्वीकार कराना मुश्किल हो रहा है। उपमुख्यमंत्री पद के लिए राजी हुए तो मंत्रियों की कम संख्या का सवाल आड़े आया और अब विभागों के बंटवारे को लेकर आखिरी पलों तक रस्साकशी होनी है।

ढाई साल का कार्यकाल | तीनों पार्टियों में चल रही इस असामान्य रस्साकशी का एक रूप कहिए या विधायकों की बढ़ी हुई संख्या का दबाव, पर महाराष्ट्र में मंत्रियों के लिए ढाई साल के कार्यकाल का नया फॉर्म्युला सामने लाया गया। राजनीतिक मजबूरियों के बीच रास्ता निकालने की कला के तौर पर निश्चित रूप से यह अच्छा कदम है। हो सकता है इससे मंत्रियों पर बेहतर काम करने का दबाव भी रहे। लेकिन संसदीय लोकतंत्र में मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के तहत काम करता है। ऐसे में सार्वजनिक तौर पर मंत्रियों को नाकाम करार दिए जाने को लेकर यह खुलापन भी सवालों से परे नहीं है।

स्थिरता और कामकाज | बहरहाल, लोकतंत्र नई चुनौतियों के नए हल निकालते हुए ही आगे बढ़ता है। ऐसे में महाराष्ट्र की नई सरकार को लेकर भी अभी से फैसले सुनाना सही नहीं होगा। तमाम मजबूरियों के बीच भी फडणवीस सरकार को स्थिरता और कामकाज की दो सबसे बड़ी कसौटियों पर ही खुद को साबित करना है और भूलना नहीं चाहिए कि महाराष्ट्र ने उस पर अपनी उम्मीदें टिका रखी हैं।

धूप-छांव

गुठलियों के दाम

प्रणव प्रियदर्शी

चाय की चुस्कियां, शाम को होने वाली चहलकदमियां और शतरंज के चंद मोहरे- देखा जाए तो यही हासिल रहा संघर्ष के करीब डेढ़ साल चले उस दौर का। लेकिन इनकी स्मृतियों की चमक फीकी नहीं पड़ रही दो दशक बाद भी। यूं देखिए तो चाय की चुस्कियां कब नहीं थीं जीवन में, चहलकदमियां भी बंद नहीं हुईं, शतरंज जरूर उस दौर की एक्सक्लूसिव चीज कही जा सकती है, पर वह भी एक हद तक ही- मगर उस दौर की पृष्ठभूमि हटाकर देखें तो ये लम्हों में सिमटने वाले अनुभव ही कहलाएंगे। इनमें ऐसी कोई बात नहीं है कि ये महीनों, सालों और दशकों का मुंह देखने की सोच भी सकें।

साफ है कि उन लम्हों को लंबा जीवन उस दौर की चुनौतियों ने दिया। पर वे चुनौतियां कैसी थीं जिनसे वह दौर इतना खास बना? अगर अच्छा खासा चलता हुआ अखबार बंद हो जाए और एक साथ दर्जनों परिवारों के अस्तित्व का सवाल खड़ा हो जाए तो बात कम से कम उन परिवारों के लिए मामूली नहीं होगी। लेकिन वह अखबार भी कोई मामूली नहीं था। गौरवशाली अतीत की विरासत उससे जुड़े हर बंदे के सिर को ऊंचा बनाए रखती थी। ऐसे अखबार की वैसी परिणति भी उन्हें क्षुब्ध बनाए हुए थी। सबसे ऊपर, उनमें अकारण ही चुनौतियों के समुद्र में धकेल दिए जाने का भाव था।

मुंबई के एक उपनगर में बीसवीं और 21वीं सदी के संधिस्थल पर खड़ा वह दौर इन्हीं वजहों से खास बना। साथ में ली जा रही चाय की हर चुस्की के साथ यह सवाल था कि पता नहीं ये कब तक नसीब होंगी। जिसके संग आप वे चुस्कियां ले रहे हैं, वह साहित्य जगत के कितने बड़े नाम हैं, यह सवाल बेतुका हो चुका था। बड़ी बात थी कि वह आपके एकदम साथ खड़े, ATM से पैसा निकालने के बाद आपकी पेशानियों पर पड़े बल को निहारने और उनका मतलब समझने वाले एकमात्र शख्स थे, जो खुद भी उन्हीं परेशानियों से रू-ब-रू थे। मगर कुछ बड़ा और सार्थक करने का संकल्प तब भी छूटा न था। इसी संकल्प ने उनमें से किसी को अपनी सारी जमा-पूंजी लगाकर नई वेब पत्रिका शुरू करने का हौसला दिया तो कुछ अन्य को आधी तनख्वाह पर उससे जुड़ने की हिम्मत दी। किसी को बगैर कोई मेहनताना लिए किसी किताब के अनुवाद में लगा दिया तो कोई नया उपन्यास लिखने में जुट गया। शतरंज के चंद निर्जीव मोहरे इन हौसलों में अपने ढंग से कुछ इजाफा कर देते थे। हालांकि कुछ समय में लगभग ये तमाम प्रयास कोई बड़ा फल दिए बगैर चुक गए, लेकिन वह दौर भी तो बीत गया। और पलटकर देखें तो वे चुस्कियां, चहलकदमियां और मोहरे आम के आम, गुठलियों के दाम की तर्ज पर अब तक साथ बने हैं।

बोल वचन

बोरी में बतिया-पाकल

राहुल पाण्डेय

इस बार ठीक से अचार नहीं बन पाया। न आम का, न कटहल का। हुआ यूं कि गर्मी में पप्पू बुआ की लड़की मन्नू जब ससुराल जाने लगी, तो बतिया-पाकल सब तुड़वाकर बोरी में भरकर अपने साथ ले गई। अम्मा ने पूछा तो ठुनककर कहती है, यहां कौन है खाने वाला? अम्मा बोलीं, पाकल आम और कटहल का अचार कहां बनता है? मन्नू और नाराज, बोली- बाग में बतिया-पाकल सब गिरा पड़ा है। कोई खाने वाला होता तो ऐसे गिरा होता? बतिया, यानी फूल से फल बस बना ही है, और पाकल, यानी पका हुआ। पाकल फल ही नहीं होता, इंसान भी होता है, जानवर भी होता है और इन दोनों का दिमाग भी कभी न कभी पकता ही है! पाकल पाका भी होता है, यानी देह में कहीं निकला फोड़ा। शब्दकोशों की मानें तो पाकल अवधी, भोजपुरी और मगही में संस्कृत से आया है। संस्कृत में इसका अर्थ कुष्ठ की ऐसी दवा से है, जिससे यह रोग पूरी तरह से जाता रहे। पाकल फोड़े को पकाने वाली दवा भी है। यह ऐसा बुखार भी है जिसमें पित्त बढ़ जाता है, कफ घट जाता है और सन्निपात की अवस्था होती है। पाकल बुखार वाला जल्दी बचता नहीं। हाथी के बुखार को भी पाकल कहते हैं, और आग को भी। पेड़ से लेकर देह तक, और देह से लेकर हाथी तक पक चुके इस शब्द के लिए इंग्लिश में कोई एक शब्द नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अम्मा की तरह इंग्लिश भी पप्पू बुआ की लड़की मन्नू से डरती हो? आएगी तो सब शब्द बोरी में भर ले जाएगी। पूछने पर कहेगी- अंग्रेजी में कौन पाकल बोलता है जी!

Suibrata Dhar

हाल में लाए गए सैंपल चंद्रमा को ग्रहीय स्तर की नई प्रयोगशाला बना रहे हैं

खुलने लगे हैं चांद की बनावट के रहस्य

चंद्रभूषण

दुनिया में अभी चंद्रमा से जुड़े चीन के कुछ ताजातरीन प्रेक्षणों की चर्चा है। ये प्रेक्षण उन सैंपल्स की बुनियाद पर टिके हैं, जिन्हें चीनी चंद्रयान चांग'ई-6 ने इसी साल जून में धरती पर भेजा था। चंद्रमा से लाए मिट्टी-पत्थर के नमूनों की पहले भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन चांग'ई-6 का मामला इस मायने में अलग है कि पहली बार इसने चंद्रमा की परली साइड से सैंपल जुटाए हैं।

सतह की बनावट में असंगति | यहां दो-एक बातें चंद्रमा की दोनों सतहों में मौजूद कुछ मोटे अंतरों को लेकर भी कर ली जाएं। इसकी जो सतह हमें दिखती है, उस पर कुछ पहाड़ भी हैं लेकिन उसका ज्यादातर हिस्सा समतल है। अपोलो-11 जहां उतरा था, वह जगह 'सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी' (शांति समुद्र) कहलाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सतह का 30 फीसदी हिस्सा चंद्रमा के शुरुआती दौर में पिघले लावे से बना है, जिसका जेनरिक नाम बेसाल्ट पत्थर है। चंद्रमा की दूर वाली सतह में इसका योगदान सिर्फ 2 फीसदी का है। उधर कहीं ज्यादा ऊंचे पहाड़ और गहरे खड्ड हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह कि उस तरफ वाली सतह पर पहाड़ों-पठारों की औसत ऊंचाई इधर से 1.9 किलोमीटर ज्यादा है। इस तरह, चंद्रमा एक गोल पिंड जरूर है लेकिन उसकी सतह की बनावट में भारी असंगति है, जो उसे धरती से बहुत अलग बनाती है।

ऊपरी सतह का नयापन | हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ख्याति की शोध पत्रिकाओं 'नेचर' और 'साइंस' में एक ही दिन छपी दो रिपोर्टों में चांग'ई-6 के सैंपल्स को लेकर कुछ दिलचस्प नतीजे पेश किए गए हैं। इनको 108 हिस्सों में बांटा गया था, जिन पर अलग-अलग टीमों ने काम किया। चीनी वैज्ञानिकों और खोजबीन में शामिल एक अमेरिकी विशेषज्ञ का दावा है कि इनमें से 107 सैंपल 2 अरब 80 करोड़ साल से जरा कम-ज्यादा आयु वाले ही पाए गए, जबकि एक नमूने की उम्र 4 अरब 30 करोड़ साल के इधर-उधर पाई गई। खास बात यह कि 1970 के दशक में लाए गए नमूनों की उमर इस अकेले नमूने के ही आसपास नापी गई थी। यानी एक नतीजा यह कि चांद की उधर वाली सतह के पत्थर इधर वाली से काफी नए हैं।

नमूनों में अंतर की गुत्थी | दूसरा नतीजा यह कि चंद्रमा के सारे पुराने सैंपल्स में पोटैशियम, फॉस्फोरस और थोरियम की शिनाख्त की गई थी, जबकि चांग'ई-6 के नमूनों में ये सारे एलीमेंट्स नदारद हैं। स्वतःस्फूर्त ढंग से मिलने वाले नमूनों में तात्विक संरचना की दृष्टि से इतना बड़ा फर्क समझ से परे है। चंद्रमा पर न तो किसी जैविक क्रिया की गुंजाइश है, न ही वहां चीजों की केमिस्ट्री बदल देने वाले हवा-पानी जैसे कारक मौजूद हैं। ज्वालामुखी फटने की घटनाएं भी वहां अब तक सीधे नहीं देखी गई हैं, जो किसी अंतरिक्षीय पिंड की सतह पर रासायनिक बहुलता पैदा करने में अहम भूमिका निभाती हैं। फिर नमूने इतने अलग कैसे हो सकते हैं?

मृत पिंड का निष्कर्ष पुराना पड़ा | चीनी वैज्ञानिकों का कहना है कि इन पत्थरों को बनाने वाला लावा चंद्रमा के भीतर किसी ऐसी जगह से आया हो सकता है, जहां पोटैशियम, फॉस्फोरस और दुर्लभ मृदा तत्वों का अभाव हो। यह प्रस्ताव खुद में अटपटा है, क्योंकि लावा उच्च तापमान वाली जिस तरल सतह की चीज है, वहां कोई ऐसी कोठरी नहीं हो सकती जहां टिका हुआ लावा अपनी अलग केमिस्ट्री बना ले। बहरहाल, एक बात तो तय है कि अमेरिकी वैज्ञानिकों ने अपोलो के सैंपल्स की जांच के बाद जिस तरह चंद्रमा को भूगर्भीय रूप से मृत पिंड कहकर आगे वहां जाना गैरजरूरी बता दिया था, वह मामला खत्म हो चुका है। कम से कम डेढ़ अरब साल इसके जिंदा रहने के सबूत मिल गए हैं।

गड्ढे के नीचे क्या है | एक और खास बात यह कि चांग'ई-6 ने ये नमूने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव-ऐटकिन बेसिन से उठाए हैं, जो न सिर्फ इस पिंड बल्कि समूचे सौरमंडल का सबसे बड़ा क्रेटर (उल्का गिरने से बना गड्ढा) है। यह गड्ढा ढाई हजार किलोमीटर लंबा, दो हजार किलोमीटर चौड़ा और तेरह किलोमीटर तक गहरा है। नासा की सैटलाइट प्रयोगशाला ग्रेल ने 2019 में निष्कर्ष निकाला था कि इस क्रेटर में सतह के नीचे कोई बहुत भारी चीज धंसी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह चंद्रमा पर चार अरब साल पहले गिरी किसी उल्का की धुरी हो सकती है। इसके वजन की माप चंद्रमा के समूचे वजन के तीन सौवें से डेढ़ सौवें हिस्से तक हो सकती है और यह चीज चंद्र-सतह से न्यूनतम 200 और अधिकतम 400 किलोमीटर की गहराई तक धंसी हो सकती है।

उल्का पिंड की धुरी | इतनी गहराई चंद्रमा के मामले में उसी इलाके का संकेत करती है, जहां से ज्वालामुखियों का लावा उठता है। भूगर्भशास्त्र की भाषा में इसे 'इनर मैंटल' कहते हैं। कोर (धुरी) और क्रस्ट (सतह) के बीच की अर्ध-तरल सतह। जाहिर है, मैंटल में तोप के बहुत बड़े गोले की तरह धंसी किसी उल्कापिंड की धुरी वहां की केमिस्ट्री और चंद्रमा की भीतरी ज्योमेट्री बदल सकती है। इस तरह चंद्रमा का चीनी सैंपल हमारे लिए ग्रहीय स्तर की एक ऐसी प्रयोगशाला के द्वार खोल रहा है, जो इसका आकर्षण और बढ़ाने वाली है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

चांद पर उल्का गिरने से बना यह क्रेटर नए सवाल खड़े कर रहा है

न्यू ईयर पार्टी के लिए फ्री वाला आइडिया

नमिता जोशी

मुन्ना भाई सोफे पर आराम से बैठेले हैं। मस्त एकदम किंग के माफिक एक हाथ में चाय का कप और दूसरे हाथ से सर्किट को एक इशारा करके बुलाया। सर्किट, एक झकास न्यू ईयर सेलिब्रेशन प्लान कर। बोले तो नया साल एकदम धमाकेदार होना चाहिए, समझा ना? ऐसा आइडिया लाओ कि लोग बोलें 'वाह मुन्ना भाई वाह!' सर्किट नोटबुक और पेन के साथ आया और बोला, मुन्ना भाई टेंशन नहीं लेने का! सर्किट के दिमाग में एकदम रापचिक आइडिया है! भाई गोवा चलते हैं। बीच पे फुल पार्टी, फायरवर्क्स, म्यूजिक और डीजे वाले बाबा का धमाल एक नंबर!

मुन्ना भाई ने गहरी सांस ली। बोले, ऐ सर्किट, गोवा का नाम भी मत लेना। इंफ्लेशन के चक्कर में प्लान कैंसल है! सर्किट अइसे हैरान होके देखने लगा जइसे नर्सरी क्लास का बच्चा। बोला- भाई, ये इंफ्लेशन कौन है? क्या वो गोवा की टिकट का रेट बढ़ा रहा है? सर्किट के मासूम सवाल को सुन के मुन्ना भाई की हंसी एकदम सीटी के माफिक छूटी, अरे सर्किट, इंफ्लेशन कोई आदमी नहीं है, ये एक बीमारी है... पर्स की! बोले तो इंफ्लेशन का मतलब ये होता है कि चीजों की दाम बढ़ जाते हैं और तेरी जेब में वही 100 का नोट बिचारा पतला हो जाता है।

सर्किट के थोबड़े पे अभी भी question mark था। बोला भाई, अभी भी नहीं समझा अपुन, तुम क्या बोल रयेला है। मुन्ना भाई बोले, मान ले तू बचपन में 10 रुपये लेकर समोसे लेने जाता था। दुकानदार तुझे तीन समोसे देता था।

AI Image

भेजा फ्राई

सर्किट खुश होकर बैकग्राउंड में चला गया, हां भाई वो टाइम बड़ा मस्त था! दस रुपये में अपुन का लंच और डिनर दोनों हो जाता था। अगले दिन पेट खराब हो जाता था तो दूसरा दिन बिना खाए गुजर जाता था। तो एक दस रुपये से दो दिन सेट। मुन्ना भाई बोला, अब वही 10 रुपये लेकर तू समोसे लेने जाएगा तो दुकानदार तुझे सिर्फ समोसे की खुशबू देगा। सर्किट हैरानी से बोला भाई, बस खुशबू क्यों? तो मुन्ना भाई ने कहा, क्योंकि समोसे का दाम बढ़ गया है। इंफ्लेशन! सर्किट गुस्से में बोला, तो भाई अपुन आज उस समोसे वाले को नहीं छोड़ेगा। वो ठग है भाई!

नहीं सर्किट, समोसे वाला ठग नहीं ये जमाना ठग है। दुनिया का नियम है, सब महंगा होता जाता है। फ्लाइट की टिकट, होटल का रूम, बीच का नारियल पानी... सब डबल रेट पर मिल रहा है। सर्किट उदास होकर तो गोवा कैंसल? मुन्ना भाई फिर से चाय की चुस्की लेते हुए बोला, पूरी तरह से कैंसल। इंफ्लेशन ने गोवा की टिकट पर ताला लगा दिया कोई और प्लान सोचो। तभी चमन चिरकुट बोला, भाई फिर तो अपुन लोग फायर नहीं, फ्लावर वाली मूवी देखने जाएगा। अक्खा इंडिया उस मूवी के वास्ते भगदड़ मचा रयेला है। अभी नए साल को दो वीक और हैं तब तक भगदड़ भी खल्लास हो जाएगा और टिकट भी सस्ता हो जाएगा। अक्खा मूवी हॉल में बादशाह के माफिक बैठ के मूवी देखेंगे। ये सुन के मुन्ना भाई ने भी इंफ्लेशन का इंजेक्शन लगा दिया। टिकट तो सस्ता हो भी जाए पन हॉल के अंदर पॉपकॉर्न और बर्गर के वास्ते अपुन अक्खा महीने का कमाई नहीं लुटा सकता।

पइसा तो भाई अपुन के पास है नहीं। तो अभी अपुन के भेजे में एक और बल्ब जलेला है। एक फ्री वाला आइडिया है भाई। घर की छत पे अपुन मस्त डिस्को लाइट लगाएगा। इस आइडिया से तो इंफ्लेशन भी मात खा जाएग। 31 दिसंबर की रात मुन्ना भाई, सर्किट, चमन चिरकुट और हनीफ हटेला, अक्खा गैंग मुन्ना भाई के अड्डे पर बैठेंगे। अपना घर, अपनी छत, अपनी बिरयानी और अपना म्यूजिक!

मुंबइया स्टाइल में मुन्ना और सर्किट का ये भेजा फ्राई आपको कैसा लगा? हमें अपनी राय लिखकर भेजिए इस मेल आईडी पर **nbtreader@timesofindia.com** और सब्जेक्ट में लिखें-'भेजा फ्राई'

दो साल तक सारी कोशिशें नाकाम होने के बाद लाना पड़ा अविश्वास प्रस्ताव

विशुद्ध राजनीति इंटरव्यू

बीते दिनों विपक्ष राज्यसभा में सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लेकर आया है। विपक्षी दलों ने सभापति जगदीप धनखड़ पर पक्षपात के आरोप लगाए हैं। इस बीच सत्तापक्ष जॉर्ज सोरोस के मामले पर मुखर रहा है, जिसके बाद सदन नहीं चल पाया। विपक्ष की रणनीति और दूसरे अहम मुद्दों पर DMK सांसद **तिरुचि शिवा** से बातचीत की अल्पयू सिंह ने। पेश हैं बातचीत के अहम अंश :

■ I.N.D.I.A. के नेतृत्व को लेकर अलायंस के घटकों में अब अलग-अलग सुर सुनाई दे रहे हैं। TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी के समर्थन में कई दल दिख रहे हैं। DMK का क्या रुख है?

जहां तक DMK की बात है तो हम I.N.D.I.A. के साथ हैं और मजबूती से खड़े हैं।

■ राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की क्या वजह रही?

दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि प्रस्ताव आने के बाद उनका व्यवहार और खराब हो गया है। ऐसा लगता है कि वह इससे चिढ़े हुए हैं। वह सदन में पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। जैसे कि जीरो आवर में 3 मिनट के भीतर ही अपनी बात रखनी होती है। सामान्य प्रक्रिया के तहत अगर इससे ज्यादा बोला जाए तो माइक खुद ऑफ हो जाएगा। लेकिन उन्होंने सत्तापक्ष के सांसद को 6 मिनट से ज्यादा बोलने का मौका दिया।

■ बीते दिनों विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे के माइक को लेकर काफी विवाद हुआ था...

विपक्ष के नेता को दो या तीन बार कहना पड़ता है कि वह अपनी बात रखना चाहते हैं। उन्हें मुश्किल से मौका मिलता है। मौका मिलने पर वह रूलिंग पार्टी का जिक्र करते हैं, तो चेयर या सत्तापक्ष के किसी सांसद की ओर से बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं और उनका माइक बंद कर दिया जाता है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। अरुण जेटली, मनमोहन सिंह, गुलाम नबी आजाद और सुषमा स्वराज विपक्ष के नेता रहे हैं। जब भी वे बोलना चाहते थे, उन्हें फ्लोर दिया जाता था। शुक्रवार को ही देखें, हम अविश्वास प्रस्ताव सामने रख चुके हैं। नियमों के मुताबिक इसे स्वीकार किया जाए या नहीं, यह चेयर या फिर सेक्रेटरी जनरल तय करते हैं। जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, मैंने पॉइंट ऑर्डर के लिए हाथ खड़ा किया। सभापति ने कहा कि आपको मौका दिया जाएगा, लेकिन राधा मोहन अग्रवाल को बोलने का मौका दिया गया। वह 15 मिनट तक बोलते रहे। 67 (B) पर बोलते रहे, जबकि प्रस्ताव पर डिबेट अभी हुई भी नहीं है। अगर प्रस्ताव पर संसद में बहस हो रही है तो चेयरमैन आसन पर कैसे हो सकते हैं?

■ सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष सदन नहीं चलने देना चाहता...

मीडिया में इस तरह की खबरें आती हैं कि विपक्ष संसद नहीं चलने देता चाहता। लेकिन सच यह है कि संसद टीवी चैनल के कैमरे विपक्ष को नहीं दिखाते, बल्कि चेयर और सत्तापक्ष को ही दिखाते हैं। सभापति को विपक्ष की ओर विनती करते दिखाया जाता है। ऐसे में इस तरह का परसेप्शन सामने आता है कि विपक्ष सत्र नहीं चलने दे रहा। सवाल यह भी है कि वे रूल की बात करते हैं तो सत्ता पक्ष लगातार सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम लेकर 238 (A) का उल्लंघन किस आधार पर कर रहा है? क्या स्थगन प्रस्ताव का इस्तेमाल सरकारों को करते देखा है? सत्तापक्ष ही सदन चलने नहीं दे रहा और आरोप विपक्ष पर डाल रहा है। अविश्वास प्रस्ताव हम एकदम से नहीं लाए हैं, बल्कि 2 साल तक हमने बर्दाश्त किया है। जब सारी कोशिशें असफल हो गईं, तो हम इसे लेकर आए।

■ वन नेशन-वन इलेक्शन को स्टालिन ने ड्रैकोनियन कहा है। संसद में इसे लेकर आपकी क्या रणनीति रहेगी?

उन्होंने जो कहा है, वही हमारा स्टैंड है। हम इसके पक्ष में नहीं हैं और शुरुआत से इसका विरोध करते रहे हैं। हमारे कई सवाल हैं, जिसका जवाब सरकार को देना होगा। अगर लोकसभा अपने कार्यकाल से पहले ही भंग हो जाती है तो क्या होगा? वर्ष 1977, 89 , 96, 98 में हम ऐसा होते देख चुके हैं। अगर NDA सरकार गिर जाती है, कोई घटक दल अलग हो जाता है तो क्या वे सारी विधानसभाओं को भंग कर एक साथ चुनाव करवाएंगे? अगर किसी विधानसभा के साथ ऐसा हुआ, तब क्या होगा? जब तक 356 संविधान का हिस्सा है, राज्य सरकारें सेफ नहीं हैं। किसी भी सरकार को गिराया जा सकता है। डेमोक्रेसी हमेशा नंबर पर निर्भर करती है।

रीडर्स मेल www.edit.nbt.in

■ महापुरुषों पर टिप्पणी गलत

संपादकीय 'नेहरू-सावरकर क्यों?' पढ़ा। लोकसभा में संविधान और आरक्षण पर हुई बहस ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की खाई को और भी चौड़ा कर दिया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की 'तू-तू, मैं-मैं' में नेहरू-सावरकर को घसीटने की प्रवृत्ति को रोकने की आवश्यकता है। लोकसभा में संविधान पर दो दिनों तक चली बहस में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने आरक्षण, तानाशाही और संविधान की रक्षा जैसे मुद्दों पर अपने विचार रखे। इस बहस के दौरान महापुरुषों को लेकर भी टिप्पणी की गई, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारे देश की राजनीति में महापुरुषों को लेकर टिप्पणी करना उचित नहीं है। हमें उनकी विरासत का सम्मान करना चाहिए और उनके आदर्शों को अपनाना चाहिए। इसके अलावा, देश के हित में काम करना चाहिए।

-**विभूति बुपक्या,** ईमेल से

■ नई चेतना के राज

संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित लेख 'राज कपूर साहब के आखिरी शब्द' (14 दिसंबर) पढ़ने को मिला। 11 वर्ष की उम्र में ही राज कपूर ने फिल्मों की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया था। राज कपूर अपनी फिल्मों के जरिए समाज को बड़ा संदेश दिया करते थे। अपनी फिल्मों के जरिए उन्होंने नई चेतना का प्रसार किया। आज भले ही राज कपूर साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अपनी फिल्मों के जरिए वह सदियों तक हमारे बीच रहेंगे।

- **मीना धानिया,** ईमेल से

■ कानूनों का दुरुपयोग

संपादकीय लेख 'कौन है स्त्री-पुरुष का यह साझा दुश्मन' (13 दिसंबर) पढ़ा। बेंगलुरु में एक युवा प्रफेशनल द्वारा आत्महत्या करने का मामला दुखद है। इस घटना से कई नए तरह के सवाल भी खड़े होते हैं। विवाह के बाद अक्सर पति और उसके परिवार पर दहेज या घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करके उससे गुजारे-भत्ते की राशि वसूल की जाती है। मानसिक शोषण अलग होता है। हालांकि बेंगलुरु की घटना अभी जांच का विषय है, फिर भी हमें कानून के दुरुपयोग की घटनाओं को रोकना चाहिए।

- **हितेंद्र डेढ़ा,** ईमेल से

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

न्यू जर्सी में ड्रोन या फिर UFO दिख रहे- एक खबर

- यानी रील की शूटिंग अब आसमान तक पहुंच गई है।

महेंद्र मीणा

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

www.speakingtree.nbt.in

सांसारिक वस्तुओं की चाहत मन का चैन छीन लेती है

सलिल पाण्डेय

जीवन में भौतिकता को ही प्रमुख लक्ष्य बना लेना अक्सर खतरनाक होता है, क्योंकि भौतिक वस्तुएं जब तक मिल नहीं जातीं, उनकी चाह बनी रहती है। और जैसे ही वे मिल जाती हैं, उनका सारा क्रेज खत्म हो जाता है और फिर इंसान दूसरी चीजों की चाह रखने लगता है। एक दिन ऐसा आता है कि भौतिक वस्तुओं की भरमार हो जाती है। कुछ बिना इस्तेमाल के खराब होने लगती हैं, जबकि इन्हें पाने के लिए अनर्गल ढंग से पैसे जुटाने से भी परहेज नहीं होता। जब भौतिक वस्तुओं की अधिकता होने लगती है तो घर-परिवार के सदस्य आलसी होने लगते हैं। उनके मन में यह बैठ जाता है कि वे जब जो चाहेंगे, मिल ही जाएगा। जब बिना परिश्रम के सभी वस्तुएं मिलने लगती हैं तो आदतें भी खराब होती हैं। बहुत सारे स्वार्थी लोग झूठी खुशामद करके निकटता भी बना लेते हैं। ऐसे लोगों की वाहवाही से अहंकार आने लगता है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

ऐसा ही अहंकार त्रेतायुग में रावण को भी हो गया था। 'पूरी लंका सोने की थी', यानी भौतिक संसाधनों की प्रचुरता थी। छल-बल से उसने देवाधिदेव महादेव द्वारा माता पार्वती के लिए बनाई लंका हासिल की, जिसे शिल्प के देवता विश्वकर्मा और रावण के सौतेले भाई कुबेर ने बनाया था। इस लंका को पाने के लिए उसने अपने ही आराध्य शिव के साथ छल तो किया ही, सौतेले भाई कुबेर पर भी आक्रमण किया। वह भगवान शिव की उपासना से प्राप्त वरदान का दुरुपयोग करने लगा। सारे संस्कारों का परित्याग कर दिया, शुभ कार्यों में उसका मन नहीं लगता था। परिणाम यह हुआ कि वह समूची लंका से ही नहीं, बल्कि अपने जीवन से हाथ धो बैठा।

ऐसी ही स्थिति इंसान की भी होती है। कोई अवसर का लाभ उठाकर, धोखा देकर या झूठ बोलकर किसी असहाय का हिस्सा लेता या हड़पता है तो साथ में उस असहाय व्यक्ति की बददुआएं भी छीनने वाले व्यक्ति के साथ जाती हैं। फिर जिसने भी इस तरह की हरकत की, उसके घर में किसी न किसी तरह की परेशानियां शुरू होने लगती हैं, संस्कार गायब होने लगते हैं। धोखे से धन कमाने वाले के आश्रित सदस्य तक उसके नियंत्रण से बाहर होने लगते हैं।

ऋषियों-मनीषियों का यह कथन शत-प्रतिशत सही है कि दुआओं और बददुआओं, दोनों में बड़ी ताकत होती है। इनसे तरंगें निकलती हैं। कोई नफरत से देखता है तो आंखों से निकलने वाली तरंगें घातक असर डालने लगती हैं। नफरत होने पर शरीर के हार्मोंस बदलने लगते हैं और शरीर के इस बदलाव से बने केमिकल की तरंगों से बीपी, शुगर, किडनी आदि पर असर पड़े बिना नहीं रह सकता। इसके उलट जब कोई स्नेह से देखता है, तब शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

अक्सर बेहद कीमती या पौष्टिक खाद्य पदार्थ का सेवन करने, लक्जरी ढंग से जीने और धर्म-कर्म में लगकर धर्माधिकारियों का आशीर्वाद तक लेते रहने वाले सुकून की जिंदगी नहीं जी पाते, और सब कुछ रहते हुए परेशान रहते हैं। इसलिए जीवन में अनीतिपूर्वक धन और वस्तु हासिल नहीं करना चाहिए।

आर.एन.आई. पंजीयन नंबर 1613/1957 स्वत्वाधिकारी बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के लिए आर. कृष्णमूर्ति द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, डॉ. डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 से प्रकाशित और उनके द्वारा (1) टाइम्स ऑफ इंडिया सबर्बन प्रेस, आकुर्ली रोड, निकट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, कांदिवली (पू.) मुंबई 400101 एवं (2) टाइम्स ऑफ इंडिया प्रिंट सिटी, प्लॉट नं. 4, टी.टी.सी. इंडस्ट्रियल एरिया, ठाणे बेलापुर रोड, ऐरोली, नवी मुंबई-400708. फोन नं. (022) 2760 9999 ; फैक्सः (022) 2760 5275। फोन मुंबई: (022) 66353535, 22733535 रेस्पांस: (022) 66353636, 22733636 फैक्सः (022) 22731889, 22731144, कांदिवली (022) 28872324 से मुद्रित। **स्थानीय संपादक (मुंबई) : सुंदर चंद ठाकुर** (पी. आर. बी. अधिनियम के अंतर्गत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी) सर्वाधिकार सुरक्षित। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। सड़क व रेल परिवहन सेवा शुल्कः मुंबई, ठाणे व रायगड जिलों के बाहर 1.00 रुपया। विमान सेवा शुल्कः रायपुर, नागपुर, गोवा एवं वाया 2.00 रुपये, इंदौर, चेन्नै एवं वाया 3.00 रुपये, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोचीन, कोयम्बतूर, एरनाकुलम, हैदराबाद, कोझीकोड, मंगलूर, त्रिवेंद्रम, उदयपुर, वाइजग एवं वाया 4.00 रुपये, दिल्ली, कोलकाता, एवं वाया 5.00 रुपये।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 259

हस्तक्षेप की नीति

सरकार ने हाल के वर्षों में कहा है कि भारत व्यापार और आर्थिक एकीकरण को लेकर समझदारी भरा रुख अपना रहा है। उसने मौजूदा मुक्त व्यापार समझौतों का बेहतर इस्तेमाल करने का प्रयास किया है और ऐसे नए समझौतों की संभावना तलाश कर रहा है। आंशिक तौर पर ऐसा इसलिए हुआ कि उसने यह बात समझ ली है कि विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बनना होगा। परंतु इसके साथ ही उसने एक नई लाइसेंस-परमिट व्यवस्था भी पेश की जिससे विभिन्न क्षेत्रों के कारोबारियों को निपटना होगा। गुणवत्ता नियंत्रण ऑर्डर (क्यूसीओ) की तादाद बढ़ी है। ये कुछ खास प्रमाणन के बिना आयात को प्रतिबंधित करते हैं। खासतौर पर भारतीय मानक ब्यूरो के प्रमाणन के बिना। इस बारे में सरकार का दावा यह है कि भारतीय उपभोक्ताओं को खराब गुणवत्ता वाली वस्तुओं से बचाने की आवश्यकता है। परंतु ऐसा भी हो सकता है कि इसका इस्तेमाल भारत की आपूर्ति श्रृंखला में चीनी उत्पादों की मौजूदगी को नियंत्रित करने के लिए किया जाए। परंतु तथ्य यह है कि नए गैर टैरिफ अवरोध खड़े किए गए हैं जो उपभोक्ता हितों के खिलाफ हैं और कारोबारियों तथा विनिर्माताओं दोनों को परेशानी में डालते हैं।

स्टील का उदाहरण लेते हैं। उद्योग जगत स्वाभाविक रूप से चीन की अतिरिक्त क्षमता को लेकर चिंतित है जो भारत में बने स्टील को गैर प्रतिस्पर्धी बना सकता है। परंतु चीन द्वारा स्टील को डंप किए जाने की समस्या को क्यूसीओ के अतिरिक्त इस्तेमाल से ही खत्म नहीं किया जा सकता है। कई प्रकार के स्टील को लेकर मनमाने ढंग से ऑर्डर जारी किए गए हैं। इस बात ने अन्य विनिर्माण कंपनियों को भी प्रभावित किया है जिन्हें शायद अपनी वस्तुएं निर्मित करने के लिए आयातित या विशेष तरह के स्टील की जरूरत होगी। इसमें निर्यात से जुड़ी वस्तुएं भी शामिल हैं। बीआईएस लाइसेंस हासिल करना महंगी और समय खपाऊ प्रक्रिया है। अगर क्यूसीओ द्वारा नहीं कवर किया जाए तो भी आयातकों से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' हासिल करने की उम्मीद तो की जाती है। कई लोग इनसे निपटने के बजाय कम गुणवत्ता वाले इस्पात का इस्तेमाल कर लेंगे। यह बात उन्हें कीमत और गुणवत्ता दोनों ही मामलों में कम प्रतिस्पर्धी बनाएगी। यह विश्वस्तरीय घरेलू विनिर्माण क्षेत्र विकसित करने का तरीका नहीं है।

यह छोटे और मझोले उपक्रमों के लिए भी खास नुकसानदेह है। बड़ी कंपनियां जिनके पास आयात के बड़े ऑर्डर हैं उनके लिए अफसरशाही बाधाओं से निपटना किफायती हो सकता है लेकिन छोटी कंपनियां स्वाभाविक रूप से इसे मुश्किल पाएंगी। ऐसे में उनके लिए यह तुलनात्मक रूप से महंगा होगा और उनकी वस्तुओं की गुणवत्ता खराब होगी। चूंकि सरकार की प्राथमिकता सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रमों यानी एमएसएमई को बढ़ावा देने और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करना है इसलिए बड़ी तादाद में क्यूसीओ का होना नुकसानदेह साबित हो सकता है। श्रम गहन कारोबार योग्य वस्तुओं मसलन टेक्सटाइल आदि को कच्चे माल में क्यूसीओ के अनचाहे परिणाम बड़े पैमाने पर भुगतने पड़े हैं। अब वे देश में ही इन उत्पादों के उत्पादन पर एकाधिकार कर चुकी कंपनियों की दया पर हैं। बाजार में इस नए तरह के अफसरशाही हस्तक्षेप से देश के उद्योग जगत का संरक्षण नहीं होगा क्योंकि बिना कच्चे माल के वह वैसे भी ठप पड़ जाएगा। बल्कि यह देश में विनिर्माण में निवेश कम करने वाला साबित होगा क्योंकि कम ही लोग ऐसे समय में क्षमता विस्तार करना चाहेंगे जबकि जरूरी कच्चे माल तक पहुंच इतनी मुश्किल हो।

सरकार विनियमन और सुधारों को लेकर अपने प्रदर्शन पर गर्व कर सकती है। हालांकि वह खराब गुणवत्ता वाली चीनी वस्तुओं से निपटने के नाम पर अफसरशाही नियंत्रण लागू करके अपनी ही उपलब्धियों को कम कर रही है। इससे पहले सरकार ने कहा था कि क्यूसीओ में 2,500 वस्तुओं को कवर किया जाएगा। इससे भारत की विदेश नीति ऐसे हालात की ओर लौटेगी जहां भारत की उत्पादकता और गुणवत्ता प्रभावित होगी। उपभोक्ता कल्याण पर भी इसका बुरा असर होगा। सरकार के हस्तक्षेप की इस अवांछनीय प्रवृत्ति पर पुनर्विचार जरूरी है।

डॉनल्ड ट्रंप लिखेंगे 2025 की इबारत

शुल्क तथा व्यापार पर ट्रंप का नजरिया अमेरिका में बहुसंख्यक आबादी के नजरिये से मेल खाता है और पूरी दुनिया को उसके हिसाब से ढलना होगा। बता रहे हैं टीटी राम मोहन

हाल फिलहाल के अतीत में तो याद नहीं आता कि नए साल की देहरी पर खड़ी दुनिया का भाग्य किसी एक व्यक्ति पर इतना निर्भर रहा हो, जितना आज है। पिछले कुछ हफ्तों में ऐसा लगा है मानो तमाम देशों के प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक फैसले अगली जनवरी तक के लिए रोक दिए गए हैं, जब डॉनल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति पद संभालेंगे।

अमेरिका निस्संदेह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। इसके राष्ट्रपति के कदमों का असर बाकी दुनिया पर पड़ना ही है। लेकिन ट्रंप अमेरिका के बाकी राष्ट्रपतियों की तरह नहीं हैं। विदेश और आर्थिक नीति के मामले में वह सबसे अलग लीक पर चलते हैं, जो अमेरिका के साथ बाकी दुनिया में भी उथलपुथल मचा सकती है। यही वजह है कि दुनिया दम थामे उन्हें देख रही है। भूराजनीति के क्षेत्र में विश्व पश्चिम एशिया और यूक्रेन पर ट्रंप के कदमों की प्रतीक्षा कर रहा है। ट्रंप ने अमेरिका में आने वाले आयात पर अधिक शुल्क लगाने और अवैध आव्रजन पर सख्ती बरतने के दो प्रमुख वादे किए थे। आर्थिक नीति निर्माता दोनों वादों पर ट्रंप की कार्रवाई देखने और झेलने के लिए तैयार हो रहे हैं।

पश्चिम में मुख्यधारा के मीडिया में ट्रंप को खलनायक बनाने की फितरत इतनी ज्यादा है कि उन्हें उस संकल्प का श्रेय भी नहीं दिया जा रहा, जिससे शायद ही कोई असहमति रखता हो। मार्च 2023 में ट्रंप ने अपने भाषण में एक बड़ी बात कही थीः दुनिया कम लड़ाइयों के साथ भी चल सकती है। उन्होंने कहा था, 'हमें अमन चाहिए। साथ ही उस नियो-कंजर्वेटिव व्यवस्था को भी पूरी तरह खत्म करने का संकल्प लेना चाहिए, जो विदेश में आजादी और लोकतंत्र की लड़ाई की आड़ में हमें अनंत युद्धों की आग में झोंक रही है मगर असल में वह हमें तीसरी दुनिया का (बेहद गरीब) देश बना रही है और तीसरी दुनिया में चल रही तानाशाही हमारे देश में भी ला रही है। विदेश मंत्रालय, रक्षा अफसरशाही, खुफिया सेवाओं और बाकी सब को पूरी तरह बदलने और नए सिरे से गढ़ने की जरूरत है ताकि सत्ता में काम कर रहे ऐसे बाहरी लोग (डीप स्टेट) खत्म हों और अमेरिका फर्स्ट का झंडा बुलंद हो।'

अगर यह क्रांतिकारी सोच नहीं है तो क्या है। बड़ा सवाल यह है कि डीप स्टेट ट्रंप को उनकी पसंद के एजेंडा पर काम करने देगा या नहीं।

संयोग कहें या ट्रंप का भाग्य कहें, पश्चिम एशिया में सीरिया के असद शासन का तख्तापलट हो गया। मुद्दा यह नहीं है कि ट्रंप सीरिया से अमेरिकी जवानों को निकाल सकते हैं या नहीं। देखना यह है कि वह ग्रेटर इजरायल बनाने की योजना और ईरान जैसी दूसरी शत्रुवत सरकारों से निपटने की नियो-कंजर्वेटिव योजनाओं पर क्या कदम उठाते हैं। अमेरिका में इजरायल समर्थक खेमा काफी ताकतवर है। ट्रंप खुद भी ईरान पर सख्त रुख दिखाते रहे हैं। ट्रंप के लिए शांति के अपने सपने को पश्चिम एशिया के मामले में साकार करना बहुत चुनौती भरा होगा।

यूक्रेन पर काफी उम्मीद नजर आती है। ट्रंप जोर-शोर से कहते आए हैं कि यूक्रेन को रूस के साथ टकराव खत्म करने के लिए बातचीत करनी चाहिए। बाइडन प्रशासन ने रूसी इलाकों में लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें दागकर ट्रंप के लिए यह रास्ता भी मुश्किल बनाने की कोशिश की। रूस ने नई मिसाइल से उसका जवाब दिया, जिससे बचने या जिसे खत्म करने लिए नाटो के पास कोई रास्ता नहीं था। दो हफ्ते की शांति के बाद यूक्रेन ने एक बार फिर रूस में लंबी दूरी की मिसाइल दागी है। रूस से इसका कड़ा जवाब आना तय है।

रूस स्पष्ट कर चुका है कि वह यथास्थिति स्वीकार करने पर राजी नहीं है और अब कोई भी समझौता रूस की ही शर्तों पर होगा। अगर ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को विवश कर वहां अमेरिका का दखल पूरी तरह खत्म करने का फैसला कर लें तो हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए।

अमेरिका में घरेलू मोर्चे पर किसी तरह का भ्रम नहीं है। शुल्क बढ़ना तय है और अवैध घुसपैठियों को वापस भेजा जाना भी तय है। सवाल यह है कि ट्रंप कितनी जल्दी और किस हद तक दोनों कदम उठाते हैं।

ट्रंप के लिए शुल्क तो आस्था का मामला है। उन्हें गहरा और पूरा विश्वास है कि समृद्ध अमेरिका का उनका सपना शुल्कों से ही साकार होगा। शुल्कों में उनका यह भरोसा 1980 के दशक से ही रहा है, जब व्यापार घाटा कम करने के लिए 1989 में उन्होंने जापान से हो रहे आयात पर 15 से 20 प्रतिशत शुल्क लगाने की मांग की थी।

जिन्हें संदेह हो वे रॉबर्ट लाइथिजर की 'नो ट्रेड इज फ्री' पढ़ सकते हैं। लाइथिजर पिछली ट्रंप सरकार में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि थे और उनके विचारों को ट्रंप का भरपूर समर्थन मिलता था। इस बार वह वित्त मंत्री या वाणिज्य मंत्री पद के लिए होड़ में थे मगर बात बन नहीं पाई। यह सोचना भूल होगी कि मुक्त व्यापार के खिलाफ होना यानी बुनियादी आर्थिक समझ को नजरअंदाज करना है। यह विचार भी काफी सोच-समझकर बनाया गया है। लाइथिजर के इस विचार के मुख्य बिंदु इस तरह हैं।

सबसे पहले मुक्त व्यापार ज्यादा कारगर होने की बात सही नहीं है क्योंकि इसके फायदे कुछ को ही मिलते हैं और नुकसान बहुत अधिक को होता है। ऐसा भी नहीं है कि नुकसान झेलने वालों को व्यापार के फायदों के जरिये भरपाई की जा रही है। उदाहरण के लिए विनिर्माण करने वालों को सेवा क्षेत्र के कुशल कामगारों की जगह नहीं दी जा सकती। पूरे समुदायों को नई जगह लाना भी कोई आसान काम नहीं है। दूसरा सेवा क्षेत्र से उतने रोजगार नहीं आते, जितने विनिर्माण से आते हैं। केवल विनिर्माण से ही ज्यादातर अमेरिकियों को अच्छी कमाई वाली नौकरी मिल सकती हैं।

तीसरा, अमेरिका को विनिर्माण चाहिए क्योंकि इस्पात और दवाओं जैसे सामान के लिए पूरी तरह दूसरों पर निर्भर होना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं है। विनिर्माण का निर्यात सेवा के निर्यात से नौ गुना अधिक है और इसीलिए अमेरिका के व्यापार घाटे पर अंकुश रखने के लिए जरूरी है। विनिर्माण में नवाचार की बहुत गुंजाइश होती है और उसी से सेवा में भी नवाचार की प्रेरणा मिली है, इसीलिए सेवाओं को विनिर्माण से अलग नहीं किया जा सकता।

चौथा, यह सोचना सही नहीं है कि अमेरिका का व्यापार घाटा डॉलर की कीमत गिरने से खुद ही खत्म हो जाएगा। अमेरिका को दशकों से व्यापार घाटा हो रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिकी डॉलर दुनिया की आरक्षित मुद्रा है, इसलिए डॉलर में पूंजी आती ही रहती है, जो डॉलर की कीमत घटने नहीं देती। अमेरिका के अग्रणी व्यापार साझेदार खास तौर पर चीन अपनी मुद्रा के साथ हेरफेर करते रहते हैं ताकि उनकी विनिमय दर कम बनी रहे। वे 'अनुचित व्यापार' में भी लिप्त रहते हैं - देसी कंपनियों को सब्सिडी देते हैं और इस तरह शुल्क लगाए बगैर भी बाधाएं खड़ी करते हैं।

लाइथिजर ने जो सबसे अहम बात कही है, वह हैः दुनिया की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं संरक्षण की दीवार के पीछे तैयार की गई हैं और अक्सर उनमें सरकारी रकम लगी है। सब्सिडी और शुल्कों की मदद से विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के कार्यक्रम लाइथिजर और ट्रंप की सोच के मुताबिक ही हैं।

अर्थशास्त्री ट्रंप के इस विश्वास का मखौल उड़ा सकते हैं कि अमेरिका को नए सिरे से गढ़ने के लिए शुल्क जरूरी हैं। मगर हाल के राष्ट्रपति चुनाव में उनकी धमाकेदार जीत बताती है कि उनका वैश्वीकरण विरोधी रुख अमेरिका के ज्यादातर मतदाताओं के विचारों से मेल खाता है। इसलिए नए साल में दुनिया के पास खुद को ट्रंप की सोच के हिसाब से बदलने के अलावा कोई और चारा नहीं है।

ड्रोन उद्योग में दूसरी पीढ़ी के सुधार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा कि एयर टैक्सी जल्द ही भारत में हकीकत बन जाएंगी। इससे संकेत मिलता है कि देश में ड्रोन के क्षेत्र में दूसरी पीढ़ी के सुधार शुरू हो सकते हैं। महज तीन साल पहले तक देश में ड्रोन बनाने और उन्हें चलाने की बात कोई सोच भी नहीं सकता था। मगर तब से अब तक काफी बदलाव आया है और देश ड्रोन तकनीक और नवाचार का नया अड्डा बन गया है। अब देश इस क्षेत्र में प्रगति के अगले चरण के लिए तैयार है।

अगस्त 2021 में बने ड्रोन नियम देश के ड्रोन उद्योग के लिए सुधारों की पहली पीढ़ी साबित हुए। मगर इस उपलब्धि के साथ अलग तरह की चुनौतियां आईं और इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी भी है। वर्षों की चर्चा और ड्रोन क्षेत्र को खोलने की मांग के बीच नागर विमानन मंत्रालय ने मार्च 2021 में ड्रोन नियमन तैयार किए। इन नियमों का लक्ष्य निजी उपक्रमों को बढ़ावा देना था मगर उन्होंने बहुत अधिक बंदिशें भी लगाईं, जिनसे उद्योग की वृद्धि का रास्ता बाधित होने का खतरा पैदा हो गया।

कहानी में असली और निर्णायक मोड़ तब आया, जब मोदी ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने कई बैठकें कीं, जिनसे मंत्रालयों, सुरक्षा एजेंसियों और इससे जुड़े दूसरे अहम पक्षों को साथ लाने में मदद मिली और अधिक प्रगतिशील रुख के साथ तालमेल पक्का हुए। मार्च 2021 के नियमों की जगह अगस्त 2021 के नियम लागू किए गए और उसके बाद इतिहास बन गया।

देश का 90 फीसदी से अधिक हवाई क्षेत्र पहले ही ड्रोन के संचालन के लिए अनुकूल घोषित कर दिया गया और मानवरहित विमान प्रणाली यातायात प्रबंधन (यूटीएम) फ्रेमवर्क को मंजूरी दे दी गई। उद्यमियों को ऊर्जा देने और प्रोत्साहित करने के लिए भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। इससे ड्रोन के समूचे तंत्र के भीतर नेतृत्व और नवाचार को बढ़ावा मिला। सरकार ने ड्रोन क्षेत्र को खोलने के साथ ही उनसे इस्तेमाल को मुख्य धारा में लाने के मकसद से परिवर्तनकारी कदम शुरू किए। मिसाल के तौर पर स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन का इस्तेमाल कर 2.90 लाख से अधिक गांवों का सर्वेक्षण किया गया और नक्शे तैयार किए गए। इस तरह लाखों लोगों को उनकी जमीन या संपत्ति के स्वामित्व के प्रमाणपत्र दिए गए, जो पहले उनके पास नहीं थे। इसी तरह नवंबर 2021 में बड़ी खदानों के लिए ड्रोन सर्वेक्षण अनिवार्य कर दिया गया। इससे सर्वेक्षण अधिक कारगर हुआ है और जवाबदेही भी बढ़ी है।

कृषि क्षेत्र में करीब 30 लाख एकड़ इलाके में हवाई छिड़काव के लिए 3,000 से ज्यादा ड्रोन तैनात किए गए हैं और आने वाले दिनों में इनकी तादाद में इजाफा ही होगा। इसी तरह ड्रोन दीदी कार्यक्रम ने ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाया है और 1,000 से अधिक महिलाओं को ड्रोन पायलट बनने का प्रशिक्षण दिया है। इस तरह ग्रामीण इलाकों में ड्रोन तकनीक का व्यावहारिक इस्तेमाल शुरू हुआ।

अजय कुमार

देसी उद्योग की वृद्धि को मदद पहुंचाने के लिए सरकार ने विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने देश में ड्रोन उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) शुरू की और निर्यात के नियमों में ढील दी। आईडेक्स चैलेंज जैसी पहलों ने स्टार्टअप को राष्ट्रीय रक्षा क्षेत्र के लिए ड्रोन तैयार करने के वास्ते प्रेरित किया, जिससे अन्य देशों को निर्यात करने की संभावनाएं तैयार हुईं। नतीजा यह हुआ कि जो भारतीय ड्रोन बाजार 2021 में लगभग शून्य था वह 2024 में बढ़कर करीब 65.4 करोड़ डॉलर हो गया और 2029 तक यह बाजार 1.43 अरब डॉलर पर पहुंच जाने की संभावना है। देश में 2024 में कुल 10,803 ड्रोन उड़ रहे हैं, जिनकी तादाद 2029 तक बढ़कर 61,393 पर पहुंच जाने की संभावना है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि देश में ड्रोन का भविष्य नवाचार से भरा और मजबूत होगा।

ड्रोन तकनीक नई-नई उपलब्धियां हासिल कर रही है, नए-नए क्षेत्रों में पहुंच रही है तब एयर टैक्सी शहरी यातायात में क्रांति ला सकती है। कई शहरों में भीड़ और यातायात की समस्या का यह कारगर समाधान हो सकती है। भारत के महानगरों में लोग काम पर जाने में ही औसतन 2 घंटे यानी पूरे दिन का करीब 7 फीसदी हिस्सा खपा देते हैं। इस मामले में दुनिया में सबसे ज्यादा वक्त भारत में ही बरबाद होता है। ड्रोन टैक्सी से लोगों का समय बच जाएगा। इसी प्रकार ड्रोन एंबुलेंस किसी भी आपात स्थिति में बहुत जल्दी पहुंच सकती है। चिकित्सा के अलावा कानून प्रवर्तन और आपदा राहत में भी एयर टैक्सी का इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिका, इजरायल, चीन और संयुक्त अरब अमीरात समेत कई देश पहले ही ड्रोन टैक्सी कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। चीन ने तो अक्टूबर 2023 में नया इतिहास बनाया, जब वहां दो यात्रियों वाली ड्रोन टैक्सी को टैक्सी श्रेणी का प्रमाणन दिया गया। इस मामले में दुबई भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।

सुधारों के पहले चरण का फायदा उठाकर भारत वैश्विक ड्रोन उद्योग में सबसे होड़ लेने वाली ताकत के रूप में उभरा है। कई स्टार्टअप स्वदेशी ड्रोन टैक्सी डिजाइन को आगे बढ़ा रहे हैं। किंतु इस क्षेत्र की संभावनाओं का पूरी तरह दोहन करने के लिए सुधारों का अगला चरण लागू करना जरूरी है। ड्रोन टैक्सी उड़ान भरने या नीचे उतरने के मामले में विमानों से अलग होती हैं और ये एकदम लंबवत उठती या उतरती (वर्टिकल टेकऑफ और लैंडिंग) हैं, इसलिए भीड़भाड़ वाले इलाकों में ये बहुत कारगर होती हैं। मगर इन्हें भी एयरपोर्ट और बस अड्डों की तरह वर्टिपोर्ट की जरूरत होती है।

इस जरूरत को समझते हुए नागर विमानन महानिदेशालय ने विमान नियम, 1937 के तहत एक मशविरा पत्र पांच सितंबर को जारी किया। इसमें वर्टिपोर्ट के लिए बुनियादी ढांचे के मानक तय किए गए हैं, जिनमें यात्री टर्मिनल, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, नीचे उतरने के लिए विजुअल मदद, बैटरी चार्जिंग के नियम-कायदे तथा आपात स्थिति में प्रतिक्रिया की प्रणाली आदि शामिल है। सही वक्त पर और दूर की सोच के साथ जारी यह मशविरा पत्र देश में ड्रोन सुधारों के दूसरे चरण की ओर पहला मगर अहम कदम है।

नागर विमानन महानिदेशालय ने यानों के वर्टिकल टेकऑफ और लैंडिंग के लिए प्रमाणन के कायदे 11 सितंबर को जारी किए। ये कायदे उन विमानों पर लागू होते हैं, जो अधिकतम 5,700 किलोग्राम वजन लेकर उड़ान भरते हैं। इनमें 40-50 यात्रियों की क्षमता वाली एयर टैक्सी आ जाती हैं। इनमें मौजूदा बंदिशें हटा दी गई हैं और एयर टैक्सी को 400 फुट से अधिक ऊंचाई पर उड़ने या नजर से ओझल हो जाने की भी इजाजत है।

भारत को ड्रोन टैक्सी के लिहाज से तैयार होना है तो स्वचालित मानवरहित यातायात प्रबंधन जैसी अहम नीतिगत व्यवस्था जरूरी है। ऐसी व्यवस्था मानव सहित या मानवरहित विमानों के अबाध संचालन के लिए आवश्यक है। अगस्त 2021 के नियमों के बाद ड्रोन परिचालन को नियमित और स्वचालित करने के लिए डिजिस्काई प्लेटफॉर्म की परिकल्पना की गई, लेकिन इसे साकार होने में देर हो रही है। इसके विपरीत अमेरिका जैसे देशों ने 2021 में ही लो ऐल्टीट्यूड ऑथराइजेशन ऐंड नोटिफिकेशन कैपेबिलिटी प्रणाली शुरू कर दी थी। इसमें संघीय विमानन प्रशासन द्वारा स्वीकृत ड्रोन सेवा आपूर्तिकर्ताओं के साथ डिजिटल संपर्क कर स्वचालित मंजूरी लेते हुए नियंत्रित हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया जा सकता है।

भारत को एयर कार्गो और यात्री एयर टैक्सी चलाने के लिए कानूनी तौर पर ड्रोन बीमा और देनदारी कवरेज भी अनिवार्य कर देनी चाहिए। यह 1999 के मॉन्ट्रियल समझौते जैसे वैश्विक मानकों के अनुकूल होगा। हवाई यात्रा में बीमा और देनदारी के नियम उसी समझौते के हिसाब से चलते हैं।

अब ड्रोन उद्योग नई ऊंचाइयों को छू रहा है और दूसरी पीढ़ी के सुधार भारत को वैश्विक ड्रोन शक्ति के रूप में स्थापित कर सकते हैं। सरकार ने हाल में नीति को जो गति दी है उससे पता चलता है कि वह आगे की चुनौतियों से निपटने को तैयार है।

आपका पक्ष

प्रदूषण का बच्चों पर नकारात्मक असर

दिल्ली सहित देश के कई शहरों में बढ़ता प्रदूषण बच्चों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन रहा है। प्रदूषित हवा में सांस लेने से बच्चों के फेफड़े क्षतिग्रस्त हो रहे हैं और अस्थमा तथा अन्य श्वसन संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं। यह न केवल बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित कर रही है बल्कि उनकी मानसिक सेहत पर भी बुरा असर डाल रही है। बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए जरूरी है कि उन्हें स्वस्थ वातावरण मिले। स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा को शामिल करना इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम होगा। उन्हें यह समझाना होगा कि स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर वे न केवल खुद स्वस्थ रह सकते हैं बल्कि पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। सरकार, स्कूल और अभिभावक मिलकर इस समस्या का समाधान खोजने के लिए आगे आएं। हमें प्रदूषण कम करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।

राजूराम प्रजापत, नागौर

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने के कारण ग्रेप-3 लागू किया गया जिसके तहत पाबंदियां लगाई गईं

साइबर ठगी से बचने के लिए संदिग्ध लिंक से बचा जाए

साइबर ठगी के उन्मूलन के लिए जागरूकता और तकनीकी सतर्कता का समन्वय अत्यावश्यक है। जटिल पासवर्ड का प्रयोग, द्वि-स्तरीय प्रमाणीकरण, सॉफ्टवेयर का नियमित अद्यतन तथा फायरवॉल और ऐंटीवायरस प्रणालियों का प्रबल उपयोग सुरक्षा के मूल स्तंभ हैं। संदिग्ध ईमेल, लिंक और संदेशों से सावधानी-पूर्वक बचाव, प्रमाणित मंचों पर ही वित्तीय लेनदेन और सार्वजनिक वाईफाई का विवेकपूर्ण उपयोग अनिवार्य है। साइबर खतरों के प्रति सजग दृष्टिकोण, नियमित सुरक्षा प्रशिक्षण और तकनीकी रूप से सशक्त समाज ही डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करने का कारगर समाधान है।

प्रो. आरके जैन, बड़वानी

ऐंटीवायरस सॉफ्टवेयर का अपडेट जरूरी

साइबर ठगी से बचने के लिए अज्ञात नंबरों से कॉल या संदेशों का जवाब न देने के साथ ही ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करने से पहले उनकी विश्वसनीयता की जांच करनी चाहिए। ऐंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर अपने डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करें। बैंक खाते, क्रेडिट कार्ड और सोशल मीडिया गतिविधियों की नियमित जांच करें। अनावश्यक रूप से अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे जन्म तिथि, बैंक खाता संख्या आदि साझा न करें।

सैयद हामिद अली, ठाणे

व्यक्तिगत जानकारी देने से बचना होगा

साइबर ठगी से बचने के लिए अपने पासवर्ड को मजबूत और अद्वितीय रखने की जरूरत है। ऑनलाइन लेनदेन करते समय सुरक्षा प्रमाणपत्र की जांच करें। किसी भी संदिग्ध ईमेल, लिंक या कॉल से और अपनी व्यक्तिगत जानकारी बताने से सावधान रहें। अपने डिवाइस और सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करें। अगर कोई साइबर ठगी का शिकार हो जाए तो तुरंत स्थानीय पुलिस या साइबर क्राइम सेल नंबर 1930 से संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।

भगवानदास छारिया, इंदौर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 'विजय दिवस' के अवसर पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर सोमवार को 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के नायकों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर रक्षा प्रमुख (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान, थलसेना प्रमुख जनरल मनोज पांडेय, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी तथा वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मौजूद थे।

संविधान पर चर्चा

मोदी के संकल्प

लोकसभा में संविधान पर चर्चा का जवाब देते हुए मोदी ने महत्वपूर्ण 11 संकल्प सामने रखे। लोकसभा में 13 दिसंबर को संविधान पर हुई चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के भावी विकास को निर्देशित करने के लिए 11 संकल्प प्रस्तुत किए। संविधान की भावना से निर्देशित इन संकल्पों में नागरिकों की आवश्यकता पर जोर देते हुए सरकारी अधिकारियों से अपने दायित्व निभाने पर जोर दिया गया था। इसके साथ ही संविधान द्वारा मूल कर्तव्यों पर भी जोर दिया गया है, पर उनका क्रियान्वयन व्यापक सार्वजनिक जागरूकता तथा संस्थागत जवाबदेही पर निर्भर है। प्रधानमंत्री ने इस बात की पुनः पुष्टि की कि उनकी सरकार 'सबका साथ सबका विकास' के माध्यम से समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि पिछले वर्षों में ढांचागत विकास तथा डिजिटल पहुंच जैसे क्षेत्रों में काफी विकास हुआ है, पर क्षेत्रीय असमानता तथा सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। इनको संबोधित करने के लिए लक्षित नीतिगत हस्तक्षेपों और संसाधनों के समुचित उच्चीकरण की जरूरत है। सार्वजनिक विश्वास और आर्थिक क्षमता को नुकसान पहुंचाने वाले भ्रष्टाचार का भी उल्लेख प्रधानमंत्री के भाषण में हुआ और उन्होंने भ्रष्टाचार की सामाजिक अस्वीकृति पर जोर दिया। उनका यह दृष्टिकोण डिजिटल पारदर्शिता तथा भ्रष्टाचार-विरोधी कानूनों से पुष्ट होता है। लेकिन इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जीवन्त क्रियान्वयन व्यवस्थायें तथा न्यायिक सक्षमता बहुत जरूरी हैं। कानूनों और परंपराओं के प्रति सम्मान एक और महत्वपूर्ण संकल्प है जिसका उद्देश्य सामाजिक एकजुटता मजबूत करना है। इसके लिए न केवल कानूनों के कठोर क्रियान्वयन, बल्कि नागरिकों को शिक्षित करने के सांस्कृतिक अभियानों की जरूरत है ताकि उनको भारत की विधिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूक किया जा सके।

इसी प्रकार प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की विरासत को औपनिवेशिक युग की सोच से मुक्त करने का आह्वान किया। इसके लिए स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों का संवर्धन, शिक्षा पाठ्यक्रम को औपनिवेशिक सोच से मुक्त करने तथा भारत की उपलब्धियों का विश्व स्तर पर सम्मान जरूरी है। मोदी ने संविधान के प्रति सम्मान तथा राजनीतिक लाभ के लिए इसका प्रयोग बंद करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अंतर्गत राजनीतिक निष्ठा और विधायी प्रक्रियाओं में रचनात्मक विचार-विमर्श जरूरी है। प्रधानमंत्री ने बिना धर्म-आधारित आरक्षण को लागू किए वर्तमान आरक्षण व्यवस्था बनाए रखने की प्रतिबद्धता प्रकट की। सामाजिक न्याय और प्रतिभा के बीच संतुलन रखना एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सतर्कता से नीतिगत निर्णय की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने 'राज्यों के विकास से देश के विकास' का मंत्र दिया। इसमें सहयोगी संघवाद का महत्व रेखांकित होता है। राज्यों की क्षमताओं के विकास तथा समतापूर्ण वितरण सुनिश्चित करना इस संकल्प की सफलता के लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित संकल्पों की सफलता अनेक आयामों पर निर्भर हैं जिनमें कर्तव्यों के साथ नागरिकों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना शामिल है। इन संकल्पों का प्रभावी क्रियान्वयन बड़ी सीमा तक प्रशासन की व्यवस्थाओं तथा जीवन्त संस्थानों पर निर्भर है। इसके साथ ही सरकार द्वारा संस्थानों के समुचित व सक्षम उपयोग के अलावा भारत के नागरिकों में अपने नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता पैदा करना जरूरी है। नागरिकों में देश के विकास तथा सामाजिक कल्याण के प्रति सतर्कता तथा सक्रियता की भावना पैदा करना प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्त संकल्पों को जमीन पर उतारने के लिए आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले लगभग एक दशक में भारत की आर्थिक प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए विश्वास प्रकट किया कि वह 2047 तक निश्चित रूप से विकसित देश बनेगा।

खाद्य सुरक्षा का वैश्विक महत्व

वैश्वीकरण से स्वदेशी खाद्य उद्योगों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा सकता है। लेकिन इन सरोकारों के बावजूद बायोटेक्नोलोजी के संभावित लाभ बहुत अधिक हैं। इससे वैश्विक खाद्य एवं ऊर्जा व्यवस्थायें बदल सकती हैं।

सुधीर हिंदवान
(लेखक, रणनीति विशेषज्ञ हैं।)

भू-राजनैतिक प्रतिद्वंद्विताओं के बढ़ते प्रभुत्व, आर्थिक अनिश्चितताओं तथा पर्यावरण क्षरण की समस्याओं से ग्रस्त दुनिया में महत्वपूर्ण खाद्य सुरक्षा चिन्ताओं को अक्सर पृष्ठभूमि में धकेल दिया जाता है। दुनिया की राजनीति आज अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रही है। इनमें साइबर धोखाधड़ी, व्यापक भ्रष्टाचार, विभिन्न देशों में फैला आतंकवाद तथा व्यापक विनाश के आयुधों का बेलगाम उपयोग शामिल हैं। पश्चिम एशिया संकट तथा रूस-यूक्रेन के बीच जारी वर्तमान युद्ध इन संकटों के उदाहरण हैं। असाधारण रूप से व्यापक शरणार्थी संकट, पर्यावरण क्षरण तथा प्राकृतिक विभीषिकाओं की बढ़ती बारंबारता से ये समस्यायें और गंभीर होती हैं। इन महत्वपूर्ण सरोकारों में खाद्य सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके बावजूद इसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। इससे दुनिया भर के अनेक देश प्रभावित होते हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन-एफएओ द्वारा 1996 में रोम विश्व खाद्य सम्मेलन में दी गई परिभाषा के अनुसार, खाद्य सुरक्षा उस समय पैदा होती है जब 'सभी लोगों को पूरे समय तक समुचित, सुरक्षित तथा पोषक भोजन तक भौतिक और आर्थिक पहुंच नहीं मिलती है। यह भोजन उनकी भोजन आवश्यकताओं तथा सक्रिय व स्वस्थ जीवन के लिए खाद्य पसंदों के अनुरूप होना चाहिए।' इस प्रकार इस परिभाषा में न केवल भोजन की भौतिक उपलब्धता, बल्कि उस तक आर्थिक पहुंच पर भी जोर दिया गया है। इसमें भोजन की मात्रा तथा उसकी पोषक गुणवत्ता, दोनों पर जोर दिया गया है। एफएओ के खाद्य सुरक्षा पैमाने के अनुसार गरीब देशों की आधी से अधिक जनसंख्या खाद्य-असुरक्षा स्थितियों का सामना कर रही है, जबकि एक तिहाई जनसंख्या गंभीर संकट का शिकार है। दुनिया भर में लगभग 789 मिलियन लोगों को उपयुक्त भोजन की कमी का सामना करना पड़ता है और लघु-पोषकों की कमी को देखतते हुए यह संख्या खतरनाक रूप से 2.4 बिलियन तक पहुंच जाती है। खाद्य सुरक्षा मुद्दों को मोटेतौर से दो व्यापक श्रेणियों-मात्रा एवं गुणवत्ता में बांटा जा सकता है। इन चुनौतियों में पांच प्रमुख आयाम- भोजन की उपलब्धता, मूल्यों में उतार-चढ़ाव, समावेशी पहुंच, समुचित उपयोग तथा स्थायित्व शामिल हैं। खासकर गरीब देशों में मूल्यों का उतार-चढ़ाव अधिकांश ऐसे लोगों में खाद्य असुरक्षा को गंभीर बना देता है जिनकी पहुंच पोषक खाद्य पदार्थों तक ठीक से सुनिश्चित नहीं होती है। वैश्विक खाद्य असुरक्षा को स्वीकार करते हुए संयुक्त राष्ट्र ने खाद्य सुरक्षा को 2015 में '2030 एजेंडा' के 17 टिकाऊ विकास लक्ष्यों-एसडीजी में शामिल किया था। दूसरी एसडीजी का लक्ष्य 'भूख समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा पोषण में सुधार करना और टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहन देना' रखा गया है। सहायक लक्ष्यों की एसडीजी 6 में 'सबके लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता तथा टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना' तथा एसडीजी 12 में 'टिकाऊ उपभोग एवं उत्पादन पैटर्न' सुनिश्चित करना शामिल किया गया है। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए टिकाऊ व्यवहारों पर जोर दिया गया है। दुनिया भर में सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी खाद्य एवं कृषि नीतियों को इन लक्ष्यों के अनुरूप व्यवस्थित करें तथा अपनी जनसंख्या के लिए उपयुक्त मात्रा में पोषक भोजन टिकाऊ आधार पर सुनिश्चित करें।

दुनिया की राजनीति आज अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रही है। इनमें साइबर धोखाधड़ी, व्यापक भ्रष्टाचार, विभिन्न देशों में फैला आतंकवाद तथा व्यापक विनाश के आयुधों का बेलगाम उपयोग शामिल हैं। पश्चिम एशिया संकट तथा रूस-यूक्रेन के बीच जारी वर्तमान युद्ध इन संकटों के उदाहरण हैं।

खाद्य असुरक्षा परिवारों तथा सामाजिक स्तर पर लोगों के लिए अनेक समस्यायें पैदा करती है। उदाहरण के लिए परिवार की खाद्य असुरक्षा को समुचित नींद न होने तथा बीमारियों के खिलाफ समुचित प्रतिरोधक क्षमता के अभाव से जोड़ा गया है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ ने टिकाऊ विकास पर 2012 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में सुरक्षित व पोषक खाद्य तक पहुंच के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पुनः प्रकट की। इस प्रतिबद्धता को 'फ्यूचर वी वांट' दस्तावेज में समेकित रूप से रखा गया है। इस सम्मेलन में संरा. के तत्कालीन महासचिव बान की मून ने 'ज़ीरो हंगर चैलेंज'-जेडएचसी भी जारी किया था जिसका लक्ष्य दुनिया भर में 2030 तक भूख और कुपोषण को समाप्त करना था। जेडएचसी का एक प्रमुख तत्व 'सभी खाद्य व्यवस्थाओं को टिकाऊ' बनाने का लक्ष्य है। इसमें स्वच्छ जल, टिकाऊ ऊर्जा, जिम्मेदार खाद्य उपभोग व उत्पादन तथा जलवायु कार्रवाई पर जोर दिया है जिसे राष्ट्रीय नीतियों तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग से प्राप्त किया जा सकता है। 1987 की ब्रंडलैंड रिपोर्ट 'अवर कामन फ्यूचर' में टिकाऊ विकास को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि इस 'विकास का अर्थ भावी पीढ़ियों द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा डाले बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकतायें पूरी करना है।' 1947 में स्वतंत्रता के बाद से ही भारत ने खाद्य सुरक्षा मजबूत करने में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। इसके लिए भारत में भारतीय कृषि शोध संस्थान के अंतर्गत अनेक संस्थानों की स्थापना की गई है जिनका निर्देशन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-आईसीएआर के पास है। कृषि संबंधी चुनौतियों को संबोधित करने में जेनेटिक इंजीनियरिंग व बायोटेक्नोलोजी में हो रही प्रगति महत्वपूर्ण योगदान कर रही है। इससे उपलब्ध खाद्य की गुणवत्ता बढ़ती है तथा विश्व स्तर पर भोजन की उपलब्धता का भी विस्तार होता है। लेकिन जेनेटिक परिवर्तित अवयवों-जीएमओ से पैदा बायोसुरक्षा जोखिमों, समुचित परिवहन, हस्तांतरण तथा इन अवयवों के निस्तारण के बारे में चिन्ता बनी हुई है। विश्व बैंक जैसे वैश्विक संस्थानों ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया है।

दुनिया वर्तमान समय में भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विताओं में उलझी है जिसके चलते विभिन्न देश भूख, गरीबी, पर्यावरण क्षरण और बेरोजगारी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को अनदेखा कर अपने प्रभुत्व पर जोर दे रहे हैं। बायोटेक्नोलोजी के समुचित व प्रभावी प्रयोग से इन चुनौतियों का सामना किया जा सकता है तथा उच्च गुणवत्ता वाले भोजन का उत्पादन सुनिश्चित करने, प्रदूषण घटाने, रोजगार सृजन करने एवं आर्थिक प्रगति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा जा सकता है। इस प्रकार हम अंतरराष्ट्रीय सहयोग से वैश्विक तनाव घटा सकते हैं तथा शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। शोध एवं विकास में निवेश से भूख, कुपोषण और खाद्य सुरक्षा, खाद्य पदार्थों में मिलावट जैसी समस्याओं का सामना किया जा सकता है। इसके साथ ही बायोटेक्नोलोजी में परिवर्तन से सारी दुनिया की भलाई और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है। लेकिन बायोटेक्नोलोजी के बारे में दो बड़ी आशंकायें बनी हुई हैं। पहला, इससे विकसित व विकासशील देशों के बीच खाई और चौड़ी हो सकती है। दूसरा, वैश्वीकरण से स्वदेशी खाद्य उद्योगों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा सकता है। लेकिन इन सरोकारों के बावजूद बायोटेक्नोलोजी के संभावित लाभ बहुत अधिक हैं। इससे वैश्विक खाद्य एवं ऊर्जा व्यवस्थायें बदल सकती हैं तथा गरीब लोगों की सहायता के लिए एक अभियान चलाया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा पहलों को भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विताओं से ऊपर रखा जाना चाहिए तथा इसमें समावेशन को बढ़ावा दे कर साझा जिम्मेदारियों पर जोर देना चाहिए। समावेशी राजनय पर जोर देने वाले भारत के पास इस दिशा में विश्व स्तर पर केन्द्रीय भूमिका निभाने की क्षमता है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

कार्यस्थल पर विभाजन

"कार्यस्थल पर ध्रुवीकरण व्यापक सामाजिक विभाजन को दर्शाता है, लेकिन पेशेवर सेटिंग्स के भीतर इसकी अनूठी चुनौतियाँ और अवसर हैं। हालांकि इससे सहयोग, विश्वास और उत्पादकता को खतरा है।"

साक्षी सेठी
(लेखक, शिक्षाविद हैं)

बढ़ता हुआ विभाजन टीमवर्क में बाधा डाल सकता है, विश्वास को कम कर सकता है और संगठनात्मक प्रभावशीलता को कम कर सकता है। 21वीं पीढ़ी के आगमन के साथ, लोगों का तीव्र विरोधी समूहों में विभाजन कार्यस्थलों में तेजी से घुसपैठ कर रहा है, जो राजनीति, संस्कृति और मूल्यों में व्यापक सामाजिक विभाजन को दर्शाता है। पेशेवर सेटिंग्स में, इसे अक्सर ध्रुवीकरण के रूप में संदर्भित किया जाता है और यह सहयोग में बाधा डाल सकता है, रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है और संगठनात्मक प्रभावशीलता को कम कर सकता है। कार्यस्थल ध्रुवीकरण को संबोधित करने के लिए सक्रिय नेतृत्व, खुला संचार और साझा लक्ष्यों पर जोर देने की आवश्यकता होती है। ध्रुवीकरण अक्सर विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होता है जैसे कि अलग-अलग व्यक्तिगत मूल्य जहां कर्मचारी अपनी राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को कार्यस्थल में लाते हैं।

लिंग, जाति और राजनीतिक विचारधाराओं जैसे संवेदनशील मुद्दों पर विश्वासों में अंतर संघर्षों को जन्म देता है। दूसरी ओर, मीडिया कवरेज, राजनीतिक अभियान या सामाजिक आंदोलन अलग-अलग दृष्टिकोण वाले कर्मचारियों के बीच तनाव को बढ़ाते हैं। टीमों के भीतर खुले संवाद की कमी प्रतिध्वनि कक्षों को बढ़ावा देती है, जहां कर्मचारी केवल समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ बातचीत करते हैं, पूर्वाग्रहों और गलतफहमियों को मजबूत करते हैं। साथ ही, पीढ़ियों के बीच कार्यशैली, प्राथमिकताओं और मूल्यों में अंतर घर्षण पैदा कर सकता है। युवा कर्मचारी सामाजिक सक्रियता को प्राथमिकता दे सकते हैं, जबकि पुराने सहकर्मी पारंपरिक कार्यस्थल मानदंडों को महत्व दे सकते हैं। संगठनात्मक स्वास्थ्य और कर्मचारी कल्याण पर इस तरह के ध्रुवीकरण का प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकता है। यह टीमवर्क को बाधित कर सकता है, क्योंकि कर्मचारी विपरीत विचार रखने वालों के साथ सहयोग करने के लिए कम इच्छुक होंगे जो नवाचार और उत्पादकता को बाधित करेगा। व्यक्तिगत या राजनीतिक मुद्दों पर असहमति भी सहकर्मियों के बीच अविश्वास का कारण बन सकती है, जिससे विषाक्त कार्य वातावरण बन सकता है। कर्मचारी जो अपने विश्वासों के कारण अलग-थलग या हाशिए पर महसूस करते हैं, वे कहीं और अवसर तलाश सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिभा का नुकसान होता है। ध्रुवीकरण में निहित कार्यस्थल संघर्ष तनाव, बर्नआउट और नौकरी की संतुष्टि में कमी ला सकते हैं। सम्मानजनक बातचीत को प्रोत्साहित करके जो कर्मचारियों को निर्णय के डर के बिना अपने दृष्टिकोण व्यक्त करने की अनुमति देता है; संरचित पहलों को लागू करके, जैसे कि सुगम चर्चा या संघर्ष समाधान कार्यशालाएँ; कर्मचारियों को एकजुट करने वाले संगठनात्मक उद्देश्यों पर जोर देकर और साझा मूल्यों या टीम मिशनों जैसे सामान्य आधार को उजागर करके, कुछ उपाय हो सकते हैं जो विभाजनकारी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने को कम कर सकते हैं और विभाजन को पाटने में मदद कर सकते हैं। कार्यस्थल पर बातचीत के लिए माहौल बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका नेता की होती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि समावेशी नेता सम्मानजनक व्यवहार का उदाहरण पेश करते हैं, विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रोत्साहित करते हैं और संघर्षों में प्रभावी ढंग से मध्यस्थता करते हैं। कार्यस्थल पर स्वीकार्य व्यवहार की रूपरेखा तैयार करने वाले दिशा-निर्देश विकसित करना, विशेष रूप से संवेदनशील विषयों पर चर्चा के संबंध में; अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए आपसी सम्मान को बढ़ावा देने वाली नीतियां बनाना या टीम-निर्माण अभ्यास, मेंटरशिप प्रोग्राम या क्रॉस-डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट जैसी पहल करना अलग-अलग दृष्टिकोण वाले कर्मचारियों के बीच अलगाव को कम करने और संबंधों को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। निस्संदेह एक संगठन की संस्कृति ध्रुवीकरण को कैसे प्रकट करती है और कैसे संबोधित की जाती है, इस पर महत्वपूर्ण रूप से प्रभाव डालती है। एक संस्कृति जो सम्मान, समावेशिता और खुले विचारों को महत्व देती है, वह ध्रुवीकरण के प्रभावों को कम कर सकती है।

इसके विपरीत, एक संस्कृति जो पक्षपात या भेदभाव को सहन करती है, वह विभाजन को बढ़ा सकती है। नेताओं को एक ऐसी संस्कृति विकसित करने को प्राथमिकता देनी चाहिए, जहाँ कर्मचारी अपने विश्वासों या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना मूल्यवान महसूस करें और उनकी बात सुनी जाए। कार्यस्थल पर ध्रुवीकरण व्यापक सामाजिक विभाजन को दर्शाता है, लेकिन पेशेवर सेटिंग्स के भीतर इसकी अनूठी चुनौतियाँ और अवसर हैं। हालांकि इससे सहयोग, विश्वास और उत्पादकता को खतरा है, लेकिन अगर इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाए तो यह विकास को भी गति दे सकता है। सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देकर, खुले संवाद को बढ़ावा देकर और साझा लक्ष्यों पर जोर देकर, संगठन ध्रुवीकरण को दूर कर सकते हैं और ऐसे वातावरण बना सकते हैं जहाँ विविध दृष्टिकोण पनपते हैं।

आप की बात

जाकिर हुसैन का जाना

देश के महान तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन संगीत जगत की अपूरणीय क्षति है। महज ग्यारह बरस की उम्र में उन्होंने तबले से नाता जोड़ा और ता-उम्र उसी को मित्र बनाकर देश-दुनिया में भारतीय संगीत को तबले की थाप से प्रसिद्धि दिलवाई। इनके पिता प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद अल्लाह रक्खा खान से इन्हें तबले में रुचि हुई और तबले में ऐसी महारत हासिल हुई की तबले की बदौलत इन्हें संगीत जगत के मशहूर ग्रैमी अवार्ड को चार बार अपने नाम किया। देश -विदेश में कई सम्मान और पुरस्कार प्राप्त करने वाले उस्ताद जाकिर हुसैन को 1988 में पद्मश्री 2002 में पद्मभूषण और 2023में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर ने इनकी प्रतिभा को पहचानकर इन्हें सबसे पहले उस्ताद कहा था, जो इनके नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। बहुत छोटी उम्र में आपने अमेरिका में पहला कॉन्सर्ट किया जिसमें उन्हें काफी पसंद किया गया , उसके बाद तो देश-विदेश में जहां भी जाते लोग उनकी तबले पर चलती उंगलियों के संयोजन से मंत्रमुग्ध होकर उनके प्रशंसक हो जाते। यहां तक कि 2016 में अमेरिका के तात्कालिक राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें आर्ल स्टार ग्लोबल कॉन्सर्ट में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया। वे पहले भारतीय थे जिन्हें निमंत्रित किया गया। जाकिर ने 1998में संगीत प्रधान फिल्म में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

–**संजय डागा**, इन्दौर

राजा भैया का उद्बोधन

उत्तर प्रदेश विधानसभा में राजा भैया का उद्बोधन सदन में उपस्थित सभी सनातनी जनप्रतिनिधियों के लिए प्रेरणा है । सदन में जितने भी सनातनी जनप्रतिनिधि बैठे हैं उनमे से किसी एक को भी संभल विवादित स्थल के सर्वे से आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्यूंकि हम सबके लिए सर्वप्रथम सनातन धर्म है। सदन में यह बात पूरी स्पष्टता और शक्ति के साथ कहना वो भी भाजपा नहीं अपितु जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के मुखिया द्वारा कहना अभिनंदनीय है राजा भैया ने पत्थरबाजों से लेकर बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की निर्मम हत्या करने वालों तक पर प्रश्न किए, उन अधिकारियों के प्रति अपनी चिंता और संवेदना भी व्यक्त की जिन पर सम्भल सर्वे के दौरान मजहबी उपद्रवियों ने पथराव और गोलीबारी की थी। निसंदेह राजनीतिक तुष्टिकरण इतना भी अँधा नहीं होना चाहिए कि सत्य दिखना ही बंद हो जाए। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष उन्हें हिन्दू नरसंघार, खंडित सनातनी मंदिरों और इस्लामिक क्रूरता के प्रति मुखर होना चाहिए जब इस्लामिक जनप्रतिनिधि बेशर्म होकर जिहादी कटटरपंथियो के समर्थन में खड़े हो जाते हैं तो सनातन धर्म में जन्म लेने वाले जनप्रतिनिधि किसी राजनीतिक दल की मुस्लिम तुष्टिकरण के विचारों की बेड़ियों से बाधित क्यों होते हैं । इन बेड़ियों को तोड़कर सनातन धर्म और अपने अग्रिम वंश की सुरक्षा हेतु मुखर होइए, प्रखर होइए, प्रतिकार कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए।

– **दिव्य अग्रवाल**

संविधान पर तर्क-वितर्क

संसद हो या संसद के बाहर देश के संविधान में संशोधनों को लेकर दोनों-पक्षों (सत्ता-विपक्ष) में लम्बे समय से वाकयुद्ध चल रहा है। कोई इसे पूर्व में परिवार के हित में किये गए संशोधनों की उपमा दे रहा है तो कोई राष्ट्रहित में किये गए संशोधनों की अपनी पुख्ता बात पर अड़ा हुआ है। वैसे संविधान में संशोधन राष्ट्रहितों के मद्देनजर ही होने चाहिए न कि राजनीतिक/व्यक्तिगत/पार्टी हित में होने चाहिए। अगर पूर्व में ऐसा कुछ हुआ है तो वह ठीक नहीं है। संसद में दोनों पक्ष मिलकर ही देश चलाते हैं न कि केवल सत्ता या सिर्फ विपक्ष। कुछ भूलें हुई हैं तो संविधान में राष्ट्रहित में दोनों को मिलकर तर्क-वितर्क करके विद्वता पूर्वक संशोधन की पहल करनी चाहिए न कि उस पर सबको मिलकर कुतर्क रूपी बहस में संसद का कीमती समय और जनधन बर्बाद करना चाहिए। ये राष्ट्रहित में किये जाने वाले संविधान में संशोधनों पर बहस का विषय है न कि लीक से हटकर राजनीतिक/पारिवारिक हित/अहित पर बेवजह की बहस करने में समय बर्बाद करने का वक्त है। यूं तो सत्ता पक्ष भी वाक्-पटुता में कम नहीं पर विपक्ष भी हम देख रहे हैं 2014 से कभी संसद में हंगामा कभी वॉकऑउट और कभी अति-आलोचना ही करता रहा है। जिससे जनहित व राष्ट्रहित के मुद्दे हंगामों की भेंट चढ़ रहे है। उसे भी अपनी वाणी में परिपक्वता लाते हुए समझदारी से काम लेना चाहिए।

–**शकुंतला महेश नेनावा**, इंदौर

विश्वसनीयता स्वीकारते नेता

ईवीएम मशीन की विश्वसनीयता को लेकर कांग्रेस चाहे जो कुछ कहे लेकिन जब विपक्षी नेता भी इस कटु सत्य को हलक नीचे उतार लें तो फिर सत्ता पक्ष पर आरोप लगाकर उंगली उठाने का कोई औचित्य नजर नहीं आता। बकौल कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह, आपको संसद के सौ से अधिक सदस्य एक ही ईवीएम का उपयोग करके मिले हैं और आप इसे अपनी पार्टी की जीत के रूप में मनाते हैं तो आप कुछ महीनों के बाद में यह नहीं कह सकते हैं कि हमें ये ईवीएम पसंद नहीं हैं, क्योंकि अब चुनाव नतीजे वैसे नहीं हैं, जैसे हम चाहते हैं। यह वक्तव्य दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए काफी है। कोर्ट से लेकर विशेषज्ञ तक सभी ईवीएम को सेट करने के आरोपों को सिरे से नकार चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस को भी इस मामले को विराम देना चाहिए जिससे सदन और देश का बहुमूल्य समय जाया होने से बचाया जा सके। क्या कांग्रेस इस हलाहल को गले उतारने की हिम्मत जुटा पाएगी ? ईवीएम को लेकर भारत में कोई भी ऐसा मामला नहीं आया है जो इसकी निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगाता हो।

–**अमृतलाल मारू रवि**, इंदौर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

Machine Translated by Google

ध्वनि और रोष

संविधान भले ही एक हो, लेकिन इस बहस ने ध्रुवीकरण को उजागर कर दिया

टी संविधान पर संसदीय बहस शासकों और सरकार के बीच तीखी नोकझोंक का एक और अवसर बन गई।

गठबंधन और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। जबकि दोनों पक्ष संविधान की सर्वोच्चता पर सहमत थे, जो अब अपने 75वें वर्ष में है, प्रत्येक ने एक दूसरे पर इसे कमज़ोर करने का आरोप लगाया। यह बहस एक तीव्र ध्रुवीकृत राजनीति के लिए एक नया साझा आधार तलाशने का अवसर हो सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सत्ताधारी दलों के वक्ताओं और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी वक्ताओं ने अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ़ तीखी टिप्पणी की और संविधान का इस्तेमाल अपनी पक्षपातपूर्ण राजनीति के लिए एक मुखौटे के रूप में किया। श्री गांधी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और श्री मोदी को एक दूसरे के खिलाफ़ ...

मोदी ने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता का आरोप लगाया और इसे हिंदुत्व विचारधारा से जोड़ने की कोशिश की। श्री मोदी ने श्री गांधी के परिवार पर, उनके परदादा और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर, बिना किसी रोक-टोक के हमला किया - कि उन्होंने चूक और कमीशन के कृत्यों के माध्यम से संविधान को कमजोर किया है। दोनों पक्षों ने चुनिंदा तथ्यों और पिछले अभिनेताओं के बयानों का इस्तेमाल इस बात को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने के लिए किया कि उनके विरोधियों ने संविधान को उनसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। इस तरह का दृष्टिकोण एक प्रचार रणनीति के रूप में काम कर सकता है लेकिन सवाल पर रचनात्मक जुड़ाव के मामले में बहुत कम कर सकता है।

संविधान, जिसे एक जीवित दस्तावेज के रूप में समझा जाता है, देश के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की नींव और रूपरेखा प्रदान करता है। संविधानवाद एक विकासशील परियोजना है, और इस पर किसी भी चर्चा में इस गतिशीलता को ध्यान में रखना चाहिए। इतिहास एक अच्छा शिक्षक है, लेकिन अतीत पर अंतहीन मुकदमेबाजी एक उपयोगी सीखने की तकनीक नहीं है। संविधान के 75 साल के इतिहास में आपातकाल सहित कई काले क्षण आए हैं, लेकिन उजला और बड़ा चित्र यह है कि यह अभी भी एक धर्मनिरपेक्ष, बहुलवादी और प्रगतिशील राष्ट्र के लिए सबसे मजबूत संभव लोकाचार प्रदान करता है। भाजपा और कांग्रेस का एक-दूसरे को नाम से पुकारना, बर्तन को केतली में काला कहने के समान है। दोनों पक्ष कहते हैं कि वे देश की एकता को मजबूत करने के लिए हैं, लेकिन एक-दूसरे पर देश को विभाजित करने का आरोप लगाते हैं। बहस से जो बात उभर कर सामने आती है, वह

श्री मोदी का यह कहना सही है कि संविधान राष्ट्र की एकता है, तथा उन्होंने समान नागरिक संहिता के लिए अपनी सरकार के प्रयास को इस एकता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता का उदाहरण बताया।

आने वाले दशकों में राजनीतिक वर्ग को असमान जनसांख्यिकीय और आर्थिक रुझानों पर बारीकी से और एकजुट होकर ध्यान देने की आवश्यकता होगी ताकि संवैधानिक योजना को फिर से परिभाषित किया जा सके। दुख की बात है कि इन सवालों पर बहुत कम समय खर्च किया गया।

महंगा जुआ

इमैनुएल मैक्रों फ्रांस को एक के बाद एक संकट में धकेल रहे हैं

जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने जून में अचानक विधान सभा चुनाव की घोषणा करने वाले थे, उनके पास दो राजनीतिक उद्देश्य थे: अपने मध्यमार्गी गठबंधन के लिए एक नया जनादेश सुरक्षित करना और यूरोपीय चुनावों में अभी-अभी समाप्त हुई दक्षिणपंथी नेशनल रैली के उभार को रोकना। लेकिन उन्हें एक त्रिशंकु संसद मिली जिसमें वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट (NFP) सबसे बड़े गुट के रूप में उभर कर सामने आया। और उन्होंने जो किया वह रिपब्लिकन पार्टी के एक रूढ़िवादी नेता मिशेल बार्नियर को सरकार बनाने के लिए चुनना था, जो चुनावों में चौथे स्थान पर रही थी। यह एक ऐसी आपदा थी जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। सरकार तीन महीने के भीतर गिर गई, जिससे फ्रांस 2025 के लिए बजट के बिना रह गया। और अब, जैसे कि उन्होंने अपने जुए से कुछ नहीं सीखा, श्री मैक्रों ने 577 सदस्यीय नेशनल असेंबली में सिर्फ 33 सीटों वाली डेमोक्रेटिक मूवमेंट पार्टी के नेता फ्रांकोइस बायरू को अगला प्रधान मंत्री नियुक्त किया है। भले ही श्री मैक्रों का गठबंधन, एनसेंबल, जो चुनावों में दूसरे स्थान पर रहा, और रिपब्लिकन एक साथ आ जाएं, लेकिन उनके पास संसद में विधेयक पारित करने के लिए बहुमत (289 सीटें) नहीं है। वामपंथी गठबंधन का हिस्सा सोशलिस्ट पार्टी ने पहले ही कह दिया है कि वह नई सरकार में शामिल नहीं होगी। इसका मतलब यह होगा कि श्री बायरू की सरकार मरीन ले पेन की दूर-दराज़ नेशनल रैली की दया पर होगी, क्योंकि श्री मैक्रॉन ने कहा कि वह सरकार में शामिल नहीं होगी।

बार्नियर की सरकार जीवित रहने के लिए थी।

बढ़ती बेरोजगारी और घरेलू खपत में गिरावट के साथ, फ्रांस को तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इसने सकल घरेलू उत्पाद के 6.1% तक स्केल डेसिट में उछाल देखा है, जो ग्रीस, स्पेन और इटली से भी बदतर है, जो 2008-09 के ऋण संकट से बुरी तरह प्रभावित यूरोजोन देश हैं। फ्रांस का ऋण भी €3.2 ट्रिलियन तक बढ़ गया है, जो इसके सकल घरेलू उत्पाद का 112% से अधिक है। संकट को और भी बदतर बनाने वाली बात है स्थिर सरकार का अभाव। श्री बायरू का तत्काल कार्य संसद में एक आपातकालीन बजट पारित करवाना है ताकि आवश्यक सेवाएँ चलती रहें। लेकिन इसके लिए दूर-दराज़ के साथ दर्दनाक बातचीत करनी होगी, जो सामाजिक व्यय में किसी भी और कटौती का विरोध करता है।

इससे राजनीतिक और आर्थिक स्थिति फिर से पहले जैसी हो गई है। समस्या का एक हिस्सा श्री मैक्रोन द्वारा राजनीतिक गतिशीलता में बदलाव को स्वीकार करने से इनकार करना है। आर्थिक पीड़ाओं से सत्ता-विरोधी वर्ग को ताकत मिल रही है। जबकि दक्षिणपंथी और वामपंथी अलग-अलग राजनीतिक मंचों से कामकाजी आबादी को संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं, श्री मैक्रोन अपनी राष्ट्रपति शक्तियों का दुरुपयोग करके यथास्थिति बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। स्पष्ट जनादेश से वंचित अलोकप्रिय नेताओं को प्रधानमंत्री नियुक्त करके वे संकट को और बढ़ा रहे हैं। यदि वे 'संस्थागत स्थिरता' के बारे में गंभीर थे, जो मैक्रोनवादियों का पसंदीदा मंत्र है, तो उन्हें सबसे बड़े समूह, वामपंथियों के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी और आम सहमति से संचालित राजनीतिक और आर्थिक कार्यक्रम के आधार पर उन्हें शासन करने में मदद करनी चाहिए थी।

भारतीय रेलवे में ग्रीनवाशिंग की छिपी हुई लागत

के. बालाकेसरी
पूर्व में भारतीय रेलवे सेवा मैकेनिकल इंजीनियर्स, सदस्य स्टा था, रेलवे बोर्ड

ए इस दैनिक में प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रेलवे की परामर्श शाखा, राइट्स लिमिटेड ने कुछ अफ़्रीकी रेलवे को निर्यात के लिए छह ब्रॉड गेज डीजल इलेक्ट्रिक इंजनों के पुन: उपयोग के लिए दो अनुबंध जीते हैं।

इन इंजनों को उन रेलमार्गों पर उपयोग के लिए परिवर्तित किया जाएगा जो भारतीय रेल की ब्रॉड गेज पर उपयोग किए जाने वाले 1,676 मिमी के केप गेज के मुकाबले 1,067 मिमी का उपयोग करते हैं। हालांकि भारतीय रेल ने अपने सलाहकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे RITES और IRCON के साथ मिलकर अतीत में एशिया और अफ्रीका के देशों को इंजनों का निर्यात किया है, यह शायद पहली बार है कि दूसरे हाथ के (प्रयुक्त) इंजनों को "गेज परिवर्तन" के बाद निर्यात करने का प्रस्ताव है। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह पुनः इंजीनियरिंग में एक सराहनीय प्रयास है जिसमें वस्तुतः एक संकरे प्लेटफार्म पर इंजनों का पुनर्निर्माण शामिल है, जो कहानी छिपी हुई है वह पूरी तरह से धार्मिक लक्ष्य की खोज में महंगी संपत्तियों और अपव्यय की भारी बर्बादी की घिनौनी गाथा है

आरटीआई डेटा और नीतिगत औचित्य रिपोर्ट में "जल्द ही बेकार हो जाने वाले डीजल इंजनों" का उल्लेख किया गया है। तथ्य यह है कि 31 मार्च, 2023 तक, सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत इस लेखक द्वारा एक साल से भी अधिक समय पहले प्राप्त की गई जानकारी के अनुसार, भारतीय रेलवे के नेटवर्क में विभिन्न स्थानों पर विद्युतीकरण के कारण 585 डीजल इंजन स्थिर (निष्क्रिय/भंडारित) थे।

इसके अलावा, इनमें से 60% से ज़्यादा इंजनों का शेष जीवन 15 साल से ज़्यादा था। आज, यह आंकड़ा लगभग 760 इंजनों का बताया जाता है।

भारतीय रेलवे ऐसी स्थिति में कैसे और क्यों पहुंच गई कि सैकड़ों डीजल इलेक्ट्रिक इंजन जो अच्छी हालत में थे और जिनमें अभी भी कई साल की सेवा बाकी थी, बेकार हो गए? इसका जवाब सरकार की उस नीति में छिपा है जिसके तहत भारतीय रेलवे के पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क को मिशन मोड में, तेज गति से विद्युतीकृत किया जाना है।

भारत में रेलवे विद्युतीकरण ने बहुत पहले ही आर्थिक और वित्तीय व्यवहार्यता जैसे सांसारिक विचारों को पार कर लिया है और विश्व शांति और सार्वभौमिक भाईचारे (वसुधैव कुटुम्बकम) जैसी सार्वभौमिक इच्छाओं के समूह में शामिल हो गया है। आज, रेलवे विद्युतीकरण को आम तौर पर दो आधारों पर उचित ठहराया जाता है: कच्चे तेल के आयात को कम करके और पर्यावरण प्रदूषण को कम करके विदेशी मुद्रा की बचत, और, दूसरे बिंदु के परिणामस्वरूप, सौर और पवन जैसे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों पर स्विच करने की अनुकूलनशीलता। वास्तव में फरवरी 2021 में रेल मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक पैम्फलेट में, जिसका शीर्षक था 'मिशन 100% इलेक्ट्रिसिटी - नेट जीरो कार्बन की ओर बढ़ना

'मिशन 100% इलेक्ट्रीकेशन' परियोजना का उद्देश्य हरित रेलवे में बदलने की मृगतृष्णा को पूरा करना है; बड़ी संख्या में उपयोगी डीजल इंजन भी बेकार हो जाएंगे

'उत्सर्जन' को कम करने के लिए मिशन के उद्देश्य इस प्रकार बताए गए हैं: लोगों को पर्यावरण अनुकूल, हरित और स्वच्छ परिवहन का साधन उपलब्ध कराना; तथा रेलवे पटरियों के किनारे उपलब्ध विशाल भूमि का उपयोग करके नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर ऊर्जा के उपयोग की क्षमता को उन्मुक्त करना।

आइए इन तर्कों की विस्तार से जांच करें। विदेशी मुद्रा की बचत का लाभ पूर्ण रूप से सत्य है। लेकिन देश में हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) तेल की कुल खपत के संदर्भ में देखा जाए तो रेलवे ट्रैक्शन की खपत नगण्य है। एसी नीलसन द्वारा किए गए और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित (जनवरी 2014) एक अध्ययन के अनुसार, जब भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण धीमी "पारंपरिक" गति से आगे बढ़ रहा था, देश में कुल डीजल तेल की खपत का 70% परिवहन क्षेत्र द्वारा किया जा रहा था। इसमें से रेलवे का हिस्सा सिर्फ 3.24% था। इसकी तुलना में, ट्रकों ने 28% और कृषि क्षेत्र ने 13.2% खपत की। 2021-22 में रेलवे का हिस्सा और घटकर लगभग 2% हो गया। इसलिए, 100% रेल विद्युतीकरण डीजल की खपत के सबसे छोटे हिस्से को खत्म कर देगा,

पर्यावरण संबंधी विचारों के बारे में सच्चाई भारतीय संदर्भ में पर्यावरण संबंधी लाभों का दावा और भी अधिक अपुष्ट है। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। बिजली ऊर्जा का एक द्वितीयक स्रोत है, सिवाय जब बिजली से उत्पन्न हो। इसे जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा या ऊंचाई पर संग्रहीत पानी की गतिज ऊर्जा (जैसे जलविद्युत परियोजनाओं में), या सौर या पवन ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत का उपयोग करके उत्पन्न किया जाना चाहिए।

भारत में क्या स्थिति है? आज देश में उत्पादित बिजली का लगभग 50% कोयला आधारित थर्मल प्लांट के माध्यम से होता है और भारतीय रेलवे कोयले को खदानों से थर्मल पावर प्लांट तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दरअसल, 2023-24 (संशोधित अनुमान) में रेलवे की कुल माल ढुलाई आय लगभग ₹1.7 लाख करोड़ का लगभग 50% विभिन्न उद्देश्यों के लिए कोयले के परिवहन से उत्पन्न हुआ था, जिसमें से 80% यानी कुल माल ढुलाई आय का 40% केवल थर्मल उत्पादन संयंत्रों तक कोयले के परिवहन से उत्पन्न हुआ था।

डीजल इंजनों को विद्युत इंजनों से प्रतिस्थापित करना लोकोमोटिव का परिणाम केवल बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में होगा - जिसका लगभग 50% कोयला जलाकर बनाया जाता है - जिसका उपयोग अधिक कोयले को कोयला-लाल थर्मल प्लांट में ले जाने के लिए किया जाता है ताकि अधिक बिजली पैदा की जा सके, अधिक कोयले का परिवहन किया जा सके। पर्यावरण की दृष्टि से, कोयले को ग्रह पर सबसे गंदा ईंधन माना जाता है। एक पूर्ण

भारतीय रेलवे द्वारा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर स्विच करने से केवल रेलवे ट्रैक के पास डीजल इंजनों द्वारा होने वाले प्रदूषण को अधिक सघन रूप में बिजली उत्पादन के स्रोत में स्थानांतरित किया जाता है, जिससे अंततः वही वातावरण प्रदूषित होता है। जब तक देश में उत्पादित कुल बिजली का लगभग 80% गैर-जीवाश्म ईंधन से नहीं आता है - और वह दिन दूर लगता है - भारतीय रेलवे के 100% विद्युतीकरण का कोई भी दावा, इसे "ग्रीन रेलवे" बनाना, कल्पना के दायरे में है। संयोग से, उस स्थिति के वास्तविकता बनने से पहले, रेलवे को वित्तीय संकट से बचने के लिए कोयले के लिए वैकल्पिक वस्तुओं की तलाश करनी होगी - जो आज, सबसे अधिक माल ढुलाई कमाने वाला एकमात्र स्रोत है।

इस लेख का उद्देश्य इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन बनाम डीजल ट्रैक्शन की पुरानी बहस को फिर से शुरू करना नहीं है। मुद्दा भारतीय रेलवे को "ग्रीन रेलवे" में बदलने की मृगतृष्णा का पीछा करने और इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में सेवा योग्य डीजल इंजनों को बेकार कर देने के बारे में है। यदि आज पहले से ही स्थिर सभी इंजनों को एक दूसरे के साथ पंक्तिबद्ध किया जाए, तो वे लगभग 16 किलोमीटर की लंबाई तक फैल जाएंगे, जिनमें से अधिकांश समय से पहले स्क्रैपयार्ड में चले जाएंगे।

'आपदा प्रबंधन, रणनीतिक उद्देश्य' रेलवे के मिशन 100% विद्युतीकरण से भी निकट भविष्य में विरोधाभास पैदा होगा। भारतीय रेलवे में आज 4,000 से अधिक डीजल इंजन हैं। प्रणाली के आसन्न 100% विद्युतीकरण के साथ, वे सभी रातोंरात बेकार नहीं हो जाएंगे। एक प्रतिष्ठित वित्तीय दैनिक में एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से हाल ही में एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार, 2,500 डीजल इंजनों को रेलवे द्वारा "आपदा प्रबंधन और रणनीतिक उद्देश्यों" के लिए बनाए रखने का प्रस्ताव है। यह समझ से परे है कि किस आपदा के लिए इतनी बड़ी संख्या में डीजल इंजनों को अलग रखने की आवश्यकता होगी, जब तक कि यह काफी शेष सेवा जीवन वाले इंजनों को समय से पहले स्क्रैपयार्ड में भेजने से बचने का एक बहाना न हो। इसके अलावा, यह बताया गया है कि ट्रैक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए लगभग 1,000 अन्य इंजन अगले कुछ वर्षों तक सेवा में बने रहेंगे। दूसरे शब्दों में, 100% विद्युतीकृत "ग्रीन" रेलवे निकट भविष्य में लगभग 3,500 "गंदे डीजल" का उपयोग करना जारी रखेगा, जिसका वित्तीय खर्च काफी हद तक एक कम-से-कम ग्रीन कमोडिटी: किंग कोल के परिवहन द्वारा चलाया जाएगा। इससे यह सवाल उठता है: 100% विद्युतीकरण की इस जल्दबाजी का अंतिम उद्देश्य क्या था?

भारतीय रेलवे का मिशन 100% विद्युतीकरण इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि क्या होता है जब सुविचारित नीतियों के स्थान पर दिखावटी परियोजनाओं को बढ़ावा देने वाले सुर्खियां बटोरने वाले नारे अपनाए जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप करदाताओं के पैसे की भारी बर्बादी होती है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

लेकिन क्या किसी को परवाह है?

तम्बाकू, चीनीयुक्त पेय पदार्थों पर उच्च जीएसटी दर लागू करें

रिजो एम. जॉन
एक स्वास्थ्य अर्थशास्त्री और प्रोफेसर
राजगिरी कॉलेज ऑफ सामाजिक विज्ञान, कोच्चि, केरल

पिछले सात वर्षों में, जब से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद से तंबाकू और चीनी-मीठे पेय पदार्थों जैसे हानिकारक उत्पादों पर जीएसटी दरों में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, सिवाय तंबाकू पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (एनसीसीडी) में दो मामूली बढ़ोतरी के। इससे ये उत्पाद अधिक किफायती हो गए हैं, जिससे इनके उपभोग पर अंकुश लगाने के प्रयासों को झटका लगा है।

इस संदर्भ में, तंबाकू और चीनी-मीठे पेय पदार्थों पर उच्चतम जीएसटी स्तर को 28% से बढ़ाकर 35% करने का मंत्रिसमूह (जीओएम) का प्रस्ताव एक स्वागत योग्य कदम है। हालाँकि, इन उत्पादों से जुड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य और पैमाने की चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आगे कर सुधार आवश्यक हैं।

प्रस्तावित जीएसटी दर वृद्धि का प्रभाव भारत विश्व स्तर पर तम्बाकू का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जहाँ 15 वर्ष से अधिक आयु के 28.6% वयस्क और 13 से 15 वर्ष की आयु के 8.5% छात्र किसी न किसी रूप में तम्बाकू का उपयोग करते हैं। तम्बाकू गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है और भारत में प्रतिदिन 3,500 से अधिक मौतों का कारण बनता है। 2017 में, तम्बाकू के उपयोग और सेकेंड हैंड धूम्रपान का वार्षिक आर्थिक बोझ ₹2,340 बिलियन या सकल घरेलू उत्पाद का 1.4% होने का अनुमान लगाया गया था - जो तम्बाकू कर राजस्व में सालाना एकत्र किए गए ₹538 बिलियन से कहीं अधिक है।

प्रस्तावित जीएसटी वृद्धि 35% होने की उम्मीद है तंबाकू की खपत कम होगी और कर राजस्व में वृद्धि होगी। प्रारंभिक अनुमानों से पता चलता है कि 35% की दर से बीड़ी के लिए 5.5% की कीमत में वृद्धि, खपत में 5% की गिरावट और 18.6% की राजस्व वृद्धि होगी। सिगरेट के लिए, कीमतों में 3.9% की वृद्धि होगी, खपत में 1.3% की गिरावट होगी और राजस्व में 6.4% की वृद्धि होगी। धूम्ररहित तंबाकू की कीमतों में 3% की वृद्धि होगी, खपत में 2.7% की गिरावट होगी और राजस्व में 1.9% की वृद्धि होगी। कुल मिलाकर, इससे सालाना 43 बिलियन रुपये की अतिरिक्त आय हो सकती है, बशर्ते उद्योग कर के बोझ को "अधिक स्थानांतरित" न करे, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त लाभ हो सकता है

समूह के प्रस्ताव के अतिरिक्त मंत्रियों ने कहा कि इन उत्पादों से जुड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य और पैमाने की चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक कर सुधारों की आवश्यकता है।

सरकारी राजस्व और सार्वजनिक स्वास्थ्य की कीमत पर।

जीएसटी दरों को 35% तक बढ़ाने की जीओएम की सिफारिश एक सकारात्मक कदम है, लेकिन जीएसटी कानून के तहत अनुमत 40% की अधिकतम दर से कम है। 40% की दर का अधिक प्रभाव होगा, जिससे कीमतों में तेज वृद्धि होगी, खपत में बड़ी कमी आएगी और राजस्व में अतिरिक्त 72 बिलियन रुपये की वृद्धि होगी। यह उद्योग द्वारा कर के बोझ को जरूरत से ज्यादा बढ़ाने के जोखिम को भी कम करेगा। वर्तमान में, तंबाकू उत्पादों पर कर का बोझ असमान है, जिसमें बीड़ी के खुदरा मूल्य का केवल 22% कर है, जबकि सिगरेट के लिए यह 49.5% और धुआं रहित तंबाकू के लिए 64% है। 35% जीएसटी दर इस अंतर को थोड़ा कम करेगी, जिससे उनके संबंधित कर हिस्से 26%, 51% और 65% हो जाएंगे

उच्च करों के कारण अवैध व्यापार में वृद्धि के बारे में तम्बाकू उद्योग की चिंताएँ निराधार हैं। भारत सहित अन्य देशों से प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि कर वृद्धि का अवैध व्यापार पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। इसके बजाय, कर प्रशासन की गुणवत्ता, विनियामक ढाँचे, सरकारी प्रतिबद्धता, शासन की मजबूती, सामाजिक स्वीकृति और अनौपचारिक वितरण नेटवर्क जैसे कारक अवैध बाजारों के पैमाने को निर्धारित करने में कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

जीएसटी और उत्पाद शुल्क में संतुलन एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा तम्बाकू उपभोग को विनियमित करने के लिए जीएसटी पर निर्भरता है, जो कि विशुद्ध रूप से मूल्यानुसार कर है। तम्बाकू के उपयोग पर अंकुश लगाने में मूल्यानुसार कर विशिष्ट उत्पाद शुल्क की तुलना में कम प्रभावी होते हैं क्योंकि वे उत्पाद की कीमतों से जुड़े होते हैं, जिनमें उद्योग हेरफेर कर सकता है। जीएसटी लागू होने के बाद से, कुल तम्बाकू कराधान में उत्पाद शुल्क का हिस्सा कम हो गया है।

तंबाकू के उपयोग को हतोत्साहित करने में कर प्रणाली की प्रभावशीलता कम हो गई है। जीएसटी या मूल्य वर्धित कर (वैट) वाले कई देश तंबाकू जैसे हानिकारक उत्पादों पर विशिष्ट उत्पाद शुल्क के साथ इनका पूरक करते हैं। भारत को एक मजबूत और अधिक व्यापक कराधान ढांचे के लिए जीएसटी संशोधन के साथ-साथ उत्पाद शुल्क बढ़ाने पर विचार करना चाहिए।

जबकि अधिकांश सार्वजनिक चर्चा तम्बाकू पर केंद्रित रही है, चीनी-मीठे पेय पदार्थों पर प्रस्तावित जीएसटी वृद्धि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

चीनी-मीठे पेय पदार्थों का अत्यधिक सेवन मोटापे, मधुमेह और अन्य गैर-संक्रामक रोगों का प्रमुख कारण है। जीएसटी दर को 35% तक बढ़ाने से खपत को हतोत्साहित किया जा सकता है और यह भारत के व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों के साथ संरेखित हो सकता है।

हालांकि, सरकार को कर ढांचे को और मजबूत करने के लिए चीनी-मीठे पेय पदार्थों पर विशेष उत्पाद शुल्क जैसे अतिरिक्त स्वास्थ्य-केंद्रित शुल्क लगाने पर भी विचार करना चाहिए।

जीएसटी परिषद के लिए मुख्य विचार चूंकि जीएसटी परिषद जीओएम की सिफारिशों पर विचार कर रही है, इसलिए उसे इस अवसर का उपयोग हानिकारक उत्पादों के कराधान में सुधार के लिए करना चाहिए।

तम्बाकू और चीनी-मीठे पेय पदार्थों के लिए जीएसटी दरों को 40% तक बढ़ाने से सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ में वृद्धि होगी और साथ ही यह जीएसटी कानून के तहत उच्चतम दर के अनुरूप होगा। इसे उच्च उत्पाद शुल्क के साथ जोड़ने से एक मिश्रित कर संरचना बनेगी, जो मुख्य रूप से मूल्यवर्धित करों पर निर्भर रहने की तुलना में खपत को कम करने में अधिक प्रभावी साबित होगी।

बीड़ी, सिगरेट और धुआँ रहित तम्बाकू के बीच कर के बोझ में अंतर को कम करना भी प्रतिस्थापन को हतोत्साहित करने और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करने के लिए महत्वपूर्ण है। ये कदम तम्बाकू और चीनी-मीठे पेय पदार्थों के स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभावों को महत्वपूर्ण रूप से कम कर सकते हैं, साथ ही विकास के लिए महत्वपूर्ण राजस्व उत्पन्न कर सकते हैं।

संपादक के नाम चिठी

संसद में बहस मीडिया के एक लेख में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कैसे राजनेता विशेष रूप से एक ही बात को बार-बार दोहराते रहते हैं। यह भारतीय राजनेताओं के बारे में बिलकुल सच है। कोई यह समझने में असमर्थ है कि आपातकाल के दौर पर हर समय बात करने से क्या उपयोगी उद्देश्य पूरा होता है, भले ही वर्तमान मुद्दों और विधायी प्रस्तावों से इसकी प्रासंगिकता कुछ भी हो। जो लोग संसद के शीर्ष पर हैं, उन्हें यह भरोसा रखना चाहिए कि आपातकाल की घटना सामूहिक स्मृति में गहराई से अंकित है। राष्ट्र यह सुनिश्चित करेगा कि भारत के लोग किसी को भी दोबारा ऐसा करने का साहस नहीं करने देंगे।

एम. जमील अहमद, मैसूर

विजय की तस्वीर भारतीय सेना प्रमुख के लाउंज में 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के भारत के सामने आत्मसमर्पण की याद में लगाई गई तस्वीर/पेंटिंग की जगह पौराणिक कथाओं और आधुनिक विषयों को दर्शाती एक और पेंटिंग लगाई गई है, जो बेहद परेशान करने वाली है। 1971 की विजय सशस्त्र बलों की वीरता और रणनीतिक नेतृत्व का प्रतीक है, जिसके कारण बांग्लादेश को मुक्ति मिली। पेंटिंग को बदलने के पीछे का कारण उन सभी लोगों के लिए स्पष्ट है जो आज की राजनीति पर नज़र रखते हैं। सशस्त्र बल राष्ट्र के हैं, किसी सरकार या पार्टी के नहीं।

राजनीतिक सुविधा के लिए सशस्त्र बलों की ऐतिहासिक उपलब्धियों को कम आंकना अपमान है।

कुरियन मैथ्यू, कोच्चि, केरल

उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक

उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन एक युग का अंत है। एक ऐसे देश के लिए जो अपनी विविधता के लिए खतरों का सामना कर रहा है, महान कलाकार एक शानदार उदाहरण थे जिन्होंने इस तथ्य को प्रदर्शित किया कि संगीत वह दिव्य और शक्तिशाली एकीकरण है जो सभी मानव निर्मित बाधाओं को पार करता है, और मानव जाति को एक छत्र के नीचे लाता है।

विज्ञापन में उनके द्वारा गढ़ा गया शब्द 'वाह ताज' 1980 के दशक के अंत में उन्होंने जो कुछ किया वह भी उनके प्रशंसकों के मन में अंकित रहेगा।

बी. सुरेश कुमार, कोयंबटूर

उस्ताद ज़ाकिर हुसैन ने जब तबला बजाया तो मंत्रमुग्ध हो गए। उनके जाने से संस्कृति की दुनिया में एक बहुत बड़ा शून्य पैदा हो जाएगा।

सुधीर जी. कांगुटकर, वंगानी, ठाणे, महाराष्ट्र

इस बार नवाब युग का क्रिकेट नहीं आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीमों के पास अपनी टीम चुनने में बहुत अधिक कौशल है और भारतीय क्रिकेटरों के प्रदर्शन और क्षमता का आकलन हमारे आधिकारिक चयनकर्ताओं से ज़्यादा ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रहा टेस्ट मैच बहुत अच्छा नहीं चल रहा है और लगातार खराब फॉर्म में चल रहे "क्रीमी" खिलाड़ियों को बेंच पर बैठा दिया जाना चाहिए था। हमारा क्रिकेट बोर्ड इतना समझदार है कि अपने बेहतरीन टैलेंट पूल से प्रतिस्थापन को बाहर कर सकता है। क्रिकेट का वह दौर अब बहुत दूर चला गया है जब लॉर्ड्स सन टैन के लिए बाहर जाते थे।

आर. नारायणन, नवी मुंबई

प्रेरणा

जो लोग अपने डर को जीत लेते हैं, वो सही मायनों में मुक्त हो जाते हैं। - अरस्तू

संपादकीय

आर्थिक असंतुलन, विकास की गति भी कम करता है

दुनिया भर के देशों में आर्थिक असंतुलन का अध्ययन करने वाले मशहूर अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी इन दिनों भारत में हैं। उनका कहना है कि भारत में दक्षिण अफ्रीका के बाद गरीब-अमीर के बीच खाई सबसे ज्यादा बढ़ी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी अहम सेवाओं पर समुचित खर्च के लिए जरूरी धनराशि देश के मात्र 167 अरबपतियों पर केवल दो प्रतिशत 'सुपररिच टैक्स' लगाकर हासिल की जा सकती है। उनके कथन के अगले कुछ ही घंटों में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि ऐसे किसी भी टैक्स से पूंजी का पलायन होगा और निवेश का माहौल खराब होगा। पिकेटी की बातों को पूरी तरह खारिज करने के बजाय सरकार को तमाम पहलुओं पर सोचना होगा। आज भारत में केवल 10% लोग आयकर देते हैं जबकि चीन में 40 साल पहले यह स्थिति थी और आज 70-80% लोग आयकर देते हैं। चीन 50 साल पहले भारत से गरीब था, लेकिन उसका विकास इसलिए तेज रहा क्योंकि उसने आर्थिक असंतुलन को भी कम किया। नीति-निर्धारकों को यह भी सोचना होगा कि वर्ष 2019-20 में केन्द्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा पूंजीगत निवेश (कैपेक्स) 4.7% था, जो वर्ष 2023-24 में घटकर 3.8% क्यों रह गया? कैपेक्स से अंतर-संरचना और भावी विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। सोचना होगा कि केवल 167 अरबपतियों पर दो प्रतिशत सुपररिच टैक्स से देश में निवेश का माहौल कैसे खराब होगा? सरकार को भी इसके लाभ होंगे। पहला, राजनीतिक लाभ, क्योंकि बड़े वर्ग को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और दूसरा, टैक्स देने की आदत और माहौल बनेगा, तो देश में शीर्ष पर मौजूद 10 प्रतिशत वर्ग भी ज्यादा टैक्स देगा। सोचना होगा कि क्या शिक्षा, स्वास्थ्य और शोध के लिए देश में अपेक्षित धन उपलब्ध है? आज देश में कर-राजस्व जीडीपी का मात्र 13 प्रतिशत है।

बामुलाहिजा • भारत और अमेरिका रणनीतिक सहयोगी, फिर आज अमेरिकी विदेश विभाग पर सवाल क्यों?

'डीप स्टेट' पर भाजपा के हमले के मायने

दूरदृष्टि

शेखर गुप्ता
एडिटर-इन-चीफ, 'द प्रिन्ट'
@ShekharGupta

हमारी राजनीतिक-रणनीति के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना घट गई और हमने उस पर उतनी बहस नहीं की, जितनी करनी चाहिए थी। यह घटना 'डीप स्टेट' पर भाजपा ही नहीं बल्कि अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से भी हमले के रूप में घटी। सरकारी नीति को प्रभावित करने वाले अपरिभाषित, भयानक और रहस्यमय राष्ट्रस्तरीय गुप्त नेटवर्क को 'डीप स्टेट' कहा जाता है। भाजपा के एक्स हैंडल ने अमेरिकी 'डीप स्टेट' पर हमला करते हुए 16 भागों वाला 'थ्रेड' पोस्ट किया था, क्योंकि उसने भारत और मोदी सरकार के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। इस तरह के हमले पर आपकी सामान्य प्रतिक्रिया यह हो सकती थी कि 'कोई बात नहीं, अब ट्रम्प राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं और वे भी 'डीप स्टेट' पर हमला करते हैं। भाजपा विजेता का साथ देती दिखना चाहती है।' लेकिन फर्क यह है कि भाजपा के पोस्ट में अमेरिकी विदेश विभाग पर यह आरोप भी लगाया गया है कि वह इस षड्यंत्रकारी नेटवर्क की अगुआई कर रहा है।

पोस्ट में कहा गया था कि 'इस एजेंडा के पीछे हमेशा अमेरिकी विदेश विभाग का हाथ रहा है... 'डीप स्टेट' का मकसद भारत में अस्थिरता फैलाना है। फ्रांसीसी खोजी मीडिया ग्रुप 'मीडियापार्ट' ने उजागर कर दिया है कि 'ओसीसीआरपी' (ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट) को अमेरिकी विदेश विभाग के 'यूएस-एड' से पैसे मिलते हैं... वास्तव में, 'ओसीसीआरपी' की 50% फंडिंग अमेरिकी विदेश विभाग से ही आती है। पोस्ट में पेगासस विवाद, अदाणी समूह के बारे में कई खुलासों आदि का खास तौर से जिक्र किया गया है और 'डीप स्टेट' की जॉर्ज सोरोस सरीखी हस्तियों का भी उल्लेख किया गया है। यह बड़ी बात यह है कि भाजपा ने अमेरिकी विदेश विभाग पर सीधा हमला किया।

याद रहे कि 'मीडियापार्ट' वह धुर वामपंथी फ्रांसीसी मंच है, जिसने भारत के राफेल सौदे की खोजी रिपोर्टिंग की थी और कांग्रेस पार्टी तथा मोदी-आलोचकों को उन पर हमला करने का मसाला मुहैया कराया था। भाजपा अब तक तो इसे भारत और मोदी सरकार को बदनाम करने की किसी फ्रांसीसी वामपंथी चौकड़ी की चाल मानती रही होगी। लेकिन अब उसने अमेरिका जैसे विश्वसनीय सहयोगी को निशाना बनाया है। 'मीडियापार्ट' का खुलासा यह बताता है कि अमेरिकी विदेश विभाग न केवल दुनियाभर में खोजी पत्रकारिता को पैसे दे रहा है (अघोषित रूप से) बल्कि प्रमुख पदों पर नियुक्तियों और मुद्दों पर वीटो भी लगा रहा है।

अगर किसी राजनीतिक दल को लगता है कि अमेरिकी सरकार के फंड से चलने वाली किसी गतिविधि के कारण उसकी सरकार को नुकसान पहुंच रहा है तो उस पर सवाल उठाना उसका अधिकार है। वैसे भारत की किसी सत्ताधारी पार्टी ने 'विदेशी हाथ' या खासकर अमेरिका पर कोई पहली बार हमला नहीं किया है। इंदिरा गांधी के दौर में कांग्रेस अक्सर यह करती रहती थी। उस दौर में विपक्षी दलों को 'सीआईए का एजेंट' घोषित कर दिया जाता था। स्वतंत्र पार्टी के पीलू मोदी तो एक दिन 'मैं सीआईए एजेंट हूं' का बिल्ला लगाकर सदन में पहुंच गए थे। आगे चलकर राजीव गांधी और पीवी नरसिंहराव भी जब दबाव में होते थे तो अमेरिका पर हमला करने लगते थे। राजीव

बाइडेन की विदा-वेला में...

बाइडेन सरकार के आखिरी चंद महीनों में भारत और अमेरिका का रिश्ता दबाव में फंस गया। भाजपा 'डीप स्टेट' पर हमला करके जैसे को तैसा जवाब दे रही है। क्या ट्रम्प के गद्दीनशीं होने का इंतजार किया जा रहा है? क्योंकि ट्रम्प भी 'डीप स्टेट' पर लगातार हमला करते हैं।

ने तो 'नानी याद करा देंगे' तक की चेतावनी दे डाली थी। नरसिंहराव ने भी संसद में बहस के दौरान कुछ इसी तरह का बयान दे दिया था। बाद में विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी दूतावास को सफाई दी थी कि ऐसा जबान फिसलने के कारण हुआ। लेकिन अमेरिकी राजदूत विलियम क्लार्क जूनियर ने हम कुछ संपादकों के साथ बातचीत में गुस्से में कहा था कि 'क्या राव की जबान 15 मिनट तक फिसलती ही रही थी?'

बहरहाल, वो कुछ अलग ही दौर था। वह भारत का अमेरिका विरोधी शीतयुद्ध था। आज हम अलग युग में हैं, जब भारत के लगातार तीन प्रधानमंत्री और अमेरिका के पांच राष्ट्रपति दोनों देशों की दोस्ती को 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंध बता चुके हैं।

भारत और अमेरिका खुद को अगर मित्र-राष्ट्र नहीं कहते तो रणनीतिक सहयोगी तो कहते ही हैं। मोदी 2023 में जब राजकीय दौरे पर वाशिंगटन गए थे तब उन्होंने कहा था, हमने जो महत्वपूर्ण फैसले किए हैं उन्होंने हमारी विस्तृत एवं वैश्विक रणनीतिक साझीदारी में नया अध्याय जोड़ दिया है। उधर राष्ट्रपति बाइडेन ने इसे दुनिया की सबसे अहम साझेदारियों में शुमार बताया था। दोनों देशों के 6,500 शब्दों वाले संयुक्त बयान में यह तक कहा गया था कि महासागरों से लेकर आसमान तक मानवीय उपक्रम का कोई कोना हम दो महान देशों की इस साझेदारी से अछूता नहीं बचा है।

भाजपा आज अमेरिकी विदेश विभाग पर जो हमला कर रही है, उसे उपरोक्त संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए। वैसे दोनों पक्ष उच्चस्तरीय कूटनीति के तहत यह जरूर कह रहे हैं कि उनके रिश्ते में कोई समस्या नहीं पैदा हुई है। इसलिए सवाल यह है कि एक-दूसरे को बार-बार सबसे अहम रणनीतिक पार्टनर बताने वाली दो महाशक्तियां इस विरोधाभास को किस तरह पचा रही हैं? अब कांग्रेस ने भी इसमें दखल देते हुए कहा है कि अदाणी को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक संबंध को खराब किया जा रहा है। यह भी इस सीजन का एक विरोधाभास ही है, क्योंकि ये डॉ. मनमोहन सिंह ही थे, जिन्हें अमेरिका के साथ ऐतिहासिक परमाणु समझौता करने के लिए अपनी ही पार्टी के पारंपरिक अमेरिका-विरोध से निबटना पड़ा था।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
ptvijayshankarmehta.com

अपने मन, वचन और कर्म में एक होने की जरूरत है

मनुष्य के शरीर की ये विशेषता है कि उसे जैसा ढालो वैसा ढल जाता है। इस शरीर से हम बहुत सारे पाप और पुण्य करते हैं। श्रीराम ने पुण्य की एक परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है, 'पुन्य एक जग महुं नहिं दूजा, मन क्रम बचन बिप्र पद पूजा।' जगत में पुण्य एक ही है, दूसरा नहीं, और वह है मन, कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। वैसे इसका सामान्य अर्थ ही ये निकलेगा कि ब्राह्मणों का मान किया जाए। लेकिन कृष्ण जी ने कहा है कि ब्राह्मण वो है, जिसका आचरण ब्रह्म जैसा है। मनुष्य ऐसी जीवनशैली जिए, जो उसे ब्रह्म की ओर ले जाए, वही ब्राह्मण है। जाति का अपना मसला अलग है। तो श्रीराम का कहना है कि जो मन में है, वही बोलो और जो सोचो और बोलो, वही करो। यही श्रीराम की दृष्टि में बहुत बड़ा पुण्य है। इसलिए हमें इस शरीर से लगातार ये प्रयास करना चाहिए कि मन, वचन और कर्म में हम एक हों। धर्म और आध्यात्मिक दुनिया में कभी-कभी भक्त परेशान हो जाते हैं। भक्त एक प्रयोग करके देख सकते हैं। थोड़े समय मन पर प्रयोग करें, कुछ समय वचन पर करें, कुछ समय कर्म पर करें और फिर तीनों पर एक साथ करें। फिर जो राम चाहते हैं वो हम कर रहे होंगे।

• Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

विश्लेषण • टीएमसी ने अदाणी मुद्दे पर कांग्रेस का साथ नहीं दिया, सपा यूपी उपचुनावों पर अलग-थलग पड़ी

'इंडिया' गठबंधन में इन दिनों सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है

सियासत

संजय कुमार
प्रोफेसर व राजनीतिक टिप्पणीकार
sanjay@csds.in

इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से उपराष्ट्रपति- जो कि राज्यसभा के सभापति भी हैं- को हटाने के लिए एकजुट होकर नोटिस पेश किया, उससे गठबंधन सहयोगियों के बीच मजबूत संबंध का आभास हो सकता है। लेकिन यह केवल एक भ्रम है। हाल के दिनों के राजनीतिक घटनाक्रमों से स्पष्ट संकेत मिलता है कि इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के बीच दरार बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है कि विभिन्न मुद्दों पर उनके बीच पहले ही कोई मतभेद नहीं थे। विचारधाराओं का टकराव और राज्यों के स्तर पर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पहले भी थी। लेकिन विभिन्न मुद्दों पर गठबंधन सहयोगियों के बीच समन्वय और परस्पर संवाद की कमी ने इसे और बढ़ा दिया है।

तमाम मतभेदों के बावजूद, इंडिया के सहयोगी लोकसभा चुनावों के दौरान भाजपा के खिलाफ एक ताकतवर मोर्चा बनाने में कामयाब रहे थे। हां, बंगाल, पंजाब और केरल जैसे कुछ राज्य जरूर अपवाद थे। लेकिन कांग्रेस, टीएमसी, सपा और द्रमुक के अच्छे प्रदर्शन ने भाजपा के खिलाफ विपक्ष के एकजुट संघर्ष की उम्मीदें जगाई थीं। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस की अप्रत्याशित हार और महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी की करारी पराजय ने सहयोगियों में उभरते मतभेद के संकेत दिए। अदाणी, संभल और यूपी उपचुनाव परिणामों पर गठबंधन सहयोगियों द्वारा अपनाए गए अलग-अलग रुख ने मतभेद को और बढ़ाने में ही योगदान दिया है।

हरियाणा में भाजपा को हराने में कांग्रेस की असमर्थता ने कुछ इंडिया गठबंधन सहयोगियों- खासकर टीएमसी और सपा के बीच इस विश्वास को मजबूत किया कि कांग्रेस आमने-सामने के मुकाबले में भाजपा से पार नहीं पा सकती है। विश्वास जगा था कि कांग्रेस आम चुनाव के बाद पुनरुद्धार की राह पर आगे बढ़ रही है। लेकिन हरियाणा में हार, विजेता गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद जम्मू-कश्मीर और झारखंड में खराब प्रदर्शन और महाराष्ट्र में भारी पराजय के बाद यह टूट गया। टीमसी ने अदाणी मुद्दे पर संसद में कांग्रेस के नेतृत्व वाले विरोध-प्रदर्शन से खुद को अलग कर लिया। टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन ने पार्टी के रुख को व्यक्त करते हुए कहा कि संसद में भाजपा को घेरने की रणनीति में विपक्षी दल एकजुट हैं, लेकिन उनके पास अलग-अलग रणनीतियां हैं। टीएमसी ने संभल मुद्दे पर सपा सहित विभिन्न मुद्दों पर अन्य विपक्षी दलों का समर्थन किया, लेकिन अदाणी मुद्दे पर विरोध-प्रदर्शन में शामिल नहीं होने का फैसला किया। एक सपा नेता ने कहा, कई दल हमेशा कांग्रेस के पीछे खड़े होकर अपनी चुनावी संभावनाओं को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि कांग्रेस कभी-कभी राहुल गांधी के प्रभाव के कारण किसी एक मुद्दे में उलझ जाती है। वहीं अन्य दलों को किसानों की मांगों और संभल के मुद्दे को छोड़ने में कोई फायदा नहीं दिखता, क्योंकि यूपी चुनाव सिर्फ दो साल दूर हैं। टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने कहा, हम नहीं चाहते कि कोई एक मुद्दा संसद को बाधित कर दे।

समाजवादी पार्टी द्वारा उठाए उत्तर प्रदेश उपचुनावों में विसंगतियों के मुद्दे पर कांग्रेस की चुप्पी पर अखिलेश यादव के समक्ष कई सांसदों ने नाराजगी जताई। एक ने कहा, जब अखिलेश यादव ने अध्यक्ष से समय मांगा और पार्टी के सांसदों और विधायकों को संभल जाने से रोके जाने का मुद्दा उठाया तब कांग्रेस संसद के बाहर अदाणी के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर रही थी। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी को इस मुद्दे को भी अध्यक्ष के समक्ष उठाना चाहिए था। सांसद ने पूछा, जब सपा ने संसद में संभल हिंसा का मुद्दा उठाया तो कांग्रेस ने जानबूझकर चुप्पी साधी, लेकिन एक दिन बाद राहुल और प्रियंका खुद ही संभल के लिए रवाना हो गए। इसे कोई क्या समझे? सपा नेतृत्व लोकसभा में फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद को अग्रिम पंक्ति से हटाने पर कांग्रेस की चुप्पी से भी नाराज है। एक सांसद ने कहा, क्या कांग्रेस प्रियंका के लिए अग्रिम पंक्ति में सीट आरक्षित रखना चाहती है? सपा की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष अबू आजमी ने हाल ही में घोषणा की कि उनकी पार्टी ने महा विकास अघाड़ी से बाहर रहने का फैसला किया है। ऐसा उन्होंने उद्धव के सहयोगी मिलिंद नार्वेकर द्वारा बाबरी विध्वंस में शामिल लोगों की कथित तौर पर प्रशंसा करने के बाद किया।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

इंडिया गठबंधन सहयोगी विभिन्न चुनावों में सीट-बंटवारे के मुद्दे को भी हल नहीं कर पाए हैं। हरियाणा में अगर कांग्रेस ने आप के साथ गठबंधन किया होता तो नतीजे अलग हो सकते थे। अब आप ने साफ कर दिया है कि वह दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी। इस सबसे इंडिया गठबंधन के भविष्य पर सवालिया निशान लग रहे हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

आपकी राय

– राजेश कुमार चौहान, जालंधर

बाल विवाह रोकने के लिए सामूहिक प्रयास बढ़ाने होंगे

बाल विवाह को जड़ से खत्म करने के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने हाल ही में 'बाल विवाह मुक्त भारत' अभियान की शुरुआत की है। पिछले दिनों आई एक रिपोर्ट में पता चला कि देश में रोजाना 4400 बाल विवाह होते हैं, लेकिन पिछले पांच साल में सिर्फ 3.8 हजार मामलों की ही शिकायत हुई। दूसरी ओर, असम में पिछले पांच सालों में बाल विवाह में 81 प्रतिशत की कमी आई है। असम मॉडल को एक नजीर माना जा रहा है। वहीं हिमाचल सरकार ने भी लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल कर दी है। हिमाचल सरकार ने बेटियों को भी उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करने और लैंगिक समानता के उद्देश्य से यह फैसला लिया है। पूर्व सीजेआई डी. वाई. चंद्रचूड के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने कई दिशानिर्देश जारी किए थे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की सगाई को गैरकानूनी बनाने के लिए चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट (पीसीएमए) में बदलाव पर विचार करने के लिए संसद से कहा था। बहरहाल केंद्र सरकार का यह अभियान कितना रंग लाएगा, यह कितनी बेटियों के लिए वरदान साबित होगा? यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन यह अभियान तभी कामयाब होगा जब बाल विवाह कानून से जुड़ी कानूनी खामियों को दूर किया जाए। इसके अलावा समाज को भी इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी।

आप अपनी राय editpage@dbcorp.in पर भेज सकते हैं

पुरस्कृत तस्वीर : कॉमेडी वाइल्डलाइफ फोटो

वन्यजीवों की कई हरकतों को देखकर हम इंसानों के लिए अपनी हंसी रोक पाना मुश्किल होता है। कुछ ऐसा ही हुआ इटली के फोटोग्राफर के साथ। पेड़ के एक छेद में फंसी हुई यह गिलहरी इससे निकलने के लिए प्रयास कर रही थी। लेकिन अपनी इस विचित्र स्थिति में फंसी गिलहरी ऐसी स्थिति में मस्ती के मूड में लग रही थी। यह तस्वीर इस साल के कॉमेडी वाइल्डलाइफ अवॉर्ड्स में विजेता चुनी गई है। तस्वीर साभार : Milko Marchetti

नजरिया • जलवायु मिशन का 100 दिनी अभियान

जलवायु सुधार निजी पसंद नहीं, सामूहिक जिम्मेदारी है...

क्लाइमेट

प्रो. चेतन सिंह सोलंकी
आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर
chetanss@gmail.com

हमारे शहर गैस चैम्बर में तब्दील होते जा रहे हैं। चर्चाओं में अक्सर बाहरी फैक्टर्स जैसे कि पराली जलाना या औद्योगिक उत्सर्जन को दोषी ठहराया जाता है। जबकि वास्तविकता यह है कि समस्या और समाधान- दोनों ही हमारे घर में हैं। हमारी सामूहिक जीवनशैली की पसंद, ऊर्जा की खपत और अपशिष्ट उत्पादन वायु-गुणवत्ता को खराब करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति की ओर से कार्रवाई की आवश्यकता है। हम जिस हवा में सांस लेते हैं वह एक साझा संसाधन है, और इसकी गुणवत्ता हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

100 घरों वाले मोहल्ले की कल्पना करें। यदि 50 घर अपने कचरे को सावधानीपूर्वक सही जगह पर छोड़ते है, लेकिन अन्य 50 अपना कचरा सड़कों पर फेंक देते हैं, तो क्या यह क्षेत्र साफ रहेगा? 'नहीं'। इसी तरह, अगर 1,000, 1 लाख या 100 लाख लोग भी अच्छी आदतें अपनाते हैं, परंतु बाकी आबादी प्रदूषण जारी रखती है, तो इससे न तो वायु की गुणवत्ता ठीक होगी या और न ही ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी समस्याओं में कमी आएगी। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण-क्षरण वैश्विक समस्याएं हैं, जो हम सबके कारण हैं। सबको समाधान का हिस्सा बनना होगा।

पिछले चार वर्षों से मैं अपनी ऊर्जा स्वराज यात्रा के साथ पूरे देश में यात्रा कर रहा हूं, पर्यावरण क्षरण, खराब वायु गुणवत्ता और ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए समर्पित उत्साही व्यक्तियों से मिल रहा हूं। उनमें से कई लोग अपने रसोई के कचरे से खाद बनाते हैं, पानी का बहुत किफायती तरीके से उपयोग करते है, काम पर साइकिल से जाते हैं और यहां तक कि अपनी छतों पर सौर पैनल भी लगाते हैं। फिर भी, अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, वे अक्सर निराशा महसूस करते हैं। उनके पड़ोस में गंदगी रहती है, हवा प्रदूषित रहती है और नदियां भी दूषित हैं। उनके नेक काम अक्सर दूसरों की प्रदूषक आदतों के सामने बौने रह जाते हैं। चाहे कुछ व्यक्ति कितने भी प्रतिबद्ध क्यों न हों, परंतु हर व्यक्ति के कार्य ही मायने रखते हैं।

लगातार सात वर्षों से भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर सामूहिक कार्रवाई की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। इस शहर ने दिखाया है कि कचरे से निपटना और स्वच्छता हासिल करना तभी संभव है, जब उसका हर व्यक्ति इसमें अपना योगदान दे। इंदौर के लोगों और संगठनों के साथ अपनी बातचीत के दौरान मैंने एकता और प्रयास की अविश्वसनीय भावना देखी है, जो इस उपलब्धि को आगे बढ़ाती है। सीईओ से लेकर ऑटो चालकों तक, नेता से लेकर कर्मचारी तक, सभी ने इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर बनाने में भूमिका निभाई है।

अदृश्य दुश्मन अक्सर दिखने वाले दुश्मन से कहीं अधिक खतरनाक होता है। इसी तरह पर्यावरण का अदृश्य कचरा दिखने वाले कचरे से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। दिल्ली में बैठे नीति-निर्माताओं सहित, पर्यावरण पर काम करने वाली अधिकतर संस्थाएं, सिर्फ सूखे और गीले कचरे जैसे दृश्यमान कचरे पर

अगर हम जलवायु सुधार में विफल रहे, तो हमारे बच्चे जलवायु-परिवर्तन के दुःखद परिणामों से पीड़ित होंगे। चुनाव आपका और मेरा है। क्या आपका शहर इंदौर की तरह अगला जलवायु सुधार मिशन शुरू करने के लिए तैयार है?

ध्यान केंद्रित करती हैं- जो भारत में प्रति परिवार औसतन 150 से 200 किलोग्राम सालाना है। जबकि कार्बन उत्सर्जन के रूप में अदृश्य कचरा करीब 10,000 किलोग्राम से ज्यादा होता है।

इंदौर ने अब एक बड़ी चुनौती ली है : कार्बन उत्सर्जन और ग्रीनहाउस गैसों के अदृश्य कचरे से निपटना। इंदौर नगर निगम ने एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के साथ मिलकर इंदौर क्लाइमेट मिशन शुरू किया है, शहर का लक्ष्य सामूहिक रूप से अपने कार्बन पदचिह्न को कम करके वैश्विक बेंचमार्क स्थापित करना है। इंदौर जलवायु मिशन का यह 100 दिवसीय अभियान 1 दिसंबर 2024 से शुरू हुआ है और 10 मार्च 2025 तक जारी रहेगा। इसका उद्देश्य ऊर्जा साक्षरता और रोजमर्रा की जलवायु-सुधार आदतों के प्रसार के माध्यम से शहर की बिजली की खपत को 20% तक कम करना है। और वैश्विक मानदंड स्थापित करते हुए इस क्षेत्र में दुनिया का नंबर 1 शहर बनना है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

डिफ्रेंट एंगल • दिसंबर के इन दिनों में रुककर खुद पर गौर करें, अगले साल की तैयारी करें

अपना सालभर का ऑडिट करने का समय आ गया है

सेल्फ-हेल्प

रश्मि बंसल
लेखिका और स्पीकर
mail@rashmibansal.in

साल खत्म होने को आया, समय कहां गया कुछ पता नहीं। कल ही तो नन्ही की शादी की तैयारियां चल रही थीं। जनवरी की सर्दी में ठिठुरते हुए बिना शॉल के हम घूम रहे थे। खैर यूं ही जिंदगी का पहिया चलता रहता है। कभी रुकता नहीं। मगर साल के अंत में आप जरा-सा रुक सकते हो। सोच सकते हो कि आखिर इस साल हुआ क्या। बाहर की दुनिया में नहीं, आपके अंदर। जहां चित्रगुप्त का असली हिसाब-किताब चल रहा है।

1. 2024 में मेरा कौन-सा 'सॉफ्टवेयर अपडेट' हुआ? कंप्यूटर को हम अपडेट करते रहते हैं, नहीं तो वो स्लो हो जाता है। इसी तरह हमारे पर्सनल कंप्यूटर- यानी दिमाग को भी अपडेट की जरूरत होती है। खासकर, जब घर के बच्चे बड़े होने लगते हैं। जैसे आपकी बेटी की नौकरी लग गई, और वो आपको किसी अच्छे रेस्तरां में खाना खिलाने के लिए ले गई। मेन्यू में आपकी नजर सिर्फ राइट साइड पर है, जहां दाम लिखा है। महंगा खाना आपके गले नहीं उतर रहा। आपको फिजूलखर्ची पसंद नहीं। लेकिन आज वो हालात नहीं जहां पाई-पाई बचाना पड़े। तो आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ : पैसा खर्च करना, उसे एंजॉय करना भी मुझे आता है। आपका भी कोई ना कोई पुराना प्रोग्राम अपडेट हुआ होगा। विचार कीजिए, नोट कीजिए। चलते हैं दूसरे सवाल पर।

2. 2024 में आप को किस चीज के लिए अवॉर्ड मिलना चाहिए? यूं तो आए दिन पेपर में पढ़ते हैं- फलाना को पुरस्कार मिला। फिर सोचते हैं, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं, उद्योगपति नहीं, मुझे कौन पुरस्कार देगा। भाई, पहले आप खुद तो पहचानिए कि मैंने कौन-सा ऐसा काम किया, जो अवॉर्ड के लायक है।

शायद आपके घर पर कोई महीनों तक बीमार था, आपने उसकी सेवा की। दुनिया जाने न जाने, आप जानते हो कि कितने धैर्य से अपनी जिम्मेदारी निभाई। तो आंख बंद करके मन के परदे पर एक चित्र लाइए। अनाउंस हो रहा है- 'अवार्ड फॉर मोस्ट डेडिकेटेड फैमिली मेंबर'। आप स्टेज पर जाकर रिसीव कर रहे हो। अगर आपका दिल भर आया, तो बस। चाहे कोई शाबासी दे या नहीं, आपको यूनिवर्स से सराहना मिल गई है। आप अपने आपको वो अवॉर्ड दीजिए, एहसास कीजिए। और अब आते हैं सवाल नंबर तीन पर।

3. 2024 में ऐसा क्या था जो आप डर की वजह से कर नहीं पाए? हमारे अंदर एक इच्छा उमड़ती है। एक छोटी-सी नाव, जो डर की लहरों से थपेड़े खाकर डूब जाती है। कि ऐसा करने से कुछ खराब हो जाएगा, फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। तो डर के मारे आप थम गए। कभी बैठे थे, अब जम गए। भाई, अंदर की आग को जरा जलाओ, उस जमी हुई बर्फ को पिघलाओ। फेल हो भी गए तो क्या, कदम तो बढ़ाया; जीवन से कुछ सीखा या किसी को सिखाया। घर पर अगर हो मार-पिटाई, क्यों सहते हो आप अन्याय। सिंगल होना कोई शाप नहीं, बच्चा पल सकता है फिर भी सही। ये तो एक उदाहरण है, वैसे डर के कई कारण हैं। आपको एक खास प्याले में किसी खास के हाथ की चाय पीने की आदत है, एक दिन वो इंसान दुनिया में रहा नहीं, अब कयामत है। जीने वालों के दिल में खौफ है मरने का। लेकिन वो तो होना ही है, तो फिर क्या डरने का।

2025 में जीना है खुलकर, खड़े मत रहो आशंका के पुल पर। आर लगाओ या पार, लेकिन चलते रहो मेरे यार। नया साल, नया जोश। जब तक है जान, जब तक है होश।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • मंगलवार • 17 दिसम्बर • 2024
www.rashtriyasahara.com

बदलते अब्दुल्ला

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस की तरफ से ईवीएम को लेकर की जा आपत्ति पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस को ईवीएम का रोना बंद कर, चुनाव नतीजों को कुबूलना चाहिए। अब्दुल्ला ने कहा, जब आपको संसद में सौ से ज्यादा सदस्य मिलते हैं तो इसे जीत के रूप में उत्साहित होते हैं। कुछ महीनों बाद जब परिणाम आपके पक्ष में नहीं आए तो पलट कर उन्हें दोष नहीं दे सकते। उन्होंने कहा अगर ईवीएम समस्या है, तो आपको लगातार समस्या होनी चाहिए। एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में अब्दुल्ला ने क्रांगेस के खिलाफ जाते हुए नये संसद भवन की तारीफ की। उनके विचारों से स्पष्ट है कि उनकी पार्टी नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस के बीच दरारें आ रही हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन के तौर पर कांग्रेस की भूमिका पर

सवाल करते हुए कहा कि संसद में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के कारण उसे लोक सभा व राज्य सभा दोनों जगह विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी भी मिली है। इस पर दूसरे दल दावा नहीं कर सकते। इससे पहले भी इंडिया गठबंधन की दो प्रमुख दल सपा व टीएमसी अडानी मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदर्शन में साथ नहीं आए। मायावती एक देश-एक चुनाव को लेकर सरकार के पक्ष में आ चुकी हैं। उधर गठबंधन में ममता बनर्जी को नेतृत्व की कमान देने जैसी बातें भी जोर-शोर से उठ रही हैं। जिसका समर्थन लालू यादव भी कर चुके हैं। अब अब्दुल्ला के भाजपा के सुर में बोलने को इसी फूट से जोड़ा जा सकता है। भले ही वह इसे अपनी स्वतंत्र सोच का उदाहरण कह रहे हैं। केंद्र सरकार भी विपक्ष द्वारा इवीएम पर उंगली उठाए जाने पर यही दलील देती है। क्षेत्रीय दलों के साथ कांग्रेस का गठजोड़ कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। गठबंधन की राजनीति के अपने कुछ कायदे हैं, कांग्रेस जिनकी अनदेखी करती रही है। उसे बिखरने से बचाने की उम्मीद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने भी कहा है कि कांग्रेस को नेतृत्व का मोह छोड़ना होगा। अय्यर ने कांग्रेस को आगे बढ़ने के लिए सभी दलों को उचित सम्मान देने की भी सलाह दी। मोदी को चुनौती देने और सरकार के खिलाफ सभी विपक्षी दलों को एक-जुट रहने के प्रयास कमजोर पड़ते जा रहे हैं। संसदीय चुनाव में इस गठबंधन ने मोदी सरकार को कड़ी टक्कर देकर काफी उम्मीदें बढ़ा ली थी। जो हरियाणा व महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव तक काफूर हो गई। यदि कांग्रेस ने अपना रवैया नहीं बदला तो सहयोगी दलों की यह अनदेखी उसको भारी पड़ सकती है।

हिंसा तो छोड़नी होगी

केंद्र सरकार नक्सलियों के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध है, इस बात के लिए सरकार की सराहना तो करनी ही चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह कथन बेहद महत्त्वपूर्ण माना जाना चाहिए कि नक्सलियों को अगर शांति के साथ जीवन बिताना है तो उन्हें हथियार छोड़ मुख्यधारा में लौटना होगा। जब से केंद्र में नरेन्द्र मोदी की सरकार सत्तासीन हुई है, तभी से नक्सलियों के समूल नाश के लिए सरकार की प्रतिबद्धता परिलक्षित हुई है। पिछली कई मुठभेड़ में नक्सलियों को भारी चोट पहुंची है और उन्हें एक सीमित इलाके में रहने को मजबूर किया गया है। यह इस बात का द्योतक है कि सरकार ने नक्सलियों पर पूरी तरह से लगाम कसने का मन बना लिया है। आंकड़ों की बात करें तो एक वर्ष में 287 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया तो 837 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। यह इस बात का प्रमाण है कि

सरकार अब देश के दुश्मनों को बख्शने के मूड में नहीं है। वैसे भी नक्सली होने की आड़ में इन्होंने जितना नुकसान समाज और देश का पहुंचाया है, उतना किसी और संगठन ने नहीं पहुंचाया है। बहरहाल, सरकार की मंशा नक्सलियों को बढ़ने देने की नहीं दिखती है। चार दशक में पहली बार ऐसा हुआ है कि नक्सली हिंसा में मारे गए आम नागरिकों और सुरक्षा बलों की संख्या 100 से कम रही है। पिछले दस वर्षों में तुलनात्मक रूप से माओवादी हिंसा में बलिदान होने वाले सुरक्षाकर्मियों की संख्या में 73 प्रतिशत और नागरिकों की मृत्यु में 70 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। दरअसल, केंद्र में मौजूद मोदी सरकार ने माओवादियों की आड़ में समाज में हिंसा फैलाने और देश में विकास कार्यों को नुकसान पहुंचाने की साजिश को वक्त रहते समझ लिया और इसके खात्मे की प्रतिबद्धता दिखाई। हालांकि नक्सलियों की गांव-देहात तक में पहुंच और कथित तौर पर बनाई गई रॉबिनहुड की छवि से सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को भारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, मगर अंततः दूरदराज के भोले-भाले लोगों को यह बात समझ में आ गई कि उनकी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा ये नक्सली हैं। लिहाजा, सरकार को भी नक्सलियों के खिलाफ एक्शन लेने में आसानी हुई। बहरहाल, मोदी सरकार ने जिस तरह नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा में आने का न्योता दिया है, उससे उम्मीद की जानी चाहिए कि हालात बदलेंगे।

बोरबेल हादसा/योगेश कुमार गोयल

मासूमों की अटकती सांसें

देश के विभिन्न हिस्सों में खुले बोरवेल मासूम बच्चों के लिए लगातार काल बन रहे हैं। कुछ वर्षों में ही सैकड़ों बच्चे बोरवेल में समाकर दम तोड़ चुके हैं, लेकिन ऐसे हादसों पर लगाम कसने में सफलता नहीं मिल रही है। केवल राजस्थान के दौसा जिले में ही साढ़े तीन महीने में चार बोरवेल हादसे सामने आ चुके हैं, मगर न तो लोग ऐसे हादसों को लेकर चेतने को तैयार हैं, न ही प्रशासन की नींद टूट रही है। विडम्बना है कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए समाज में कहीं कोई जागरूकता नजर नहीं आती। ऐसे हादसों में बहुत ही कम बच्चों या लोगों को बचाने में सफलता मिलती है। इसलिए खेतों में बोरवेल के खुले होने को लेकर देशव्यापी बहस छेड़े जाने की सख्त जरूरत महसूस होने लगी है।

एनडीआरएफ की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में कई बच्चे बोरवेल में गिर चुके हैं, लेकिन उन्हें बचाने में 70 प्रतिशत रेस्क्यू ऑपरेशन नाकाम रहे हैं। ऐसे हादसों को लेकर सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि मासूम बच्चों की समाधि बनते इन बोरवेल हादसों को लेकर समाज से लेकर पूरा सिस्टम आखिर कब गंभीर होगा? एनडीआरएफ के मुताबिक बोरवेल उपयोग के मामले में भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है और बोरवेल से जुड़े अधिसंख्य हादसों में छोटे बच्चे ही शिकार बनते हैं, जिनमें से महज 30 प्रतिशत बच्चों के ही सुरक्षित बाहर निकाले जाने की संभावना होती है। आंकड़े देखें तो भूगर्भ जल विभाग के अनुमान के अनुसार देशभर में करीब 2.7 करोड़ बोरवेल हैं, लेकिन सक्रिय बोरवेल की संख्या, अनुपयोगी बोरवेल की संख्या और उनके मालिक का राष्ट्रीय स्तर पर कोई डाटाबेस नहीं है। बोरवेल हादसों में बच्चों को बचाने में अक्सर सेना-एनडीआरएफ की बड़ी विफलताओं को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं कि अंतरिक्ष तक में अपनी धाक जमाने में सफल हो रहे भारत के पास चीन तथा कुछ अन्य देशों जैसी वे स्वचालित तकनीक क्यों नहीं हैं, जिनका इस्तेमाल कर ऐसे मामलों में बच्चों को अपेक्षाकृत काफी जल्दी बोरवेल से बाहर निकालने में मदद मिल सके। देश में ऐसी स्वचालित तकनीकों की व्यवस्था करने की दरकार है, जो ऐसी विकट परिस्थितियों में शीघ्र राहत प्रदान करने में सक्षम हों।

शास्त्रीय संगीत के सुपर स्टॉर

आलोक पराड़कर

उस्ताद जाकिर हुसैन को भारतीय शास्त्रीय संगीत का सुपरस्टॉर कहना गलत न होगा। साधक तो वे तबला के थे, जिसे मुख्यतः संगत वाद्य ही माना गया है, लेकिन उनकी लोकप्रियता सब पर भारी थी। वे भारतीय शास्त्रीय संगीत के संभवतः सर्वाधिक पारिश्रमिक लेने वाले कलाकार थे, उनके कार्यक्रमों के लिए आयोजकों को लंबा इंतजार करना होता था, उनका आकर्षण ऐसा था कि फिल्मों और विज्ञापनों में भी उन्हें लिया जाता रहा। वे विश्व में भारत के सांस्कृतिक राजदूत भी थे और प्रख्यात सितार वादक पंडित रविशंकर के बाद वे ही थे जिन्होंने विभिन्न देशों में भारतीय संगीत को लोकप्रिय बनाया और एक बड़ा प्रशंसक वर्ग तैयार किया।

'ग्रैमी' जैसे प्रतिष्ठित अवार्ड में भी उन्होंने भारतीयता का परचम लहराया, लेकिन लोकप्रियता के शिखर पर होने और अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद उनके काम में कहीं समझौता नहीं था। वास्तव में उनमें नाम और काम का संतुलन कुछ वैसा ही था जैसा उनके तबले में बाएं और दाएं का। उनकी उपस्थिति जहां समारोहों की सफलता का पर्याय थी, वहीं उनकी संगत से मुख्य कलाकार का कार्यक्रम भी निखर उठता था। लंबे समय की सफलता उनकी विनम्रता को बदल नहीं सकी थी। हंसमुख, हाजिर जवाब और हरदिल अजीज उस्ताद जाकिर हुसैन अपने व्यक्तित्व में भी कृतित्व जैसी खूबसूरती जीवनपर्यंत कायम रख सके।

तबले को मुख्यतः संगत का वाद्य ही माना गया है, लेकिन उस्ताद जाकिर हुसैन उन कुछ तबला वादकों में थे जिन्होंने इसे एकल और मुख्य वाद्य के रूप में भी स्थापित किया। वे जब लोकप्रिय होने लगे तो पिता के साथ उनकी जुगलबंदी का चलन खूब था। पिता-पुत्र का तबला वादन खूब पसंद किया जाता था। उस्ताद जाकिर हुसैन के एकल वादन की खास बात यह भी होती कि उन्होंने अपने वादन को शास्त्रीय संगीत के मर्मज्ञों के योग्य ही नहीं बनाया बल्कि इसे आम लोगों के लिए भी रुचिकर बना दिया था। जिस प्रकार प्रख्यात कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज अपनी तिहाइयों को दर्शकों को समझाने के लिए तरह-तरह की कथा-प्रसंगों का सहारा लेते थे, कभी चिड़ियों का उदाहरण देते तो कभी बच्चों के गेंद खेलने का, उस्ताद जाकिर हुसैन भी तबले पर कभी डमरू, कभी मंदिर की घंटी, कभी रेल तो कभी घोड़े की टाप का वादन करते हुए आम लोगों में भी अपनी गहरी पैठ बना लेते थे। शास्त्र को लोकप्रिय मुहावरे में इस प्रकार ढाल लेने का कौशल उन्हें खूब आता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वे एकल वादन के ही उस्ताद थे। एकल वादन के साथ ही उनकी संगत की भी खूब मांग और धूम थी। वे जब संगत करते तो कार्यक्रमों का एक नया ही रंग बन जाता। पहले प्रख्यात सितार वादक पंडित रविशंकर के साथ और फिर प्रख्यात बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, प्रख्यात संतूर

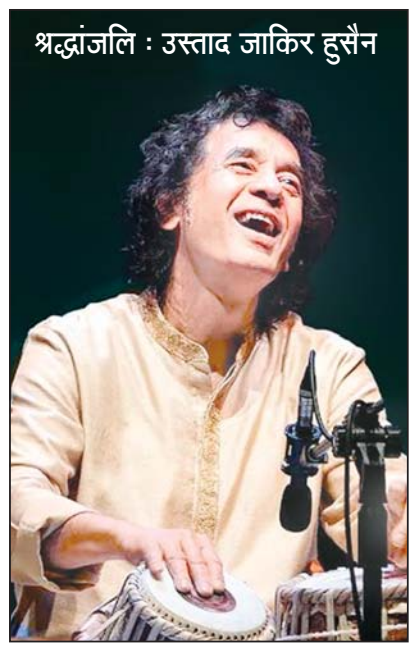

वादक पंडित शिवकुमार शर्मा, प्रख्यात कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज जैसे कलाकारों के साथ उन्होंने खूब कार्यक्रम किए। शिव-हरि के साथ उनकी संगत खूब फबती थी जिसके कई वीडियो आज भी यू-ट्यूब पर देखे जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने हर प्रमुख कलाकार के साथ संगत की, शास्त्रीय संगीत से लेकर सुगम और फिल्म संगीत तक, वरिष्ठ एवं प्रख्यात कलाकार से लेकर युवा और उभरते कलाकारों तक, उन्होंने सबके साथ बजाया।

लोकप्रिय पार्श्व गायक हरिहरन के साथ गजलों के अलबम में उनकी उपस्थिति साफ नजर आती है। उस्ताद जाकिर हुसैन ने संगत को लेकर अपने दृष्टिकोण से जुड़ा एक बड़ा जरूरी किस्सा एक बार लखनऊ में बताया था। उन्होंने बताया था कि मैं 17 साल का था और पंडित रविशंकर जी के साथ यात्रा पर था। एक कार्यक्रम हुए, दूसरा कार्यक्रम हुआ, मैंने रविशंकर जी से पूछा कि कैसा हो रहा है? रविशंकर जी ने कहा कि तुम मेरे साथ तबला बजाते हो लेकिन मुझे देखते क्यों नहीं? उसके बाद शाम को जब कार्यक्रम हुआ तो उस्ताद जाकिर हुसैन पंडित रविशंकर की ओर थोड़ा और घूमकर बैठ गए। उस दिन संगत की एक नई किताब खुल गई। वह पंडित जी को देखकर बजाने लगे और उन्हें समझ में आने लगा कि संगत कैसे करनी है। वह कहते थे कि जब आपकी तालीम होती है तो आपकी एकल वादन की तालीम होती है। आप सीखी हुई चीजें बजा देंगे और आपकी प्रशंसा हो जाएगी, लेकिन जब तक संगत करना नहीं आएगा तब तक आप तबलिए नहीं बन सकते।

वह यह भी कहते थे कि सभी रंग का तबला आपके तबले में समाहित नहीं है तो आप एक अच्छे संगतकार नहीं बन सकते। सिर्फ दिल्ली का बजाकर, सिर्फ बनारस का बजाकर, सिर्फ पंजाब का बजाकर आप अच्छे संगतकार नहीं बन सकते। हालांकि उस्ताद जाकिर हुसैन कभी भी संगत में हावी होने की कोशिश नहीं करते थे, अपनी लोकप्रियता का दंभ नहीं दिखाते थे, वे मुख्य कलाकार की जरूरत और सोच के अनुसार ही तबला वादन करते थे लेकिन कई बार ऐसा भी होता था कि उनकी लोकप्रियता पूरे कार्यक्रम में हावी हो जाती थी। ऐसे में यह भी हुआ कि कई कलाकार उनकी लोकप्रियता से आक्रांत होने लगे, उनसे परहेज करने लगे। उस्ताद जाकिर हुसैन भारतीय संगीत के सांस्कृतिक राजदूत भी थे। ज्यादातर प्रसिद्ध कलाकार विदेश में कार्यक्रम करते हैं, कई-कई महीने वहां गुजारते हैं, लेकिन प्रख्यात सितार वादक पंडित रविशंकर के बाद उस्ताद जाकिर हुसैन ही थे जिन्हें विश्व के संगीतप्रेमियों ने सिर-आंखों पर बिठाया। वे लंबे समय से अमेरिका में ही रहते थे। विभिन्न देशों के संगीत के साथ उनके कार्यक्रम भी खूब होते थे।

इन सबके बावजूद वे भारत में भी लगातार सक्रिय रहते थे। अपने सुदर्शन व्यक्तित्व के कारण उन्हें फिल्मों में अभिनय करने का आमंत्रण मिला था। विज्ञापन में तो वे बहुत पहले ही आ चुके थे। उनके समकालीन मानते थे कि उनकी लोकप्रियता में बड़ा योगदान विज्ञापनों का भी रहा है, जिसके कारण वह घर-घर में पहचाने जाने लगे थे। वाह उस्ताद उनके नाम से जुड़ गया था, लेकिन अचानक वे अपने प्रशंसकों को आह भरता छोड़ गए।

वे लंबे समय से अमेरिका में ही रहते थे। विभिन्न देशों के संगीत के साथ उनके कार्यक्रम भी खूब होते थे। इन सबके बावजूद वे भारत में भी लगातार सक्रिय रहते थे। अपने सुदर्शन व्यक्तित्व के कारण उन्हें फिल्मों में अभिनय करने का आमंत्रण मिला था। विज्ञापन में तो वे बहुत पहले ही आ चुके थे। उनके समकालीन मानते थे कि उनकी लोकप्रियता में बड़ा योगदान विज्ञापनों का भी रहा है, जिसके कारण वह घर-घर में पहचाने जाने लगे थे

अच्छी लाइफस्टाइल कई बीमारियों के खिलाफ सुरक्षा कवच

- -अब कम उम्र में ही लोग डायबिटीज, बीपी, दिल की बामारियों के शिकार हो रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, इन बीमारियों के पीछे एक बड़ा कारण खराब लाइफस्टाइल है
- इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) की रिपोर्ट कहती है कि इन रोगों से होने वाली मौतों का अनुपात साल 1990 में 37.9 से बढ़कर वर्ष 2016 में 61.8 फीसद हो गया है। अब देश में 66 फीसद से ज्यादा मौतें ऐसी बीमारियों से होती हैं
- खाने-पीने की खराब आदतें, बिल्कुल भी एक्सरसाइज न रना, वायु प्रदूषण, स्मोकिंग, मोटापा समेत अनेक कारण इन बीमारियों के लिए जिम्मेदार ठहराए जाते हैं

(स्रोत : मीडिया इनपुट्स)

जिन 'वीआइपी' लोगों के लिए संभव हो, उन्हें हेलीकॉप्टर से आना-जाना चाहिए। समय बचेगा और जनता की मुश्किलें भी कम होंगी। ट्रैफिक रोकने से ट्रेन-विमान-अस्पताल-स्कूल को जाने वालों पर कैसी आफत आ जाती है। कितना अमला खपता है। सायरन बजते हैं। धुआं उड़ता है।

ओम थानवी, पत्रकार
@omthanvi

प्रियंका के पहले भाषण ने जीता दिल

लोक सभा अमरेंद्र कुमार राय

प्रियंका गांधी से लोगों को शुरू से ही बहुत उम्मीदें रही हैं। ऐसे लोगों की कमी नहीं जो मानते थे कि अगर प्रियंका राजनीति में उतरें तो अपनी दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी की तरह अपने सभी राजनीतिक विरोधियों की छुट्टी कर देंगी। वे उनमें इंदिरा गांधी की शक्ल देखते थे। वही आंखें वैसा ही नाक-नक्श; हू ब हू, लेकिन प्रियंका गांधी लंबे समय तक राजनीति में नहीं आईं, आईं भी तो अपने आप को सिर्फ अमेठी और रायबरेली तक समेटे रहीं।

अब वो दिन भी आया जब प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में आईं। उम्मीद की गई कि वे पार्टी को उत्तर प्रदेश में मजबूत बनाएंगी। उन्होंने कोशिश भी की। सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी का ढांचा चरमरा गया है। उसे मजबूत करने की जरूरत है। प्रियंका गांधी ने इस दिशा में पहल भी की। उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपनी सक्रियता भी बढ़ाई। लोग उनसे जुड़े भी, लेकिन चुनावों में इसका असर बिल्कुल भी नहीं दिखा। बल्कि यूं कहें कि इसका उलटा हुआ। पिछले विधान सभा चुनावों में पार्टी करीब ढाई प्रतिशत वोटों पर सिमट गई। तब कहा जाने लगा कि प्रियंका को राजनीति में लाने में देर कर दी गई। बाद में तो यह भी चर्चा सुनी जाने लगी कि प्रियंका गांधी राज्य सभा के जरिये संसद में जाना चाहती हैं। हिमाचल में कांग्रेस की जब जीत हुई और सरकार बनी तो चर्चा चली कि प्रियंका वहां से राज्य सभा में जा सकती हैं।

बाद में ऐसी ही चर्चा राजस्थान और तेलंगाना से भी जाने में हुई, मगर यह सब कयासबाजी ही साबित हुई। लोक सभा चुनाव में स्मृति ईरानी लगातार ताल ठोंक रही थीं और अमेठी से राहुल गांधी को चुनाव लड़ने के लिए ललकार रही थीं। वे 2019 में राहुल को अमेठी से हरा चुकी थी और उनके हौसले बुलंद थे। हालांकि जितने सर्वे हो रहे थे उन सबमें यही दिख रहा था कि राहुल गांधी स्मृति ईरानी पर भारी पड़ रहे हैं, फिर भी राहुल या कांग्रेस ने ये साफ नहीं किया कि वे अमेठी से चुनाव लड़ेंगे ही। आखिर में जब सोनिया ने साफ किया कि खराब स्वास्थ्य के कारण वे चुनाव नहीं लड़ेंगी तो एक बार फिर चर्चा चली कि राहुल अमेठी से और प्रियंका रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन आखिर में राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड से चुनाव लड़े। राहुल अमेठी

और वायनाड दोनों जगहों से जीते। जब उन्होंने वायनाड छोड़ा तो प्रियंका वहां से चुनाव लड़ीं। वहां से वो चार लाख से ज्यादा वोटों से जीततीं। अभी पिछले हफ्ते ही उन्होंने लोक सभा में अपना पहला भाषण दिया। भाषण अच्छा था। सबने उन्हें सम्मान दिया। पक्ष ने भी और विपक्ष ने भी। उनके भाषण के दौरान सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी कम ही टोकाटोकी की। उनका भाषण काफी संतुलित और तथ्यपरक था। वे पूरी तैयारी से सदन में आई थीं और लिखकर ले आई थीं और उसे पढ़ रही थीं। लोगों ने उनके भाषण की तारीफ की फिर भी लोगों का कहना है कि प्रियंका गांधी जब बिना स्क्रिप्ट के भाषण देती हैं तो वो ज्यादा अच्छा और असरदार होता है। अभी चल रहे संसद के मौजूदा सत्र में लोक सभा में तीन लोगों के भाषण की ज्यादा चर्चा हो रही है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। प्रियंका गांधी ने करीब आधे घंटे भाषण दिया, राहुल गांधी ने करीब 26 मिनट जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घंटे भर से ज्यादा। सभी जानते हैं कि मोदी बहुत अच्छा भाषण देते हैं। प्रियंका गांधी भी अच्छा बोलती हैं, लेकिन उनके भाषण की तुलना अभी तक मोदी के भाषण से नहीं हुई थी। राहुल कमजोर वक्ता हैं, ये सभी लोग मानते हैं, लेकिन इस बार संसद में हुए भाषणों में जो तथ्य आये हैं उसने मोदी जी की लोकप्रियता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। संसद टीवी पर उनके भाषण को एक खास समय में सिर्फ 26 हजार लोगों ने देखा, जबकि भाषण के मामले में कमजोर माने जाने वाले राहुल गांधी के भाषण को 86 हजार लोगों ने देखा। इस मामले में तो प्रियंका गांधी इन दोनों से ही बहुत आगे रहीं। उनके भाषण को नरेंद्र मोदी के भाषण से सात गुना ज्यादा लोगों ने देखा। उनके भाषण को एक लाख 89 हजार लोगों ने देखा।

ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री पर लोगों का भरोसा कम हो रहा है। उनकी लोकप्रियता में कमी आ रही है। यही वजह है कि उनका भाषण अच्छा होने के बावजूद उन्हें कम लोगों ने देखा, जबकि विपक्ष के नेता राहुल पर लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। लोग मान रहे हैं क राहुल भले अच्छा भाषण न देते हों पर वे सच बोलते हैं, दिल से बोलते हैं और लोगों की दिल से भलाई चाहते हैं। इसीलिए उनका भाषण कमजोर होने के बावजूद मोदी से तीन गुना ज्यादा लोगों ने देखा। प्रियंका संसद में पहली बार बोल रही थीं। शायद इस वजह से भी उनका भाषण बहुत ज्यादा लोगों ने देखा। पर इतना तो तय है कि वे एक अच्छी वक्ता है। कांग्रेस को लोक सभा में अच्छे हिंदी वक्ता की कमी जो खल रही थी अब उसे पूरा करने के लिए वे आ गई है। प्रियंका भले दक्षिण भारत से जीतकर लोक सभा में पहुंची है पर इससे उत्तर भारत में कांग्रेस को नया बल मिल सकता है।

स्वप्न ओशो

यह सच है। अब तुम्हें और गहरा करना है इस अनुभूति को, ताकि कभी तुम अनुभव कर सको कि तुम भी एक स्वप्न हो। और गहरे उतरो इस अनुभूति में। एक घड़ी आती है जब तुम जान लेते हो कि जो भी है, सब सपना ही है। जब तुम यह जान लेते हो कि जो भी है सब सपना है, तो तुम मुक्त हो जाते हो। यही तो अर्थ है हिन्दुओं की माया की धारणा का। वह यह नहीं कहती कि सब कुछ झूठ है; वह इतना ही कहती है कि सब कुछ सपना है। सवाल सच या झूठ का नहीं है। तुम क्या कहोगे सपने को? वह सच है या झूठ? यदि वह झूठ है, तो कैसे दिखाई पड़ता है वह? यदि वह सच है, तो कैसे मिट जाता है वह इतनी आसानी से? तुम अपनी आंखें खोलते हो और वह कहीं नहीं होता। सपना जरूर कहीं सच और झूठ के बीच होगा। उसमें जरूर कुछ न कुछ अंश होगा सच्चाई का और उसमें जरूर कुछ -न-कुछ अंश होगा झूठ का। सपना भी होता तो है, सपना एक सेतु है, न वह इस किनारे पर है और न उस किनारे पर है; न इधर है, न उधर है। यदि तुम सपने को सच मान लेते हो, तो तुम सांसारिक हो जाओगे। यदि तुम सपने को झूठ मान लेते हो तो तुम बच कर भागने लगोगे हिमालय की ओर; तुम असांसारिक हो जाओगे। और दोनों ही दृष्टिकोण अतियां हैं। सपना ठीक मध्य में है। वह सच और झूठ, दोनों है। उससे भागने की कोई जरूरत नहीं है, वह एक झूठ है। उसे पकड़ने की भी कोई जरूरत नहीं है, वह एक झूठ है। सपनों के पीछे जिंदगी गंवाने की कोई जरूरत नहीं है, वे झूठ हैं। और उन्हें त्याग देने की भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कैसे तुम झूठ का त्याग कर सकते हो? उनका उतना भी अर्थ नहीं है। और इसी समझ से संन्यास की मेरी धारणा का जन्म होता है। तुम सपने को यह जानते हुए जीते हो कि वह एक सपना है। तुम संसार में यह जानते हुए जीते हो कि वह एक सपना है। तब तुम संसार में होते हो, लेकिन संसार नहीं होता तुम में। तुम संसार में चलते हो, लेकिन संसार नहीं चलता है तुम में। तुम बने रहते हो संसार में। असल में, तुम अब उसका और भी आनंद लेते हो क्योंकि एक सपना ही है; तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तब तुम गंभीर नहीं होते। असल में, तुम खेलने लगते हो बच्चों की भांति क्योंकि सपना ही है। तुम उसका आनंद ले सकते हो, उसका मजा ले सकते हो। अपराधी अनुभव करने जैसा कुछ नहीं है उसमें। एक उत्सव है जीवन का।

रीडर्स मेल

https://t.me/AllNewsPaperPaid

उस्ताद को नमन

महान तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन संगीत जगत की अपूरणीय क्षति है। महज ग्यारह बरस की उम्र में उन्होंने तबले से नाता जोड़ा और ता-उम्र उसी को मित्र बनाकर देश-दुनिया में भारतीय संगीत को तबले की थाप से प्रसिद्धि दिलवाई। इनके पिता प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद अल्लाह रक्खा खान से इन्हें तबले में रुचि हुई और तबले में महारत हासिल की। इन्होंने संगीत जगत के मशहूर ग्रैमी अवार्ड को चार बार अपने नाम किया। ऐसे जन-जन के लोकप्रिय उस्ताद जाकिर हुसैन को हृदय से नमन।

संजय डागा, इंदौर, मप्र

महिला कानून का हो सही उपयोग

महिला सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का उद्देश्य महिलाओं को न्याय दिलाना और उन्हें उत्पीड़न से बचाना था। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए इसका प्रमुख उदाहरण है, जिसे दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा से विवाहिता महिलाओं की सुरक्षा के लिए लागू किया गया, लेकिन समय के साथ इस कानून का दुरुपयोग एक गंभीर समस्या बन गया है। झूठे आरोपों और दुर्भावनापूर्ण मामलों के कारण निर्दोष परिवारों को कानूनी, सामाजिक और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। इस समस्या के समाधान के लिए कानूनी सुधार आवश्यक हैं। सबसे पहले, मुकदमा दर्ज करने से पहले पर्याप्त साक्ष्यों की जांच होनी चाहिए। पुलिस को भी निर्देश दिया जाए कि बिना ठोस प्रमाणों के मामला न दर्ज करें। यदि कोई मामला झूठा साबित हो, तो शिकायतकर्ता पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही, कानूनी साक्षरता बढ़ाने की आवश्यकता है। जागरूकता अभियान के माध्यम से यह समझाना होगा कि कानून का उद्देश्य न्याय सुनिश्चित करना है, न कि किसी निर्दोष को फंसाना। महिला सुरक्षा के कानूनों का सही उपयोग ही न्याय और शांति सुनिश्चित करेगा।

अवनीश कुमार गुप्ता, आजमगढ़

साजिश की बू

9 अगस्त 2024 को कोलकाता स्थित आर.जे. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में जिस तरह से एक महिला चिकित्सक का बलात्कार के बाद हत्या की गयी थी वो बेहद दुखद एवं हृदयविदारक था, मगर उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसमे पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग कम और उसमे राजनीति का दुर्गन्ध ज्यादा फैल गया था। जिस तरह से महीनों तक इस पर मीडिया कवरेज किया गया। मीडिया पर बार-बार एक ही बात कही जा रही थी कि इसके पीछे राज्य सरकार का हाथ है। बीजेपी के लोग एवं मीडिया इस तरह से उस घटना को लेकर अतिरंजित प्रतिक्रिया दे रहे थे उससे ये लग रहा था मानो देश की ये पहली घटना थी। इस कॉलेज के प्रिंसिपल को जिस तरह से बेइज्जत करके गिरफ्तार किया गया था उसका अंतिम परिणाम क्या निकला? प्रिंसिपल संदीप घोष और पुलिस अधिकारी अभिजीत मंडल के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने में केंद्रीय जांच ब्यूरो अबतक विफल रही है। उनके पास कोई सबूत ही नहीं है। अदालत ने अंततः घोष और मंडल को 13 दिसम्बर को जमानत दे दी। इससे क्या साबित होता है की इस घटना के बहाने बीजेपी का राइटर्स बिल्डिंग पर कब्जा करने का गेमप्लान था। जो अब पूरी तरह से विफल हो चुका है।

जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर, झारखंड

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750

वर्ष-34, अंक 120 आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्

भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

तबले ने खो दिया 'उस्ताद'

भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में लोकप्रिय कलाकार और संगीत रत्नों में से एक तबला वादक जाकिर हुसैन अब हमारे बीच में नहीं रहे। अमेरिका के सैन फ्रांस्सिको के अस्पताल में उन्होंने 73 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। इसके साथ ही संगीत की दुनिया में तबले की एक बेमिसाल थाप शांत हो गई। जाकिर हुसैन संगीत की दुनिया के वो सितारा थे जिनकी चमक को शब्दों में प्रभावित करना असंभव है। तबले पर उनकी उंगलियों की थिरकन कभी हमें बारिश की रिमझिम का अहसास दिलाती थी तो कभी आकाशीय बिजली की गर्जन का अहसास करती थी। उनके तबले की थाप से कभी भावनाएं नदी के प्रवाह की तरह बहने लगती थी तो कभी दिल की धड़कनें तेज हो जाया करती थी। उनकी उंगलियों की थिरकन आत्मा को छू जाती थी और सुनने वाला यह कह उठता था 'वाह उस्ताद वाह' उनके पिता उस्ताद अल्लारखा खान भी तबले के महान उस्ताद थे और उन्होंने ही अपने बेटे को तबले की सारी विधाएं बताई थी। यह सही है कि जाकिर हुसैन को संगीत विरासत में मिला लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा से उसे नई ऊंचाईयां दी हैं।

जाकिर हुसैन ने अपने करियर की शुरूआत छोटी उम्र में कर दी थी। वे 11 साल की उम्र में स्टेज प्रोग्राम करने लगे थे। उन्होंने न केवल भारतीय शास्त्रीय संगीत में बल्कि पश्चिमी संगीत में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था। उन्होंने पंडित रवि शंकर, उस्ताद अली अकबर खान, पंडित शिवकुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया जैसे दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया। उनकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान तब बनी जब उन्होंने यो-यो मा, जॉन मैकलॉफलिन और मिकी हार्ट जैसे प्रसिद्ध पश्चिमी कलाकारों के साथ शो किए।

पिता के साथ-साथ उन्होंने उस्ताद विलायत हुसैन खान और उस्ताद लतीफ अहमद से भी तबले की तालीम ली। उन्होंने बतौर अभिनेता 12 फिल्मों में भी काम किया लेकिन उनको संतुष्टि और शोहरत तबला वादन से ही मिली। उनका ताल्लुक तबला वादन के लिए मशहूर पंजाब घराने से रहा। 4 फरवरी 2023 को उन्होंने एक ही रात में दुनियाभर में प्रतिष्ठित तीन ग्रैमी अवार्ड जीत लिए उन्होंने दो अन्य ग्रैमी अवार्ड भी जीते। वह ऐसा कमाल करने वाले पहले भारतीय रहे। जाकिर हुसैन को सबसे कम उम्र में देश के नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बाद में उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। उनको कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा जाता रहा। वह पहले भारतीय संगीतकार थे जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की उपस्थिति में व्हाइट हाउस में अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिला। भले ही उन्हें दुनियाभर में शोहरत मिली लेकिन एक अमर गीत 'मिले सुर मेरा तुम्हारा' ने उन्हें हर भारतीय के घर-घर तक पहुंचा दिया। तबले को उसके पारंपरिक शास्त्र से निकाल कर उसे ग्लोबली मशहूर करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। भारतीय तबला और अमेरिकी जैज को लेकर उन्होंने जो प्रयोग किया, संगीत और ताल शास्त्र की दुनिया में इसे न केवल बेहद सम्मानित नजर से देखा जाता है बल्कि अद्वितीय भी माना जाता है। यह प्रयोग उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि साबित हुआ।

> **जाकिर हुसैन को सबसे कम उम्र में देश के नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बाद में उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। उनको कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा जाता रहा। वह पहले भारतीय संगीतकार थे जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की उपस्थिति में व्हाइट हाउस में अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिला। भले ही उन्हें दुनियाभर में शोहरत मिली लेकिन एक अमर गीत 'मिले सुर मेरा तुम्हारा' ने उन्हें हर भारतीय के घर-घर तक पहुंचा दिया। तबले को उसके पारंपरिक शास्त्र से निकाल कर उसे ग्लोबली मशहूर करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। भारतीय तबला और अमेरिकी जैज को लेकर उन्होंने जो प्रयोग किया, संगीत और ताल शास्त्र की दुनिया में इसे न केवल बेहद सम्मानित नजर से देखा जाता है बल्कि अद्वितीय भी माना जाता है।**

जाकिर हुसैन हर साज को एक प्रेरणा मानते थे। वे मानते थे कि साज की भी अपनी जुबान और आत्मा होती है। वे अक्सर कहते थे कि संगीत सरस्वती का वरदान है। शिवजी का डमरू या गणेश जी का पखावज या फिर कृष्ण की बांसुरी हिन्दोस्तान पर इन सबका आशीर्वाद है तो स्वाभाविक है इसमें आत्मा तो होगी ही। संगीत की भाषा धर्मनिरपेक्ष है क्योंकि संगीत सबसे पवित्र है। नाद ब्रह्म यानि ध्वनि ईश्वर है। आजादी से पहले तो संगीत राजमहलों तक सीमित था। मंच पर इसे कैसे पेश किया जाना है यह जाकिर हुसैन बखूबी जानते थे। उन्हें तबले से इतनी मोहब्बत थी कि वह तबले को गोद में लेकर सो जाया करते थे। हवाई यात्रा में भी वह तबले को गोद में लेकर यात्रा करते थे। तबला उनके लिए सरस्वती समान रहा। वे इस बात का ध्यान रखते थे कि किसी का पांव तबले को न छू जाए। उनके हेयर स्टाइल को भी लोगों ने बहुत अपनाया।

उन्होंने कुछ फिल्मों के अलावा अमेरिकी धारावाहिकों में भी काम किया। उन्होंने खुद को कई मौके भी दिए। 40 फिल्मों में संगीत भी दिया। इतना काम करने के बावजूद उन्होंने खुद को अभिनेता की बजाय बेहतरीन तबला वादक ही पाया। शक्ति नामक विश्व प्रसिद्ध बैंड के जरिए उन्होंने भारतीय और पश्चिमी संगीत के बेजोड़ संगम को पेश किया जिसकी दुनिया दीवानी हो उठी। इतनी शोहरत प्राप्त करने के बावजूद जाकिर हुसैन ने कभी खुद को उस्ताद नहीं माना और एक शागिर्द की तरह हर रोज नया सीखा और उसे पेश किया। रागों की ताल और लय के साथ तबले पर कभी थिरकती, कभी तैरती और कभी उड़ती हुई जाकिर हुसैन की उंगलियां संगीत का एक जादू पैदा करती रही। वह एक किंवदंती थे जो भारत के तो अपने थे लेकिन पूरी दुनिया के थे। भारत को भविष्य में ऐसा कोई उस्ताद मिलेगा यह कहना मुश्किल है। उस्ताद जाकिर हुसैन हमेशा हमारे दिलों में याद रहेंगे।

और टीबी जैसी बीमारी को जड़ से...

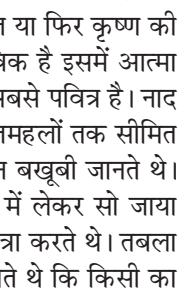

चलो अच्छे स्वास्थ्य की ओर एक कदम बढ़ाएं,
और टीबी जैसी बीमारी को जड़ से मिटाएं,
नुक्कड़, गली, मोहल्ला, गांव और संपूर्ण देश में जागरूकता फैलाएं,
बुखार और लंबी खांसी होने पर समय से जांच और ईलाज करवाएं,
नि:क्षय मित्र पर गौर फरमाएं,
माननीय प्रधानमंत्री के टीबी मुक्त भारत अभियान को सफल बनाएं...!!

गीता पाढा

यादों के आंगन में राज साहब का राज

डा. विजय दर्डा
संपादक : लोकमत समूह
पूर्व राज्यसभा सांसद

स्कूल में मेरा एक दोस्त था भाऊ देशमुख कलेक्टर का बेटा था। अब वो डॉक्टर है, बचपन में बड़े लोगों को पत्र लिखना उसका शगल था। उस जमाने में बड़े लोग पत्रों की प्राप्ति का संदेश भेजते थे। भाऊ ने एक पत्र राज कपूर को लिखा था और प्राप्ति का संदेश उसने मुझे भी दिखाया, तो मन में एक चाह उठी कि काश कभी राज कपूर साहब से मिलने या कम से कम देखने का मौका तो मिल जाए। उस वक्त क्या पता था कि वक्त के सुनहरे पन्नों पर नई कहानी लिखी जाएगी।

उनकी जन्मशताब्दी के मौके पर उन सुनहरे पन्नों पर दर्ज यादें एक-एक कर जीवंत होने लगीं...जैसे कल की ही बात हो। यूं तो उस दौर में चार अभिनेताओं-राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार और सुनील दत्त के प्रति मैं ज्यादा आकर्षित था लेकिन राज साहब और देवानंद के प्रति खास तरह की दीवानगी थी। राज कपूर को सामने से देखने का मौका मुझे अपने कॉलेज के जमाने में मिला। 'मेरा नाम जोकर' फिल्म के गाने 'जीना यहां, मरना यहां...' की शूटिंग के लिए मेरे कॉलेज से विद्यार्थियों को बुलाया गया था। उनमें मैं भी शामिल था, अपने चहेते अभिनेता को पास से देखना दिल को खुशियों से भर देने वाला था। मगर मुलाकात नहीं हुई।

हालांकि कुछ ही वर्षों के भीतर मुलाकात का वक्त भी आ पहुंचा, मैं उस वक्त की श्रेष्ठ फिल्म पत्रिका 'माधुरी' में प्रशिक्षु पत्रकार था। मैंने राज साहब से मिलने का वक्त मांगा और कमाल देखिए कि बुलावा भी आ गया। बड़े प्यार से उन्होंने स्वागत किया, केन की चटाई पर लुंगी और सफेद कुर्ते में कलम और दवात के साथ लिखा-पढ़ी वाली तखत लेकर बैठे थे। उनके पीछे नरगिस के साथ उनकी सदाबहार तस्वीर लगी हुई थी। मैं उस तस्वीर में खो गया, मेरी तंद्रा तब टूटी, जब उन्होंने कहा-'तस्वीरों में क्या रखा है...मुझे देखिए न! आपने कभी तस्वीरों को बोलते हुए देखा है।' मेरे मुंह से निकला...जी हां, तस्वीरें यदि बोलती नहीं तो हम रखते ही क्यों? फिर हमारी चर्चा शुरू हो गई। मैंने उनसे पूछा कि इतनी अच्छी फिल्में आप कैसे बनाते हैं? उन्होंने तपाक से कहा कि जैसे आप खबरें लिखते हैं, वैसे ही हम फिल्में बनाते हैं। मैंने कहा कि खबरें तो घटनाओं पर आधारित होती हैं। वे कहने लगे कि जो समाज में हम देखते हैं, वही तो फिल्मों में परोसते हैं, फिल्म 'आवारा' में एक तरह की पीड़ा की अभिव्यक्ति थी। 'जिस देश में गंगा बहती है' में वक्त के हालात को प्रदर्शित किया। फिल्में लोगों को अपनी जिंदगी के करीब लगनी चाहिए, मेरे साथी शैलेंद्र से क्या आप मिले हैं? शैलेंद्र जानते हैं कि फिल्म हिट कैसे होगी। आपकी सोच को समझने वाले ही आपके साथी बन सकते हैं, मेरी टीम भी मेरे विचारों में मेरे जितना ही सहभागी होती है।

बातचीत के बीच उन्होंने पूछा कि आप कहां रहते हैं? मैंने कहा-चर्च गेट तो कहने लगे कि चलिए, मैं भी उधर ही जा रहा हूं, बातचीत करते चलेंगे। निकलते वक्त उन्होंने कहा कि आपके पिताजी, दर्डा जी को मैं जानता हूं, मेरे पिताजी पृथ्वीराज कपूर और आपके परिवार के संबंध रहे हैं। मैंने कहा कि मुझे पता है कि पृथ्वीराज कपूर जी को यवतमाल में झंडावंदन के लिए बाबूजी ने बुलाया था। वे एक ड्रामा लेकर भी आए थे, दोनों अवसर की तस्वीरें मेरे पास हैं। वे प्रसन्न हो गए कि मुझे ये

बातें पता हैं। मेरे जेहन में तत्काल यह बात कौंधी कि शायद इन संबंधों के कारण ही मुझ जैसे प्रशिक्षु को इन्होंने मुलाकात का मौका दिया।

कार में एक पैड उनके हाथ में था, वे कभी मौन होते, तो कभी कुछ लिखने लगते। बीच-बीच में सवालों के जवाब भी देते, मैंने पूछा कि आप गाते-बजाते भी हैं, जिंदगी में इतनी विविधता कैसे ला पाते हैं? बड़े दार्शनिक अंदाज में बोले कि खुशियों के साथ जीना या जीवन में गम भर लेना अपने हाथ में है, महत्वपूर्ण बात है कि दो रोटी आप गुनगुनाते हुए खाते हैं या रोते हुए खाते हैं। मैंने बहुत पैसे वालों को भी रोते हुए रोटी खाते देखा है और ऐसे गरीब भी देखे हैं जो मस्ती में खाना खाते हैं। लगे हाथ मैंने पूछा कि आपके परिवार की लड़कियां फिल्मों में काम क्यों नहीं करती हैं? वे कहने लगे कि लड़कों का भी मूवी में जाना अच्छा नहीं माना जाता था। हमारे दादाजी इच्छुक नहीं थे कि हम फिल्मों में काम करें। बातों ही बातों में लोकमत नागपुर संस्करण की चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि मेरी बहन उर्मिला का रिश्ता सिआल परिवार में है, एक शादी में बच्चों के साथ नागपुर आए थे। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी कृष्णा जबलपुर की हैं लेकिन काफी समय वह नागपुर में भी रही हैं तो मैंने उन्हें बताया कि मेरे बाबूजी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जबलपुर की जेल में थे। उन्होंने जबलपुर के न्यू एम्पायर सिनेमा हॉल के बारे में भी चर्चा की जो उनके ससुराल वालों का था। संदर्भ के लिए बता दें कि मशहूर एक्टर प्रेमनाथ, राजेंद्रनाथ तथा नरेंद्रनाथ उनके साले थे।

बातचीत के इसी दौर में कार चौपाटी में भारतीय विद्या भवन के पास एक पान दुकान पर रुकी। पान वाले ने तत्काल पान बनाए। उन्होंने पान खाया, कुछ पान बंधवा लिये और वहां से कार सीधे चर्च गेट में गेलार्ड होटल में आकर रुकी, मैं कुछ ही दूर रहता था लेकिन घर जाने के बजाय मैं भी उनके पीछे-पीछे हो लिया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि गेलार्ड होटल अंदर से कैसा है? एक किनारे की टेबल पर जयकिशन बैठे थे। पता चला कि राज साहब प्राय: वहां चाय पीने आते थे, राज साहब ने कहा कि आर.के. स्टूडियो की होली में कभी आओ लेकिन कभी मैं जा नहीं पाया।

राज साहब से जुड़ा एक प्रसंग याद आ रहा है। बाबूजी उद्योग मंत्री थे तो राज साहब मिलने आए और कहा कि घर बनाने के लिए सीमेंट नहीं मिल रहा है। तब सीमेंट की बड़ी किल्लत थी। सीमेंट देने के लिए ए.आर. अंतुले की अपनी शर्तें थीं लेकिन बाबूजी ने लीक से हटकर सीमेंट दिलवाया क्योंकि राज कपूर को बाबूजी भारत का सांस्कृतिक दूत मानते थे। वास्तव में रूस, जापान और इजराइल में उन्हें लोग आज भी याद करते हैं। अलमाटी में एक होटल का पूरा फ्लोर उनके नाम पर है।

राज साहब यवतमाल आने वाले थे लेकिन नहीं आ पाए। यह बात ऋषि कपूर को पता थी इसलिए वे कबड्डी के कार्यक्रम में यवतमाल आए, उम्मीद है कि रिश्तों का यह धागा जोड़ते हुए रणबीर कपूर कभी यवतमाल जरूर आएंगे। रणबीर में तो मुझे राज साहब का अक्स दिखाई देता है। विनम्र आदरांजलि राज साहब, हम आपको कभी भुला न पाएंगे।

गुकेश : शह और मात का नया शहंशाह

डा. आर. के. सिन्हा
पूर्व राज्यसभा सांसद

सारा भारत आज के दिन डी. गुकेश के विश्व शतरंज चैंपियन बनने से गौरवान्वित महसूस कर रहा है। गुकेश ने एक नया इतिहास रच दिया है। वे सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं। उन्होंने अपने अद्भुत प्रदर्शन से पूरे भारत का मान बढ़ाया है। उनकी इतनी शानदार सफलता में उनकी असाधारण प्रतिभा, समर्पण और रणनीतिक दृष्टिकोण अहम रहे। गुकेश ने बहुत कम उम्र में शतरंज खेलना शुरू कर दिया था जिससे उन्हें खेल की बारीकियों को समझने और अपनी प्रतिभा को विकसित करने का पर्याप्त समय मिला। उनमें जन्मजात प्रतिभा है और उनकी ग्रहण करने की क्षमता बहुत तेज है जिससे वे जटिल शतरंज रणनीतियों को आसानी से समझ पाते हैं। उन्होंने शतरंज के प्रति पूर्ण समर्पण दिखाया है और लगातार अभ्यास करके अपनी क्षमताओं को निखारा है।

गुकेश को अनुभवी और कुशल प्रशिक्षकों का मार्गदर्शन मिला, जिन्होंने उनकी खेल तकनीकों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण और संसाधनों तक पहुंच मिली जिससे उन्हें विश्व स्तर के खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिली। गुकेश के प्रशिक्षण में आधुनिक तकनीकी उपकरणों का उपयोग शामिल था जिससे उनकी खेल रणनीति का विश्लेषण करना और सुधार करना आसान हो गया।

गुकेश के पास शतरंज में गहरी रणनीतिक सोच है जो उन्हें खेल के दौरान तत्काल सही निर्णय लेने में मदद करती है। वे दबाव की स्थितियों में भी शांत और संयमित रहते हैं जिससे वे महत्वपूर्ण मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। उनमें मानसिक रूप से मजबूत होने की क्षमता है जिससे वे हार से निराश नहीं होते और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहते हैं।

गुकेश नियमित रूप से शतरंज का अभ्यास करते हैं और अपनी कमजोरियों को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे अपने पिछले मैचों का विश्लेषण करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं जिससे उनकी खेल रणनीति में लगातार सुधार होता रहता है। वे शतरंज के महान खिलाड़ियों के खेलों का लगातार गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करते रहते हैं और उनसे नई तकनीकों को सीखते हैं। गुकेश ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया है जिससे उन्हें उच्च स्तर के खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का अनुभव मिला है।

उन्होंने अलग-अलग शैली के खिलाड़ियों का सामना किया है जिससे उनकी खेल में विविधता आई है और उन्हें विभिन्न स्थितियों के लिए तैयार किया गया है। गुकेश को अपने परिवार से भरपूर समर्थन और प्रेरणा मिली है जो उनकी सफलता में एक महत्वपूर्ण कारक है। परिवार ने उनके संघर्षों के दौरान उनका भावनात्मक रूप से समर्थन किया और उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इन सभी कारणों के संयोजन ने गुकेश को विश्व शतरंज चैंपियन बनने में मदद की है। उनकी सफलता न केवल उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा और मेहनत का परिणाम है, बल्कि यह भारत में शतरंज के विकास और प्रोत्साहन का भी प्रतीक है।

इस बीच, कुछ जानकार गुकेश और पूर्व विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद की तुलना भी रहे कर रहे हैं। गुकेश और विश्वनाथन आनंद, दोनों ही भारतीय शतरंज के महान खिलाड़ी हैं लेकिन उनकी शैलियों, दृष्टिकोण और खेल में कुछ समानताएं और कुछ मौलिक अंतर भी

हैं। दोनों ही खिलाड़ियों में शतरंज की असाधारण प्रतिभा है। वे जटिल स्थितियों को समझने और सटीक चाल चलने में माहिर हैं।

दोनों ही खिलाड़ी अपनी रणनीतिक गहराई के लिए जाने जाते हैं। वे न केवल तात्कालिक लाभ पर ध्यान देते हैं, बल्कि लंबी अवधि की योजनाओं को भी ध्यान में रखते हैं। दोनों ही खिलाड़ियों में दृढ़ संकल्प है और वे कभी भी हार नहीं मानते हैं। उन्होंने कई बार मुश्किल परिस्थितियों से वापसी की है और जीत हासिल की है। दोनों ही खिलाड़ी अपनी शालीनता और खेल भावना के लिए जाने जाते हैं। वे हारने पर भी सम्मान बनाए रखते हैं। विश्वनाथन आनंद एक अनुभवी खिलाड़ी हैं जो 90 के दशक से खेल रहे हैं, जबकि गुकेश एक युवा और उभरते हुए खिलाड़ी हैं। आनंद ने कंप्यूटर युग से पहले शतरंज खेला, जबकि गुकेश का विकास कंप्यूटर के युग में हुआ है। आनंद अपनी तेज और आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं, जबकि गुकेश एक अधिक रणनीतिक और रक्षात्मक खिलाड़ी हैं। आनंद त्वरित चालों और जटिलताओं में माहिर हैं जबकि गुकेश स्थिति को नियंत्रित करने और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

जाहिर है, आनंद के पास खेल का अधिक अनुभव है और उन्होंने कई विश्व चैंपियनशिप जीती हैं, जबकि गुकेश अभी भी अपने करियर के शुरुआती चरण में हैं। आनंद ने दशकों तक शीर्ष स्तर पर खेला है जबकि गुकेश अभी भी वैश्विक शतरंज समुदाय में अपनी जगह बना रहे हैं। आनंद एक अधिक सहज और रचनात्मक खिलाड़ी हैं, जबकि गुकेश अधिक व्यवस्थित और वैज्ञानिक खिलाड़ी हैं। आनंद स्वाभाविक रूप से प्रेरित होकर खेलते हैं, जबकि गुकेश अपनी तैयारी पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। भारत में शतरंज पहले से ही काफी लोकप्रिय है लेकिन गुकेश जैसे युवा खिलाड़ियों के उदय से यह और भी लोकप्रिय हो सकता है। गुकेश जैसे युवा खिलाड़ियों की सफलता से युवा पीढ़ी को शतरंज में रुचि लेने की प्रेरणा मिलेगी। युवाओं के लिए एक आदर्श मॉडल होने से अधिक युवा शतरंज खेलने के लिए आकर्षित होंगे।

ऑनलाइन शतरंज प्लेटफॉर्म और कंप्यूटर विश्लेषण उपकरणों की उपलब्धता से खेल अधिक सुलभ हो गया है। इंटरनेट के माध्यम से सीखने और खेलने के विकल्पों ने शतरंज को अधिक सुविधाजनक बना दिया है। शतरंज को अब पहले से अधिक मीडिया कवरेज मिल रहा है जिससे खेल के बारे में जागरूकता बढ़ रही है। प्रमुख समाचार चैनलों और खेल वेबसाइटों पर शतरंज की घटनाओं को कवर किया जा रहा है। शतरंज को अब स्कूलों में एक शैक्षणिक उपकरण के रूप में मान्यता दी जा रही है जिससे बच्चों को खेल के लाभों का अनुभव करने का अवसर मिल रहा है। स्कूलों में शतरंज को बढ़ावा देने से आने वाली पीढ़ी के लिए इसे और लोकप्रिय बनाया जा सकता है।

शतरंज में प्रायोजन में वृद्धि से खेल को और अधिक लोकप्रिय बनाने में मदद मिलेगी। प्रायोजकों द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने से खिलाड़ियों को अपनी क्षमताओं को विकसित करने और प्रदर्शन में सुधार करने में मदद मिलेगी। गुकेश का विश्व चैंपियन बनना भारत में शतरंज को और लोकप्रिय बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे युवा खिलाड़ियों को प्रेरित किया जाएगा और शतरंज में करियर बनाने के लिए एक नया रास्ता खुलेगा।

भारत, बंगलादेश के युद्ध नायक एक-दूसरे के यहां गए

ढाका, (एजेंसी): भारत और बंगलादेश में विजय दिवस समारोहों में भाग लेने के लिए 1971 के 'मुक्ति संग्राम' का हिस्सा रह चुके आठ भारतीय सैनिक ढाका पहुंचे हैं, जबकि वहां की सेना के आठ अधिकारी कोलकाता पहुंचे हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

विजय दिवस पाकिस्तानी सेना द्वारा भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किए जाने की याद में मनाया जाता है। भारत की ऐतिहासिक जीत के कारण बंगलादेश को आजादी मिली। बंगलादेश के प्रतिनिधिमंडल में 'मुक्ति योद्धा' शामिल थे, जो पूर्वी पाकिस्तान में उस गुरिल्ला समूह का हिस्सा थे जिन्होंने वहां पाकिस्तानी शासन का विरोध किया था।विजय दिवस समारोह और दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों की ये यात्राएं भारत-बंगलादेश के बीच जारी तनाव के बीच हो रही हैं। बंगलादेश में पांच अगस्त को छात्र-नेतृत्व वाले विद्रोह में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के सत्ता से हटने के बाद से अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ कथित हिंसा को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति है। हसीना देश से पलायन कर चुकी हैं और उन्होंने भारत में शरण ली है। कोलकाता में सोमवार को आयोजित विजय दिवस समारोह में भाग ले रहे एक मुक्ति योद्धा ने कहा कि पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष भी बांग्लादेश के निर्माण के उत्सव में कोई अंतर नहीं है।मुक्ति योद्धा लेफ्टिनेंट कर्नल (सेवानिवृत्त) काजी सज्जाद अली जहीर ने बांग्लादेश के लोगों के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा

दिए गए बलिदान को याद करते हुए कहा, ''हम जो यहां आए हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं; हमने भारतीय सेनाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी।'' फोर्ट विलियम स्थित सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय में पुष्पांजलि समारोह के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में लेफ्टिनेंट कर्नल (सेवानिवृत्त) जहीर ने 1971 में पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में बंगाली आबादी को भारतीय लोगों द्वारा दी गई सहायता का भी उल्लेख किया।जहीर से जब बांग्लादेश में कुछ लोगों द्वारा दिए गए भारत विरोधी बयानों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ''बांग्लादेश एक शांतिपूर्ण राष्ट्र है। आप इधर-उधर से बयान सुन सकते हैं, लेकिन इतिहास बहुत उत्साहित करने वाला है।'' उन्होंने परस्पर विकास के लिए दोनों पड़ोसियों के बीच अच्छे संबंधों के महत्व पर भी जोर दिया।बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को लेकर जहीर ने कहा, ''हम पड़ोसी हैं और एक-दूसरे के विकास के लिए हमें अच्छा पड़ोसी बनना होगा। दोस्ती टिकाऊ होनी चाहिए।'' बांग्लादेश में पांच अगस्त को शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के पतन के बाद से अल्पसंख्यक हिंदुओं को 200 से अधिक हमलों का सामना करना पड़ा है। बांग्लादेशी नागरिक होने के बावजूद भारत द्वारा 'पद्मश्री' से सम्मानित जहीर ने पाकिस्तान की विशिष्ट 14वीं पैरा ब्रिगेड के सदस्य के रूप में अपनी पृष्ठभूमि साझा की। तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे अत्याचारों के बारे में जानने के बाद वह पाकिस्तानी सेना छोड़कर भारत आ गए थे।

जहीर ने 1971 के युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत को विश्व इतिहास की सबसे बेहतरीन जीत में से एक बताते हुए कहा कि संघर्ष के दौरान भारतीय सेना द्वारा अत्याचार का एक भी मामला सामने नहीं आया था।

मशीन चोरी मामले में आजम खान की अदालत से गुहार

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान द्वारा दायर याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा। याचिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें मशीन चोरी के एक मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आजम खान और उनके बेटे ने उच्च न्यायालय के 21 सितंबर के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया है। खान, उनके बेटे और पांच अन्य के खिलाफ 2022 में आपराधिक मामला दर्ज किया गया था।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

नशे के खिलाफ

सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय युवाओं के बीच नशीले पदार्थों के सेवन को लेकर न केवल चिंता जाहिर की है, बल्कि मादक द्रव्यों के सेवन को सामान्य मानने-बताने की बढ़ती प्रवृत्ति पर भी अफसोस जताया है। नशा करना कहीं से भी सामान्य या सरल बात नहीं है, पर आज दुनिया में नशा करना धीरे-धीरे न्यू नॉर्मल होता जा रहा है। न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क में शामिल होने के एक आरोपी के खिलाफ एनआईए की जांच की पुष्टि करते हुए यह कहा है। यह आरोपी पाकिस्तान से भारत नशीले पदार्थों की समुद्री मार्ग से तस्करी करता था। दरअसल, देश में एक वर्ग ऐसा है, जो मादक द्रव्यों को सामान्य रूप से स्वीकार करता है। ऐसा व्यवसायी वर्ग भी है, जो मादक द्रव्यों की तस्करी में जुटा हुआ है और यह वर्ग सही-गलत के विचार से खुद को ऊपर मानता है। ऐसे में, यह बहुत जरूरी है कि नशे के कारोबार और नशा करने वाले तमाम लोगों को सही आईना दिखाया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने यही जरूरी काम किया है।

हम सामाजिक विकास के मोर्चे पर ऐसे संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, जब नशाखोरी के खिलाफ किसी भी सलाह को घिसी-पिटी मानने वाले बहुत हो गए हैं। मादक पदार्थों के सेवन पर तो वैसे भी प्रतिबंध है, लेकिन जिन राज्यों में शराबबंदी भी है, वहां भी नशे के खिलाफ किसी सलाह को बीती बात मानने वाले बहुत हैं। ऐसे में, न्यायमूर्ति नागरत्ना का यह कहना बहुत महत्वपूर्ण है कि इससे देश के युवाओं की चमक खत्म होने का खतरा है। नशा न केवल सामाजिक, आर्थिक, बल्कि मानसिक रूप से भी कमजोर करता है। सबसे अच्छी बात है कि अदालत ने माता-पिता, समाज और सरकारी संगठनों से तत्काल व सामूहिक कार्रवाई का आह्वान किया है। मादक पदार्थों के खिलाफ हमारी लड़ाई तब तक सफल नहीं हो सकती, जब तक कि तमाम जिम्मेदार लोग सजग न हो जाएं। हर धर्म, हर जाति, हर उम्र के लोग नशा करने लगे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि नशे को सही मान लिया जाए। नशीली चीजों का व्यापार समाज को अस्थिर करते हुए हिंसा व आतंक को भी वित्त पोषित करता है। अपराधियों के लिए धन कमाने का आसान मार्ग बन जाता है। मादक पदार्थों की तस्करी-बिक्री से भारी धन कमाने वाले अपराधी अपने बचाव के लिए भी इसी धन का इस्तेमाल करते हैं।

हम नशे के खिलाफ आंदोलन चलाना चाहते हैं, तो सभी को योगदान देना होगा। सबसे पहले नशे को 'कूल' या 'न्यू नॉर्मल' मानने की प्रवृत्ति से बाज आना होगा।

यह तो कहना ही चाहिए कि मादक पदार्थों के क्रय-विक्रय के लिए बहुत हद तक भ्रष्टाचार ही जिम्मेदार है। अगर भ्रष्टाचार न हो, तो अपराधियों को पकड़ने और दंडित करने में आसानी हो सकती है। अतः सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि अदालतें भी मादक पदार्थों के दुष्ट व समाजद्रोही कारोबारियों पर कड़ाई से अंकुश लगाएं। क्या यह सच नहीं है कि मादक पदार्थों की तस्करी और कारोबार में लगे लोगों को भी कई बार जमानत मिल जाती है? वह अपराधी जेल से बाहर आकर फिर उसी काले धंधे में जुट जाता है। अगर वाकई हम नशे के खिलाफ आंदोलन चलाना चाहते हैं, तो सभी को इसमें योगदान देना होगा और सबसे पहले नशे को 'कूल' या 'न्यू नॉर्मल' मानने की प्रवृत्ति से बाज आना होगा। बहरहाल, न्यायमूर्ति नागरत्ना की विशेष रूप से प्रशंसा करनी चाहिए। उन्होंने समझाया है कि किशोरों की सबसे महत्वपूर्ण चाह माता-पिता का स्नेह है। यथोचित स्नेह से ही मादक द्रव्यों के गलत सेवन की चाह का सही इलाज संभव है।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले
17 दिसंबर, 1949

नौसेना दिवस

देश में आज नौसेना दिवस मनाया जा रहा है। बंबई, कोचीन, मद्रास, और विशाखापट्टनम भारतीय नौसेना के मुख्य केन्द्र हैं और इन स्थानों में यह दिवस विशेष उत्साह और समारोह के साथ मनाया जायेगा। जनता भारतीय नौसेना के जंगी जहाजों और कर्मचारियों को अपने केन्द्रों में देख सकेगी। जनता के मनोरंजन और नौसेना संबंधी ज्ञानवर्द्धन के भी आयोजन संगठित किये जायेंगे। नौसेना भारतीय सेना की एक शाखा है और भारत के प्रधानमंत्री ने ठीक ही कहा है कि भारतीय सेना वस्तुतः लोक सेना है। इसलिए यह उचित ही है कि जनता और सेना के बीच घनिष्ठ संपर्क स्थापित किया जाये। यदि जनता को सेना की विभिन्न शाखाओं के बारे में जानकारी दी जायेगी तो उसकी दिलचस्पी बढ़ेगी और उसके सहयोग का दरवाजा खुल जायेगा। जनता का सहयोग हमारी सेना को सुदृढ़ बना सकेगा। इस दृष्टि से भारतीय नौसेना दिवस के आयोजन का हम स्वागत करते हैं।

भारत तीन ओर से समुद्र द्वारा घिरा है। उसकी समुद्रवर्ती सीमायें हजारों मील की दूरी में फैली हुई है। देश के स्वतंत्र होने के साथ ही अपनी सीमाओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हमारे अपने कंधों पर आ गई है। भारत अपनी तटवर्ती सीमा की रक्षा उस समय तक नहीं कर सकता, जब तक कि उसकी अपनी नौसेना काफी सशक्त और बलवान न हो। पराधीनता के युग में भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा करने का भार ब्रिटिश नौसेना पर था। इस कारण भारत की अपनी नौसेना के संगठन और विस्तार की कोई विशेष आवश्यकता नहीं समझी गई। युद्धकालीन परिस्थितियों के दबाव ने भारतीय नौसेना को थोड़ा विकास का अवसर दिया। किन्तु देश के विभाजन के कारण उसे कम धक्का नहीं लगा। कराची भारतीय नौसेना का सर्वोच्च अड्डा था और यह पाकिस्तान में चला गया। देश के स्वतंत्र होने के बाद भारत सरकार ने एक बड़ा युद्धपोत, जिसका नाम 'दिल्ली' रखा गया है और तीन विध्वंसक हस्तगत किये हैं। किन्तु आर्थिक तंगी उसे अपनी इस इच्छा को पर्याप्त मात्रा में पूरा नहीं करने दे रही है। सरकार नौसेना का विस्तार करना चाहती है। भारतीय नौसेना के मार्ग में सबसे मुख्य कठिनाई इस कला में प्रवीण कर्मचारियों की है। भारत के पास जितने कर्मचारी थे, उन्हें करीब-करीब उन जहाजों में नियोजित किया जा चुका है, जो हाल ही में हस्तगत किये गये हैं।

विरोधी विचारों ने भी माना विधान

राय की राय
यहां स्कैन करें

विभूति नारायण राय | पूर्व आईपीएस अधिकारी

75 वर्षों के प्रयोग के बाद भिन्न विचारधाराओं द्वारा स्वीकृति ही संविधान की सबसे बड़ी सफलता है। यह इस बात की पुष्टि है कि भारतीय मेधा मध्यमार्ग की तरफ ही आकर्षित होती है।

भारतीय वैचारिकी के तमाम रहस्यवादी भाष्यों की तरह भारतीय संविधान के साथ भी कई ऐसे आख्यान जुड़े हुए हैं, जिनका पुनर्पाठ बहुत ही दिलचस्प होगा, खास तौर से इसकी निर्मिति के 75 वर्ष पूरे हो जाने के बाद इन्हें याद करना बड़ा रोचक लगता है। आज वे तमाम लोग इसकी कसमें खा रहे हैं; इसकी रक्षा में कोई भी कुर्बानी देने को तत्पर हैं, जो 1949 में न सिर्फ इसके उद्देश्यों और कामयाबी को लेकर सशंकित थे, वरन उन्होंने इसे लागू करने का प्राण-पण से विरोध किया था। मैं यहां इससे जुड़े एक बड़े मिथक का जिक्र करूंगा, जिसके चलते जब कभी ऐसा लगता है कि इसकी मूल भावना पर कोई संकट है, तो बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के देश की पीड़ित-प्रताड़ित जनता की बड़ी संख्या इसकी हिमायत में खड़ी हो जाती है।

यह मिथक बाबा साहेब आंबेडकर को लेकर है। उनके अनुयायियों, खास तौर से अनुसूचित जातियों से जुड़ा विशाल समुदाय यह मानता है कि संविधान सभा द्वारा पारित विधान के मुख्य निर्माता डॉक्टर आंबेडकर थे। यह एक सामान्य जानकारी है कि वह संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और उस कमेटी में उनके अतिरिक्त आधे दर्जन से अधिक अन्य सदस्य भी थे। इस कमेटी से उनके जुड़ने की कथा भी कम दिलचस्प नहीं। दरअसल, जब संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल इस पद के लिए एक जर्मन संविधान विशेषज्ञ का नाम लेकर महात्मा गांधी के पास गए थे। आपसी बातचीत के दौरान गांधीजी ने उन्हें इस जिम्मेदारी के लिए डॉ आंबेडकर का नाम सुझाया और लंबे विमर्श के बाद यह नाम अंतिम रूप से तय हुआ। बाद में एक भाषण में डॉ आंबेडकर ने स्वयं स्वीकार किया कि जब ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता का प्रस्ताव उनके सामने आया, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उस समय वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, बल्कि महात्मा गांधी व पंडित नेहरू से उनके गंभीर मतभेद किसी से छिपे नहीं थे।

यह अलग बात है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के कई सदस्य अपने स्वास्थ्य कारणों या दिल्ली में अपनी अनुपस्थिति के चलते संविधान सभा की कार्यवाहियों में कोई खास भूमिका नहीं निभा पाए। अपनी मेधा और अंग्रेजी भाषा पर असाधारण अधिकार के चलते डॉ आंबेडकर ही सभा की सारी कार्यवाहियों में छाए रहे और शायद इसी के चलते यह धारणा बनी कि संविधान उन्होंने बनाया है। किसी दूसरे संविधान की तरह इसे बनाने वाली संविधान सभा, जिसमें कांग्रेस का प्रचंड बहुमत था, पूरी तरह से निर्णायक भूमिका में थी और हर प्रावधान पर लंबी बहसों के बाद अंतिम निर्णय वही लेती थी।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत एवं 26 जनवरी, 1950 को देश में लागू यह संविधान खुद डॉ आंबेडकर की पहली पसंद नहीं था। उन्होंने 'यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया' के संविधान के नाम से एक ड्राफ्ट तैयार किया था और उसे अपने कुछ मित्रों के मध्य वितरित भी किया था। कई मामलों में यह उस मसौदे से काफी भिन्न है, जिसे हमारी संविधान सभा ने अंतिम रूप से अंगीकृत किया। इसमें बीमा व बड़े उद्योगों का नियंत्रण राज्य के अंतर्गत रखने की बात की गई थी और हिंदू स्त्रियों के उन अधिकारों का जिक्र था, जिसे वह चाहते हुए भी हिंदू कोड बिल में शामिल नहीं करा सके थे। कांग्रेस व नेहरू से उनकी दूरी के पीछे यह भी एक बड़ा कारण था।

नया संविधान भारतीय समाज के लिए एक अनूठे अनुभव की तरह था। इसका आना उसके सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक संसार में किसी झंझावात की तरह सिद्ध हुआ। लिहाजा स्वाभाविक था कि हर तरह के अतिवादियों के लिए इसे पचा पाना मुश्किल साबित हुआ। मैं यहां दो विपरीत बिंदुओं पर खड़ी दो विचारधाराओं का जिक्र करूंगा, जिन्होंने शुरुआती वर्षों में इस संविधान का जमकर विरोध किया और आज दोनों इसकी रक्षा की बात करते हैं। पहले वामपंथी थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के झंडे तले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद देश में दूसरी बड़ी राजनीतिक उपस्थिति थे। अपने महासचिव बीटी रणदिवे के नेतृत्व में उन्होंने *देश की जनता भूखी है... यह आजादी झूठी है* का नारा लगाते हुए संविधान को नकार दिया और तेलंगाना मे सशस्त्र संघर्ष की शुरुआत कर दी। बहुत समय नहीं लगा, जब उनकी समझ में आ गया कि हथियारों के बल पर भारतीय राज्य को झुकाना असंभव है, तब उन्होंने अपना नेतृत्व व राजनीति परिवर्तित कर नए संविधान के अंतर्गत 1952 के आम चुनावों में भाग लिया और पहली लोकसभा में कांग्रेस के बाद दूसरे स्थान पर रहे। आज चुनावों में भाग लेने वाली मुख्यधारा की कम्युनिस्ट पार्टियों के अलावा अभी भी सशस्त्र संघर्षों में विश्वास करने वाले उनसे छिटके हुए संघटक इसी संविधान की रक्षा की कसमें खाते रहते हैं।

विभाजन के समय हिंदुत्व की राजनीति में विश्वास करने वालों में सबसे बड़ा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था, जिसने शुरू से ही इस संविधान का विरोध करना शुरू कर दिया। उसके मुखपत्र *ऑर्गनाइजर* ने तो संविधान लागू होने के दूसरे दिन ही अपने एक संपादकीय में स्पष्ट कर दिया कि पश्चिमी मूल्यों वाले इस दस्तावेज को हिंदू स्वीकार नहीं करेंगे, उनके लिए तो मनुस्मृति ही देश का संविधान हो सकती है। इसी पत्रिका ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इस आधार पर स्वीकार करने से मना कर दिया था कि तिरंगा अशुभ है और शिवाजी का हिंदू पद पादशाही वाला भगवा ध्वज ही यह स्थान ले सकता है। अब आरएसएस और उसके अनुषांगिक संगठन भी इसी संविधान को स्वीकृत करते हैं।

75 वर्षों के प्रयोग के बाद भिन्न विचारधाराओं द्वारा स्वीकृति ही इस संविधान की सबसे बड़ी सफलता है। यह इस बात की भी पुष्टि है कि भारतीय मेधा मध्यमार्ग की तरफ ही आकर्षित होती है। वाम और दक्षिण- दोनों के अतिवाद के साथ देर तक इसकी नहीं निभ सकती। यदि हम ध्यान से देखें, तो सदन के नेता जवाहरलाल नेहरू और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भीमराव आंबेडकर की अगुवाई में संविधान सभा ने भारतीय परंपरा को मैग्नाकार्टा से लेकर फ्रांसीसी क्रांति तक के वैश्विक लोकतांत्रिक आंदोलनों से जोड़कर एक अद्भुत व जीवंत दस्तावेज रचा, जिसकी प्रासंगिकता निरंतर बनी हुई है। एक तरफ, उस पर काल्पनिक या वास्तविक संकट आते ही देश के असंख्य पीड़ित जन उसकी सुरक्षा के लिए तनकर खड़े हो जाते है, दूसरी तरफ दक्षिण व वाम- दोनों ने शुरुआती हिचकिचाहट के बाद इसे स्वीकार कर लिया है। हिंदी आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों मे यह विरुद्धों के बीच अद्भुत सामंजस्य है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

युद्धों की भारी कीमत आखिर कब तक चुकाएगा पर्यावरण

यहां स्कैन करें

अर्चना दत्ता | पूर्व महानिदेशक, दूरदर्शन व एआईआर

दुनिया दो महाद्वीपों में जारी दो बड़े युद्धों से घिरी हुई है- पूर्वी यूरोप में रूस-यूक्रेन जंग से और पश्चिम एशिया में इजरायल-हमास युद्ध से। बड़े पैमाने पर विनाश के निशान छोड़ने के साथ ही इन युद्धों ने प्राकृतिक व मानव निर्मित पर्यावरण, दोनों को क्षति पहुंचाकर 'पर्यावरण आतंकवाद' को भी अंजाम दिया है। युद्धों में भारी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन होता है। इनमें इस्तेमाल होने वाले विस्फोटकों से ही नहीं, जहां इनका व अन्य युद्ध सामग्रियों का निर्माण होता है, वहां से भी उत्सर्जन होता है। ऊर्जा की भारी खपत होती है। इसके अलावा, युद्धग्रस्त इलाकों में जरूरी पुनर्निर्माण में भी बड़े पैमाने पर उत्सर्जन होता है। अकेले 2023 में दुनिया में 170 सशस्त्र संघर्ष और लगभग 12 करोड़ लोगों का विस्थापन दर्ज किया गया था। निस्संदेह, यह बहुत दुखद है। युद्ध अलग-अलग प्रकार से विश्व पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं।

युद्धों के आधुनिक इतिहास में प्रथम विश्व युद्ध बहुत हानिकारक साबित हुआ था। विशाल घास के मैदान, पौधे और जानवरों के आवास उस युद्ध के चलते नष्ट हुए थे। बड़े पेड़ों की कटाई के कारण मिट्टी को भी बहुत नुकसान हुआ था। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध में हवाई बमबारी ने रासायनिक प्रदूषण को बहुत बढ़ा दिया था, जिसका बहुत घातक असर वनस्पतियों व जीवों पर पड़ा। 1960 के दशक के वियतनाम युद्ध में वनों को भारी नुकसान पहुंचा था। वर्ष 1990 के दशक का खाड़ी युद्ध विशाल ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार था, क्योंकि तेल के कुओं को निशाना बनाया गया था, जिससे समुद्र में बड़े पैमाने पर तेल फैला और हर समुद्री प्रजाति को नुकसान पहुंचा था।

अब समय आ गया है कि युद्धों से विश्व पर्यावरण को जो भयानक नुकसान पहुंच रहा है, उसका समग्र आकलन किया जाए।

अनुमान है, रूस-यूक्रेन युद्ध के पहले दो वर्षों में 17.50 करोड़ टन से अधिक उत्सर्जन हुआ। भले ही हमारे पास गाजा संघर्ष के दौरान हुए नुकसान का सही मूल्यांकन नहीं है, फिर भी उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, इसमें कम से कम पांच करोड़ टन उत्सर्जन हुआ है। यहां विमानों को हमले के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, तो कम ईंधन जलता है। अमेरिका खुले हाथों से इजरायल की मदद कर रहा है। गाजा और एक बड़े इलाके में मिट्टी और पानी को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। बिना विस्फोट वाले आयुधों, एस्बेस्टस और अन्य खतरनाक पदार्थों के साथ अनगिनत टन मलबे ने लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरे पैदा कर दिए हैं। गौरतलब है, संघर्ष के पहले तीन महीनों में पांच साल से कम उम्र के बच्चों में तीव्र श्वसन संक्रमण के 1,79,000 व दस्त के 1,36,400 मामले सामने आए थे। दुनियावी गतिविधियों में शुद्ध सैन्य गतिविधियों की मात्रा लगभग 5.5 प्रतिशत है। हालांकि, यदि हथियारों के निर्माण, लौह और इस्पात उत्पादन व आपूर्ति शृंखला के उद्यम को अगर जोड़ लिया जाए, तो कुल उत्सर्जन 29 प्रतिशत तक पहुंच जाता है।

दुर्भाग्य से, 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल या 2015 के पेरिस समझौते के तहत देश सैन्य गतिविधियों से उत्सर्जन की रिपोर्ट करने के लिए बाध्य नहीं हैं। ऐसे आंकड़ों को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर गुप्त रखा जा सकता है। युद्ध से अर्थव्यवस्थाओं को बहुत नुकसान पहुंचता है, इसके बावजूद अनेक देशों ने इस पर खर्च को कम नहीं किया है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका ने इस पर 60.7 अरब डॉलर खर्च किए हैं। यूक्रेन को बहुत सैन्य सहायता के साथ ही पिछले ढाई वर्ष में इजरायल को कम से कम 17.9 अरब डॉलर की सहायता दी गई है। यूक्रेन को ब्रिटेन ने 12.8 अरब डॉलर, जर्मनी ने 61.1 अरब डॉलर, डेनमार्क ने सात अरब डॉलर और नीदरलैंड ने 5.5 अरब डॉलर खर्च दिए हैं। जहां तक रूस की बात है, तो उसने 2025 के लिए 126 अरब डॉलर का रिकॉर्ड रक्षा बजट पेश किया है, जो उस साल के सरकारी खर्च का लगभग 32.5 प्रतिशत है। कथित तौर पर ईरान भी अपने सैन्य खर्च को तीन गुना करने को तैयार है। वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि युद्ध पर हो रहे खर्च घटाने पर जरूर चिंतन होना चाहिए, पर ऐसा कैसे होगा?

जैसा कि युवल नूह हरारी ने भविष्यवाणी की थी, शक्ति के दुरुपयोग के कारण पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए गंभीरता से काम करने का समय आ गया है।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

नए सिरे से मिलना सीखें

किसी ने प्रश्न किया है कि जब मैं आपको सुनता हूं, तो सब कुछ स्पष्ट और नया लगता है; लेकिन घर जाकर फिर वही पुरानी बेचैनी आ घेरती है। मेरे साथ दिक्कत क्या है?

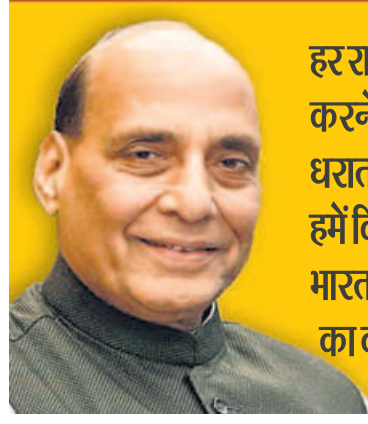

हमारे जीवन में वास्तव में क्या होता है? लगातार कोई चुनौती है और उसका प्रत्युत्तर है। चुनौती सदा नूतन होती है और प्रतिक्रिया सदा पुरातन। मैं आपसे कल मिला था और आज भी आप मेरे पास हैं। आज आप कुछ भिन्न हैं, कुछ अलग से हैं, आप में कुछ नयापन है, लेकिन कल आप जैसे थे, मेरे दिमाग में उसकी एक तस्वीर है। अतः मैं पुराने में नए को जज्ब कर लेता हूं। मैं नए सिरे से आपसे नहीं मिलता, अतः उस चुनौती का मेरा प्रत्युत्तर सदा संस्कारबद्ध होता है।

दूसरे शब्दों में, नूतन सदा पुरातन, पुरानी आदतों, रीति-रिवाजों, परंपराओं, स्मृतियों में विलीन होता रहता है। नया कभी संभव ही नहीं हो पाता, क्योंकि आपकी नए से मुलाकात तो होती है, लेकिन हमेशा पुराने बोझ के साथ। समस्या यह है कि विचार को पुरातन से कैसे मुक्त किया जाए, जिससे वह सदा नवीन बना रहे? जब आप किसी फूल, चेहरे, आकाश, वृक्ष या किसी की मुस्कराहट को देखते हैं, तो यह सब देखना नए ढंग से कैसे हो? ऐसा क्यों होता है कि हम कुछ भी नई दृष्टि से नहीं देख पाते? ऐसा क्यों होता है कि पुराना नए को निगलकर उसमें रद्दोबदल कर देता है?

पुरानी प्रतिक्रिया का उदय विचारक से ही होता है। क्या विचारक सदा पुराना नहीं होता? चूंकि आपके विचार अतीत पर आधारित हैं, अतः जब आप नए से भेंट करते हैं, तो यह विचारक ही है, जो भेंट कर रहा होता है, यह बीते हुए कल का अनुभव ही है, जो उस नए से मिल रहा होता है। इस प्रकार हम फिर उसी समस्या पर आ जाते हैं कि मन को विचारक की भूमिका से कैसे मुक्त किया जाए? स्मृति को समाप्त कैसे करें, तथ्यात्मक स्मृति को नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक स्मृति को, जो अनुभवों का संचय है? अनुभव के अवशेष से मुक्त हुए बिना नए का ग्रहण संभव नहीं है। मगर विचार को मुक्त करना, विचार-प्रक्रिया से मुक्त होना तथा नवीन का साक्षात् करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि हमारे सभी विश्वास (धर्म), हमारी सभी परंपराएं, शिक्षा की हमारी समस्त पद्धतियां नकल और अनुकरण की प्रक्रिया ही हैं, जो स्मृति-भंडार बढ़ाती रहती हैं।

अनुभव के अवशेष से मुक्त हुए बिना नए का ग्रहण संभव नहीं है, जबकि हमारे सभी विश्वास, सभी परंपराएं, शिक्षा की समस्त पद्धतियां नकल और अनुकरण की प्रक्रिया ही हैं।

ऐसे में, क्या यह संभव है कि हम सदा नए से मिल सकें? यकीनन ऐसा किया जा सकता है। इसके लिए हमें अपनी भावना में, अपनी सोच में क्रांति लानी होगी। आप स्मृतियों से स्वतंत्र तभी हो सकते हैं, जब प्रत्येक घटना से पल-पल निपटते चलते हैं; हर प्रतिक्रिया को पूरी तरह समझ लेते हैं, उस पर सरसरी निगाह डालकर एक तरफ नहीं कर देते।

जे कृष्णमूर्ति

राजनाथ सिंह | केंद्रीय रक्षा मंत्री

हर राजनीतिक और राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक सामाजिक-सांस्कृतिक धरातल तैयार करना पड़ता है। इसलिए यदि हमें विकसित भारत का निर्माण करना है, तो भारत में फिर से सांस्कृतिक पुनर्जागरण का वातावरण बनाना होगा।

विगत दशकों की छेड़छाड़ पड़ रही भारी

किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान ही सर्वोपरि होता है, जिसके आधार पर न्याय, समता, समानता जैसे मूल्यों की बुनियाद पर 'निर्धन हो या हो धनवान, कानून सभी के लिए समान' की अवधारणा का अनुपालन अपेक्षित होता है, किंतु यदि राजनीतिक स्वार्थों के कारण संविधान में समय-समय पर संशोधन करके उसे राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति का माध्यम बनाया जाए, तो यह स्थिति किसी भी राष्ट्र में मानवीय दृष्टिकोण से घातक सिद्ध हो सकती है। भारत में संविधान के साथ हुई छेड़छाड़ से ऐसा ही संदेश जनमानस को मिला है।

संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में संविधान पर चर्चा हुई। कितने जन-प्रतिनिधियों ने विशुद्ध रूप से संविधान पर चर्चा की और कितनों ने अपने राजनीतिक एजेंडे को सामने रखा, यह विश्लेषण का विषय है, मगर देश के संविधान को समय-समय पर तुष्टिकरण के लिए बदलने वाली कांग्रेस अब इसकी अधिक दुहाई दे रही है। संसद में संविधान पर हुई बहस में नेता प्रतिपक्ष ने सत्ता पक्ष पर एकलव्यों का अंगूठा काटने का आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष यह भूल गए कि यदि किसी ने संविधान से सर्वाधिक छेड़छाड़ करके देश की पंथ निरपेक्षता को तार-तार किया है, तो वह कांग्रेस ही है। कभी इंदिरा गांधी की हत्या के उपरांत 1984 में निरीह सिखों का कत्लेआम हुआ, तो कभी वक्फ बोर्ड को विशेषाधिकार देकर सांप्रदायिक सौहार्द को तार-तार किया गया। कौन नहीं जानता कि शाह बानो प्रकरण में देश के उच्चतम न्यायालय के निर्णय को दरकिनार करते हुए मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने संबंधी आदेश की अवमानना की गई, यही नहीं, 1991 पूजा स्थल अधिनियम के माध्यम से पूजा स्थलों पर धर्म विशेष के अनुयायियों के अवैध कब्जों को सही ठहराने का प्रयास किया गया?

रहा सवाल एकलव्यों का अंगूठा काटने का, तो एक ही वंश का वर्चस्व बनाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रतिभावान एकलव्यों का कितना सम्मान किया गया, यह किसी से छिपा नहीं है। कांग्रेस का वंशवादी इतिहास यदि खंगाला जाए, तो स्पष्ट होगा कि इस पार्टी ने सिर्फ एकलव्यों का अंगूठा ही नहीं काटा, वरन उनका मर्दन भी किया है। धार्मिक तुष्टिकरण के नाम पर देश के सांप्रदायिक सौहार्द का कत्ल किया है।

सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि समय-समय पर संविधान को अपने पैरों तले रौंदने वाली कांग्रेस आखिर किस मुंह से संविधान बचाने की दुहाई दे सकती है, जबकि संविधान से खिलवाड़ करने की सर्वाधिक दोषी वही है?

सुधाकर आशावादी, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम
संविधान

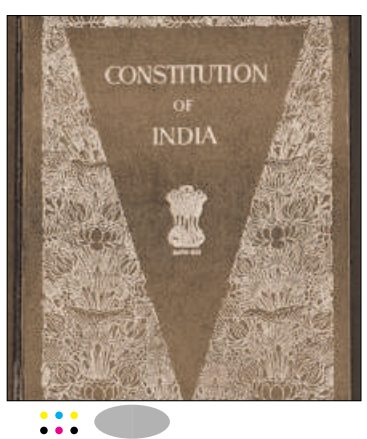

संविधान का अब ज्यादा अनादर हो रहा

लोकसभा में तो हो गया, अब उच्च सदन राज्यसभा की बारी है। हालांकि, वहां भी बहस का वही रंग-ढंग दिख रहा है, जो निचले सदन में दिखा। संविधान पर जिस तरह की चर्चा लोकसभा में हुई, उसमें तो कोई खास नई बात सामने नहीं आई, सिवाय इसके कि जिस संविधान को 26 नवंबर, 1949 को अंगीकार किया गया था, वह राष्ट्रवादी शासन-व्यवस्था को एकदम पसंद नहीं है। मगर उसके पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है कि संविधान के बिना सरकार को कैसे चलाया जा सके? बहरहाल, शुक्रवार और शनिवार को लोकसभा में इस पर चर्चा हुई और शनिवार को जब बहस का अंत किया गया, तो केवल और केवल कांग्रेस को घेरने का प्रयास हुआ। भाई-भतीजावाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर वही-वही बातें की गईं, जो 2014 के पहले से कही जाती रही हैं। आपातकाल को कांग्रेस के माथे का कलंक बताया गया और कहा गया कि उसी के चलते हमारा संविधान लहूलुहान हुआ। तो क्या 6 दिसंबर, 1992 की घटना संविधान के सम्मानार्थ थी? कहा गया कि नेहरू ने संविधान में संशोधन किए और फिर इंदिरा गांधी के मुंह खून लग गया और उन्होंने भी बदलाव किए, जबकि अब तक कुल 106 संविधान संशोधनों में 30 के करीब संशोधन गैर-कांग्रेसी सरकारों ने किए। रही परिवारवाद की बात, तो किस पार्टी ने परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया? वर्ष 1947 से अब तक केवल पांच कांग्रेस अध्यक्ष हुए, जो नेहरू-गांधी परिवार से थे, बाकी 13 अध्यक्ष इसके बाहर से हुए हैं। अंदेशा यही है कि जिस तरह से लोकसभा में संविधान पर की गई चर्चा राजनीति की भेंट चढ़ गई, कुछ ऐसा ही हाल राज्यसभा में भी होने वाला है।

जंग बहादुर सिंह, टिप्पणीकार

संविधान की सुध

संविधान के नाम पर सियासी रोटियां सेंकने का चलन इन दिनों बढ़ गया है। स्वार्थी राजनेता और नौकरशाह भूल गए हैं कि संविधान के रूप में कितनी बड़ी ताकत हमारे पूर्वजों ने हमें सौंप रखी है, तभी तो आज गण और तंत्र के बीच फासला बढ़ता जा रहा है। संविधान पर हुई चर्चा में सभी संविधान की सुध लेते दिखे, लेकिन यह हकीकत तभी बन सकता है, जब सरकारी प्रतिष्ठान इसकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हों। दुखद है, हाल के वर्षों में ऐसे कई मौके आए, जब सांविधानिक प्रावधानों को तार-तार करने का प्रयास किया गया। राजनेता संविधान में क्या परिवर्तन चाहते हैं, यह मायने नहीं रखता, लेकिन आमजन यही चाहता है कि वे संशोधन उसके हितों से समझौता न कर सकें।

महिमा, टिप्पणीकार

उपेक्षा के बजाय

एक संवेदनशील समाज अपने बीच पल रही नकारात्मक प्रवृत्तियों की पहचान करता और उसे नजरअंदाज करने के बजाय दूर करने के लिए उचित रास्ते अपनाता है। विडंबना है कि हमारे आसपास कई ऐसी स्थितियां होती हैं, जिन्हें लेकर समाज आमतौर पर उपेक्षा और कई बार उसे खारिज करने का रवैया अख्तियार कर लेता है। नतीजतन वह समस्या और जटिल होती जाती है। समूचे देश के युवाओं के बीच मादक पदार्थों की बढ़ती लत या नशे की आदत एक ऐसी समस्या है, जिससे निपटने में समाज से लेकर सरकार तक ने एक तरह की उदासीनता ही दर्शायी है। बल्कि आमतौर पर मादक पदार्थों के लती युवाओं में सुधार या नशे से मुक्ति की गुंजाइश पैदा करने के बजाय उन्हें सबके लिए खतरनाक व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। जबकि यह हमेशा साबित हुआ है कि इस तरह की नकारात्मक सामाजिक प्रतिक्रिया की वजह से जो युवा मादक पदार्थों के दलदल से बाहर आ सकते थे, वे भी अपनी उपेक्षा और खुद को अपमानित किए जाने की वजह से उस संजाल में और ज्यादा उलझते चले जाते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मादक पदार्थों के सेवन के खिलाफ लड़ाई से जुड़े महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर रोशनी डाली और इससे प्रभावित युवाओं का 'दानवीकरण' करने के बजाय उनके पुनर्वास पर जोर दिया। यह छिपा तथ्य नहीं है कि समाज में एक बड़ा तबका किसी न किसी तरह के मादक पदार्थ का सेवन करता है, मगर इसके समांतर ऐसे लोगों के प्रति एक नकारात्मक भाव भी होता है। जब कोई युवा संगति या अन्य वजहों से धूम्रपान, शराब या इससे ज्यादा घातक नशीले पदार्थों का सेवन करने लगता है, तब उसके प्रति एक आम सामाजिक प्रतिक्रिया ऐसी नहीं होती, जिसमें उसके उस जाल में फंसने के कारणों पर गौर करके उससे निकालने की इच्छाशक्ति दिखे। इसके उलट इस दुश्चक्र में फंसे युवाओं के बारे में नकारात्मक धारणा बनाई जाती है। इसका नतीजा यह होता है कि एक लत का शिकार होकर पहले ही उद्वेलन और द्वंद्व के मनोविज्ञान में फंस गया व्यक्ति अपने प्रति अपमानजनक और उपेक्षित रवैये से चोट खाकर और ज्यादा नशे में डूब जाता है।

सवाल है कि नशे के संजाल में फंसे युवा के एक बेहतर मनुष्य होने की उम्मीद पालने वाले समाज को इससे क्या हासिल होता है। व्यवहार मनोविज्ञान की कसौटी पर देखें तो मादक पदार्थों की लत या अनुचित आदत का शिकार हो गए व्यक्ति में भी अपने प्रति संवेदनशील बर्ताव और उचित तौर-तरीके के जरिए बदलाव लाया जा सकता है, उसे इस जाल से बाहर निकाला जा सकता है। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मादक द्रव्यों की लत के बहुआयामी कारणों की ओर इशारा किया, जिसमें शैक्षणिक दबाव, पारिवारिक अशांति और नशीली दवाओं की आसान उपलब्धता शामिल है। ये कारक ही अक्सर किशोरों और युवाओं के बीच भावनात्मक पलायनवाद के रूप में मादक पदार्थों के सेवन को बढ़ावा देते हैं। पिछले कुछ समय से इन्हीं जटिल परिस्थितियों का फायदा उठा कर अवैध व्यापार करने वाले इसका इस्तेमाल आतंकवाद और हिंसा को बढ़ावा देने में कर रहे हैं, जिसका दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक नुकसान हो रहा है। ऐसे में नशे का शिकार होने वाले युवाओं की उपेक्षा करने या उन्हें 'शैतान' समझने के बजाय उनके प्रति रचनात्मक व्यवहार और उनका पुनर्वास एक ठोस रास्ता है, जो भटके हुए युवाओं को फिर से एक सचेतन और संवेदनशील इंसान बना सकता है।

विदा उस्ताद

तबले का कायदा उन्हें घुट्टी में मिला था। पिता अल्लारक्खा कुरैशी मशहूर तबलावादक थे। संगीत के माहौल में ही उनकी परवरिश शुरू हुई थी। मगर जाकिर हुसैन जैसे पैदा ही तालवाद्य के लिए हुए थे। बचपन से ही उनकी अंगुलियां थिरकनी शुरू हो गई थीं। पिता ने उन्हें तबले की तालीम देनी शुरू की। बारह साल की उम्र तक पहुंचते-पहुंचते उन्होंने वह काबिलियत हासिल कर ली थी कि अमेरिका के संगीत समारोह में अपना हुनर दिखा सकें। अमेरिका के पहले कार्यक्रम में ही उन्हें ऐसी शोहरत मिली कि फिर उन्होंने पीछे लौट कर नहीं देखा। जाकिर हुसैन ने उसे वाद्य के रूप में नहीं साधा, बल्कि तबले को उन्होंने जीया था। तबले में जितनी संभावनाएं उन्होंने तलाश कीं, उसकी जितनी बारीकियां उन्होंने उजागर कीं, उनसे पहले किसी तबला नवाज ने नहीं किया था। हर तरह के तालवाद्य और तारवाद्य के साथ उन्होंने जुगलबंदी की, देश और दुनिया के हर नामचीन गायक और वादक के साथ उन्होंने संगत की- अपनी पहले की पीढ़ी के भी, अपने समय और अपने बाद की पीढ़ी के भी। तबले को उन्होंने पश्चिमी देशों में भी प्रतिष्ठा दिलाई।

जाकिर हुसैन न केवल अद्भुत तबलावादक थे, बल्कि उनका बजाने का अंदाज भी अनोखा था। तबला बजाते हुए उनके लंबे बाल जिस अंदाज में लहराते, लगता कि उनके बाल और ताल जुगलबंदी कर रहे हों। उनका वह अंदाज सभी को मोहता था। वे पहले वादक थे, जिन्होंने तबले से अन्य वाद्य यंत्रों की ध्वनियां भी निकालने का प्रयोग किया, जैसे उनका तबले से शिव के डमरु का नाद बहुत लोकप्रिय हुआ था। वे मंचीय प्रदर्शनों में तबले से धुनें निकाल कर भी कौतुक रच दिया करते थे। भारतीय शास्त्रीय संगीत के अलावा उन्होंने अमेरिकी जैज में भी अपने तबले से नया रंग भर दिया। इसका नतीजा था कि इसी साल अप्रैल में उन्हें एक साथ तीन ग्रेमी अवार्ड प्राप्त हुए। इससे पहले उन्हें दो ग्रेमी मिल चुके थे। ग्रेमी अवार्ड संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय भी किया था, कई विज्ञापन उनके अभिनय से यादगार हो गए। भारत सरकार उन्हें तीनों पद्म सम्मानों से सम्मानित कर चुकी थी। उनका जाना निस्संदेह ताल की दुनिया को कुछ सूना कर गया है।

युद्ध के दुस्वप्न से जूझते बच्चे

निरंतर हमलों, हिंसा के भय और खतरों का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर हुआ है। विस्थापन ने लाखों बच्चों को अपने परिवारों से अलग कर दिया है।

जयप्रकाश त्रिपाठी

युद्ध-पीड़ित क्षेत्रों में बमबारी से बचा हर छठवां बच्चा भुखमरी और कुपोषण की मार झेल रहा है। सबसे ज्यादा नवजात शिशु प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि प्रसूताओं को पर्याप्त भोजन नसीब नहीं है। इस बीच दुनिया के लगभग एक अरब बच्चे जलवायु संकट की चपेट में आ चुके हैं। विश्व भर में, दस से उन्नीस वर्ष के हर सात में से एक बच्चा-किशोर अवसाद में जी रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की एक नई रपट बताती है कि यूक्रेन पर रूसी सैन्य आक्रमण से प्रतिदिन कम से कम दो बच्चे चपेट में आ रहे हैं। बच्चों को हर दिन करीब छह घंटे भूतल या अन्य भूमिगत स्थानों पर रहना पड़ रहा है। डेढ़ हजार से अधिक शैक्षणिक संस्थान और 660 स्वास्थ्य केंद्र युद्ध में क्षतिग्रस्त या ध्वस्त हो चुके हैं। सर्दी के मौसम में बच्चों को जमा देने वाली ठंड का सामना करना पड़ रहा है।

नार्वेजियन शरणार्थी परिषद (एनआरसी) के मुताबिक, गाजा और यूक्रेन जैसे हिंसा ग्रस्त क्षेत्रों में कक्षाओं में बच्चे सो जाते हैं। पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई के कारण उनका शैक्षणिक प्रदर्शन खराब हो रहा है। यूक्रेन में युद्ध के दौरान 1,072 विश्वविद्यालयी विद्यार्थियों (इनमें 80 फीसद लड़कियां) पर केंद्रित एक अध्ययन में बताया गया है कि जो बच्चे कभी अंतरिक्ष यात्री, फुटबाल खिलाड़ी, वैज्ञानिक और डाक्टर बनने के सपने देखा करते थे, वे अभिघातजन्य नींद की समस्याओं से पीड़ित हैं। उनमें भयावह मानसिक आघात के लक्षण मिल रहे हैं। चिकित्सा क्षेत्र में, गहरे आघात, अनिद्रा, बुरे सपनों के बीच तरह-तरह के लक्षण रेखांकित होते रहे हैं, लेकिन अध्ययनकर्ताओं को वर्तमान जटिलताएं ज्यादा असाध्य लग रही हैं।

पश्चिमी यूक्रेन, सूडान और गाजा के बच्चों में युद्ध से संबंधित आघात, डर, बुरे सपने, अनिद्रा और अभिघातजन्य तनाव गंभीर रूप लेते जा रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन, नार्वे, ब्रिटेन और जर्मनी में हुए अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों और शोध के मुताबिक, पीड़ित बच्चों पर केंद्रित मनोवैज्ञानिक परिणाम चौंकाने वाले हैं। अवसाद पीड़ित किशोर-किशोरियों में आत्मघाती विचार जड़ें जमा रहे हैं। विस्थापन की यातनाएं भोग रहे बच्चों और किशोरों को अपने परिवार के लिए रोटी-पानी, चाय और ईंधन के साथ रसोई गैस के लिए कतारों में छह-छह घंटे खड़े रहना पड़ता है।

निरंतर हमलों, हिंसा के भय और खतरों का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर हुआ है। विस्थापन ने लाखों बच्चों को अपने परिवारों से अलग कर दिया है। सूडान में युद्ध पीड़ित एक करोड़ चालीस लाख बच्चों को जीवनरक्षक सहायता की जरूरत है। वहां की आंतरिक हिंसा ने दुनिया में सबसे बड़े बाल विस्थापन को जन्म दिया है। गाजा में संघर्ष बढ़ने और यूक्रेन पर रूसी हमले तेज होने से सूडान को भुला देना भी एक त्रासदी है। वहां पैंतीस लाख से ज्यादा किशोर-किशोरियां सुरक्षित स्थानों की तलाश में अपने घरों से भाग गए हैं। पांच साल से कम उम्र के तीस लाख से अधिक बच्चे गंभीर कुपोषण का शिकार हैं। अगर उपचार नहीं मिला, तो सात लाख बच्चे

अपनी जान गंवा सकते हैं। दुखद यह भी है कि वहां बड़ी संख्या में बच्चे स्कूलों से वंचित हो गए हैं।

संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों का मानना है कि युद्ध के तौर-तरीके बच्चों के मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे करोड़ों बच्चों का शिक्षा-

> **युद्ध और हिंसक घटनाओं के अनुभवों से गुजर रहे बच्चों और किशोरों में कई तरह के मानसिक आघात के लक्षण पाए गए हैं। मानसिक आघात के बाद उपजे तनाव से ग्रस्त बच्चों को बार-बार बुरे सपने आते हैं। बचपन में ही उन्हें नींद न आने की बीमारी हो रही है। हर वक्त तनाव का सामना करते हुए, खतरे के उच्च स्तर तक वे नींद में भी डरे-डरे पाए जा रहे हैं। अभिघात के लक्षण बच्चों की सीखने की क्षमता को नष्ट कर रहे हैं। ऐसे 83 अध्ययनों में, लगभग 60 फीसद बच्चे दीर्घकालिक दुस्वप्नों के आघात के शिकार हैं। उनकी सामाजिक समझ का तेजी से लोप हो रहा है। युद्ध और हिंसक झड़पें उनके जीवन पर इतनी अमानवीय छाप छोड़ रही हैं कि उनकी दुनिया जैसे जंगल में तब्दील हो चुकी है।**

संकट तो कल्पना से परे हो गया है। अगर बच्चे कुछ सीख-पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो युद्ध-पीड़ित देशों में भविष्य का आधार कैसे बनेगा, समझा जा सकता है। शिक्षा, शांति स्थापित करने का एक शक्तिशाली कारक होती है, क्योंकि जब बच्चे कक्षाओं में होते हैं, तो स्वयं को सुरक्षित-संरक्षित महसूस करते हैं। अपने अवचेतन में शांतिपूर्वक सह-अस्तित्व में रहना सीखते रहते हैं। ये ऐसे मूल्य हैं, जिन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। जिन मूल्यों के साथ बच्चों को जीना चाहिए, उनका पालन-पोषण होना चाहिए, सब नदारद हैं। शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को वेतन तक नहीं मिल रहा है, तो बच्चों की फुलवारी कौन सींचे, यह सबसे बड़ा सवाल है।

युद्ध और हिंसा पीड़ित देशों से भारी विस्थापन के कारण अछूते क्षेत्र भी इस समस्या की चपेट में आ रहे हैं। एक रपट के अनुसार, पांच वर्ष से कम उम्र के लगभग 40 करोड़ बच्चे, घरों में आक्रामक बर्ताव और शारीरिक दंड का सामना कर रहे हैं। इस बीच यूनिसेफ के मुताबिक, हर आठ में से एक और लगभग 37 करोड़ लड़कियों और महिलाओं को यौन आक्रामकता का सामना करना पड़ रहा है। आनलाइन उत्पीड़न ने तो लगभग 65 करोड़ लड़कियों- महिलाओं का जीना दुश्वार कर दिया है। ये स्थितियां ऐसे करोड़ों घरों के बच्चों का वर्तमान और भविष्य चौपट कर रही हैं। गंभीर टकरावों वाले क्षेत्रों में रहने को विवश बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। इन बच्चों में इंटरनेट के जरिए बढ़ती कनेक्टिविटी और लगातार बढ़ता आनलाइन दुर्व्यवहार भी भयानक मुद्दा हो गया है। रपट बताती है कि अब भी लगभग 16 करोड़ बच्चे बालश्रम, मानव तस्करी और यौन शोषण से जूझ रहे हैं। उनका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है। ऐसे में नशीले पदार्थों की लत उन्हें आत्महत्या के लिए उकसा रही है।

युद्ध और हिंसक घटनाओं के अनुभवों से गुजर रहे बच्चों और किशोरों में कई तरह के मानसिक आघात के लक्षण पाए गए हैं। मानसिक आघात के बाद उपजे तनाव से ग्रस्त बच्चों को बार-बार बुरे सपने आते हैं। बचपन में ही उन्हें नींद न आने की बीमारी हो रही है। हर वक्त तनाव का सामना करते हुए, खतरे के उच्च स्तर तक वे नींद में भी डरे-डरे पाए जा रहे हैं। अभिघात के लक्षण बच्चों की सीखने की क्षमता को नष्ट कर रहे हैं। ऐसे 83 अध्ययनों में, लगभग 60 फीसद बच्चे दीर्घकालिक दुस्वप्नों के आघात का शिकार हैं। उनकी सामाजिक समझ का तेजी से लोप हो रहा है। युद्ध और हिंसक झड़पें उनके जीवन पर इतनी अमानवीय छाप छोड़ रही हैं कि उनकी दुनिया जैसे जंगल में तब्दील हो चुकी है। गाजा पट्टी की तो 2007 से सैन्य घेरेबंदी है, जिससे लगभग बीस लाख फिलिस्तीनी बुनियादी जरूरतों से वंचित हो चुके हैं। उनको अब तक चार बड़े युद्धों का सामना करना पड़ा है। इजराइली सैन्य अभियानों से मौत और हिंसा का अकल्पनीय तांडव हुआ है। गाजा में 64 से 67 फीसद बच्चे तनाव झेल रहे हैं।

इस बीच संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, दक्षिण एशिया में अगले वर्ष 2025 में जलवायु और स्वास्थ्य आपदाओं तथा आर्थिक झटकों के कारण लगभग 4.70 करोड़ बच्चों को मानवीय सहायता की आवश्यकता होगी। इस समय भी बाढ़, भूस्खलन, समुद्री तूफान और सूखा आदि से लाखों बच्चे लगातार जलवायु आपदाओं में फंसे पड़े हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं आपात स्थिति से गुजर रही हैं। इससे खासकर बच्चे गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं।

रास्ता और मंजिल

सुरेश कुमार मिश्रा 'उरतृप्त'

आज के इस दौड़-धूप वाले युग में हम अक्सर सफलता प्राप्ति के लिए इतने व्यस्त हो जाते हैं कि समय की वास्तविकता को समझने और उसे सही दिशा में लगाने में चूक जाते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में हम किसी न किसी लक्ष्य की प्राप्ति की कामना करते हैं। हमें लगता है कि अगर हम तुरंत सफलता प्राप्त कर लें, तो हमारे जीवन की यात्रा पूरी हो जाएगी। मगर यह सच है कि किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए समय, सहनशीलता और संयम की आवश्यकता होती है। महर्षि पतंजलि ने कहा है, 'साधनानि सम्प्रयुक्तानि यदि समयेन पुराणानि, तर्हि सिद्धयः सिध्यन्ति।' यानी जब कोई कार्य समय के साथ पूरी मेहनत और परिश्रम से किया जाता है, तब वह कार्य सफलता की ओर अग्रसर होता है। किसी भी कार्य में सफलता के लिए धैर्य और समय का अहम स्थान है। समाज में यह धारणा बन गई है कि हमें सफलता तुरंत मिलनी चाहिए, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो या व्यवसाय में। लेकिन क्या हम यह जानते हैं कि हर महान व्यक्ति ने सफलता प्राप्ति के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना किया और कितने वर्षों तक संघर्ष किया?

भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं, 'विवेकस्य विजयः सर्वं प्रबलं क्रिया केन वा,' यानी कोई भी व्यक्ति अपनी कठिनाइयों को पार कर विवेक और संयम के साथ संघर्ष करता है, तभी वह सफलता प्राप्त करता है। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जब तक हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी मेहनत और संयम से काम नहीं करेंगे, तब तक हम सफलता की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते। समय के सर्वोत्तम होने को समझना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। समय एक ऐसी मूल्यवान चीज है, जो एक बार निकल जाने के बाद फिर कभी वापस नहीं आती। हमें समय को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं है और यह लगातार हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने की दिशा में कार्य करता है।

हमारे प्रयास चाहे छोटे हों, पर वे समय के साथ हमें बड़ी सफलता तक ले जाते हैं। इसीलिए हमें हर छोटे कदम को महत्त्व देना चाहिए। जब लोग मेहनत के बावजूद तुरंत परिणाम नहीं पाते, तो वे थक कर हार मान लेते हैं। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हर असफलता से कुछ सीखने को मिलता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, 'सफलता उसी को मिलती है जो किसी भी कार्य को पूरी निष्ठा और समय के साथ करता है।' सहनशीलता और संयम किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण गुण है। जब हम किसी कार्य में पूर्ण समर्पण से जुट जाते हैं, तो हमें हर छोटी-छोटी जीत की सराहना करनी चाहिए, क्योंकि यही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। धैर्य हर कार्य में सफलता को सुनिश्चित करता है।

सभी बड़े नेता, उद्योगपति और खिलाड़ी, जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया, उन्होंने समय के महत्त्व को समझा और संयम से सफलता प्राप्त की। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में यह सिद्ध कर दिखाया कि समय का सही उपयोग और निरंतर संघर्ष ही सफलता का मार्ग है। हमें भी उन महान व्यक्तियों के संघर्षों से प्रेरणा लेकर अपने कार्य में समय और परिश्रम का सही उपयोग करना चाहिए। आज के युग में हम जितना तेजी से परिणाम चाहते हैं, उतना ही कम हम समय के साथ काम करने का धैर्य रखते हैं। मगर यह सच्चाई है कि बिना समय के साथ किए गए प्रयासों के सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। समय का सम्मान और सहनशीलता के साथ काम करने का मंत्र हमें सफलता की ओर ले जाता है।

गीता में कहा गया है कि कार्य में पूर्ण समर्पण और कठिनाइयों का सामना किए बिना सफलता प्राप्त करना असंभव है। इसलिए हमें समय का सम्मान करते हुए सहनशीलता और संयम के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। यह जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वह शिक्षा हो, व्यवसाय हो, या कोई व्यक्तिगत लक्ष्य हो। हमें यह याद रखना चाहिए कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। यह समय के साथ साकार होती है, जब हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं। हमें उन महान व्यक्तियों की तरह कार्य करना चाहिए, जिन्होंने संघर्ष के दौरान समय का सर्वोत्तम उपयोग किया और आखिर सफलता को प्राप्त किया। सफलता का कोई संक्षिप्त रास्ता नहीं होता। किसी भी कार्य में समर्पण, मेहनत और समय का सामंजस्य अत्यंत आवश्यक है। जैसे नदी धीरे-धीरे अपनी राह बनाती है और अंत में समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही हम भी अपने कार्य में समय, सहनशीलता और संयम से लगातार आगे बढ़ते हुए सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

दरअसल, सफलता पाने के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण चीज है धैर्य और समय का सही उपयोग। जब हम किसी कार्य में जल्दबाजी करते हैं, तो अक्सर हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए सफलता के लिए हमें पूरी मेहनत और समर्पण के साथ कार्य करना चाहिए। समय के साथ हर प्रयास हमें एक कदम और हमारी मंजिल के करीब ले जाता है। यही जीवन की सच्ची सफलता है। हमें हर मुश्किल घड़ी में यही प्रेरणा मिलती है कि अगर हम अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहें, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती।

दुनिया मेरे आगे

> **हमारे प्रयास चाहे छोटे हों, पर वे समय के साथ हमें बड़ी सफलता तक ले जाते हैं। इसीलिए हमें हर छोटे कदम को महत्त्व देना चाहिए। जब लोग मेहनत के बावजूद तुरंत परिणाम नहीं पाते, तो वे थक कर हार मान लेते हैं। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हर असफलता से कुछ सीखने को मिलता है।**

सदन का समय

'सहमति के बजाय' (संपादकीय, 12 दिसंबर) पढ़ा। संसदीय गतिरोध से यह प्रश्न उठा है कि कुछ सांसद अपने मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं। संसद की कार्यवाही के दौरान प्रति मिनट लाखों रुपए बर्बादी के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। सिर्फ खानापूरी के वास्ते संसद संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक की अब कोई प्रासंगिकता नहीं, क्योंकि विपक्ष कई वर्षों से संसदीय संहिता को छिन्न भिन्न करने पर उतारू है। जब गैर-संसदीय विषयों को संसद पटल पर उठाने की मनाही है, तो ऐसे मुद्दों से संसद को ठप करना सर्वथा अनुचित ही माना जाना चाहिए। राज्यसभा के सभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सत्र संचालन अवधि में 14 दिनों पूर्व दिया जाना चाहिए, लेकिन इसे सत्रावसान के मात्र दस दिनों पहले पेश किया गया है। संसद में हंगामे के दौरान नित्य अशोभनीय आचरण दिखता है। निजी हमले, कटाक्ष और अत्यधिक शोरगुल ने लोकतंत्र को धूमिल कर दिया है। सवाल है कि जब विपक्ष सत्ता पक्ष के प्रति द्वेष, दुराग्रह और वैमनस्य के अग्निकुंड में अपने संसदीय कर्तव्यों की आहुति देने में सक्रिय है, तो आखिर सत्ता पक्ष किस प्रकार संसद सत्र के संचालन में सहयोग करेगा।

– अशोक कुमार, पटना

गौरव का क्षण

युवा ग्रैंडमास्टर डी गुकेश ने साबित कर दिया कि छोटी उम्र में भी विजय प्राप्त करना संभव है। उन्होंने रूस के गैरी कास्पारोव का 14 साल पुराना कीर्तिमान तोड़ दिया, जिन्होंने 22 साल की उम्र में सबसे युवा विश्व चैंपियन का खिताब जीता था। गुकेश की यह जीत शतरंज के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ती है। यह देश के लिए गौरव का क्षण है। विश्वनाथन आनंद के बाद, गुकेश दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने विश्व चैंपियन का खिताब जीता है। चौदहवें चक्र में गुकेश ने 58 चालों में डिंग लिरेन को हरा कर शतरंज के इतिहास में 18वें विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। अक्तूबर 2022 में, इस खिलाड़ी ने तब सभी का ध्यान आकर्षित किया था, जब उन्होंने रैपिड शतरंज टूर्नामेंट में उस समय के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया था। अब विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत कर उन्होंने भारत के सम्मान में एक और उपलब्धि जोड़ दी है।

– दत्तप्रसाद शिरोड़कर, मुंबई

ठिठुरते लोग

कड़के की सर्दी शुरू होते ही धुंध के कारण जन-जीवन ठहर-सा जाता है। रेलगाड़ियों और हवाई जहाजों के संचालन में दिक्कत आने लगती है। धुंध में दृश्यता कम होने से सड़क मार्ग से यात्रा जोखिम भरा होता है। दुर्घटना की संभावना भी रहती है। इन दिनों सबसे ज्यादा मार गरीबों और बेघर लोगों पर पड़ती है। साधन-संपन्न लोग तो बचाव कर लेते हैं, पर जिसके पास घर की छत भी नहीं, वह ठिठुरन से बचने के लिए अलाव की मदद लेता है। कई तो रैन बसेरों में आश्रय लेते हैं। खुले आसमान के नीचे किसी रेलवे प्लेटफार्म पर या किसी पुल के नीचे कुछ लोग सोते हुए दिखते हैं। रात भर ठिठुरते हुए वे सुबह का इंतजार करते हैं। कुछ लोग तथा कुछ स्वयंसेवी संगठन कंबल और रजाई आदि बांटते हैं जो नाकाफी होते हैं। सरकारी रैन-बसेरों की दशा से सब वाकिफ हैं। अगर लोग सहायता करें तो फिर वे निर्धन और बेसहारा लोगों को ठिठुरन से बचा कर उनके जीवन में खुशियां ला सकते हैं।

– वेद प्रकाश, गुरुग्राम

पर्यावरण की चिंता

'जलवायु पर बढ़ते संकट के जिम्मेदार' (लेख, 13 दिसंबर) में सच ही बताया गया कि प्रदूषण बढ़ाने वाले देश स्वयं भी प्रदूषण के दुष्प्रभाव से बच नहीं सकेंगे। बाकू में हुए जलवायु सम्मेलन में अमेरिका, चीन, आस्ट्रेलिया और कनाडा आदि बड़े देशों को प्रदूषण बढ़ाने के लिए जवाबदेह ठहराया गया, क्योंकि सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाले भी यही देश हैं। प्रदूषण बढ़ाने वाले देश अपनी चिंता करने के साथ दुनिया के अन्य देशों की भी चिंता करें, क्योंकि जीडीपी तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की सेहत बनाने में सक्षम है, जबकि जीईपी हर देश के पर्यावरण की सेहत बनाती है। प्रदूषण कम करने के लिए महज चर्चा से काम नहीं चलेगा, बल्कि कठोर और सार्थक कदम उठाने होंगे। विकसित और बड़े देशों को स्वयं आगे आकर कम कार्बन उत्सर्जित करना होगा।

– बीएल शर्मा 'अकिंचन' उज्जैन

www.readwhere.com

दैनिक जागरण

सीमित आकांक्षाओं में ही असीमित सुख का सार निहित है

नक्सलियों पर दबाव

छत्तीसगढ़ में नक्सली संगठनों के गढ़ में पहुंचकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सलियों से आत्मसमर्पण करने की अपील करते हुए यह जो कहा कि उनके समक्ष इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, वह कहना इसलिए आवश्यक था, क्योंकि नक्सली अब भी मुख्यधारा में लौटने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। इन स्थितियों में यही उचित होगा कि उनके आत्मसमर्पण की राह खुली रखने के साथ ही उन पर निरंतर दबाव बनाए रखा जाए। उनके सामने यह बार-बार स्पष्ट करना होगा कि वे बंदूक के बल पर सत्ता एवं व्यवस्था परिवर्तन का जो सपना देख रहे हैं, वह कभी पूरा होने वाला नहीं है। केंद्रीय गृहमंत्री पिछले कुछ समय से यह दोहरा रहे हैं कि केंद्र सरकार मार्च 2026 तक नक्सलवाद की समस्या को पूरी तरह खत्म कर देगी। इस लक्ष्य को पाने के लिए जहां यह आवश्यक है कि नक्सल प्रभावित राज्यों की सरकारें केंद्र सरकार का पूरा सहयोग करें, वहीं नक्सलियों के प्रभाव वाले इलाकों में विकास एवं जनकल्याण की योजनाएं तेजी से आगे बढ़ाई जाएं। ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए, ताकि नक्सली संगठन और उनके वैचारिक समर्थक कहे जाने वाले तत्व यानी अर्बन नक्सल यह दुष्प्रचार न करने पाएं कि दूरदराज के इलाकों में शासन विकास पर ध्यान नहीं देता। वैसे इस दुष्प्रचार की कलई खुल चुकी है और यह साबित हो चुका है कि नक्सली ही ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों में बाधक बने हुए हैं।

यह किसी से छिपा नहीं कि नक्सली किस तरह अपने इलाकों में सड़कें नहीं बनने देते और स्कूलों एवं अस्पतालों के निर्माण में अड़ंगा लगाते हैं। उनकी इन्हीं हरकतों के चलते इसका पर्दाफाश हो चुका है कि वे निर्धन तबकों के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वास्तव में वे इन वर्गों के हितों की रक्षा में सबसे अधिक बाधक बनकर उभरे हैं और इसीलिए उनका प्रभाव कम होता चला जा रहा है। यह उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ वर्षों में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। 2019 में नक्सली हिंसा से प्रभावित जिलों की संख्या 90 थी। अब यह संख्या 40 से भी कम रह गई है। इस संख्या में और अधिक कमी तब आएगी, जब नक्सलियों को यह महसूस होगा कि उनके छिपने के लिए कोई जगह नहीं रह गई है। शायद तभी वे अपने निरर्थक संघर्ष को विराम देने के लिए तैयार होंगे। जब तक वे ऐसा नहीं करते, तब तक उनके खिलाफ कठोरता का परिचय देने में संकोच नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए और भी नहीं, क्योंकि वे जब-तब सुरक्षा बलों को निशाना बनाते रहते हैं। यह सही है कि नक्सलियों की ताकत कम हुई है, लेकिन उनके खिलाफ अभियान इसलिए जारी रहना चाहिए, ताकि वे नए सिरे से खुद को संगठित न कर सकें। नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान के तहत यह अवश्य देखा जाना चाहिए कि उन तक आधुनिक हथियार कैसे पहुंच रहे हैं।

हिमाचल के हित में

पिछले कुछ समय से देश-प्रदेश की राजनीति में मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का जो चलन चला है, वह अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए घातक साबित हो सकता है। विभिन्न प्रकार की सब्सिडी भी इसी श्रेणी में आती है। अगर इस राशि को बचाकर जनहित के कार्यों में लगाया जाए तो प्रदेश एवं देश के विकास को और गति मिलेगी। कर्ज के बोझ के तले दबे हिमाचल को पटरी पर लाने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने साहस दिखाया है और कड़वे निर्णय लिए जा रहे हैं। रविवार को मुख्यमंत्री का यह कहना कि टैक्स देने वालों को सब्सिडी नहीं मिलेगी, प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है। यह बिल्कुल सही है कि अगर कोई करदाता है तो उसे बिजली, पानी की सब्सिडी लेने की क्या आवश्यकता। सब्सिडी का लाभ उन्हीं वर्गों को मिलना चाहिए, जो वास्तव में पात्र हैं। प्रदेश सरकार ने पहले ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त में दिए जा रहे पानी की सुविधा बंद की। सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ही सब्सिडी मिलेगी जबकि बाकी लोगों को भुगतान करना पड़ेगा। इसी तरह 125 यूनिट निश्शुल्क बिजली के दायरे से करदाताओं बाहर करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उद्योगों को बिजली पर दी जा रहे प्रति यूनिट एक रुपये की सब्सिडी भी बंद की गई। अभी इन निर्णयों का विरोध हो सकता है, लेकिन दीर्घकाल में इनके अच्छे परिणाम सामने आना तय है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए हर पक्ष को इसमें सहयोग करना होगा। यह इसलिए भी आवश्यक है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था कर्ज और केंद्रीय सहायता पर अधिक निर्भर है। छोटी-छोटी बचत से आर्थिक चुनौतियों से पार पाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

प्रदेश सरकार का टैक्स देने वालों को सब्सिडी के दायरे से बाहर करने का निर्णय उचित है

सिर उठाता परिसीमन का प्रश्न

डा. एके वर्मा

जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को कुछ अतिरिक्त लोकसभा सीटें आवंटित होनी चाहिए

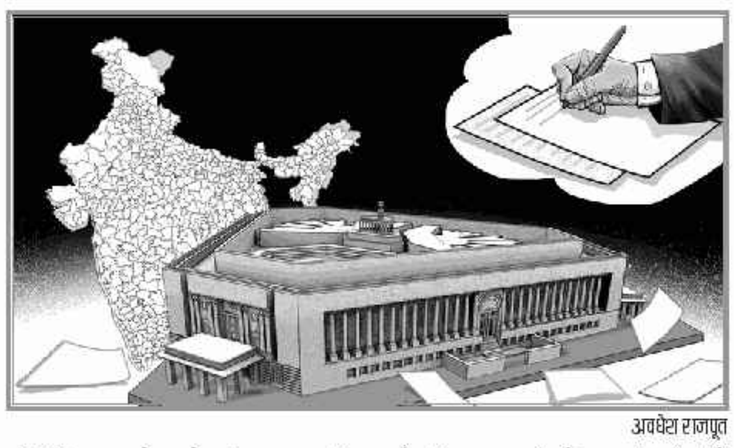

अवधेश राजपूत

देश में चुनावों पर चर्चा होती है, लेकिन चुनाव इकाइयों अर्थात निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर चर्चा नहीं होती। प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन कराने का प्रविधान है। संविधान (अनु.327) संसद को परिसीमन का अधिकार देता है, जिसमें दो बड़े मुद्दे हैं-प्रथम, लोकसभा और विधानसभाओं में कितने-कितने जनप्रतिनिधि होने चाहिए? दूसरा, लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं, उनके आकार-प्रकार में क्या कोई बदलाव जरूरी है? संविधान संसद को अधिकार देता है कि वह उपरोक्त दोनों मुद्दों के समाधान हेतु अभिकरण बनाए और परिसीमन प्रक्रिया निर्धारित करे। प्रथम लोकसभा और विधानसभा चुनावों हेतु परिसीमन राष्ट्रपति कार्यालय ने किया। संसद ने 1952 में प्रथम परिसीमन आयोग का गठन किया, जिसने 1957 के चुनावों हेतु परिसीमन किया। उसके बाद 1962 और 1972 में द्वितीय और तृतीय परिसीमन आयोगों ने 1971 एवं 1972 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर 42वें संविधान संशोधन द्वारा अगले 25 वर्ष तक परिसीमन पर रोक लगा दी। फलतः 1981 और 1991 में परिसीमन नहीं हो सका। संसद द्वारा 2002 में चतुर्थ परिसीमन आयोग का गठन हुआ, लेकिन 84वें संविधान संशोधन (2001) द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में सांसदों और विधायकों की संख्या बढ़ाने पर 2026 के बाद होने वाली जनगणना तक इस आधार पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि 2026 तक देश में जन्मदर और मृत्युदर बराबर हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फलतः चतुर्थ परिसीमन आयोग केवल आंशिक परिसीमन कर सका।

1972 के बाद पचास वर्षों से अधिक समय से पूर्ण परिसीमन नहीं हुआ है। आज देश की जनसंख्या चीन से ज्यादा हो गई है, पर सांसदों और विधायकों की संख्या नहीं बढ़ी। इससे सांसद और विधायक अत्यधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक सांसद औसतन 25 लाख और विधायक पांच-सात लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जबकि इंग्लैंड के सांसद एक लाख और अमेरिका के सात लाख लोगों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः आगामी परिसीमन आयोग द्वारा सांसदों और विधायकों की संख्या बढ़ाने का प्रतिवेदन जरूरी है। जनप्रतिनिधियों की संख्या न बढ़ने से दूसरी समस्या यह है कि प्रतिनिधित्व की समानता का सिद्धांत ध्वस्त हो गया है। ज्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद के मत का मूल्य वही है, जो कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद का। यदि केवल जनसंख्या को परिसीमन और सीटों के आवंटन का आधार बनाया जाएगा, तो वे राज्य दंडित होंगे, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है। आगामी परिसीमन में अनुमानतः कर्नाटक में 8, तेलंगाना और आंध्र में 3-3, तमिलनाडु में 2 सीटें बढ़ेंगी, जबकि केरल में एक लोकसभा सीट घट सकती है। वहीं मध्य प्रदेश में 18, राजस्थान में 19, महाराष्ट्र में 20, बिहार में 30 और उत्तर प्रदेश में 48 सीटें बढ़ सकती हैं। आगामी परिसीमन में जनसंख्या नियंत्रण और 'प्रतिनिधित्व की समानता' में संतुलन चुनौतीपूर्ण होगा।

परिसीमन में लोकसभा की सीटें बढ़ना तय हैं। मोदी सरकार ने दूरदर्शिता से नई संसद का निर्माण कराया, जिसमें 888 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन राज्यों ने इस पर अभी ध्यान नहीं दिया है। लोकसभा में करीब डेढ़-दो सौ सीटें बढ़ना तय है। युवाओं को इसका लाभ लेना चाहिए। पीएम मोदी ने युवाओं से राजनीति में आने का आह्वान भी किया है। नारीशक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं हेतु लोकसभा और विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें आरक्षित की गई हैं। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या पर 181 महिला सीटें आरक्षित होंगी और यदि परिसीमन से न्यूनतम 150 लोकसभा सीटें भी बढ़ती हैं, तो लोकसभा में 231 महिला सीटें आरक्षित होंगी, जिसका लाभ महिलाओं को मिलेगा। एससी-एसटी की आरक्षित सीटों में भी वृद्धि होगी, क्योंकि अनु. 330(2) के अनुसार प्रत्येक राज्य को आवंटित सीटों में एससी और एसटी के लिए उसी अनुपात में सीटें आरक्षित होंगी, जो अनुपात उनका राज्य की आबादी में होगा। जब 2006 में आंशिक परिसीमन हुआ था, तब लोकसभा सीटों के बढ़ने पर तो प्रतिबंध था, पर एससी की आरक्षित सीटें 79 से बढ़कर 84 और एसटी की सीटें 41 से बढ़ कर 47 हो गई थीं। अगले परिसीमन में यह संख्या और बढ़ेगी।

आगामी परिसीमन आयोग को या तो लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या तय कर उन्हें राज्यों को आवंटित करने का फार्मूला बनाना होगा या यह तय करना होगा कि 2026 में भारत की अनुमानित जनसंख्या एक अरब 42 करोड़ में कोई सांसद अधिकतम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। इसके आधार पर ही लोकसभा सीटों की संख्या निर्धारित होगी। संसद को परिसीमन आयोग अधिनियम 2026 में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि आयोग संवैधानिक प्रविधानों का अनुपालन करते हुए जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को पुरस्कृत कर उनको कुछ अतिरिक्त लोकसभा सीटें आवंटित करे। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि परिसीमन में अपने यहां लोकसभा सीटों की संख्या में कटौती की आशंका के कारण दक्षिण के कुछ राज्य जनसंख्या बढ़ाने की अपील कर रहे हैं।

पूर्ववर्ती परिसीमन आयोगों ने यह नहीं बताया कि उन्होंने किस फार्मूले के आधार पर परिसीमन किया। आयोग में प्रत्येक राज्य से पांच सांसद और विधायक क्रमशः लोकसभा और विधानसभाओं के स्पीकर द्वारा नामित किए जाते हैं, पर वे भी परिसीमन प्रक्रिया की बारीकियों को नहीं जानते या जानना नहीं चाहते। उन्हें अपना निर्वाचन क्षेत्र बचाने की ही चिंता होती है। अतः अगले परिसीमन आयोग को कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के साथ ही विषय विशेषज्ञों को भी परामर्श प्रक्रिया में सम्मिलित करना होगा। इससे परिसीमन में जानबूझकर या अनजाने में होने वाली गलतियों से बचा जा सकता है। परिसीमन में पारदर्शिता और परामर्श इसलिए और जरूरी है, क्योंकि अनु.329 परिसीमन आयोग के निर्णयों में न्यायपालिका हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देता।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं सेंटर फार द स्टडी आफ सोसायटी एंड पालिटिक्स के निदेशक हैं)
response@jagran.com

संगीत और संस्कृति के महान साधक

जाकिर हुसैन के निधन से भारत ने एक महान तबलावादक, शास्त्रीय संगीत के विख्यात फनकार और भारतीय संस्कृति के प्रसारक को खो दिया। वह जितने बड़े कलाकार थे, उतने ही बेहतरीन इंसान। उन्होंने बचपन से ही तबला वादन शुरू कर दिया था और कम उम्र में शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए थे। उन्होंने तमाम दिग्गज कलाकारों के साथ प्रस्तुतियां दीं-देश में भी और विदेश में भी। उन्होंने अपने पिता की पीढ़ी के दिग्गज फनकारों के साथ भी काम किया और नई पीढ़ी के उभरते कलाकारों के साथ भी। उन्होंने तबले को देश और दुनिया में पहचान तो दिलाई ही, उसे लोकप्रिय बनाने का भी काम किया। उनका नाम तबले का पर्याय बन गया था और पूरी दुनिया उनके नाम से परिचित थी। वह उस्ताद कहलाते थे, लेकिन खुद को सदैव शागिर्द मानते थे। वह इतने प्रतिभाशाली थे कि उन्होंने सात साल की उम्र में अपना पहला कंसर्ट किया और 12 साल की उम्र से विदेश में कार्यक्रम करने शुरू कर दिए।

जाकिर हुसैन बेहद हंसमुख और मिलनसार इंसान थे। वह जितना आदर बड़ों को देते थे, उतना ही छोटों को प्यार देते थे। मुझे याद है कि करीब दो वर्ष पहले दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने बेहद आत्मीयता से बात की। कार्यक्रम के बाद उनसे मिलना मुश्किल होता था। इसलिए मैं उनसे कार्यक्रम के पहले ही मिलना पसंद करता। वह हम जैसे कलाकारों से मिलते समय ऐसा जताते कि हमें अच्छे से जानते हैं। यदि कोई अपने बारे में बताने लगता तो कहते कि हां भाई, मैं आपको अच्छे से जानता हूं और आपसे मिल चुका हूं। वह उस जमाने में तबला वादक के रूप में स्टार बन गए थे, जब इंटरनेट मीडिया का चलन नहीं था और संगीत जगत और खासकर शास्त्रीय संगीत में नाम कमाना एक मुश्किल काम था। वह केवल तबला वादन में ही दक्ष नहीं थे, वह शास्त्रीय संगीत की अन्य विधाओं से भी अच्छी तरह परिचित थे। वह जिस भी काम में रुचि दिखाते, उसमें महारत हासिल कर लेते। वह हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तत्पर रहते थे और अपने शिष्यों से कहते थे कि गुरु से जो सीखें, उससे इतर भी कुछ नया करने की कोशिश करें। वह जबरदस्त कलाकार थे। मैं जब भी उनसे मिला, उनसे कुछ न कुछ सीखने को मिला। वह जहां भी जाते, खुद को वहां के माहौल में ढाल लेते। वह विदेश में भी स्टार कलाकार का दर्जा रखते थे। उन्होंने विदेश में भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार में जैसी भूमिका निभाई, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। उनकी संगीत साधना और जीवन भारतीय संस्कृति का परिचायक था।

जाकिर हुसैन के पिता भी विख्यात तबला वादक थे, लेकिन तबला वादन में चार चांद लगाने का काम उन्होंने ही किया

वसीफुद्दीन डागर

खुद को सदैव शागिर्द मानने वाले उस्ताद। एएनआइ

जाकिर हुसैन जितने भारत में लोकप्रिय थे, उतने ही विदेश में भी। पश्चिम में उनकी पहचान एक महान भारतीय संगीतकार के रूप में भी थी। उन्होंने कुछ फिल्मों में संगीत भी दिया। इनमें हिंदी फिल्में भी हैं और हालीवुड फिल्में भी। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी की फिल्मों में अभिनय भी किया। उनका कहना था कि उन्होंने अभिनय इसलिए किया, क्योंकि कुछ नया सीखना चाहते थे। वह अमेरिका में बस गए थे। वह वहां युवाओं को तबला वादन सिखाते थे और भारतीय संगीत के बारे में पढ़ाते थे। वह हमेशा कहते थे कि भारत एक प्राचीन देश है और उसके पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। वह यह मानते थे कि देवी सरस्वती की उन पर खास कृपा है। उनका यह किस्सा खूब प्रचलित है कि उनके जन्म के बाद उनके पिता ने किस तरह उनके कान में तबले की थाप सुनाई थी, जबकि रिवाज यह है कि बच्चे के जन्म के बाद उसके कान में अजान सुनाई जाती है। उनके पिता उस्ताद अल्लारक्खा का कहना था कि हमारी इबादत तो देवी सरस्वती की आराधना है। आम लोग भले ही ज्ञान की देवी सरस्वती की आराधना खास अवसरों पर करते हों, लेकिन हम जैसे शास्त्रीय संगीत के साधक तो हर दिन उनकी आराधना करते हैं और यह मानते हैं कि उनके दिए हुए ज्ञान से ही हम कुछ हासिल कर सके। उनके पिता भी विख्यात तबला वादक थे, लेकिन मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि तबला वादन में चार चांद लगाने का काम जाकिर हुसैन ने किया। वह संगीत को आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत मानते थे। उनका कहना था कि संगीत विश्व में शांति ला सकता है और अच्छाई एवं सच्चाई सब तक पहुंचा सकता है। उन्हें यह पता रहता था कि शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में कहां कौन बेहतर कर रहा है और कहां कौन से वाद्ययंत्र बनते हैं। एक बार फेस्टिवल आफ इंडिया के तहत जेनेवा में आयोजित एक कार्यक्रम में डागर बंधुओं और पंडित शिवकुमार शर्मा के साथ जाकिर हुसैन की प्रस्तुति होनी थी। अपने गुरुओं के साथ मैं भी वहां था। कार्यक्रम के पहले कुछ स्थानीय लोग डमरुनुमा वाद्ययंत्र लेकर आए और जाकिर हुसैन से बोले, यह भी नए तरह का तबला है। उन्होंने वह बजाया और फिर उन्हें समझाया कि यह वाद्ययंत्र कैसे तबला से अलग है और उसकी खासियत क्या है?

जाकिर हुसैन भारतीय और पश्चिमी संगीत में संगम यानी फ्यूजन का माध्यम भी बने। वह भारतीय और पश्चिमी शास्त्रीय संगीत को अलग-अलग करके नहीं देखते थे। उनका कहना था कि उनकी नजर में संगीत एक ही है। जाकिर हुसैन को एक ओर जहां पद्मश्री, पद्म भूषण, और पद्म विभूषण जैसे सम्मान मिले, वहीं ग्रैमी पुरस्कार भी। एक साथ तीन ग्रैमी जीतने वाले वह पहले भारतीय संगीतकार बने। उन्होंने भारतीय संगीतज्ञ के रूप में जैसा मुकाम हासिल किया, उसके चलते वह हम सबके प्रेरणास्रोत थे, हैं और बने रहेंगे।

(लेखक विख्यात ध्रुपद गायक हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

स्वांत: सुखाय

कुछ कार्य केवल निजी आनंद या आत्मतुष्टि के उद्देश्य से किए जाते हैं, जिन्हें 'स्वांतः सुखाय' की श्रेणी में रखा जाता है। स्वांतः सुखाय का रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने समावेश करते हुए आशय भी स्पष्ट किया है कि इस रचना का सृजन मैं अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए कर रहा हूं। प्रायः कोई भी कार्य प्रारंभ करते समय लोक आलोचना का विचार मन को आंदोलित करता रहता है कि इस पर जनमानस की क्या प्रतिक्रिया होगी। उसे सराहना मिलेगी अथवा आलोचना का शिकार होना पड़ेगा। बहुत बार इसी संकोच में या तो कार्य आरंभ ही नहीं किए जाते अथवा उन्हें अधूरा छोड़ दिया जाता है, किंतु स्वांतः सुखाय के उद्देश्य को सामने रखकर किए जाने वाले कार्य इसके अपवाद होते हैं। उन्हें करते समय किसी आलोचना अथवा सराहना की परवाह मन में नहीं रहती। यदि स्वांतः सुखाय से संबंधित कार्यों को बहुजन हिताय हेतु से भी संबद्ध कर लिया जाए तो यह सोने पर सुहागा सिद्ध होगा जो न केवल आत्मसंतुष्टि देगा, वरन जनकल्याणकारी होकर आत्मसंतुष्टि के स्तर को द्विगुणित करने का सुयोग भी उपलब्ध कराएगा।

ऐसे अनेक उदाहरण रहे हैं जहां आरंभ में कर्ता को उपहास का शिकार होना पड़ा, किंतु अपने मानसिक संकल्प के दम पर अंततः वह इतिहास रचने में सफल हुए और बाद में उनके कार्यों, प्रयासों और उपलब्धियों को सराहा गया। स्मरण रहे कि दृढ़संकल्प के साथ और बिना यह विचारे कि लोग क्या कहेंगे, उससे बेपरवाह होकर लक्ष्य प्राप्ति के लिए पूरे समर्पण भाव से कार्य करने की जीवटता के साथ आगे बढ़ा जाए तो सफलता भी अवश्यंभावी है और स्वांतः सुखाय की अनुभूति होना भी निश्चित है। फिर भी, कभी असफलता ही मिले तो वह भी एक उपलब्धि ही होगी, क्योंकि तब एक अनुभव की सार्थकता सुलभ होगी जो आगे पथ प्रदर्शन में सहायक सिद्ध होगी।

एसएन दुबे 'स्नेही'

समुद्री व्यापार का अगुआ था भारत

शुभम केवलिया

संपूर्ण जगत को सर्वप्रथम समुद्री मार्ग से व्यापार करना भारतीयों ने ही आज से 4500 वर्ष पूर्व सिखाया था

किसी भी राष्ट्र की उन्नति का मार्ग विदेशी व्यापार ही प्रशस्त करता है। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था का आधार भी विदेशी व्यापार ही है। उल्लेखनीय है कि भारत का 95 प्रतिशत विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। वैसे तो समुद्र को लांघकर व्यापार करने का प्रचलन अत्यंत प्राचीन है, परंतु संपूर्ण जगत को सर्वप्रथम समुद्री मार्ग से व्यापार करना भारतीयों ने ही आज से 4500 वर्ष पूर्व सिखाया था। भारत की प्राचीनतम सरस्वती-सिंधु सभ्यता के चरमोत्कर्ष का कारण भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार ही था, जो प्रायः समुद्री मार्ग से होता था। यूं तो उस सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, परंतु पुरातात्विक साक्ष्य भारत की प्राचीन सभ्यता में समुद्री मार्ग से होने वाले व्यापार के प्रमाण उपलब्ध करवाते हैं।

वर्तमान गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित लोथल नामक पुरास्थल इस सभ्यता के समुद्र द्वारा होने वाले अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख केंद्र था। लोथल से हमें एक विशाल गोदी बाड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसका निर्माण पकी ईंटों द्वारा किया गया था। यह एक नहर के माध्यम से समुद्र से जुड़ा हुआ था। 4500 वर्ष पूर्व निर्मित इस गोदी के अंदर किए गए उत्खनन से पांच लंगर प्राप्त हुए हैं। इस गोदी के भीतर जहाज लंगर डाल कर खड़े किए जाते थे। इससे इस बात का आंकलन किया जा सकता है कि सरस्वती-सिंधु सभ्यता में विशाल जहाजों का निर्माण किया जाता था। जहाज पर माल लाद कर फारस की खाड़ी होते हुए मेसोपोटामिया तक जाता था। लोथल के अतिरिक्त कुंतासी, पादरी, नागेश्वर, बगसरा, नगवाड़ा, देसलपुर आदि से भी समुद्री व्यापार किया जाता था। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से एक मुहर प्राप्त हुई है जिस पर जहाज का अंकन है। इस पर दो पक्षियों का भी अंकन है। विद्वानों का ऐसा मत है कि पक्षियों का उपयोग संभवतः समुद्र के मध्य में दिशाओं का ज्ञान करने के लिए होता था।

उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष यह बताते हैं कि सरस्वती-सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा कपास के कपड़ों का निर्यात किया जाता था। सुमेरियन सभ्यता के प्राचीन नगर उम्मा से कपास के कपड़े की एक गांठ प्राप्त हुई है। इस पर सरस्वती-सिंधु सभ्यता की मुहर लगी हुई है। भारत से उस काल में पत्थरों के बने मनके भी निर्यात किए जाते थे। उर नामक पुरास्थल से मिले हाथी दांत से निर्मित कंघे भी भारत से ही निर्यात किए गए थे। लोथल से प्राप्त फारस की खाड़ी की एक मुहर भी द्विपक्षीय व्यापार की संकेतक है। भारत के इस उन्नत इतिहास को आज विश्व पटल पर स्थापित करने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा भारत के मैरिटाइम हेरिटेज पर करवाया जा रहा प्रथम कांक्लेव निश्चित तौर पर भारतीय इतिहास के इस पहलू को जनमानस से परिचित करवाएगा।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

संतुलित हो कानून का रवैया

'बदला लेने का जरिया बने कानून' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में दीपिका नारायण भारद्वाज ने इस विषय पर विभिन्न संदर्भों में प्रकाश डाला। झूठे मुकदमे न केवल निर्दोषों का शोषण करते हैं, बल्कि कानून की विश्वसनीयता को भी कमजोर करते हैं। महिला सुरक्षा के लिए बने कानून जब न्याय देने के बजाय प्रतिशोध का जरिया बन जाएं, तो समाज में असंतुलन पैदा होना तय है। अखबारों और अदालतों में झूठे केसों की भरमार ने यह साबित कर दिया है। कानूनी संरक्षण के नाम पर निर्दोष व्यक्तियों का उत्पीड़न न्याय के मूल सिद्धांतों को आघात पहुंचाता है। कुछ आंकड़े बताते हैं कि धारा 498 ए के तहत दर्ज मामलों में से अधिकांश में आरोपित निर्दोष पाए जाते हैं। इस समस्या के समाधान हेतु ठोस कानूनी सुधार आवश्यक हैं। सबसे पहले, झूठे मुकदमों की जांच के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष तंत्र की स्थापना होनी चाहिए। पुलिस को चाहिए कि वह बिना किसी साक्ष्य के मामले दर्ज न करे। साथ ही, यदि आरोप झूठे साबित हों तो शिकायतकर्ता पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, कानूनी साक्षरता अभियान चलाकर लोगों को यह समझाना जरूरी है कि कानून का उद्देश्य न्याय प्रदान करना है, न कि किसी का चरित्र हनन या आर्थिक हानि करना। महिलाएं समाज का सशक्त स्तंभ हैं, परंतु जब कानून का दुरुपयोग कर एक वर्ग को प्रताड़ित किया जाता है, तो इससे सामाजिक असंतुलन उत्पन्न होता है। न्यायालयों और विधि विशेषज्ञों को इस समस्या पर गहन विचार करना होगा ताकि कानून का उपयोग वास्तविक पीड़ितों के लिए हो और झूठे मुकदमों की प्रवृत्ति पर रोक लगे।

awanishg30@gmail.com

मेलबाक्स

हिंदू नहीं भूलेंगे अपमान

'प्लेसेज आफ वरशिप एक्ट 1991' द्वारा हिंदुओं से अपेक्षा की गई है कि वे अपने देवालयों के ध्वस्त होने के राष्ट्रीय अपमान को भूल जाएं। कितना हास्यास्पद है भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं से यह अपेक्षा कि वे 1947 से पहले की अपनी संस्कृति को जानने का प्रयास भी न करें, वे अपने समृद्धशाली भवन निर्माण कला को न खोजें। इस एक्ट द्वारा हिंदुओं से उसी का इतिहास जानने को अधिकार छिन लिया गया। उसे अपने राष्ट्रीय और आत्म सम्मान के स्मारकों, अपनी श्रद्धा के स्मारकों को ध्वस्त करने वाले गुनहगारों को जानने का भी अधिकार नहीं, उसे अपने आस्थास्थलों, उपासनास्थलों, राष्ट्रीय गौरव के स्मारकों को संवैधानिक प्रकार से न्यायालय के माध्यम से प्राप्त करने का भी अधिकार नहीं। डा. आंबेडकर ने संविधान की रचना करते समय हिंदुओं से उनके ये मौलिक अधिकार नहीं छिने थे। बाबा साहब ने तो किसी के कोर्ट में जाने के अधिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था। कितना विकृत कर दिया कांग्रेस ने उस संविधान को जो बाबा साहब के राष्ट्रीय सोच का दर्पण था। क्या भारत के राष्ट्रवादी विचारकों, बहुसंख्यक हिंदुओं, गंगा-जमुनी तहजीब के वाहकों को यह राष्ट्रीय अपमान का विष स्वीकार होगा!

विपिन गोयल, हापुड़

विकसित भारत का सपना

संसद में दो दिन संविधान पर चर्चा हुई।। प्रधानमंत्री द्वारा 11 संकल्प गिनाए गए। उनमें विकसित भारत का सपना और नागरिकों के कर्तव्यों तथा अधिकारों के संतुलन की भविष्योन्मुखी व्याख्या की गई। इसके अलावा अंत तक विपक्ष और सत्ता पक्ष पुरानी बातों को दोहराते रहे और एक दूसरे पर एक चुनावी सभा की भांति आरोप दोहराते रहे। अच्छा होता, ये दो दिन इस सार्थक चर्चा में जाते कि वर्तमान देशकाल परिस्थिति तथा वैश्विक वातावरण के अनुसार हमें संविधान के दायरे में रहते हुए-किन योजनाओं, कानूनों, नीतियों का निर्माण करना चाहिए या किन संशोधनों की संविधान को आवश्यकता है। वैसे भी संसद चलती नहीं है और अगर चलती भी है कुछ घंटे, तो माननीय सांसद, पार्टियां भूत काल को याद करते हैं, पर देश के भविष्य की बुनियाद के निर्माण हेतु जरूरी विचारों के मंथन का अभाव रहता है। ऐसे में विकसित भारत का सपना कहीं सपना बनकर न रह जाए।

पीयूष शंकर गर्ग, गाजियाबाद

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए; नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

संपादकीय जागरण

(12) मंगलवार, 17 दिसंबर, 2024 : पौष कृष्ण - 2 वि. 2081

सीमित आकांक्षाओं में ही असीमित सुख का सार निहित है

नक्सलियों पर दबाव

छत्तीसगढ़ में नक्सली संगठनों के गढ़ में पहुंचकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सलियों से आत्मसमर्पण करने की अपील करते हुए यह जो कहा कि उनके समक्ष इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, वह कहना इसलिए आवश्यक था, क्योंकि नक्सली अब भी मुख्यधारा में लौटने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। इन स्थितियों में यही उचित होगा कि उनके आत्मसमर्पण की राह खुली रखने के साथ ही उन पर निरंतर दबाव बनाए रखा जाए। उनके सामने यह बार-बार स्पष्ट करना होगा कि वे बंदूक के बल पर सत्ता एवं व्यवस्था परिवर्तन का जो सपना देख रहे हैं, वह कभी पूरा होने वाला नहीं है। केंद्रीय गृहमंत्री पिछले कुछ समय से यह दोहरा रहे हैं कि केंद्र सरकार मार्च 2026 तक नक्सलवाद की समस्या को पूरी तरह खत्म कर देगी। इस लक्ष्य को पाने के लिए जहां यह आवश्यक है कि नक्सल प्रभावित राज्यों की सरकारें केंद्र सरकार का पूरा सहयोग करें, वहीं नक्सलियों के प्रभाव वाले इलाकों में विकास एवं जनकल्याण की योजनाएं तेजी से आगे बढ़ाई जाएं। ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए, ताकि नक्सली संगठन और उनके वैचारिक समर्थक कहे जाने वाले तत्व यानी अर्बन नक्सल यह दुष्प्रचार न करने पाएं कि दूरदराज के इलाकों में शासन विकास पर ध्यान नहीं देता। वैसे इस दुष्प्रचार की कलई खुल चुकी है और यह साबित हो चुका है कि नक्सली ही ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों में बाधक बने हुए हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि नक्सली किस तरह अपने इलाकों में सड़कें नहीं बनने देते और स्कूलों एवं अस्पतालों के निर्माण में अड़ंगा लगाते हैं। उनकी इन्हीं हरकतों के चलते इसका पर्दाफाश हो चुका है कि वे निर्धन तबकों के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वास्तव में वे इन वर्गों के हितों की रक्षा में सबसे अधिक बाधक बनकर उभरे हैं और इसीलिए उनका प्रभाव कम होता चला जा रहा है। यह उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ वर्षों में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। 2019 में नक्सली हिंसा से प्रभावित जिलों की संख्या 90 थी। अब यह संख्या 40 से भी कम रह गई है। इस संख्या में और अधिक कमी तब आएगी, जब नक्सलियों को यह महसूस होगा कि उनके छिपने के लिए कोई जगह नहीं रह गई है। शायद तभी वे अपने निरर्थक संघर्ष को विराम देने के लिए तैयार होंगे। जब तक वे ऐसा नहीं करते, तब तक उनके खिलाफ कठोरता का परिचय देने में संकोच नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए और भी नहीं, क्योंकि वे जब-तब सुरक्षा बलों को निशाना बनाते रहते हैं। यह सही है कि नक्सलियों की ताकत कम हुई है, लेकिन उनके खिलाफ अभियान इसलिए जारी रहना चाहिए, ताकि वे नए सिरे से खुद को संगठित न कर सकें। नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान के तहत यह अवश्य देखा जाना चाहिए कि उन तक आधुनिक हथियार कैसे पहुंच रहे हैं।

गुणवत्ता जरूरी

श्रम संसाधन विभाग ने राज्य के सभी 149 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता की मानीटरिंग पर काम करना शुरू कर दिया है। विभाग ने जनवरी के पहले सप्ताह तक एक ऐसा पोर्टल तैयार करने की पहल की है, जो इन संस्थानों की शिक्षण की गुणवत्ता की परख करेगा। इस पोर्टल पर प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा जानकारियां दर्ज की जाएंगी। इन आवश्यक सूचनाओं की मुख्यालय स्तर पर हर माह समीक्षा की जाएगी। इससे यह पता चल सकेगा कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में किस तरह के कुशल तकनीशियन तैयार किए जा रहे हैं। चूंकि इन संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे लोगों के लिए रोजगार के व्यापक अवसर हैं। यदि उनकी शिक्षा की गुणवत्ता ठीक नहीं रहेगी तो इसका वे पूरा लाभ नहीं उठा सकेंगे। विभाग की यह भी कोशिश है कि इन संस्थानों में शार्ट टर्म कोर्स भी चलाए जाएं। फिलहाल सोलर तकनीशियन की संभावनाएं बढ़ी हैं। बिजली के उत्पादन में सोलर के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। आम जरूरतों के उपकरण बाजार में विविधताओं के साथ हैं। यदि कोई व्यक्ति सोलर तकनीशियन का प्रशिक्षण प्राप्त कर ले तो रोजगार के द्वार खुल सकते हैं। केंद्र से लेकर राज्य सरकार के स्तर पर सौर ऊर्जा के उपयोग को लेकर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आने वाला समय सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले उपकरणों का है। इसे ध्यान में रखकर ज्यादा से ज्यादा सोलर तकनीशियन तैयार करने पर बल देने की जरूरत है। इन संस्थानों में प्लंबर के कोर्स भी कराए जाते हैं। इस क्षेत्र में भी व्यापक संभावना है। इसके साथ-साथ अन्य पाठ्यक्रम भी ऐसे हैं, जो स्वरोजगार के साथ-साथ नौकरी के दरवाजे भी खोलते हैं।

सोलर उपकरणों के बढ़ते उपयोग को देखते हुए इसके ज्यादा से ज्यादा तकनीशियन तैयार करने की जरूरत है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या वीर सावरकर पर राहुल गांधी की टिप्पणी शिवसेना-यूबीटी की मुश्किलें बढ़ाएगी?

आज का सवाल
ब्रिसबेन टेस्ट में भारतीय टीम पर हार का खतरा मंडरा रहा है?

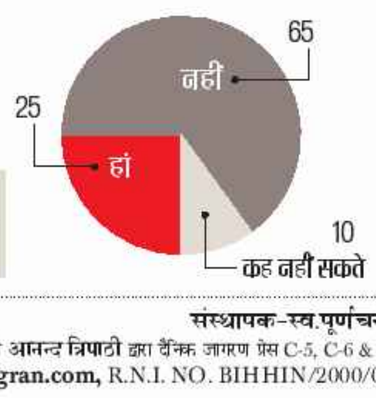

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

सिर उठाता परिसीमन का प्रश्न

डा. एके वर्मा

जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को कुछ अतिरिक्त लोकसभा सीटें आवंटित होनी चाहिए

देश में चुनावों पर चर्चा होती है, लेकिन चुनाव इकाइयों अर्थात निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर चर्चा नहीं होती। प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन कराने का प्रविधान है। संविधान (अनु.327) संसद को परिसीमन का अधिकार देता है, जिसमें दो बड़े मुद्दे हैं- प्रथम, लोकसभा और विधानसभाओं में कितने-कितने जनप्रतिनिधि होने चाहिए? दूसरा, लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं, उनके आकार-प्रकार में क्या कोई बदलाव जरूरी है? संविधान संसद को अधिकार देता है कि वह उपरोक्त दोनों मुद्दों के समाधान हेतु अभिकरण बनाए और परिसीमन प्रक्रिया निर्धारित करे। प्रथम लोकसभा और विधानसभा चुनावों हेतु परिसीमन राष्ट्रपति कार्यालय ने किया। संसद ने 1952 में प्रथम परिसीमन आयोग का गठन किया, जिसने 1957 के चुनावों हेतु परिसीमन किया। उसके बाद 1962 और 1972 में द्वितीय और तृतीय परिसीमन आयोगों ने 1971 एवं 1972 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर 42वें संविधान संशोधन द्वारा अगले 25 वर्ष तक परिसीमन पर रोक लगा दी। फलतः 1981 और 1991 में परिसीमन नहीं हो सका। संसद द्वारा 2002 में चतुर्थ परिसीमन आयोग का गठन हुआ, लेकिन 84वें संविधान संशोधन (2001) द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में सांसदों और विधायकों की संख्या बढ़ाने पर 2026 के बाद होने वाली जनगणना तक इस आधार पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि 2026 तक देश में जन्मदर और मृत्युदर बराबर हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फलतः चतुर्थ परिसीमन आयोग केवल आंशिक परिसीमन कर सका।

1972 के बाद पचास वर्षों से अधिक समय से पूर्ण परिसीमन नहीं हुआ है। आज देश की जनसंख्या चीन से ज्यादा हो गई है, पर सांसदों और विधायकों की संख्या नहीं बढ़ी। इससे सांसद और विधायक अत्यधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक सांसद औसतन 25 लाख और विधायक पांच-सात लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जबकि इंग्लैंड के सांसद एक लाख और अमेरिका के सात लाख लोगों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः आगामी परिसीमन आयोग द्वारा सांसदों और विधायकों की संख्या बढ़ाने का प्रतिवेदन जरूरी है। जनप्रतिनिधियों की संख्या न बढ़ने से दूसरी समस्या यह है कि प्रतिनिधित्व की समानता का सिद्धांत ध्वस्त हो गया है। ज्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद के मत का मूल्य वही है, जो कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद का। यदि केवल जनसंख्या को परिसीमन और सीटों के आवंटन का आधार बनाया जाएगा, तो वे राज्य दंडित होंगे, जिन्होंने जनसंख्या

अवधेश राजपूत

नियंत्रण में अच्छा काम किया है। आगामी परिसीमन में अनुमानतः कर्नाटक में 8, तेलंगाना और आंध्र में 3-3, तमिलनाडु में 2 सीटें बढ़ेंगी, जबकि केरल में एक लोकसभा सीट घट सकती है। वहीं मध्य प्रदेश में 18, राजस्थान में 19, महाराष्ट्र में 20, बिहार में 30 और उत्तर प्रदेश में 48 सीटें बढ़ सकती हैं। आगामी परिसीमन में जनसंख्या नियंत्रण और 'प्रतिनिधित्व की समानता' में संतुलन चुनौतीपूर्ण होगा। इस पर आश्चर्य नहीं कि दक्षिण के राज्य परिसीमन को लेकर आशंका जताने लगे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने संसद को सूचित किया था कि लोकसभा चुनाव बाद जनगणना और परिसीमन कराया जाएगा।

परिसीमन में लोकसभा की सीटें बढ़ना तय हैं। मोदी सरकार ने दूरदर्शिता से नई संसद का निर्माण कराया, जिसमें 888 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन राज्यों ने इस पर अभी ध्यान नहीं दिया है। लोकसभा में करीब डेढ़-दो सौ सीटें बढ़ना तय है। युवाओं को इसका लाभ लेना चाहिए। पीएम मोदी ने युवाओं से राजनीति में आने का आह्वान भी किया है। नारीशक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं हेतु लोकसभा और विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें आरक्षित की गई हैं। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या पर 181 महिला सीटें आरक्षित होंगी और यदि परिसीमन से न्यूनतम 150 लोकसभा सीटें भी बढ़ती हैं, तो लोकसभा में 231 महिला सीटें आरक्षित होंगी, जिसका लाभ महिलाओं को मिलेगा। अनुसूचित जाति-एससी और अनुसूचित जनजाति-एसटी की आरक्षित सीटों में भी वृद्धि होगी, क्योंकि अनु. 330(2) के अनुसार प्रत्येक राज्य को आवंटित सीटों में एससी और एसटी के लिए उसी अनुपात में सीटें आरक्षित होंगी, जो अनुपात उनका राज्य की आबादी में होगा। जब 2006 में आंशिक परिसीमन हुआ था, तब लोकसभा सीटों के बढ़ने पर तो प्रतिबंध था, पर एससी की आरक्षित सीटें 79 से बढ़कर 84 और एसटी की सीटें 41 से बढ़ कर 47 हो गई थीं। अगले परिसीमन में यह संख्या और बढ़ेगी।

आगामी परिसीमन आयोग को या तो लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या तय कर उन्हें राज्यों को आवंटित करने का फार्मूला बनाना होगा या यह तय करना होगा कि 2026 में भारत की अनुमानित जनसंख्या एक अरब 42 करोड़ में कोई सांसद अधिकतम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। इसके आधार पर ही लोकसभा सीटों की संख्या निर्धारित होगी। संसद को परिसीमन आयोग अधिनियम 2026 में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि आयोग संवैधानिक प्रविधानों का अनुपालन करते हुए जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को पुरस्कृत कर उनको कुछ अतिरिक्त लोकसभा सीटें आवंटित करे। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि परिसीमन में अपने यहां लोकसभा सीटों की संख्या में कटौती की आशंका के कारण दक्षिण के कुछ राज्य जनसंख्या बढ़ाने की अपील कर रहे हैं।

पूर्ववर्ती परिसीमन आयोगों ने यह नहीं बताया कि उन्होंने किस फार्मूले के आधार पर परिसीमन किया। आयोग में प्रत्येक राज्य से पांच सांसद और विधायक क्रमशः लोकसभा और विधानसभाओं के स्पीकर द्वारा नामित किए जाते हैं, पर वे भी परिसीमन प्रक्रिया की बारीकियों को नहीं जानते या जानना नहीं चाहते। उन्हें अपना निर्वाचन क्षेत्र बचाने की ही चिंता होती है। अतः अगले परिसीमन आयोग को कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के साथ ही विषय विशेषज्ञों को भी परामर्श प्रक्रिया में सम्मिलित करना होगा। इससे परिसीमन में जानबूझकर या अनजाने में होने वाली गलतियों से बचा जा सकता है। परिसीमन में पारदर्शिता और परामर्श इसलिए और जरूरी है, क्योंकि अनु.329 परिसीमन आयोग के निर्णयों में न्यायपालिका हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देता।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं सेंटर फार द स्टडी आफ सोसायटी एंड पालिटिक्स के निदेशक हैं)
response@jagran.com

संगीत और संस्कृति के महान साधक

वसीफुद्दीन डागर

जाकिर हुसैन के पिता भी विख्यात तबला वादक थे, लेकिन तबला वादन में चार चांद लगाने का काम उन्होंने ही किया

खुद को सदैव शागिर्द मानने वाले उस्ताद ● एएनआइ

जाकिर हुसैन के निधन से भारत ने एक महान तबलावादक, शास्त्रीय संगीत के विख्यात फनकार और भारतीय संस्कृति के प्रसारक को खो दिया। वह जितने बड़े कलाकार थे, उतने ही बेहतरीन इंसान। उन्होंने बचपन से ही तबला वादन शुरू कर दिया था और कम उम्र में शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए थे। उन्होंने तमाम दिग्गज कलाकारों के साथ प्रस्तुतियां दीं-देश में भी और विदेश में भी। उन्होंने अपने पिता की पीढ़ी के दिग्गज फनकारों के साथ भी काम किया और नई पीढ़ी के उभरते कलाकारों के साथ भी। उन्होंने तबले को देश और दुनिया में पहचान तो दिलाई ही, उसे लोकप्रिय बनाने का भी काम किया। उनका नाम तबले का पर्याय बन गया था और पूरी दुनिया उनके नाम से परिचित थी। वह उस्ताद कहलाते थे, लेकिन खुद को सदैव शागिर्द मानते थे। वह इतने प्रतिभाशाली थे कि उन्होंने सात साल की उम्र में अपना पहला कंसर्ट किया और 12 साल की उम्र से विदेश में कार्यक्रम करने शुरू कर दिए।

जाकिर हुसैन बेहद हंसमुख और मिलनसार इंसान थे। वह जितना आदर बड़ों को देते थे, उतना ही छोटों को प्यार देते थे। मुझे याद है कि करीब दो वर्ष पहले दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने बेहद आत्मीयता से बात की। कार्यक्रम के बाद उनसे मिलना मुश्किल होता था। इसलिए मैं उनसे कार्यक्रम के पहले ही मिलना पसंद करता। वह हम जैसे कलाकारों से मिलते समय ऐसा जताते कि हमें अच्छे से जानते हैं। यदि कोई अपने बारे में बताने लगता तो कहते कि हां भाई, मैं आपको अच्छे से जानता हूं और आपसे मिल चुका हूं। वह उस जमाने में तबला वादक के रूप में स्टार बन गए थे, जब इंटरनेट मीडिया का चलन नहीं था और संगीत जगत और खासकर शास्त्रीय संगीत में नाम कमाना एक मुश्किल काम था। वह केवल तबला वादन में ही दक्ष नहीं थे, वह शास्त्रीय संगीत की अन्य विधाओं से भी अच्छी तरह परिचित थे। वह जिस भी काम में रुचि दिखाते, उसमें महारत हासिल कर लेते। वह हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तत्पर रहते थे और अपने शिष्यों से कहते थे कि गुरु से जो सीखें, उससे इतर भी कुछ नया करने की कोशिश करें। वह जबरदस्त कलाकार थे। मैं जब भी उनसे मिला, उनसे कुछ न कुछ सीखने को मिला। वह जहां भी जाते, खुद को वहां के माहौल में ढाल लेते। वह विदेश में भी स्टार कलाकार का दर्जा रखते थे। उन्होंने विदेश में भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार में जैसी भूमिका निभाई, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। उनकी सादगी, उनकी संगीत साधना और उनका जीवन भारतीय संस्कृति का परिचायक था। यह उनकी लोकप्रियता का कमाल था कि उन्होंने कई उत्पादों के लिए विज्ञापन भी किए।

जाकिर हुसैन जितने भारत में लोकप्रिय थे, उतने ही विदेश में भी। पश्चिम में उनकी पहचान एक महान भारतीय संगीतकार के रूप में भी थी। उन्होंने कुछ फिल्मों में संगीत भी दिया। इनमें हिंदी फिल्में भी हैं और हालीवुड फिल्में भी। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी की फिल्मों में अभिनय भी किया। उनका कहना था कि उन्होंने अभिनय इसलिए किया, क्योंकि कुछ नया सीखना चाहते थे। वह अमेरिका में बस गए थे। वह वहां युवाओं को तबला वादन सिखाते थे और भारतीय संगीत के बारे में पढ़ाते थे। वह हमेशा कहते थे कि भारत एक प्राचीन देश है और उसके पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। वह यह मानते थे कि देवी सरस्वती की उन पर खास कृपा है। उनका यह किस्सा खूब प्रचलित है कि उनके जन्म के बाद उनके पिता ने किस तरह उनके कान में तबले की थाप सुनाई थी, जबकि रिवाज यह है कि बच्चे के जन्म के बाद उसके कान में अजान सुनाई जाती है। उनके पिता उस्ताद अल्लारक्खा का कहना था कि हमारी इबादत तो देवी सरस्वती की आराधना है। आम लोग भले ही ज्ञान की देवी सरस्वती की आराधना खास अवसरों पर करते हों, लेकिन हम जैसे शास्त्रीय संगीत के साधक तो हर दिन उनकी आराधना करते हैं और यह मानते हैं कि उनके दिए हुए ज्ञान से ही हम कुछ हासिल कर सके। उनके पिता भी विख्यात तबला वादक थे, लेकिन मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि तबला वादन में चार चांद लगाने का काम जाकिर हुसैन ने किया। वह संगीत को आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत मानते थे। उनका कहना था कि संगीत विश्व में शांति ला सकता है और अच्छाई एवं सच्चाई सब तक पहुंचा सकता है। उन्हें यह पता रहता था कि शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में कहां कौन बेहतर कर रहा है और कहां कौन से वाद्ययंत्र बनते हैं। एक बार फेस्टिवल आफ इंडिया के तहत जेनेवा में आयोजित एक कार्यक्रम में डागर बंधुओं और पंडित शिवकुमार शर्मा के साथ जाकिर हुसैन की प्रस्तुति होनी थी। अपने गुरुओं के साथ मैं भी वहां था। कार्यक्रम के पहले कुछ स्थानीय लोग ड्रमनुमा वाद्ययंत्र लेकर आए और जाकिर हुसैन से बोले, यह भी नए तरह का तबला है। उन्होंने वह बजाया और फिर उन्हें समझाया कि यह वाद्ययंत्र कैसे तबला से अलग है और उसकी खासियत क्या है?

जाकिर हुसैन भारतीय और पश्चिमी संगीत में संगम यानी फ्यूजन का माध्यम भी बने। वह भारतीय और पश्चिमी शास्त्रीय संगीत को अलग-अलग करके नहीं देखते थे। उनका कहना था कि उनकी नजर में संगीत एक ही है। जाकिर हुसैन को एक ओर जहां पद्मश्री, पद्म भूषण, और पद्म विभूषण जैसे सम्मान मिले, वहीं ग्रैमी पुरस्कार भी। एक साथ तीन ग्रैमी जीतने वाले वह पहले भारतीय संगीतकार बने। उन्होंने भारतीय संगीतज्ञ के रूप में जैसा मुकाम हासिल किया, उसके चलते वह हम सबके प्रेरणास्रोत थे, हैं और बने रहेंगे।

(लेखक विख्यात ध्रुपद गायक हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

स्वांतः सुखाय

कुछ कार्य केवल निजी आनंद या आत्मतुष्टि के उद्देश्य से किए जाते हैं, जिन्हें 'स्वांतः सुखाय' की श्रेणी में रखा जाता है। स्वांतः सुखाय का रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने समावेश करते हुए आशय भी स्पष्ट किया है कि इस रचना का सृजन मैं अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए कर रहा हूं। प्रायः कोई भी कार्य प्रारंभ करते समय लोक आलोचना का विचार मन को आंदोलित करता रहता है कि इस पर जनमानस की क्या प्रतिक्रिया होगी। उसे सराहना मिलेगी अथवा आलोचना का शिकार होना पड़ेगा। बहुत बार इसी संकोच में या तो कार्य आरंभ ही नहीं किए जाते अथवा उन्हें अधूरा छोड़ दिया जाता है, किंतु स्वांतः सुखाय के उद्देश्य को सामने रखकर किए जाने वाले कार्य इसके अपवाद होते हैं। उन्हें करते समय किसी आलोचना अथवा सराहना की परवाह मन में नहीं रहती। उन्हें करते समय कर्ता के मन में केवल आत्मसंतुष्टि के भावों की प्रधानता होती है। यदि स्वांतः सुखाय से संबंधित कार्यों को बहुजन हिताय हेतु से भी संबद्ध कर लिया जाए तो यह सोने पर सुहागा सिद्ध होगा जो न केवल आत्मसंतुष्टि देगा, वरन जनकल्याणकारी होकर आत्मसंतुष्टि के स्तर को द्विगुणित करने का सुयोग भी उपलब्ध कराएगा।

ऐसे अनेक उदाहरण रहे हैं जहां आरंभ में कर्ता को उपहास का शिकार होना पड़ा, किंतु अपने मानसिक संकल्प के दम पर अंततः वह इतिहास रचने में सफल हुए और बाद में उनके कार्यों, प्रयासों और उपलब्धियों को सराहा गया। स्मरण रहे कि दृढ़संकल्प के साथ और बिना यह विचारे कि लोग क्या कहेंगे, उससे बेपरवाह होकर लक्ष्य प्राप्ति के लिए पूरे समर्पण भाव से कार्य करने की जीवटता के साथ आगे बढ़ा जाए तो सफलता भी अवश्यंभावी है और स्वांतः सुखाय की अनुभूति होना भी निश्चित है। फिर भी, कभी असफलता ही मिले तो वह भी एक उपलब्धि ही होगी, क्योंकि तब एक अनुभव की सार्थकता सुलभ होगी जो आगे पथ प्रदर्शन में सहायक सिद्ध होगी।

एसएन दुबे 'स्नेही'

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

संतुलित हो कानून का रवैया

'बदला लेने का जरिया बने कानून' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में दीपिका नारायण भारद्वाज ने इस विषय पर विभिन्न संदर्भों में प्रकाश डाला। झूठे मुकदमे न केवल निर्दोषों का शोषण करते हैं, बल्कि कानून की विश्वसनीयता को भी कमजोर करते हैं। महिला सुरक्षा के लिए बने कानून जब न्याय देने के बजाय प्रतिशोध का जरिया बन जाएं, तो समाज में असंतुलन पैदा होना तय है। अखबारों और अदालतों में झूठे केसों की भरमार ने यह साबित कर दिया है। कानूनी संरक्षण के नाम पर निर्दोष व्यक्तियों का उत्पीड़न न्याय के मूल सिद्धांतों को आघात पहुंचाता है। कुछ आंकड़े बताते हैं कि धारा 498 ए के तहत दर्ज मामलों में से अधिकांश में आरोपित निर्दोष पाए जाते हैं। इस समस्या के समाधान हेतु ठोस कानूनी सुधार आवश्यक हैं। सबसे पहले, झूठे मुकदमों की जांच के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष तंत्र की स्थापना होनी चाहिए। पुलिस को चाहिए कि वह बिना किसी साक्ष्य के मामले दर्ज न करे। साथ ही, यदि आरोप झूठे साबित हों तो शिकायतकर्ता पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, कानूनी साक्षरता अभियान चलाकर लोगों को यह समझाना जरूरी है कि कानून का उद्देश्य न्याय प्रदान करना है, न कि किसी का चरित्र हनन या आर्थिक हानि करना। महिलाएं समाज का सशक्त स्तंभ हैं, परंतु जब कानून का दुरुपयोग कर एक वर्ग को प्रताड़ित किया जाता है, तो इससे सामाजिक असंतुलन उत्पन्न होता है। न्यायालयों और विधि विशेषज्ञों को इस समस्या पर गहन विचार करना होगा ताकि कानून का उपयोग वास्तविक पीड़ितों के लिए हो और झूठे मुकदमों की प्रवृत्ति पर रोक लगे।

awanishg30@gmail.com

भिखारी ठाकुर को सच्ची श्रद्धांजलि

एक साहित्यकार या कलाकार जिस चरित्र को जीता है या जिस परिवेश में रहता है, उसकी कलम उसी तरह से चलती है। भिखारी ठाकुर भी ऊंचनीच के भेदभाव को सहन करते हुए विषमताओं से लड़े थे। इसी कारण वे जीवन भर सामाजिक कुरीतियों और बुराइयों के विरुद्ध कई स्तरों पर जूझते रहे। उनके निर्देशन में बनी भोजपुरी फिल्म 'बिदेसिया' आज भी दर्शकों के बीच लोकप्रिय बनी हुई है। उनके कई भोजपुरी नाटक जैसे 'बेटी बेचवा', 'गबर घिचोर', 'बेटी वियोग' का आज भी मंचन होता रहता है। इन नाटकों और फिल्मों के माध्यम से भिखारी ठाकुर ने सामाजिक सुधार की दिशा में अद्भुत पहल की। कल 18 दिसंबर उनकी जन्मतिथि है, कई स्थानों पर समारोह होंगे, उनके कृतित्वों की चर्चा होगी। उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी, जब समाज से ऊंच-नीच का भेद समेत अन्य कुरीतियां सामूहिक प्रयास से खत्म कर दी जाएं। कवि भिखारी ठाकुर विलक्षण थे। उन्हें मात्र अक्षर ज्ञान था, फिर भी पूरा रामचरितमानस उन्हें कंठस्थ था। उन्होंने कुल 29 पुस्तकें लिखीं। वह भोजपुरी साहित्य और संस्कृति के समर्थ प्रचारक और संवाहक बने। उनके सभी नाटकों में बदलाव को दिशा देने वाले एक सामाजिक चिंतक की व्यथा साफ दिखती है। वह अक्सर अपने नाटकों में सूत्रधार बनते और अपनी बात बड़े चुटीले अंदाज में कह जाते थे। अब नाट्य विधा में उनकी परंपरा आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, जो नए संदर्भ प्रस्तुत करें।

प्रसिद्ध यादव, बाबूचक, पटना

मंदिर-मस्जिद विवाद

हृदयनारायण दीक्षित द्वारा लिखित आलेख वास्तविकता पर पर्दा डालने का प्रयास पढ़ा। मंदिर हमारी सभ्यता और संस्कृति के केंद्र रहे हैं। प्राचीन काल में मंदिर शिक्षा प्राप्ति का केंद्र हुआ करते थे। मुगल आक्रांताओं ने देश की सांस्कृतिक विरासत को छिन्न-भिन्न करने के लिए अनगिनत मंदिरों को ध्वस्त कर मस्जिदों का निर्माण कराया। लगभग पांच सौ वर्षों के संघर्ष के उपरांत अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का सपना साकार हुआ है। मुगल आक्रांताओं के कृत्यों पर पर्दा डालने के कांग्रेस की सरकार ने पूजा उपासना अधिनियम कानून बनाया। अपने इतिहास को जानना हर नागरिक का कर्तव्य है, लेकिन यह कानून नागरिकों को सच्चाई जानने से रोकता है। उत्तर प्रदेश के संभल में दंगे की जांच कर रहे अधिकारियों को दशकों से बंद पड़ा मंदिर का मिलना आश्चर्यचकित करता है। उस मंदिर की साफ-सफाई कराई गई, लोगों ने पूजा-अर्चना शुरू की। इस तरह की घटनाएं हिंदुओं को आहत करती हैं। आज भी इस तरह के कई मंदिर गुमनाम हैं। मुस्लिम समाज को उदारता का परिचय देते हुए इस तरह के मंदिरों को सम्मानपूर्वक हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। उन्हें छिपाने, ढंकने या कब्जे का प्रयास नहीं करना चाहिए। देश में हर मस्जिद के नीचे मंदिर को खोजना व्यावहारिक नहीं है। भारत में कई कालखंड में विदेशी आक्रांताओं ने बहुत कुछ नष्ट किया या बदला है। ऐसे में सरकार को मंदिर-मस्जिद विवाद का व्यावहारिक हल निकालना चाहिए।

ई हिमांशु शेखर, केसपा, गया

पोस्ट

एक थाप से शिवजी के डमरू की गूंज, दूसरी से शंख की ध्वनि जैसा दिव्य संगीत सिर्फ जाकिर हुसैन साहब ही दे सकते थे। राधिका खेड़ा@Radhika_Khera

संविधान से जुड़ी बहस में निर्मला सीतारमण का संबोधन सुनने के बाद कांग्रेस पछता रही होगी कि उसने इस मुद्दे पर बहस की शुरुआत ही क्यों की। तवलीन सिंह@tavleen_singh

एक कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट किया कि यदि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो आतिशी नहीं, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। आखिर महिलाओं को हमेशा अस्थायी जिम्मेदारियां क्यों दी जाती हैं? पल्लवी घोष@_pallavighosh

भारतीय पारी में करीब 17 ओवर का खेल ही हुआ है, लेकिन उसमें ही बल्लेबाजों की कलई खुल गई। पहली पारी की बल्लेबाजी बड़ी चिंता बनी हुई है। बल्लेबाज ध्यान रखें कि पारी की शुरुआत में गेंदों को छोड़ना भी अच्छा शाट होता है। हर्षा भोगले@bhogleharsha

नवंबर में व्यापार घाटे का आंकड़ा रिकार्ड 37.5 अरब डालर के स्तर पर पहुंच गया है। इससे रुपये के समक्ष नई चुनौतियां उत्पन्न होंगी और फरवरी में भी नीतिगत ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश घटती जाएगी। तमाल बंद्योपाध्याय@TamalBandyo

जनपथ

जैसे-जैसे देश का मौसम होता सर्द,
मणिशंकर का आजकल छलक रहा है दर्द।
छलक रहा है दर्द याद कर बात पुरानी,
लिखकर एक किताब सुनाने लगे कहानी।
अब गांधी परिवार के लिए हैं वे ऐसे,
मक्खी फेंकी जाय दूध के बाहर जैसे!

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त

जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प, बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक पिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 243

****

अमर उजाला

प्रवाह

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

नई दिल्ली ■ मंगलवार, 17 दिसंबर 2024

संगीत की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि जब यह आप पर चोट करता है, तो आपको कोई दर्द महसूस नहीं होता। -बॉब मार्ली

उस्ताद जाकिर हुसैन का जीवन और संगीत इस तथ्य के साक्षात प्रमाण हैं कि कला केवल प्रदर्शन का माध्यम नहीं, बल्कि हर इन्सान के भीतर जो अलौकिक है, उसकी ही अभिव्यक्ति है। वह अपने पीछे संगीत की एक असाधारण विरासत छोड़ गए हैं, जिसकी गूंज आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई देती रहेगी।

आखिरी थाप की गूंज

भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे महान दूतों में से एक उस्ताद जाकिर हुसैन का तबला, जिसके जरिये उन्होंने पूरी दुनिया को शांति व मानवता का संदेश दिया और जिस पर उनकी अविश्वसनीय गति, प्रवीणता और रचनात्मकता ने सभी संस्कृतियों के दर्शकों को बांध कर रखा, अब खामोश हो गया है। उन्होंने जिस तरह तबले को एक वाद्ययंत्र से ऊपर उठाते हुए आत्माभिव्यक्ति का जरिया बनाकर संगीत को एक जादुई संवाद बना दिया, उसे देखते हुए अगर उनका नाम तबले के पर्याय के रूप में लिया जाता है, तो हैरत नहीं होती। उस्ताद के तबले की थाप ने संगीत को नए सिरे से पारिभाषित करते हुए न केवल भारतीय शास्त्रीय संगीत को जीवंत किया, बल्कि उसमें आधुनिकता का ऐसा रंग भी भरा, जिससे हर पीढ़ी खुद को उससे जोड़ पाती थी। उनकी कला केवल सुरों का सरगम न होकर, भारतीय परंपरा और संस्कृति की गहराई का प्रतीक थी। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जाकिर हुसैन को सही मायनों में एक जीनियस कलाकार और सांस्कृतिक एकता का दूत कहा था, जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत का पूरी दुनिया में डंका बजाया। अपने पिता, महान तबला वादक उस्ताद अल्ला रक्खा से मिली प्रेरणा और उन्हीं के पदचिह्नों पर चलते हुए उन्होंने तबले को एक नया और ऐसा आयाम दिया, जो अब तक अज्ञात था। जाकिर साहब का जीवन भी किसी प्रेरणा से कम नहीं। सात साल की उम्र से ही उन्होंने पंडित रविशंकर, अली अकबर खान और शिवकुमार शर्मा जैसे दिग्गज भारतीय कलाकारों के साथ काम करना शुरू किया, तो यो-यो मा, जॉन मैकलॉफलिन, चार्ल्स लॉयड और जॉर्ज हैरिसन जैसे पश्चिमी संगीतकारों के साथ उनके अभूतपूर्व काम ने भारतीय संगीत को अंतरराष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचाया। 1973 का शक्ति बैंड काफी चर्चा में रहा, जिसके जरिये उन्होंने देसी-विदेशी कलाकारों के साथ मिलकर भारतीय शास्त्रीय संगीत और जैज संगीत को मिलाने का प्रयोग

किया और विश्व के दिग्गज संगीतकारों के साथ जुगलबंदी कर देश का मान भी बढ़ाया। अपने कॅरिअर में चार बार प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले वह भारत के पहले संगीतज्ञ थे, जिन्होंने एक ही वर्ष में तीन ग्रैमी पुरस्कार भी जीते। उस्ताद जाकिर हुसैन का जाना महज एक कलाकार का जाना नहीं है, बल्कि यह एक युग का अंत भी है। उनका जीवन और संगीत इस तथ्य के साक्षात प्रमाण हैं कि कला केवल प्रदर्शन का माध्यम नहीं, बल्कि हर इन्सान के भीतर जो अलौकिक है, उसकी ही अभिव्यक्ति है। संगीत प्रेमी उनकी अनुपस्थिति को महसूस करेंगे। लेकिन वह अपने पीछे संगीत की एक असाधारण विरासत छोड़ गए हैं, जिसकी गूंज आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई देती रहेगी।

बीच संगत से उठकर गए तुम जाकिर

एक समय था, जब दुनिया भर में हमारे कार्यक्रम होने लगे और खूब हुए। ऐसा बहुत बार हुआ कि कभी वह कार चला रहे होते, तो कभी मैं। साथ ही खाते और साथ ही बजाते। मंच से उतरे, कार में बैठे और दूसरे शहर को निकल पड़े। लेकिन वह साथ छोड़कर हमेशा के लिए निकल जाएंगे, कभी सोचा भी न था।

उस्ताद जाकिर हुसैन केवल मेरे तबला वादक या संगतकार नहीं थे, मेरे साथी कलाकार ही थे, बल्कि इन सबसे अधिक वह मेरे परिवार के सदस्य की तरह थे। उनका हमारा बहुत लंबा साथ रहा, संगीत में भी और जीवन में भी। यह साथ तबसे था, जब वह बहुत छोटे थे।

वह बचपन से ही अपने पिता उस्ताद अल्ला रक्खा खान साहब के साथ मेरे पास आया करते थे। उनके पिता और मैं तब फिल्मों के संगीत के लिए काम किया करते थे। जाकिर अपने पिता के साथ आ जाया करते थे और वहीं रहते थे। उस दौरान जाकिर को देखकर किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यह बालक एक दिन इतना बड़ा तबला वादक, इतना बड़ा कलाकार बन जाएगा और पूरी दुनिया में उसका इस प्रकार खूब नाम रोशन होगा। उनके पिता मेरे साथ कार्यक्रमों में भी बजाया करते थे। बाद में जाकिर हुसैन भी मेरे साथ बजाने लगे और खूब बजाने लगे।

पं. हरिप्रसाद चौरसिया
प्रख्यात बांसुरी वादक

मेरे साथ संगत में बहुत सारे कलाकार रहे हैं, लेकिन मेरे साथ जाकिर हुसैन की संगत को लोगों ने काफी पसंद किया और यह सिलसिला चल पड़ा। गांव में, शहर में, दिल्ली में, कोलकाता में, अमेरिका में, लंदन में हर जगह दुनिया भर में हमारे कार्यक्रम होने लगे और खूब हुए। ऐसा बहुत बार हुआ कि हम साथ-साथ रहे, कभी वह कार चला रहे होते, कभी मैं चला रहा होता, साथ ही खाते और साथ ही बजाते। मंच से उतरे, कार में बैठे और दूसरे शहर के लिए निकल पड़े। यह वह दौर था, जब हमारे साथ में खूब कार्यक्रम हो रहे थे। हम कार से एक जगह से दूसरी जगह जाना पसंद करते थे। इससे साथ भी रहता था और हवाई जहाज का खर्च भी बच जाया करता था। कई बार ऐसा भी हुआ कि हम साथ भी रहे, एक ही होटल, एक ही कमरे में।

कुछ कलाकारों से ऐसा ही रिश्ता हो जाता है, इतने अपनेपन का, परिवार की तरह। उनके साथ ऐसा ही हुआ। मुझे याद आ रहा है कि

उस्ताद अल्ला रक्खा जी के घर में जो पहली शादी हुई, उनकी बेटी खुर्शीद की, तो मैं, सितारा देवी, पंडित राम नारायण जी और पंडित शिवकुमार जी ने मिलकर खूब नृत्य किया था। खुर्शीद लंदन में हैं। मंच पर हमने खूब नृत्य किया, इस तरह जैसे यह हमारे परिवार में शादी हो। सोचिए क्या दृश्य रहा होगा, कोई सोच भी नहीं सकता, कल्पना से परे लगता है कि ये कलाकार मंच पर इस तरह नाच रहे हैं, हम देर तक नाचते रहे। ऐसा इस कारण ही हो सका कि हम सब एक परिवार की तरह ही थे। हम सबको यही लगा कि यह हमारे ही घर-परिवार की शादी है।

ऐसा भी हुआ कि मेरा, पंडित शिवकुमार शर्मा और उस्ताद जाकिर हुसैन का साथ काफी पसंद किया गया। आयोजक कहते थे कि शिव-हरि और जाकिर। कभी हम तीनों के साथ कार्यक्रम होते, तो कभी मेरे और जाकिर या शिव जी और जाकिर के। हमारे साथ को खूब लोकप्रियता मिली। हमारे साथ को संगीत रसिक खूब पसंद करते थे। हमारे कार्यक्रम तो खूब हुए ही, अलबम भी कई निकले। वास्तव में संगीत में ऐसा तभी संभव हो पाता है, जब आपके मन मिलते हों, जब आप एक-दूसरे को अच्छी तरह समझते हों। कलाकार को समझते हों, उसकी कला को समझते हों। हम साथ-साथ होते, तो खूब बातें होतीं, घूमते-फिरते।

एक और बात मुझे जाकिर हुसैन की बहुत अच्छी लगती थी। उनकी हर चीज में एक सोच, एक समझ दिखती थी। वह अगर संगीत में कुछ कह रहे होते, संगत कर रहे होते, बजा रहे होते, तो बहुत सोच-समझकर वह काम करते थे। संगत में सोच-समझकर जवाब देते ही थे, जब बजाने के बारे में बोल रहे होते, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में या किसी दूसरे तबला वादक के बारे में बोलते, तो बहुत ही समझदारी के साथ बोलते थे। वह जितने विनम्र थे, उतने ही समझदार थे।

उस्ताद जाकिर हुसैन जैसे कलाकार बहुत कम होते हैं, यदा-कदा आते हैं। उन्होंने संगीत को एक नई ऊंचाई, एक नई पहचान दी। उसे लोकप्रियता का नया आयाम दिया। न सिर्फ भारत में, बल्कि विदेश में उन्होंने एक बड़ा प्रशंसक वर्ग तैयार किया। तरह-तरह के प्रयोग करते रहे। भारतीय संगीत के साथ भी और विश्व के दूसरे देशों के संगीत के साथ भी।

कुछ समय पहले ही उनके इस तरह के प्रयोगात्मक संगीत को प्रतिष्ठित ग्रैमी अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था। मुझे इस बात की हमेशा प्रसन्नता रहेगी कि जाकिर हुसैन और मैं इतने समय तक साथ रहे, साथ-साथ घूमते-फिरते रहे, कार्यक्रम करते रहे। एक-दूसरे के साथ इतना अधिक वक्त व्यतीत किया। वास्तव में ऐसा तभी होता है, जब आप परिवार की तरह एक-दूसरे से जुड़ जाते हैं, लेकिन मुझे यह शिकायत भी रहेगी कि मुझे उनकी अस्वस्थता का पता नहीं चल सका। शायद उन्हें कुछ समय से समस्या थी, लेकिन उन्होंने मुझसे कभी इसकी चर्चा नहीं की। उन्हें मुझे बताना चाहिए था। वैसे मुझे पता चला था कि वह भारत के अपने कुछ कार्यक्रम स्थगित करने लगे थे। उन्होंने यह अच्छा किया कि अमेरिका चले गए। उनका परिवार वहीं है, वह अपने अंतिम समय में परिवार के लोगों के साथ थे।

लेकिन वह मेरे सामने बच्चे ही थे, बहुत छोटे थे। उनका इस प्रकार निधन बहुत दुखद है। पहले पंडित शिवकुमार शर्मा चले गए, अब जाकिर हुसैन भी नहीं रहे, लेकिन मेरे पास यमराज आएंगे, तो मैं उन्हें मारने के लिए दौड़ा लूंगा। संगीत या बांसुरी तो उन्हें समझ में नहीं आएगा, तो मैं अपनी बांसुरी से उनकी पिटाई कर दूंगा। बोलूंगा कि तुम ये काम छोड़ो, कोई दूसरा काम करो।

(आलोक पराड़कर से बातचीत पर आधारित)
edit@amarujala.com

जीवन धारा

जाकिर हुसैन
9 मई 1951-15 दिसंबर 2024

वाद्ययंत्रों के साथ ऐसा रिश्ता होना चाहिए कि वे घुटने टेककर आपसे कहें कि आप जो चाहें करें, जो स्वर निकालना चाहें, निकालें-यानी अपने वाद्य पर नियंत्रण रखें, उसे अपने अनुसार बजाएं और महारत हासिल करें।

आज तबला क्या कहता है

संगीत की दुनिया में, और खासकर जब बात पारंपरिक संगीत की हो, तो जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। आपको अपने वाद्ययंत्र के साथ रिश्ता बनाने के लिए समय चाहिए। वाद्ययंत्र की आत्मा से जुड़ना होता है, तब जाकर चीजें होती हैं। ऐसा नहीं होता कि आज आप नया सितार खरीदें और कल जाकर मंच पर उसे बजाना शुरू कर दें। सितार और आपके बीच एक रिश्ता बनना चाहिए। कुछ महीनों तक इसे बजाने के बाद ही आप सहज महसूस करेंगे कि हां, अब मैं इसे मंच पर बजा सकता हूं। मैं तबले के साथ क्या करता हूं? मुझे लगता है कि

आप चाहते हैं कि वाद्ययंत्र आपकी आज्ञा का पालन करे, तो सबसे पहले आपको उसे स्वीकार करना होगा।

खुलापन और स्पष्टता ही है, जो हम इससे निकालकर दर्शकों-श्रोताओं के बीच लाते हैं। मैं जो प्रस्तुत करता हूं, वह अर्थपूर्ण होना चाहिए, चाहे वह वाद्ययंत्र और संगीतकार के बीच दिल से दिल की बातचीत हो या विचार प्रक्रिया में निःसंकोचपन का भाव हो या मानदंडों के बारे में निश्चिंतता हो, आपका संगीत यथासंभव स्पष्ट होना चाहिए।

मुझे एक प्यारी घटना याद आ रही है। किशन महाराज जी मंच पर जाने वाले थे, तभी किसी ने कहा, महाराज जी, एक शानदार संगीत कार्यक्रम होना चाहिए। उन्होंने जवाब दिया, देखेंगे भैया, आज तबला क्या कहता है। यह सभी वाद्ययंत्रों के साथ होता है- गिटार, पियानो, बास या वायलिन। आपको वाद्ययंत्र के साथ एक रिश्ता बनाने की जरूरत है, क्योंकि आप चाहते हैं कि वह आपकी आज्ञा का पालन करे। उसे आपको स्वीकार करना होगा, और आपको दिखाना होगा कि वह आपके साथ विश्वास की छलांग लगाने के लिए तैयार है। उदाहरण के लिए, मुझे तबले की चमड़ी में एक निश्चित मात्रा में लचीलापन चाहिए-ताकि जब मैं इस पर थाप दूं, तो यह एक निश्चित तरीके से प्रतिक्रिया और प्रतिध्वनि करे। स्वर में मंद्र, तिहरा और मध्यमा की एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए। मेरे हाथ का दबाव किसी और के हाथ के दबाव से अलग है, इसलिए यह चमड़ी की मोटाई को प्रभावित करता है-चमड़ी इतनी मोटी होनी चाहिए कि यह उस तरह से झुक सके, जैसा मैं चाहता हूं।

उस्तादों का कहना है कि आपका अपने वाद्ययंत्रों के साथ ऐसा रिश्ता होना चाहिए कि वाद्ययंत्र घुटने टेककर आपसे कहे कि आप जो चाहें करें, जो स्वर निकालना चाहें, निकालें-यानी आप अपने वाद्य पर नियंत्रण रखें, उसे अपने अनुसार बजाएं एवं उस पर महारत हासिल करें। एक और विचारधारा है, जो मानती है कि वाद्ययंत्र संगीत प्रस्तुत करने का एक माध्यम मात्र है। इससे मुझे एक और दिलचस्प घटना याद आती है। सुल्तान खान साहब और मैं एक बार कैलिफोर्निया में अली अकबर खान साहब की कक्षा में बैठे थे और उन्होंने कहा, सुल्तान, क्या तुम अपनी सारंगी लाए हो? क्या तुम कुछ बजाओगे? सुल्तान भाई ने जवाब दिया, खान साहब, मुझे खेद है कि मैं उसे होटल में छोड़ आया हूं। मैं बस आपको नमस्ते कहने आया था। अली अकबर खान साहब ने जोर देकर कहा, हमारे म्यूजिक स्टोर में एक सारंगी है, चलो उसे निकालते हैं। उन्होंने सारंगी निकाली और उसे नीचे रख दिया। सुल्तान भाई ने उसे देखा और कहा, खान साहब, यह सारंगी टूट गई है। इसकी हालत खराब है। मुझे नहीं लगता, मैं इसे बजा पाऊंगा। अली अकबर साहब मुस्कराते हुए बोले, सारंगी अगर ठीक नहीं है, तो क्या हुआ? हाथ तो तुम्हारा है। सुल्तान भाई बोले, ओह! फिर उन्होंने सारंगी को जितना हो सका, उतना ठीक किया और उसे बजाने लगे।

('जाकिर हुसैनः ए लाइफ इन म्यूजिक इन कन्वर्सेशन विद नसरीन मुन्नी कबीर' के अंश)

दूसरा पहलू

उत्तराखंड में आज भी फ्रेडरिक विल्सन या फिरंगी राजा को लोग याद तो करते हैं, लेकिन देवदारों के हत्यारे के रूप में।

तब पहाड़ी इलाकों में उस फिरंगी के सिक्के चलते थे

यह पहाड़ की कहानी है...जहां शिखर पर पहुंचने के लिए जी-तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। राह में आते-जाते लोगों की सलाह सुन तो ली जाती है, पर भरोसा खुद पर ही करना होता है। एक भी गलत कदम खाई में गिरा देता है और वर्षों में बनाया वजूद पल भर में नेस्तनाबूद हो जाता है। ऐसा ही वर्षों पहले सुदूर उत्तराखंड में फ्रेडरिक विल्सन के साथ हुआ। वह अपने संघर्ष और पराक्रम से टिहरी के दुर्गम पर्वतीय इलाकों में उत्कर्ष पर पहुंचा और सबकी आंखों का तारा बन गया। एक ऐसा वक्त भी आया, जब 1857 के दौरान उसने इतनी अकूत संपत्ति कमाई कि उसे फिरंगी राजा का तमगा तक मिल गया। उसके नाम के सिक्के चल गए थे। टिहरी गढ़वाल खासकर हर्षिल और आसपास के इलाकों में आज भी उस फिरंगी के किस्से आम हैं।

विनोद पुरोहित

एक ऐसा वक्त भी आया, जब 1857 के दौरान उसने इतनी संपत्ति कमाई कि उसे फिरंगी राजा का तमगा तक मिल गया। उसके नाम के सिक्के चल गए थे।

फ्रेडरिक विल्सन नामक व्यक्ति मूल रूप से यॉर्कशायर, इंग्लैंड का था। ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में अफसरी हासिल कर हिंदुस्तान आया था। हालात कुछ ऐसे बने कि अपने ही उच्च अधिकारी की हत्या कर दी। छिपते-छिपाते वह टिहरी के दुर्गम और अनजाने इलाकों में जा पहुंचा, लेकिन उसे इंग्लैंड वापस जाना पड़ा। हालांकि, उसके जुनून ने हिलोर मारी और वह जल्द ही लौट आया। यहां उसने नए सहयोगी तलाशे। माइकल जॉन के नाम से एक बुजुर्ग के घर में शरण ली। बाद में उसकी बेटी राईमत्ता से शादी कर ली। राईमत्ता के निधन के बाद विल्सन ने उसकी ही रिश्तेदार गुलाबो से ब्याह रचाया। उसने वन्यजीवों के शिकार और उनकी खाल का व्यापार शुरू किया। इसके बाद गंग नहर और रेलवे की परियोजनाओं के लिए देवदार की लकड़ी के ठेके लिए।

वक्त के साथ विल्सन की सफलता तो दर्ज हो रही थी, उसकी विफलता की इबारत भी लिखी जा रही थी। उसने धन के लालच में टिहरी के समृद्ध जंगलों को नष्ट कर दिया। सबसे अमीर बनने की राह में आने वालों को तबाह कर दिया।

इतिहास के गुमनाम किरदारों के ख्यात लेखक राजगोपाल सिंह वर्मा ने अपनी किताब *फिरंगी राजा* में इस अंग्रेज की रोचक दास्तान प्रस्तुत की है। वक्त के साथ विल्सन की सफलता तो दर्ज हो रही थी, उसकी विफलता की इबारत भी लिखी जा रही थी। उसने धन के लालच में टिहरी के समृद्ध जंगलों को नष्ट कर दिया। वहां का प्राकृतिक संतुलन तहस-नहस कर दिया। सबसे अमीर आदमी बनने की राह में आने वालों को तबाह कर दिया। अपने मनमाने व्यवहार की वजह से आज लोग उसे शापित इन्सान के रूप में ज्यादा जानते हैं। तभी तो कहा जाता है कि पहाड़ पर एक गलत कदम इन्सान को गर्त में पहुंचा देता है। स्थानीय लोग कहते हैं- किंवदंतियों और किस्सों में हुलसन (विल्सन) आज भी जिंदा है, लेकिन देवदारों के हत्यारे के रूप में।

आंकड़े

टोल संग्रह

राजमार्गों पर वाहनों से देश भर में शुरू हुई टोल व्यस्था के तहत टोल शुल्क वसूलने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है।

उत्तर प्रदेश	32,510
राजस्थान	29,808
महाराष्ट्र	25,929
गुजरात	24,597
आंध्र प्रदेश	22,287

आंकड़े टोल वसूलने वाले शीर्ष राज्यों के, राशि करोड़ रुपये में | स्रोत : MoRTH, NR

ब्रह्मज्ञान न कराने पर राजा जयंतपाल विद्वानों और साधुओं को जेल में डाल देते थे। भक्त मुकुंदराज ने करीब छह सौ लोगों को राजा की कैद से मुक्त करवाया।

भक्त मुकुंदराज

महाराष्ट्र के एक राजा जयंतपाल ब्रह्मज्ञानी संत की तलाश में थे। इसलिए उनके दरबार में आने वाले विद्वानों से वह कहते थे, 'आप लोग ब्रह्मज्ञान की बड़ी-बड़ी बातें कहते हैं, क्या आपने ब्रह्म का साक्षात्कार किया है और यदि किया है, तो क्या वैसा साक्षात्कार आप मुझे करा सकते हैं?' राजा के सवाल का ठीक से जवाब न देने पर वह विद्वानों को जेल में बंद करवा देते थे। करीब छह सौ विद्वान और साधुओं को राजा ने जेल में डाल रखा था।

यह बात जब भक्त मुकुंदराज को पता चली, तो वह राजा के पास गए। राजा ने उनसे भी वह सवाल किया। मुकुंदराज ने कहा, 'मैं तुम्हें ब्रह्म का साक्षात्कार करा दूंगा, जहां कहोगे उस जगह पर।' इसके बाद राजा को एक घोड़े पर बैठाकर मुकुंदराज ने उनके सिर पर हाथ रख दिया। राजा की घोड़े पर ही समाधि लग गई और तीन दिन तक राजा घोड़े पर ही सवार रहे। समाधि टूटने पर राजा एकदम भाव-विह्वल हो उठे। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। राजा ने अपने आंसुओं से मुकुंदराज के चरण धोए और उनके शरणागत हो गए। मुकुंदराज के कहने पर राजा ने बंदी बनाए गए सभी विद्वानों और साधुओं को मुक्त कर दिया। राजा को पूर्ण बोध कराने के लिए मुकुंदराज ने *विवेकसिंधु* की रचना की। *विवेकसिंधु* को मराठी साहित्य का आद्य ग्रंथ माना जाता है। इसमें 18 वृत्त हैं। इसके अलावा भक्त मुकुंदराज ने *परमामृत* की रचना की।

अंतर्यात्रा
संकलित

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 22 अक्तूबर, 1962

चीनियों को खदेड़ा जाएगा : नेहरू

चीनियों को खदेड़ा जायगाःनेहरू
'चीनियों से संघर्ष लम्बा चलने वाला मामला'

प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा कि हाल ही में उत्तरी सीमा पर हमारी जो पराजय हुई है, उससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय सेना चीनियों को खदेड़कर अपने खोए ठिकानों को फिर से हासिल करेगी।

हिंदी विरोधी राजनीति स्कॉटलैंड से सबक लेगी?

जिस ब्रिटेन की वजह से हिंदी देसी धरती पर अपना वाजिब आसन नहीं हासिल कर पाई है, वहीं के एक प्रांत में हिंदी में सरकारी कामकाज की मांग उठी है।

उमेश चतुर्वेदी | भाषा

इसे विडंबना ही कहेंगे कि राजभाषा का दर्जा हासिल होने के बावजूद अपनी हिंदी गैर हिंदीभाषी क्षेत्रों में राजनीतिक विरोध का जरिया बनी हुई है। संसद के मौजूदा शीत सत्र में पारित 'भारतीय वायुयान विधेयक' के विरोध में गैर हिंदीभाषी सांसद मुखर हो गए थे, क्योंकि विधेयक का नाम हिंदी में है। ऐसे माहौल में सात-साढ़े सात हजार किलोमीटर दूर विलायती धरती से हिंदी को लेकर सुखद खबर आई है। जिस ब्रिटेन ने भारत को करीब दो सौ साल तक गुलाम रखा, जिसके शासन की वजह से हिंदी देसी धरती पर अब तक अपना वाजिब आसन नहीं हासिल कर पाई है, उसी ब्रिटेन में हिंदी में सरकारी कामकाज किए जाने की मांग उठी है।

जिसे दुनिया ब्रिटेन के नाम से जानती है, उस यूनाइटेड किंगडम का स्कॉटलैंड द्वीपीय प्रांत है। इसी प्रांत की स्थानीय संसद के भारतीय मूल के सांसद ने सार्वजनिक संदेश भेजने के लिए हिंदी का भी

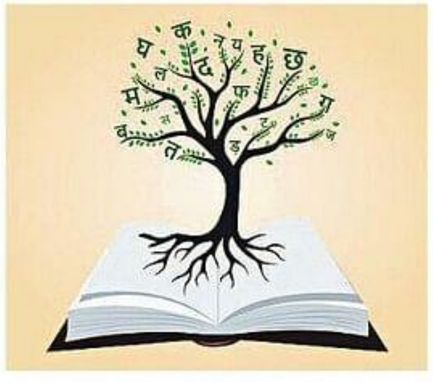

इस्तेमाल किए जाने की मांग रखी है। स्कॉटलैंड की स्थानीय संसद में ग्लास्गो से डॉक्टर संदेश गुल्हाने सांसद हैं। उनका तर्क है कि चूंकि 2022 की जनगणना के लिहाज से स्कॉटलैंड में भारतीय मूल के लोगों की जनसंख्या दूसरे नंबर पर है, लिहाजा यहां के सार्वजनिक संदेश और स्वास्थ्य जानकारियां हिंदी में भी भेजे और प्रसारित किए जाने चाहिए। डॉक्टर गुल्हाने की मांग पर स्कॉटलैंड की सरकार की राय जानने से पहले हमें जानना चाहिए कि अगर भारत में ऐसी मांग किसी गैर हिंदीभाषी राज्य में उठी होती, तो वहां के राजनेताओं की प्रतिक्रिया क्या होती? निश्चित तौर पर उस गैर हिंदीभाषी इलाके की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा इस मांग के खिलाफ उठ खड़ा होता। गैर हिंदीभाषी इलाकों के लोग इसे हिंदी का साम्राज्यवाद या वर्चस्ववाद बाद में बताते, हिंदीभाषी इलाकों की कुछ बौद्धिक और राजनीतिक ताकतें इसे वर्चस्ववादी मांग बताकर खारिज करने का सुझाव रख देतीं।

लेकिन स्कॉटलैंड में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि स्कॉटलैंड या ऐसी दूसरी विदेशी जगहों पर न सिर्फ भारतीय मूल, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप, जिसमें बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और कुछ हद तक अफगानिस्तान तक शामिल है, के लोग आपसी संवाद या संपर्क के लिए ज्यादातर हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। वह हिंदी निश्चित तौर पर भारत की खड़ी बोली हिंदी नहीं होती। उसमें उन लोगों की स्थानीय भाषाओं के साथ ही अंग्रेजी या उस देश विशेष की भाषा का भी पुट शामिल होता है, जिस देश में वह समूह रहता या नौकरी करता है। इस लिहाज से कह सकते हैं कि भारत की सीमाओं के बाहर भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक हिंदी ही है।

ब्रिटेन में छाया या शैडो कैबिनेट की परंपरा है। प्रमुख विपक्षी दल भी अपने नेताओं को मंत्रियों की तरह विभाग बांटता है और जिम्मेदारी प्राप्त लोग अपने-अपने विभागों पर नजर रखते हैं। सरकारी योजनाओं की कमियों को जाहिर करते हैं और उसी आधार पर उसकी आलोचना करते हैं। चुनावों में विपक्षी दल की जीत के बाद छाया मंत्रिमंडल के ही ज्यादातर सदस्य मंत्री बनते हैं और जिन विभागों का काम विपक्ष में रहते वक्त वे संभालते रहे हैं, उन्हीं विभागों और मंत्रालयों का दायित्व उन्हें मिलता है। डॉक्टर संदेश गुल्हाने स्कॉटलैंड के छाया मंत्रिमंडल के सदस्य भी हैं और स्वास्थ्य महकमे पर निगाह रखते हैं। स्कॉटलैंड की संसद एडिनबर्ग में है। उसकी बैठक में एक प्रश्न के जरिये डॉक्टर संदेश गुल्हाने ने स्कॉटलैंड की प्रथम उपमंत्री केट फोर्ब्स से अपील की।

गुल्हाने के मुताबिक, स्कॉटलैंड में हिंदी बोलने वालों की संख्या ऑस्ट्रेलियाई शहर पर्थ की जनसंख्या के बराबर है। उनके सवाल के जवाब में स्कॉटलैंड की प्रथम मंत्री फोर्ब्स का जवाब था कि सरकार गुल्हाने की मांग पर 'विचार करेगी', क्योंकि स्कॉटलैंड में हिंदीभाषियों का भी बहुत योगदान है। फोर्ब्स के जवाब की अगली पंक्ति देश की गैर हिंदीभाषी राजनीति को हैरत में डाल सकती है। फोर्ब्स का जवाब रहा, 'यह बहुत महत्वपूर्ण है कि स्कॉटलैंड के भारतीय मूल के लोगों को लगे कि सभी सरकारी सूचनाएं उनकी अपनी भाषा में उपलब्ध हैं।' जिस विलायत ने अपनी भाषा के जरिये हमारे यहां मानसिक उपनिवेशवाद की नींव को मजबूत किया है, उसी की धरती पर हिंदी का सम्मान होना मामूली बात नहीं है। बेहतर होता कि भारत की हिंदी विरोधी राजनीति भी इससे कुछ सीख लेती।

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। –वाल्तेयर

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

हादसे रोकने की हो चिंता, सिर्फ गिनती ही काफी नहीं

सड़क मार्ग पर ऐसे स्थान जहां बार-बार हादसे होते हों, उन्हें ब्लैक स्पॉट के रूप में चिह्नित किया जाता है। मकसद भी यही होता है कि ऐसे स्थानों पर हादसों की वजह की पड़ताल कर ऐसे बंदोबस्त किए जाएं जिनसे यहां फिर हादसे नहीं हो। लेकिन चिंता की बात यह है कि देश में तेरह हजार से ज्यादा ऐसे ब्लैक स्पॉट और कहीं नहीं बल्कि हाइवेज पर हैं जिनके निर्माण में गुणवत्ता का पग-पग पर ध्यान रखने का दावा किया जाता है। सड़कों के विस्तार के साथ-साथ उम्मीद यही की जाती है कि इन्हें सुरक्षित बनाने की दिशा में भी मजबूती से काम होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि पिछले वर्षों में सिर्फ ब्लैक स्पॉट तय करने से ज्यादा कुछ नहीं हुआ।

राजस्थान व मध्यप्रदेश समेत देश के दस राज्य सबसे अधिक ब्लैक स्पॉट वाले राज्यों की गिनती में आते हैं। हाइवेज पर ब्लैक स्पॉट उन्हें कहा जाता है जहां पिछले तीन साल में पांच सड़क हादसों में एक ही जगह पर दस मौतें या गंभीर घायल होने के मामले आए हों। जाहिर है पूरे तीन साल तक सिर्फ यही काम होता है कि किसी स्थान को ब्लैक स्पॉट बनने दिया जाए। सवाल यह है कि आखिर कोई एक स्थान भी ऐसा क्यों रहना चाहिए जहां एक हादसे के बाद दूसरे का इंतजार किया जाए। क्या किसी की जान की कीमत सिर्फ गिनती ही होनी चाहिए? यह सवाल इसलिए भी क्योंकि कहा यही जाता है कि ब्लैक स्पॉट यानी हादसों का केंद्र कोई स्थान कोई एक कारण से नहीं बनता। कहीं ओवरस्पीड वाहनों के कारण, कहीं सड़कों की गलत डिजाइनिंग तो कहीं लेन सिस्टम की अनदेखी इनकी वजह होती है। हादसों के बाद मौतों की संख्या पर नियंत्रण नहीं कर पाने की वजह यह भी है कि घायलों को त्वरित उपचार नहीं मिल पाता। यानी इन तमाम कारणों में कोई भी ऐसा नहीं है जिसका समाधान संभव नहीं हो। सड़कों की गलत डिजाइनिंग को स्वीकृति देने वाले इंजीनियरों को आखिर ऐसा जिम्मेदारी भरा काम दिया ही क्यों जाए? रहा सवाल ट्रकों की हर कहीं पार्किंग का, तो हाइवेज पर दौड़ते सड़क गश्ती दल को इन्हें भला हादसों के लिए क्यों खड़े रहने देना चाहिए। यह इसलिए भी क्योंकि राजमार्गों पर ट्रकों की पार्किंग की जगह बाकायदा चिह्नित की गई होती है। मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों की अनदेखी भी कम नहीं।

केंद्रीय मंत्री गडकरी की सड़क हादसों में मरने वालों के लिए यह चिंता वाजिब ही है कि ये किसी लड़ाई या दंगे में नहीं मरे। सरकार ने ब्लैक स्पॉट के लिए 40 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। लेकिन सिर्फ इसी से जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। हाइवेज पर टोल वसूली पूरी होती है तो हादसों की गिनती ही नहीं, सड़कों को हादसा रहित बनाने के जतन भी करने होंगे।

तबले पर थाप से कहानियां बुनने वाले जादूगर

स्मृति शेष: उस्ताद जाकिर हुसैन की बहुमुखी प्रतिभा उन्हें ग्रैमी अवॉर्ड तक ले गई। वे पहले भारतीय तबला वादक ही नहीं बल्कि पहले संगीतज्ञय थे, जिन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार 4 बार मिला। अमरीका में रहते हुए उन्होंने वहां के स्थानीय संगीतज्ञों के साथ फ्यूजन तैयार किए, जिससे भारतीय शास्त्रीय संगीत को वैश्विक मंच पर नई पहचान मिली। जाकिर साहब श्रोताओं की नब्ज पहचानते थे। वे कहते थे - 'समय के साथ न बहो। संगीत में रम जाओगे तो श्रोता भी खुद ही संगीत का आनंद लेने लगेंगे।'

पं. विश्व मोहन भट्ट, संगीतज्ञ
(पदम भूषण और ग्रैमी अवॉर्ड से सम्मानित)

भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उस्ताद जाकिर हुसैन एक ऐसा नाम हैं, जिन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। तबले के इस जादूगर ने न केवल भारतीय संगीत को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया, बल्कि इसे पारंपरिक और आधुनिक शैलियों का अनोखा संगम भी बनाया। उनका संबंध पंजाब घराने से था और तबला उनके खून में शामिल था। उनके पिता, उस्ताद अल्लारखा खां, जो स्वयं तबले के महान उस्ताद थे, ने उन्हें जो तालीम दी, उसे जाकिर हुसैन ने न केवल आगे बढ़ाया बल्कि इसे आम लोगों के बीच लोकप्रिय और सुलभ बना दिया। उन्होंने अपनी वादन शैली को अधिक मनोरंजक और संवादात्मक बनाया, जिससे तबले को हर वर्ग के श्रोता समझ सकें और उन्हें आनंदित कर सकें।

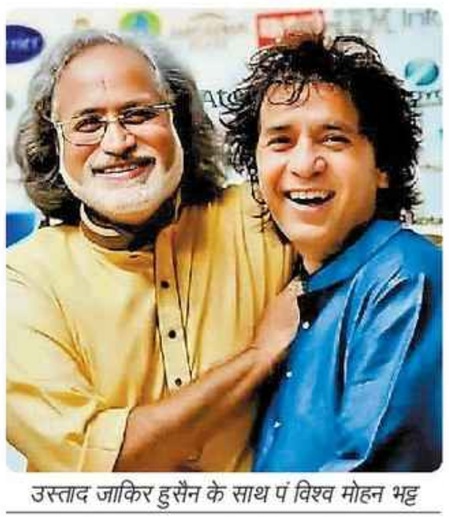

उस्ताद जाकिर हुसैन ने तबले को एक ऐसा वाद्य बना दिया, जो सिर्फ संगीत का साधन नहीं, बल्कि एक कहानी कहने का माध्यम बन गया। वे घोड़े की टाप, ट्रेन की आवाज, भगवान शंकर के डमरू, शंख और घंटी जैसी अनकों ध्वनियों को तबले से निकालने में सिद्धहस्त थे। ये प्रयोग न केवल उनके कौशल को दर्शाते थे, बल्कि उनकी रचनात्मकता और संगीत के प्रति जुनून को भी दिखाते थे। उनकी प्रस्तुतियां श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती थीं और उनके साथ गहरा जुड़ाव स्थापित करती थीं। उनकी सोलो प्रस्तुतियां जितनी अद्भुत होती थीं, उतनी ही जब वे संगत करते थे, तो मुख्य कलाकार को हमेशा प्राथमिकता देते थे। यही वजह है कि संगीत जगत में हर कलाकार उनका नाम सम्मान के साथ लेता है। एक बार चेन्नई में जब मैं मंच पर प्रस्तुति दे रहा था, तब जाकिर साहब ने तबले पर संगत की। उनकी सादगी और विनम्रता ऐसी थी कि मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मेरे साथ दुनिया का महानतम तबला वादक मंच साझा कर रहा है। वे छोटे कलाकारों को भी उतना ही सम्मान देते थे, जितना बड़े कलाकारों को। वे हमेशा संगीत धर्म का पालन करते थे और पुराने उस्तादों की बंदिशों को सुनाने से पहले उनका नाम जरूर लेते थे। जाकिर हुसैन ने चार पीढ़ियों के साथ काम किया। 12 साल की उम्र में बड़े गुलाम अली खान, उस्ताद अमीर खान और ओंकारनाथ ठाकुर जैसे दिग्गजों के साथ संगत शुरू की। 16-17 साल की उम्र में पंडित रविशंकर और अली अकबर खां जैसे उस्तादों के साथ काम किया। बाद में, हरि प्रसाद चौरसिया, शिव कुमार शर्मा और अमजद अली खान के साथ संगत की और फिर नए जमाने के शाहिद परवेज, राहुल शर्मा और अमान-अयान जैसे नए कलाकारों के साथ काम किया। उन्होंने पुरानी और नई पीढ़ियों के बीच सेतु का काम किया, दोनों को जोड़ने का प्रयास किया।

उस्ताद जाकिर हुसैन के साथ पं विश्व मोहन भट्ट

उनकी यही बहुमुखी प्रतिभा उन्हें ग्रैमी अवॉर्ड तक ले गई। वे पहले भारतीय तबला वादक थे, जिन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार 4 बार मिला। अंतिम ग्रैमी अवॉर्ड जनवरी 2024 में मिला था। अमरीका में रहते हुए उन्होंने वहां के संगीतज्ञों के साथ फ्यूजन तैयार किए, जिससे भारतीय शास्त्रीय संगीत को वैश्विक मंच पर नई पहचान मिली। जाकिर साहब श्रोताओं की नब्ज पहचानते थे। वे कहते थे- 'समय के साथ न बहो। संगीत में रम जाओ तो श्रोता खुद ही संगीत का आनंद लेने लगेंगे।' उनकी मंच पर मौजूदगी ऐसी होती थी कि श्रोता उनसे आंखें हटाने में असमर्थ रहते थे। वे सादगी और सहजता के प्रतीक थे। एक बार जयपुर में जब मैं उनसे होटल में मिला, तो उन्होंने स्कूटर से मेरे घर जाने की इच्छा जताई। वे मेरे स्कूटर पर पीछे बैठकर घर आए, घंटों हमारे साथ समय बिताया और फिर स्कूटर से ही होटल लौटे जबकि मैंने उनसे कहा कि थोड़ी देर में कार की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया।

अहमदाबाद में पिछले 45 वर्षों से संगीत फेस्टिवल 'सप्तक' चलता है। 1 से 13 जनवरी के बीच आयोजन होता है। जाकिर साहब हर बार इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए अमरीका से आते थे। यहां न केवल अपनी प्रस्तुति देते थे बल्कि श्रोतों से मिलकर उनसे बातें करते थे, उनके साथ फोटो भी खिंचवाते थे।

सबसे खास बात वे नए कलाकारों के लिए भी अलग से समय निकालते थे। वह चाहते थे तो कम समय का हवाला देकर इन सबसे बच जाते, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया। शादी के बाद वे अमरीका में रहने लगे थे, लेकिन वे नियमित रूप से अपने मुंबई के पुश्तैनी घर पर आते रहे थे। उन्होंने ग्रैमी अवॉर्ड के साथ पदमश्री, पदम भूषण और पदम विभूषण अवॉर्ड मिला है। ये सब उनके कद को ऊंचा करते हैं लेकिन असल में वे इससे भी बड़े अवॉर्ड के हकदार थे। उनकी सोच भी प्रेरणादायक थी। एक बार जब मैंने उनके घुंघराले बालों पर सवाल किया, तो उन्होंने कहा, 'कलाकार को हमेशा हीरो की तरह दिखना चाहिए। मंच पर हमारी उपस्थिति उतनी ही महत्त्वपूर्ण है, जितनी हमारी प्रस्तुति।' उनके जैसे कलाकार सदियों में एक बार आते हैं। भारतीय संगीत को उनके योगदान के लिए हमेशा गर्व रहेगा।

फैक्ट फ्रंट

स्कारलेट टैनाजर

स्कारलेट टैनाजर अपने चमकदार लाल और काले पंखों के कारण पक्षी प्रेमियों के बीच अधिक लोकप्रिय है। यह मुख्य रूप से उत्तरी अमरीका में पाया जाता है और गर्मी में पूर्वी अमरीका के जंगलों में अपना घर बनाता है। सर्दी में यह मध्य और दक्षिण अमरीका के गर्म क्षेत्रों में कुछ समय के लिए चला जाता है। इसकी नर प्रजाति की पहचान उसके गहरे लाल रंग के शरीर और काले पंखों से होती है, जबकि मादा अधिक हल्के हरे और पीले रंग की होती है। यह पक्षी लगभग 6.5 इंच लंबा होता है और इसकी चोंच छोटी लेकिन मजबूत होती है।

रोशनी में नहाई विरासत : छुट्टियों की चमक के बीच काउबॉय बूट्स

सैन एंटोनियो (अमरीका) में स्थित यह 40 फीट ऊंचे और 30 फीट लंबे काउबॉय जूतों की जोड़ी, जिसे स्थानीय रूप से द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट काउबॉय बूट्स कहा जाता है, इस क्षेत्र की पहचान का एक बड़ा हिस्सा है। यह आकृति 1979 में कलाकार बॉब वेड ने बनाई थी और यह नॉर्थ स्टार मॉल के पास है। छुट्टियों के मौसम में इन जूतों को रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है, जो रात के समय अद्भुत ही दिखते हैं। इस अद्वितीय कला को हर साल लाखों पर्यटक देखने आते हैं, जिससे यह स्थान स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है। धीमी शटर स्पीड से ली गई यह तस्वीर न केवल इस ऐतिहासिक संरचना की सुंदरता को दिखाती है बल्कि आधुनिक रोशनी के प्रभाव और परिवहन की गतिशीलता का भी उदाहरण है।

प्रसंगवश

रोडवेज की बसों में सुविधाएं नहीं होंगी तो कहां से आएंगे यात्री

रोडवेज, निजी बस सेवा के मुकाबले अपनी सेवाओं को कमतर करते हुए यात्रियों को दूर करती जा रही है

'शुभास्ते पन्थान संतु।' राजस्थान रोडवेज के इस ध्येय वाक्य को देखकर ही लगता है कि यात्रियों की राह मंगलमय होने की कामना की जा रही है। लेकिन रोडवेज बसों की हालत को देखकर लगता नहीं कि यह यात्रा इस ध्येय वाक्य के अनुरूप होने वाली है। ताजा मामला रोडवेज के बस बेड़े में खरीदी गई 510 नई बीएस-6 मॉडल बसों का है। कहने को तो सरकार ने ये बसें यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने और पर्यावरण अनुकूल वातावरण प्रदान करने के मकसद से अपने बेड़े में शामिल की है। लेकिन नई बसों में सीटों की बीच की जगह कम करने से यात्रियों की यात्रा परेशानी भरी हो गई है। लंबी दूरी की यात्रा तो सचमुच दर्दभरी हो रही है क्योंकि इसमें यात्रियों के पैर टकराते हैं, घुटने अटक जाते हैं तो पैरों में दर्द की समस्या बढ़ जाती है।

राजस्थान रोडवेज एक तरफ घाटे से जूझती रहती है वहीं निजी क्षेत्रों की बस सेवा के मुकाबले अपनी सेवाओं को कमतर करते हुए यात्रियों को दूर करती जा रही है। हैरत की बात यह है कि नई बसों में भी यात्री सुविधाओं की अनदेखी की गई है। इस बात की चिंता करनी ही होगी कि आखिर रोडवेज की इन बसों के मुकाबले निजी बस संचालकों की बसें खचाखच क्यों नजर आती है? क्यों सरकारी बस स्टेंडों के आसपास से ही निजी बसों के संचालन को छूट मिलती है। सवाल यह भी उठता है कि क्या ऐसी नई बसें, जो यात्रियों के लिए असुविधाजनक साबित हो रही हैं, रोडवेज को निजी क्षेत्र से मुकाबला करने में मदद करेंगी? यात्रियों को बस सेवाओं को लेकर सिर्फ वाहनों की संख्या बढ़ाने से ही संतुष्ट नहीं किया जा सकता। बसों में उन सुविधाओं को शामिल करना होगा जो निजी बसों में नजर आती है। बसों की यह दशा तो तब है जब रोडवेज ने अपनी पुरानी खस्ताहाल बसों को बेड़े से हटाकर ये नई बसें खरीदने की तैयारी की थी। नई बसों में खरीद के दौरान यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। रोडवेज पहले ही अपनी बसों की खस्ताहालत के लिए बदनाम है। यहां तक कि वातानुकूलित बस सेवाओं में भी यात्री सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जाता। और तो और, निजी बस संचालकों को फायदा पहुंचाने की गरज से रोडवेज ने कई मार्गों पर या तो अपनी वातानुकूलित बसों को बंद ही कर दिया या उनके फेरे घटा दिए हैं। रोडवेज को घाटे से उबारना है, तो उसे बसों की संख्या के साथ सुविधाएं बढ़ाने पर भी ध्यान देना होगा।

- युगलेश शर्मा
yuglesh.sharma@epatrika.com

महिला सशक्तीकरण : समाज और सरकार के प्रोत्साहन की जरूरत

पर्यटन क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण से महिलाओं की बढ़ेगी भागीदारी

डॉ. अनुकृति शर्मा
एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य और प्रबंधन विभाग, निदेशक कौशल विकास केंद्र, कोटा विश्वविद्यालय
@patrika.com

पर्यटन उद्योग आज देशभर में तेजी से बढ़ता हुआ आर्थिक क्षेत्र है। यह उद्योग रोजगार के अवसरों का एक प्रमुख स्रोत है, विशेषकर महिलाओं के लिए। महिलाएं अक्सर आतिथ्य, आवास, खानपान और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में कार्यरत होती हैं, जिनका स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में योगदान होता है। महिलाएं न केवल पर्यटन क्षेत्र में बड़ी संख्या में कार्यरत हैं, बल्कि वे इस क्षेत्र के विकास और प्रगति में महती भूमिका निभा रही हैं। पर्यटन शिक्षा इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने और उन्हें सशक्त बनाने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए वर्ष 2020 में भारतीय ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन और फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। गैर सरकारी संगठनों, कार्यान्वयन एजेंसियों, ट्रैवल उद्योग संघों आदि द्वारा आयोजित कार्यशालाओं के माध्यम से महिलाओं को तैयार किया और आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए ग्रामीण और शहरी होम स्टे की महिलाओं के नेतृत्व वाली पहल की।

पर्यटन मंत्रालय ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सभी राज्य सरकारों और उद्योग हितधारकों के साथ परामर्श कर ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप तैयार किया। पर्यटन उद्योग में प्रवेश करने की इच्छुक महिलाओं के सामने एक प्रमुख चुनौती प्रशिक्षण की कमी है। इस अंतर को पाटने के लिए कई सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों ने विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं और क्षमता निर्माण की पहल करने के लिए सहयोग किया है। ये कार्यक्रम न केवल महिलाओं को आवश्यक तकनीकी कौशल देते हैं, बल्कि आत्मविश्वास और नेतृत्व गुणों को स्थापित करने पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। चूंकि पर्यटन क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को कभी-कभी सुरक्षा संबंधी चिंताओं और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता हैं। सुरक्षित कार्य वातावरण बनाने के लिए कड़े कानूनों, जागरूकता अभियानों और शिकायत तंत्र की भी जरूरत महसूस की जाती है। कुछ जगह महिलाओं को गलत प्रथाओं और भेदभाव का सामना करना पड़ता है जो उनकी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है और उनकी क्षमता को सीमित करता है। होटल, रेस्तरां, ट्रैवल एजेंसियां, टूर गाइड, हस्तशिल्प और अन्य संबंधित क्षेत्रों में महिलाएं बड़ी संख्या में कार्यरत हैं। पर्यटन क्षेत्र में महिला उद्यमियों की संख्या बढ़ रही है। वे अपने स्वयं के व्यवसाय शुरू कर रही हैं, जैसे कि होम स्टे, गेस्ट हाउस, टूर ऑपरेटर, और हस्तशिल्प की दुकानें। यह उन्हें अपनी रचनात्मकता और कौशल का उपयोग करने, आर्थिक रूप से सशक्त होने और अपने समुदायों के विकास में योगदान करने का मौका देता है। पर्यटन उद्योग महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक के रूप में उभरा है, जो उन्हें आर्थिक अवसरों, सामाजिक उन्नति और व्यक्तिगत विकास के रास्ते प्रदान करता है।

हालांकि महिलाओं को अक्सर शिक्षा, वित्त और प्रशिक्षण के अवसरों तक सीमित पहुंच का सामना करना पड़ता है, जिससे पर्यटन उद्योग में उनकी भागीदारी बाधित होती है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करना होगा जो महिलाओं को इन संसाधनों तक समान पहुंच प्रदान करते हैं। पर्यटन शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को इस क्षेत्र में आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करने की जरूरत है, जिससे वे विभिन्न जगहों पर काम करने के लिए तैयार हो सकें। सरकार को पर्यटन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और अधिक निवेश करना चाहिए। महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पर्यटन से जुड़े रोजगार परक कोर्स संचालित किए जाने चाहिए। पर्यटन उद्योग को महिलाओं के लिए और अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए। समाज को भी महिलाओं को पर्यटन क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

सख्त कदम : निजी के साथ सार्वजनिक क्षेत्र में भी हो रहे प्रयोग

नई तकनीकों का लाभ उठाने के लिए खर्चों में कटौती की कवायद

एड्रियन वूल्ड्रिज
ग्लोबल बिजनेस स्तंभकार
ब्लूमबर्ग
वाशिंगटन पोस्ट से विशेष अनुबंध के तहत

सामान्य परिस्थितियों में 'विराम लगाने या रुकावट' डालने की विचारधारा निजी क्षेत्र से लेकर सार्वजनिक क्षेत्र तक तेजी से फैल रही है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने दस मंत्रालयों को कम कर दिया है, सार्वजनिक खर्च को एक तिहाई कम किया है। इधर, अमरीका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने सरकारी खर्च को कम करने के लिए एलन मस्क को एक नए विभाग गवर्नमेंट ऑफ एफिशिएंसी (डीओजीइ) की जिम्मेदारी सौंपी है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे कटौती में माहिर हैं। यहां तक कि ब्रिटिश लेबर सरकार ने भी इस ओर कदम बढ़ा दिए हैं। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने बदलाव के लिए कई सिविल सेवकों पर टिप्पणी की है। कैबिनेट मंत्री पैट मैकफैडेन ने कहा है कि वह चाहते हैं कि स्टार्टअप विभिन्न तरीकों का परीक्षण करके नए दृष्टिकोण से काम करे। एयरबीएनबी, वाट्सएप और स्पॉटिफाइ जिस तरह से उभरे हैं, हम सार्वजनिक क्षेत्र में वही साहसी भावना क्यों नहीं अपना सकते?

यह देखना दिलचस्प होगा कि इस तरह की भावनाएं इतनी लोकप्रिय क्यों हैं। कुछ हद तक, सार्वजनिक क्षेत्र की उत्पादकता निजी क्षेत्र की उत्पादकता से काफी पीछे है, क्योंकि 'सुपर स्टारों' को बर्खास्त करना या पुरस्कृत करना बहुत कठिन है। सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारी 'सुपरवाइजर्स' का पटल बनाने के आदी हैं। अमरीकी सेना में अधिकारियों और सूचीबद्ध कर्मियों का अनुपात पिछले दो दशकों में दोगुना हो गया है। उन्हें किसी बदलाव का विरोध करने की विशेषज्ञता भी हासिल है। सिविल सेवकों के बारे में सबसे बड़ी कॉमेडी उनकी 'यस मिनिस्टर' कहने को लेकर है। प्रशासनिक मामलों के विभाग के एक मुखिया का कहना है कि 'हां' का मतलब हमेशा 'नहीं' होता है और 'अभी नहीं' का अर्थ हमेशा 'कभी नहीं' होता है। अर्थशास्त्री विलियम बॉमोल ने रेखांकित किया था कि श्रम-सघन संगठनों में दक्षता बढ़ाना काफी कठिन है। ज्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन श्रम-सघन हैं। पर एआइ क्रांति ने अब नौकरशाही प्रक्रियाओं को स्वचालित करने का मौका प्रदान किया है। सवाल यह है कि क्या 'विराम लगाने या रुकावट' डालने की प्रक्रिया अपनी कुंठाओं से निपटने या नई तकनीक के अवसरों का लाभ उठाने का सबसे अच्छा तरीका है? सार्वजनिक क्षेत्र मौलिक रूप से निजी क्षेत्र से काफी अलग है। निजी कंपनियां व्यवधान की संस्कृति से विफल हो सकती हैं। 'व्यवधान' के सिद्धांत के साथ मूल समस्या यह है कि यह अनुत्पादक हो सकती है, यह सुधारों को बदनाम कर देती है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लिज ट्रूस ने देश को आर्थिक संकट से उबारने के लिए आर्थिक योजना पेश की थी जिसके असफल होने से आर्थिक उथलपुथल उत्पन्न हो गई और उन्हें केवल 49 दिन में ही इस्तीफा देना पड़ा। एलन मस्क की यूएस को टेस्ला-एंड-ट्विटर ट्रीटमेंट देने की योजना आधी-अधूरी ही दिखती है।

मस्क ने देश के खर्चों में से 2 ट्रिलियन डॉलर की कटौती करने का वादा किया है, बिना यह बताए कि वह सामाजिक सुरक्षा भुगतान में कितनी कटौती करेंगे। सरकारी दक्षता विभाग में उनके सह-प्रमुख विवेक रामास्वामी ने संकेत दिए हैं कि वह आधे संघीय कर्मचारियों को बर्खास्त कर देंगे। फिर भी देखा जाए तो यूएस सरकार में नियुक्तियों पर वास्तविक खर्च ठेकेदारों पर हुआ है, प्रत्यक्ष कर्मचारियों पर नहीं, जिनकी संख्या दशकों से स्थिर बनी हुई है।

एक तथ्य यह भी है कि निजी कंपनियां पहले से ही 'लॉर्ज लैंग्वेज मॉडल' समेत अन्य चीजों में अपनी कुछ अपेक्षाओं को कम करना शुरू कर रही हैं। एआइ निजी क्षेत्र में गंभीर समस्या है और यह सार्वजनिक क्षेत्र में भी घातक साबित हो सकता है। पर आने वाले एक दशक में एआइ-संचालित सुधार महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं। निश्चित रूप से यह दखलअंदाजी ताकतवर उपकरण हो सकती है पर केवल तभी, जब इसे बड़े धमाके की बजाय नियंत्रित प्रयोग में लाया जाए।

आपकी बात

अधिकृत संस्था से ही लें बीमा

बीमा एजेंट्स से लिखित में लें कि मैच्योरिटी, एक्सीडेंटल या मेडिकल क्लेम के समय बीमा राशि का सही भुगतान होगा। आजकल कुछ एजेंट केवल अपने टारगेट के लिए सही जानकारी नहीं देते हैं। बीमा हमेशा आरबीआइ अधिकृत बैंक या लाइसेंस प्राप्त कंपनियों से लिया जाए।

- मुकेश सोनी, जयपुर

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की अन्य प्रतिक्रियाएं

पत्रिकायन का सवाल था, 'बीमा कंपनियों की मनमानी को रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं?' प्रतिक्रियाएं ऑनलाइन भी देखें।

इसे स्कैन करें
https://shorturl.at/NDJKq

आज का सवाल

सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आम जनता क्या करे?

ईमेल करें
edit@epatrika.com

चिंतन

काश संसद में संविधान के लक्ष्यों पर बहस होती

संसद में संविधान पर चर्चा एक अच्छी पहल है। भारतीय संविधान ने अपनी 75 वर्ष की यात्रा पूरी कर ली है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तब से देश ने संविधान के लक्ष्यों के अनुरूप अनेक स्तर पर प्रगति की है, लेकिन कई लक्ष्य अधूरे भी हैं। यह समीक्षा होनी ही चाहिए कि 75 वर्ष की यात्रा में लक्ष्यों की स्थिति क्या है? संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन की दशा व दिशा क्या है? हालांकि सरकार संसद में संविधान पर बहस विपक्ष की मांग के बाद करवा रही है, लेकिन संविधान के लक्ष्यों पर बात होती तो देश लाभान्वित होता। इसमें जो गौर करने वाली बात है कि विपक्ष ने आरोप के साथ संविधान पर बहस शुरू की है, ये ऐसे आरोप हैं जिसमें राजनीति के सिवा कोई तथ्य नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव के समय से कांग्रेस ने एक नैरेटिव गढ़ा है कि भाजपा नीत राजग सरकार संविधान बदलना चाहती है, भाजपा के बयानवीर नेताओं ने मौका भी दिया, जबकि तथ्यात्मक रूप से यह संभव नहीं है। अब तक करीब 126 संविधान संशोधन हुए हैं, जिनमें से करीब 98 से अधिक कांग्रेस सरकार के समय हुए हैं। संविधान में संशोधन वक्त की जरूरत के हिसाब से संसद के जरिये होते हैं, संशोधन करना संविधान बदलना नहीं है। संविधान पर चर्चा इसे बदलने के राजनीतिक आरोप के साथ नहीं होनी चाहिए, बल्कि विपक्ष को तथ्यों के साथ संसद में यह बात रखनी चाहिए कि अधूरे लक्ष्य कौन-कौन हैं? डा. भीमराव आंबेडकर ने संविधान में राजनीतिक लोकतंत्र के साथ सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की अवधारणा को भी समावेशित किया था, संविधान ने 75 वर्ष में इन लक्ष्यों को हासिल नहीं किया है। संविधान में वर्णित समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकारों पर आधारित राष्ट्र निर्माण और उसे मजबूत करने के लक्ष्यों में देश की राजनीति बाधक बन रही है। जातिगत व संप्रदायगत राजनीति देश की एकता व अखंडता और भाईचारे का बड़ा नुकसान कर रही है। यह समय सभी राजनीतिक दलों के लिए ठहर कर सोचने का है कि वे अपनी-अपनी विभाजनकारी राजनीति से देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं। संविधान पर चर्चा के दौरान चाहे कांग्रेस सांसदों ने अपनी बात रखी हो, या सत्ता पक्ष से भाजपा सांसदों ने अपनी बात रखी हो, सभी ने केवल एक-दूसरे पर आरोप लगाए हैं। किसी ने भी ईमानदारी से संविधान के लक्ष्यों पर चर्चा नहीं की है। संविधान में आरक्षण का प्रावधान दस वर्ष के लिए था, यह राजनीतिक एजेंडा क्यों बना हुआ है? देश में जातिगत आरक्षण के फायदों को लेकर सोशल ऑडिट क्यों नहीं हुआ है? सामाजिक न्याय की बात होती है, पर इसके लिए राष्ट्रीय पैमाना अब तक क्यों नहीं तय हुआ? जातिवाद के खात्मे के लिए सरकारी प्रयास क्यों नहीं हुए? जाति गणना से राष्ट्र को क्या लाभ होने वाला है? सामाजिक पिछड़ेपन का आधार जाति क्यों है? संसदीय व दलीय राजनीति में समावेशी प्रतिनिधित्व की अवधारणा केवल चुनावी समीकरण तक क्यों सीमित हैं? आमजन के लिए इंसाफ के दरवाजे तक पहुंच सरल क्यों नहीं है? सरकार अपनी विफलताओं के लिए जवाबदेह क्यों नहीं है? ऐसे अनेक प्रश्न हैं, जिस पर संसद में बहस होनी चाहिए, पर दुर्भाग्य यह है कि न ही विपक्ष के पास संविधान पर चर्चा के विषय की तैयारी है और न ही सत्ता पक्ष की रुचि है। लग रहा है जैसे कांग्रेस केवल भाजपा पर आरोप लगाने के लिए संविधान पर चर्चा कर रही है। न संविधान बदल रहा है न इस पर कोई खतरा है।

श्रद्धांजलि

गीता शुक्ला

अब किसे कहेंगे 'वाह उस्ताद'

> उस्ताद जाकिर हुसैन की मृत्यु से सारा देश उदास है। वे सर्वप्रिय थे। उस्ताद जाकिर हुसैन अपनी अद्भुत तकनीक और तबले पर महारत के लिए सदैव याद किए जाएंगे। उनकी लय और ताल की समझ अविश्वसनीय थी। वे जटिल तालों को भी सहजता से बजाते थे, जिससे संगीत में एक अलग ही रंगत आ जाती थी। जाकिर हुसैन का संगीत सिर्फ तकनीकी कौशल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें भावनाओं की गहराई भी है। उनकी हर थाप में एक कहानी छिपी होती है, जो दर्शकों के दिलों को छू जाती है। वो फरवरी का महीना था और साल था 2012 । राजधानी दिल्ली में उस दिन शास्त्रिय संगीत के रसिया नेहरू पार्क का रुख कर रहे थे जाकिर हुसैन के जादू को देखने के लिए।

उस्ताद जाकिर हुसैन का एक चित्र महान कथक नृतक बिरजू महाराज के राजधानी के शाहजहां रोड के फ्लैट में ड्राइंग रूम में लगा हुआ था। उसमें उस्ताद जाकिर हुसैन और बिरजू महाराज खिलखिला रहे हैं। उसे देखकर बिरजू महाराज कहते थे, उस्ताद जाकिर हुसैन से बेहतर तबला वादक अब कोई पैदा नहीं होगा। ये दोनो ही अपनी-अपनी कलाओं के महारथी थे, और जब वे साथ में प्रस्तुति करते, तो एक जादुई माहौल बन जाता था। उस्ताद जाकिर हुसैन की मृत्यु से सारा देश उदास है। वे सर्वप्रिय थे। उस्ताद जाकिर हुसैन अपनी अद्भुत तकनीक और तबले पर महारत के लिए सदैव याद किए जाएंगे। उनकी लय और ताल की समझ अविश्वसनीय थी। वे जटिल तालों को भी सहजता से बजाते थे, जिससे संगीत में एक अलग ही रंगत आ जाती थी। जाकिर हुसैन का संगीत सिर्फ तकनीकी कौशल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें भावनाओं की गहराई भी है। उनकी हर थाप में एक कहानी छिपी होती है, जो दर्शकों के दिलों को छू जाती है। वो फरवरी का महीना था और साल था 2012 । दिल्ली में जाड़ा पड़ रहा था। उस दिन राजधानी के शास्त्रीय संगीत के रसिया नेहरू पार्क का रुख कर रहे थे उस्ताद जाकिर हुसैन के जादू को देखने के लिए।

उस्ताद जाकिर हुसैन ने अपनी उंगलियों और हथेलियों से ऐसी ध्वनियां निकालीं, जो पहले कभी नहीं सुनी गईं थीं। दरअसल उस दिन तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन ने नेहरू पार्क में शिव कुमार शर्मा के साथ जुगलबंदी पेश की थी। करीब 500 संगीत प्रेमियों के बीच जब दोनों उस्तादों ने तान छेड़ी तो फिर जो समां बंधा उसे कौन शब्दों में बयां कर कर सकता है। करीब दो घंटे की गुगलबंदी में दोनों उस्तादों ने अपने चाहने वालों की भरपूर तालियां बटोरीं। अफसोस कि उस जुगलबंदी के दोनों उस्ताद अब संसार में नहीं रहे। उस्ताद जाकिर हुसैन दिल्ली में बीती आधी सदी से भी अधिक समय से अपने कार्यक्रम दे रहे थे। भारतीय संगीत को उनके खास अंदाज की वजह से अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली थी। उन्होंने दिल्ली में दर्जनों कंसर्ट पेश किए। वे दशकों से दिल्ली में आ रहे थे। जाकिर हुसैन ने कमानी सभागार में 2019 में एक यादगार प्रस्तुति दी थी। मौका था श्रीराम कला केन्द्र के संस्थापक लाला चरत राम की याद में आयोजित एक कार्यक्रम का। उसमें श्रीराम कला केन्द्र की प्रमुख शोभा दीपक सिंह ने बताया था कि जाकिर हुसैन श्रीराम कला केन्द्र के कार्यक्रमों में अपने पिता उस्ताद अल्लाह रक्खा खान के साथ आते थे।

उस समय वे 15-16 के थे। जाकिर हुसैन ने जब दिल्ली के कमानी सभागार में प्रस्तुति दी, तो वह एक अविस्मरणीय शाम थी। उनके तबले की गूंज पूरे सभागार में छा गई और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कला मर्मज्ञ डॉ. रविन्द्र कुमार उस्ताद जाकिर हुसैन के निधन का समाचार सुनकर गमगीन हो गए।

कहने लगे, जाकिर हुसैन का कोई सानी नहीं था। उनकी उंगलियां तबले पर ऐसे चलती थी जैसे कोई जादू हो। उनकी लयकारी और ताल की समझ अद्भुत थी। वे हर ताल को नए अंदाज में पेश करने में माहिर थे। उस्ताद जाकिर हुसैन की लय पर पकड़ अद्भुत थी। उनकी उंगलियां तबले पर इस तरह नाचती थी कि हर ताल और लय स्पष्ट और सटीक होती थी। वह पारंपरिक तबला

वादन में तो माहिर थे ही, साथ ही उन्होंने अपनी तकनीक में कई नए तत्वों को भी जोड़ा भी। वे विभिन्न प्रकार की तालों और लय में कुशलता से तबला बजाते थे। उनकी गति अविश्वसनीय थी। वे बहुत तेज गति से तबला बजा सकते थे, लेकिन उनकी सटीकता और स्पष्टता कभी कम नहीं होती। जाकिर हुसैन सिर्फ तबला नहीं बजाते, बल्कि संगीत के साथ संवाद करते थे।

वे अन्य संगीतकारों के साथ मिलकर शानदार संगीत बनाते थे। उनके तबले वादन में गहरी भावनाएं होती थीं। वे अपनी कला से खुशी, दुख, उत्साह और शांति जैसे विभिन्न भावों को व्यक्त कर सकते थे। वे भारतीय शास्त्रीय संगीत के साथ-साथ जैज़ और फ्यूजन संगीत में भी माहिर थे। उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों के संगीत को एक साथ मिलाकर एक नई शैली बनाई। जाकिर हुसैन ने कई युवा तबला वादकों को प्रेरित किया। उन्होंने तबला वादन को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया। वे हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते थे। उन्होंने तबले वादन के क्षेत्र में कई नए प्रयोग किए और इस कला को आगे बढ़ाया। वे दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित तबला वादकों में से एक थे। उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान जीते हैं। इतने बड़े कलाकार होने के बावजूद, जाकिर हुसैन बहुत ही सरल और विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। वे अपने संगीत के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते थे। वे अपने संगीत और दर्शकों के प्रति गहरा प्यार रखते थे। वे दर्शकों के सवालों के जवाब देते थे, उनसे बतियाते थे। उस्ताद जाकिर हुसैन को भारत और दुनियाभर में बसे उनके चाहने वाले सदैव याद रखेंगे।

जाकिर हुसैन का जन्म 9 मार्च, 1951 को मुंबई में हुआ था। वे उस्ताद अल्लाह रक्खा खान के पुत्र थे, जो खुद एक प्रसिद्ध तबला वादक थे। जाकिर ने तबला बजाना तभी शुरू कर दिया था जब वे ड्रम तक पहुंच सकते थे। अपने पिता के साथ उनका अध्ययन गहन था 'आप दिन के 24 घंटे संगीत के माहौल में बड़े होते हैं,' उन्होंने कहा, 'और आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है।' उन्हें एक नवोन्मेषक के रूप में याद किया जाएगा। वे नवाचार को निरंतरता के साथ संतुलित करने की आवश्यकता को समझते हैं: 'आपको अपनी परंपरा के बहुत करीब रहना होगा, लेकिन साथ ही दुनिया की पेशकश में से कुछ को शामिल करने में भी सक्षम होना चाहिए। अब समय आ गया है कि भारतीय संगीत को बाहर की ओर देखना चाहिए, न कि केवल बाहरी दुनिया को भारतीय संगीत से उधार लेने देना चाहिए। जाकिर हुसैन ने न्यूयॉर्क शहर के फिलमोर ईस्ट में रवि शंकर के साथ अपना पहला अमेरिकी प्रदर्शन किया। न्यूयॉर्क में रहते हुए, उनकी मुलाकात गिटारवादक जॉन मैकलॉघलिन से हुई और उनकी दोस्ती ने शक्ति नामक एक संगीत समूह का गठन किया, जिसमें भारतीय वायलिन वादक एल. शंकर भी शामिल थे। पिछले कुछ वर्षों में, जाकिर हुसैन ने कुछ महान भारतीय संगीतकारों के साथ काम किया है और लंदन स्ट्रिंग चौकड़ी और वैन मॉरिसन जैसे विविध कलाकारों के साथ सहयोग किया। उनके हिस्से में दुनिया के तमाम प्रमुख पुरस्कार आए। 1991 में, उन्हें भारत के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान द्वारा संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया और 1996 में वे अटलांटा में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के लिए संगीत रचना में शामिल थे। 73 साल की उम्र में जाकिर हुसैन का निधन हो गया। जाकिर हुसैन ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आखिरी सांस ली। जाकिर हुसैन फेफड़ों से जुड़ी एक गंभीर बीमारी और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज थे। जिसके चलते उन्हें दिल से जुड़ी समस्याएं पैदा हुईं। उनकी कला और संगीत सदियों तक हम सबके दिलों में जीवित रहेंगे।

(लेखिका वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।
लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

दो टूक

रवि शंकर

'रेवड़ी कल्चर' से बिगड़ रही राज्यों की अर्थव्यवस्था

रेवड़ी कल्चर भले ही चुनाव जीतने और सत्ता पाने की गारंटी बन चुका हो, लेकिन इसका नतीजा ये हो रहा है कि राज्यों की आर्थिक सेहत बिगड़ने लगी है और वो कर्ज के बोझ तले दबने लगे हैं। जाहिर है अगर खर्च ज्यादा और आमदनी कम हो, फिर कर्ज तो लेना ही पड़ेगा। इस तरह की घोषणाएं अक्सर तात्कालिक लाभ तो देती हैं, लेकिन दीर्घकालिक आर्थिक दृष्टिकोण से ये देश की वित्तीय स्थिति पर भारी बोझ डालती हैं। भारत जैसे देश में हर तीन-चार महीने बाद किसी न किसी विधानसभा का चुनाव हो रहा होता है और इस नाते राजनीतिक दलों में चुनाव जीतने के लिए रेवड़ी संस्कृति बढ़ती जा रही है। जो वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने के रास्ते में एक बड़ी बाधा है। मालूम हो, देश के दक्षिण राज्यों खासकर तमिलनाडु में सबसे पहले मुफ्त बांटने की सियासत शुरू हुई। यहां चुनाव जीतने के लिए मंगलसूत्र, टीवी, प्रेशर कुकर, वॉशिंग मशीन और साड़ी फ्री में बांटी जाने लगी। तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता के कार्यकाल में अम्मा कैंटीन खूब फली-फूली। दक्षिण भारत के बाद अब ये 'रेवड़ी कल्चर' उत्तर भारत के साथ-साथ पूरे देश में वोट पाने का एक शॉर्टकट जरिया बन चुका है। वोटरों को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों ने मुफ्त बिजली-पानी, अनाज, लैपटॉप, मोबाइल, स्कूटी और बेरोजगारी भत्ता को हथियार बनाया। इसका नतीजा ये हुआ कि आज कई राज्यों की अर्थव्यवस्था कर्ज के बोझ तले दबने लगी है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि यूरोप के कुछ विकसित देश इसी रेवड़ी संस्कृति के कारण आज आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। भारत के पड़ोस में ही श्रीलंका, पाकिस्तान का भी इसी रेवड़ी संस्कृति ने बुरा हाल किया है। अपने देश में ही देखा जाए तो कई राज्य सरकारें इस रेवड़ी संस्कृति के कारण लगभग दीवालिया होने की कगार पर हैं। उनका बजट घाटा बढ़ता जा रहा है, लेकिन वे मुफ्तखोरी की राजनीति का परित्याग करने के लिए तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक मुफ्त की योजनाओं की वजह से आर्थिक असंतुलन और विकास पर पड़ने वाले विपरीत असर को लेकर चिंता व्यक्त करते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चार अगस्त 2022 में इस मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि चुनाव आयोग ने इस मामले में समय रहते कदम उठाया होता है तो शायद कोई भी राजनीतिक दल ये हिम्मत नहीं करता। लेकिन अब मुफ्त रेवड़ियां बांट कर वोट बटोरना भारत के राजनीतिक दलों का मुख्य हथियार बन गया है। अहम प्रश्न ये है कि लोकलुभावन वादों को नैतिक माना जाए या अनैतिक? क्या इन पर रोक नहीं लगनी चाहिए? इसे लेकर देश में दशकों से प्रश्न उठाए जाते रहे हैं। इस पर राजनीतिक दलों की राय अलग-अलग है। मुफ्त के वादे करने वाले दलों का तर्क है कि देश के विकास और समाज में समानता लाने के लिए ऐसा करना जरूरी है, अन्यथा समाज में विषमता बनी रहेगी। वहीं, विरोध करने वालों का कहना है कि ऐसी घोषणाएं आर्थिक ढांचे को कमजोर करने और असंतुलन बढ़ाने के अतिरिक्त कुछ नहीं करतीं। सुप्रीम कोर्ट भी इस मुद्दे पर एक राय व्यक्त नहीं कर सका है। इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी 'रेवड़ी कल्चर' से देश को होने वाले नुकसान को लेकर आगाह कर चुका है। 'स्टेट फाइनेंसेसः अ रिस्क एनालिसिस' नाम से आई आरबीआई की रिपोर्ट की मानें तो पंजाब, राजस्थान, केरल, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की हालत डांवाडोल है। सब्सिडी पर राज्य सरकारों के खर्च में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे कर्ज बढ़ता जा रहा है। सब्सिडी पर सबसे ज्यादा खर्च उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, केरल और तेलंगाना ने किया। वहीं पंजाब, गुजरात और छत्तीसगढ़ सरकार ने सब्सिडी पर अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 10 फीसदी से ज्यादा खर्च किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकारें सब्सिडी की बजाय मुफ्त दे रही हैं, जिससे फ्री पानी, फ्री बिजली, बिल माफी और कर्ज माफी से सरकारों को कोई कमाई नहीं हो रही है। उल्टे सरकार को इस पर खर्च करना पड़ रहा है। बहरहाल, वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा है कि राजनीतिक दलों ने 'रेवड़ी कल्चर' को अपना अधिकार समझ लिया है। उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि जनता को जानने का अधिकार है कि उससे किए जा रहे वादे कैसे पूरे होंगे? उनके लिए धन कहां से आएगा? साथ ही, उन्होंने इस बाबत उम्मीदवारों या संबंधित राजनीतिक दलों से एक प्रपत्र भरवाने की प्रक्रिया शुरू करने की बात भी कही है। चुनाव आयोग के इस रुख से उम्मीद जगी है कि देरे-सबेर 'रेवड़ी कल्चर' पर रोक लगेगी।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

ईश्वर के सान्निध्य में ही मिलता है आत्मबल

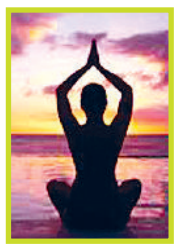

संकलित

दर्शन

जब व्यक्ति किसी कार्य को करने चलता है, तो उसके मन-हृदय में बारंबार विचार-भाव उठते हैं कि वह कार्य करें या नहीं, उससे होगा या नहीं और परिणाम भी सफलता और असफलता के रूप में सामने आता है। किसी कार्य को करने के लिए बल की आवश्यकता होती है। इसके बिना उसको गति देना असंभव है। कई बार किसी कार्य को करते समय नाना-प्रकार के संकट उसमें बाधा बन खड़े हो जाते हैं। ऐसे में कोई व्यक्ति उस कार्य को बीच में ही छोड़ देता है। परिणामस्वरूप उसे असफलता हाथ लगती है। असफलता यह सिद्ध करती है कि अमुक कार्य को पूरे मनोयोग से नहीं किया गया। मनोयोग का अर्थ होता है-तन, मन और हृदय से समर्पित होकर किसी कार्य को करना। किसी कार्य में सफल होने के लिए व्यक्ति में मानसिक संतुलन, विश्वास, जिज्ञासा, लगन, संघर्ष करने की क्षमता और तन्मयता जैसे गुणों का होना जरूरी होता है। इनकी प्राप्ति आत्मबल से होती है। आत्मबल की प्राप्ति के लिए ईश्वर के सान्निध्य में जाना पड़ता है। सान्निध्य पाने के लिए ईश्वर का विश्वास आवश्यक है। विश्वास पाने के लिए तप-साधना करनी पड़ती है। चूंकि आत्मबल में ईश्वर की शक्ति निहित होती है, इसीलिए इसे ब्रह्मबल भी कहते हैं। आत्मबल से संपन्न मनीषी के लिए कोई कार्य असंभव नहीं रहता है। उसका कोई कार्य बीच में नहीं रुकता है। जब शरीरबल और मनोबल टूट जाता है तो उस समय आत्मबल सहारा देता है। आत्मबल से युक्त व्यक्ति कभी हताश-निराश नहीं होता है।

मंत्र का असर

संकलित

प्रेरणा

एक निर्धन औरत एक साधु के पास गई, 'स्वामी जी! कोई ऐसा पवित्र मन्त्र लिख दीजिये जिससे मेरे बच्चों का रात को भूख से रोना बन्द हो जाये...।'साधु ने कुछ पल एकटक आकाश की ओर देखा फिर अपनी कुटिया में अन्दर गया और एक पीले कपड़े पर एक मन्त्र लिखकर उसे ताबीज की तरह लपेट-बाँधकर उस महिला को दे दिया। साधु ने कहा, 'इस मन्त्र को घर में उस जगह रखना, जहाँ अपनी मेहनत की कमाई का धन रखती हो।' महिला खुश होकर चली गई। ईश्वर कृपा से उस दिन उसके पति की आमदनी ठीक हुई और बच्चों को भोजन मिल गया। रात शान्ति से कट गई। अगले दिन भोर में ही उन्हें पैसों से भरी एक थैली घर के आंगन में मिली। थैली में धन के अलावा एक पर्चा भी निकला, जिस पर लिखा था, कोई कारोबार कर लें...। इस बात पर अमल करते हुवे उस औरत के पति ने एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली और काम शुरू किया। धीरे धीरे कारोबार बढ़ा, तो दुकानें भी बढ़ती गईं...। जैसे पैसों की बारिश सी होने लगी...। पति की कमाई तिजोरी में रखते समय एक दिन उस महिला की नज़र उस मन्त्र लिखे कपड़े पर पड़ी...। 'न जाने, साधु महाराज ने ऐसा कौन सा मन्त्र लिखा था कि हमारी सारी तंगी दूर हो गई?' सोचते सोचते उसने वह मन्त्र वाला कपड़ा खोल डाला...। जिस लिखा था कि.. जब पैसों की तंगी समाप्त हो जाये, तो सारा पैसा तिजोरी में छिपाने की बजाय कुछ पैसे ऐसे घर में डाल देना जहाँ से रात को बच्चों के रोने की आवाज़ें आती हों..!!

अंतर्मन

आज की पाती

बांग्लादेश का हिंदू किसके भरोसे?

विश्व के अनेक देशों में आज युद्ध की जो स्थिति बनी हुई है, वैसा ही संकट बांग्लादेश में उत्पन्न हो रहा है। इस संकट का बीजारोपण आज नहीं, बल्कि धर्म और जिहाद की आड़ में वर्षों पहले ही रोपित हो चुका था। बांग्लादेश, जो कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भारत का घनिष्ट पड़ोसी है, वहां अल्पसंख्यक समुदाय, विशेष रूप से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार न केवल मानवाधिकारों का हनन है, बल्कि यह क्षेत्रीय स्थिरता और भारत-बांग्लादेश संबंधों के लिए भी चुनौती बन गया है। बीते कुछ वर्षों में, बांग्लादेश में चरमपंथी ताकतों का उभार हुआ है और उनके हाथों में सत्ता की चाबी आने के बाद से स्थिति और भी विकट हो गई है। बांग्लादेश में हिंदू लंबे समय से उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। - *सतीश जायसवाल, दुर्ग*

ट्रेंड

वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि

आज, विजय दिवस पर, हम उन बहादुर सैनिकों के साहस और बलिदान का सम्मान करते हैं जिन्होंने 1971 में भारत की ऐतिहासिक जीत में योगदान दिया था। यह दिन उनकी असाधारण वीरता और उनकी अटल भावना को श्रद्धांजलि है। उनका बलिदान हमेशा प्रेरित करेगा।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

घोटालों से पहचान

मध्य प्रदेश की पहचान आज घोटालों से हो गई है। किसान के साथ खाद और बीज में घोटाला, नौजवानों के साथ रोज़गार में घोटाला और हर काम में घोटाला। किसान खाद बीज और फसल के सही दाम के लिए परेशान हो रहे हैं।

-कमलनाथ, पूर्व सीएम मप्र

भ्रष्टाचार और भूमाफिया

बरेली में लापता लेखापाल का सिर नाले में मिलने के बाद परिजनों ने उप्र के अंदर चल रही उस सांठगांठ पर अंदेशा जताया है जिसके एक छोर पर सरकारी भ्रष्टाचार और दूसरे छोर पर भूमाफिया है।

-अखिलेश यादव, सपा सांसद

ज़ाकिर के निधन पर दुख

ज़ाकिर हुसैन के निधन के बारे में सुनकर गहरा दुख हुआ। एक सच्चे उस्ताद के रूप में, मंच पर उनकी उपस्थिति किसी रॉक स्टार से कम नहीं थी। उन्होंने भारतीय और वैश्विक संगीत पर अमिट छाप छोड़ी।

-अनिल कपूर, अभिनेता

करंट अफेयर

भारतीयों के लिए द. अफ्रीका में पर्यटन की संभावनाएं

दक्षिण अफ्रीका की पर्यटन मंत्री पैट्रिसिया डी लिली ने हाल में भारत की यात्रा से लौटने के बाद कहा कि भारतीय बाजार के लिए एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में दक्षिण अफ्रीका में अपार संभावनाएं हैं। डी लिली ने भारत में दक्षिण अफ्रीका के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य भारतीय पर्यटन व्यापारियों, टूर ऑपरेटर और संघों, कारोबारी दिग्गजों और मीडिया के साथ सीधे संपर्क स्थापित करना था। इस मकसद था कि भारत से दक्षिण अफ्रीका आने वाले पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए निकट सहयोग से काम किया जा सके। डी लिली ने कहा, 'इस मिशन का उद्देश्य पर्यटन उद्योग के दिग्गजों और पर्यटन मूल्य श्रृंखला में अन्य प्रासंगिक हितधारकों के साथ संवाद के माध्यम से संबंध बनाना तथा पर्यटन को आर्थिक विकास के एक उपकरण के रूप में महत्व देना था।' उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की जी-20 अध्यक्षता के दौरान यहां पर्यटन संबंधी स्थलों को बढ़ावा देने पर भी टिप्पणी की। दक्षिण अफ्रीका ने इस वर्ष एक दिसंबर को ब्राजील से जी-20 समूह की अध्यक्षता संभाली।

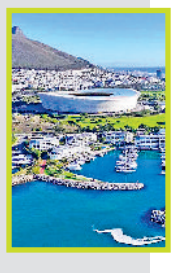

ऑफ बीट

गर्म होती दुनिया में पक्षी अपना स्वरूप बदल रहे

हालिया शोधों से पता चला है कि, तापमान वृद्धि के कारण, समय के साथ ऑस्ट्रेलियाई पक्षियों की 100 से अधिक प्रजातियों के शरीर छोटे और चोंच बड़ी हो गई हैं। जब हम आकार बदलने की बात करते हैं, तो हम 'वेयरवुल्फ' (एक व्यक्ति जो कुछ समय के लिए भेड़िये में बदल जाता है) या 'एंट-मैन' की बात नहीं कर रहे हैं। बल्कि, हम शरीर के आकार के छोटे होने और चोंच, पूंछ जैसे उपांगों के बड़े होने की बात कर रहे होते हैं। इससे जीवों को ज्यादा गर्मी को अधिक कुशलता से सहन करने में मदद मिलती है। जिस प्रकार रेडिएटर में गर्म पानी की पाइप परिधि के माध्यम से आंतरिक गर्मी को फैलाने में मदद करती है, उसी प्रकार पक्षियों की चोंच रक्त वाहिकाओं से जुड़ी होती है जो गर्मी को शरीर से चोंच तक स्थानांतरित करती है, जहां से यह पर्यावरण में घुल जाती है। इस तरह, रेडिएटर और चोंच दोनों के लिए, संरचना के सतह क्षेत्र को बढ़ाने से गर्मी का लोप अधिकतम हो जाता है। शरीर के आकार और गर्मी के लोप के बीच संबंध के कारण यह अनुमान लगाया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण वक्त के साथ जानवरों के शरीर का आकार बदल जाएगा।

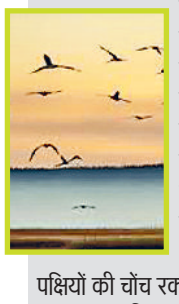

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।